Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही

3 मार्च, 2014

खण्ड-1, अंक-5

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 3 मार्च, 2014

	पृष्ठ संख्या
बजट अनुमानों पर चर्चा की अवधि संबंधी मामला उठाना	(5) 1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(5) 2
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(5) 28
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(5) 29
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना	(5) 42
वाक-आउट	(5) 44
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-	
(i) राज्य में निजी विद्यालयों के संचालकों में रोष संबंधी वक्तव्य-	(5) 44
शिक्षा मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में	(5) 48
(ii) हरियाणा के खेलकूद प्राधिकरण के गठन संबंधी	

वक्तव्य-

खेल एवं राज्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/अल्पावधि चर्चा की सूचना (5) 49

वर्ष 2014-15 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा तथा वित मंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भण) (5) 53

बैठक का समय बढ़ाना (5) 98

वर्ष 2014-15 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा तथा वित मंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भण) (5) 98

बैठक का समय बढ़ाना (5) 106

वर्ष 2014-15 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा तथा वित मंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भण) (5) 106

बैठक का समय बढ़ाना (5) 115

वर्ष 2014-15 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा तथा वित मंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भण) (5) 115

बैठक का समय बढ़ाना (5) 123

वर्ष 2014-15 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा तथा वित मंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भण) (5) 123

वर्ष 2014-15 के बजट की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (5) 129

विधान कार्य- (5) 138

(i) दि ईस्ट पंजाब यूटिलाइजेशन ऑफ लैण्डस (हरियाणा अमैंडमैन्ट) बिल, 2014

(ii) दि हरियाणा वैल्यू ऐडेड टैक्स (अमैंडमैन्ट) बिल, 2014

(iii) दि पंजाब शिड्यूल्ड रोड्ज एंड कंट्रोल्ड एरियॉज रिस्ट्रिक्शन ऑफ अनरैगुलेटेड डिवैल्पमैंट (हरियाणा अमैंडमैन्ट) बिल, 2014

बैठक का समय बढ़ाना (5) 143

विधान कार्य (पुनरारम्भण)-

(iv) दि हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रैगुलेशन ऑफ सोसायटीज (अमैंडमैन्ट) बिल, 2014 (5) 143

(v) दि हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्ज (टैम्पोरेरी रिलीज) अमैंडमैन्ट बिल, 2014

(vi) दि प्रिजन्स (हरियाणा अमैंडमैन्ट) बिल, 2014

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 3 मार्च, 2014

बिधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हॉल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में बाद दोपहर 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कुलदीप शर्मा) ने अध्यक्षता की।

बजट अनुमानों पर चर्चा की अवधि संबंधी मामला उठाना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, Now the Questions Hour.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर.....

Mr. Speaker : Mr. Arora, I will allow you and listen you after the Questions Hour. You may please sit down.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, आपके प्रोग्राम में आया है कि आज बजट पर डिस्कशन भी होगा और आज ही उसे पास करने जा रहे हैं। ऐसी क्या जल्दी है। हम भी इस सदन में बहुत सालों से देखते आ रहे हैं और आप पिछला इतिहास भी उठाकर देख लो ज्वाईंट पंजाब से लेकर अब तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन बजट पर डिस्कशन शुरू हुआ हो और उसी दिन बजट पास हो गया हो। सर, अभी तक हममें से न तो किसी ने गवर्नर अभिभाषण पर कोई चर्चा की है और न ही अपने-अपने हल्के की बात रखी है। मैं तो यह कहता हूं कि आज भी डबल सीटिंग करो और कल भी डबल सीटिंग करो ताकि सारे सदस्य अपनी बात रख सकें।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, आपने बहुत लिमिटिड पीरियड रखा है। अभी तक हममें से कोई भी सदस्य न तो गवर्नर अभिभाषण पर बोला है और न ही किसी सदस्य ने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी हैं। सर, हर विधायक के अपने क्षेत्र की बहुत समस्याएं होती हैं और जनता की भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनको हम आपके सामने रखते हैं और सरकार उन समस्याओं पर गौर करती है।

Mr. Speaker : I will give you full time.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, फुल टाईम भी कितना होगा? आज ही बजट पर डिस्कशन होना है और आज ही बजट पास हो जाएगा।

Mr. Speaker : I will give you maximum time.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मैक्सीमम टाईम भी कितना होगा?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, अब जाते-जाते हाऊस का समय तो बढ़ा दो। ताकि विपक्ष यह तो कहे कि स्पीकर साहब ने बहुत समय दिया।

श्री अध्यक्ष : कोई भी आदमी यहां दोबारा नहीं आना चाहता।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, आज जितने तक जो भी स्पीकर रहे हैं उनके मुकाबले ज्यादा समय देकर आप तो नया इतिहास लिख सकते हैं। लेकिन सर, जो भी स्पीकर रहा है वह लगभग दोबारा आया नहीं है। इसलिए अगर आप लम्बा समय दे दो तो अच्छी बात होगी और अच्छी परम्परा शुरू हो जाएगी। हम चाहते हैं कि बजट पर लम्बी डिबेट हो और उसके बाद सरकार अपना डिटेल जवाब दे।

Mr. Speaker : I fully agree with you and I will try to adjust everybody.

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Questions Hour.

तारांकित प्रश्न संख्या-1892

(इस समय माननीय श्री देवेन्द्र कुमार बंसल सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न नहीं पूछा गया।)

Replacement of Transformers

***1998. Shri Jagbir Singh Malik :** Will the Power Minister be pleased to stae whether the 10 MVA transformer has been placed in Bhatgoan village Power House as assured by the Power Ministe in March Session 2013; if not, the time by which the aforesaid transformer is likely to be replaced?

Power Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, the Power Transformers have not been installed yet. The existing 1x6.3/8+1x6.3/MVA Power Trasnformers are likely to be replaced with 2x10 MVA by 31.03.2014.

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे हल्के में जल्दी ही ट्रांसफार्मर लगाने के लिए कहा था लेकिन बहुत समय हो गया अब तक वहां ट्रांसफार्मर नहीं लगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, हमने जो फ्लॉर ऑफ दि हाऊस कमिटमैंट है हम उसको पूरा करेंगे और 31 मार्च 2014 तक इस काम को पूरा कर दिया जाएगा।

Mr. Speaker : He has given a date i.e. 31st March, 2014.

श्री जगबीर सिंह मलिक : स्पीकर सर, सन् 2013 में भी मंत्री जी ने टाईम दिया था आज भी मंत्री जी टाईम ही दे रहे हैं। यह ट्रांसफार्मर तबदील क्यों नहीं किए क्या इन्होंने हमारे क्षेत्र से पहले किसी दूसरे क्षेत्र के ट्रांसफार्मर तो तबदील नहीं किए हैं अगर किए हैं तो हमें वह लिस्ट दिखाएं और हाऊस में यश करके बताएं। Whether it is a last commitment?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, हमने यह काम एम एस सेंच्यूरी इम्फ्रा ऑफ पावर लिमिटिड, जयपुर को दिया है और लाइकली डेट ऑफ कम्पलीशन इसको पूरा कर दिया जाएगा।

श्री जगबीर सिंह मलिक : स्पीकर सर, उस ट्रांसफार्मर से 30 किलो मीटर दूर बिजली जाती है लेकिन वहां टांसफार्मर न लगने की वजह से वहां बिजली नहीं मिल रही वहां बिजली देने के लिए फोर्स करना पड़ता है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, 31 मार्च 2014 तक वहां ट्रांसफार्मर लग जाएगा।

श्री जगबीर सिंह मलिक : स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी ने इतने पावर स्टेशन लगा दिए लेकिन वहां ट्रांसफार्मरों की कमी के कारण बिजली नहीं पहुंच पा रही है। वैसे तो वहां चार-चार प्रभाणु ऊर्जा लगा दिए इतनी प्रोटैक्शन कर दी लेकिन उसकी सप्लाई करने में, रैगुलेशन करने में कमी रही है। सर, मैं यह कमिटमैंट चाहता हूं कि इसके लिए मेरे को दोबारा ना कहना पड़े।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, Hon'ble Member wants a very strong commitment.

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं मलिक साहब को विश्वास दिलाता हूँ कि 31 मार्च 2014 तक भटगांव बिजली घर में 10 एम.वी.ए.का ट्रॉंसफार्मर बदल दिया जायेगा तथा माननीय सदस्य को इस बारे में दोबारा से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अतिरिक्त मैं सदन के माध्यम से यह बताना भी उचित समझता हूँ कि सोनीपत में 14 नये सब-स्टेशंज लगाये गये हैं इसके अतिरिक्त 42 सब-स्टेशन का आगमैंटेशन किया गया है। इस प्रकार यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि काम करने में कोई कौताही बरती गई है। (विघ्न)

श्री जगबीर सिंह मलिक : स्पीकर सर, जैसाकि अभी मंत्री जी ने कहा है कि 10 एम.वी.ए. का ट्रॉंसफार्मर बदल दिया जायेगा, उस सूरत में मैं आज सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि अब इस तरह की शब्दावली से कि "करवायेंगे" या फिर "लगवायेंगे" काम नहीं चलेगा? हमें हल्के के अन्दर लोगों को फेस करना पड़ता है। मैं आज दोबारा से फिर इस सदन के माध्यम से मेरे हल्के की बिजली की समस्या से दुखी व त्रस्त लोगों की आवाज माननीय मंत्री जी को सुनाना चाहता हूँ। सरकार द्वारा बिजली की प्रोडक्शन बढ़ाकर लोगों को 24 घंटे बिजली मुहैया करवाई जा रही है लेकिन खराब ट्रॉंसफार्मर्ज नहीं बदले जाने की वजह से लोगों को बिजली सप्लाई में बाधा आ रही है। इसकी वजह से सरकार की ईमेज भी धूमिल होती है।(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, मंत्री जी ने अब कमिटमैंट कर दी है अब आपको ट्रॉंसफार्मर लगवाने के लिए दोबारा से कहना नहीं पड़ेगा।

श्रीमती सुमिता सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि हमारे किसानों को जो पीले रंग के ट्रॉंसफार्मर्ज उपलब्ध करवाये गये हैं, उन ट्रॉंसफार्मर्ज की चोरी की घटनायें आजकल आम होती जा रही हैं जिसकी वजह से किसान बहुत परेशान होते हैं। जब वे चोरी किये गये ट्रॉंसफार्मर्ज की एफ.आई.आर. लिखवाने जाते हैं तो अक्सर देखने में आता है कि संबंधित एस.डी.ओज. भी उनके साथ सहयोग नहीं करते हैं। क्या बिजली विभाग की तरफ से कोई ऐसी टाईम लिमिट निश्चित की गई है या फिर कोई ऐसा प्रावधान किया गया है कि जिसके तहत अगर कोई ट्रॉंसफॉर्मर चोरी हो जाये तो within a few days यानि 4 या 5 दिन के अन्दर ही चोरी किये गये ट्रॉंसफार्मर की जगह दूसरा ट्रॉंसफॉर्मर लगा दिया जायेगा। स्पीकर सर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जीरी की फसल बहुत ज्यादा मात्रा में लगाई जाती है। यदि जीरी के सीजन में ट्रॉंसफार्मर चोरी की घटना हो जाये तो आप खुद समझ सकते हैं कि किसान को कितनी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा? अत: मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाये?

Mr. Speaker : Mr. Minister, you may please respond to this.

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूँगा कि नार्मली तो गांव में जो ट्रॉंसफार्मर्ज जल जाते हैं उनको 24 घंटे के अन्दर बदल दिया जाता है बाकी जिन ट्रॉंसफार्मर्ज में कोई टैक्निकल खराबी आ जाती है उनको 48 घंटे के अन्दर बदल दिया जाता है। एच.पी.डी.एस.सी. की स्कीम के तहत प्राईवेट कॉंट्रेक्टर्ज को इन ट्रॉंसफार्मर्ज की देखरेख का जिम्मा दिया गया है। मैं समझता हूँ कि इसी वजह से माननीय सदस्या द्वारा बताई गई समस्या क्रियेट हुई है। अब जहां तक ट्रॉंसफार्मर्ज की चोरी रोकने की बात है तो इस मामले को गंभीरता से लिया गया है और अब ट्रॉंसफार्मर्ज में कॉंपर की कॉंयल(तार) के स्थान पर एल्युमिनियम कॉंयल (तार) का प्रयोग किया जाता है। कॉंपर की केबल महंगी होती थी इसी वजह से ट्रॉंसफॉंर्मर्ज में चोरी की संभावना बनी भी रहती थी। अब यह नया कदम उठाने की वजह से ट्रॉंसफॉंर्मर्ज की चोरी की घटनायें भी कम हो रही है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, जैसाकि मैडम सुमिता जी ने प्रश्न किया है कि किसानों को जो पीले रंग के इंडीविजुअल ट्रॉंसफॉंर्मर्ज उपलब्ध करवाये गये हैं, वह चोरी हो जाते हैं तथा जब चोरी किये गये ट्रॉंसफॉंर्मर्ज की एफ.आई.आर. लिखवाने जाते हैं तो संबंधित अधिकारी भी सहयोग नहीं करते हैं। उनके जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि चूंकि एच.पी.डी.एस.सी. की स्कीम के तहत प्राईवेट कॉंट्रेक्टर्ज को इन ट्रॉंसफार्मर्ज की देखरेख का जिम्मा दिया गया है इसलिए माननीय सदस्या द्वारा बताई गई समस्या क्रियेट हुई होगी। इस संबंध में मैं थोड़ा आगे बढ़ते हुए माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जब किसान के पीले रंगे के ट्रॉंसफॉंर्मर्ज चोरी हो जाते हैं तो चोरी किये गए ट्रॉंसफॉंर्मर्ज की जगह नये ट्रॉंसफॉंर्मर्ज लगवाने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है वह भी किसान से ही चार्ज किया जाता है। इस प्रकार से मेरे माननीय मंत्री जी से दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि यह जो पीले ट्रॉंसफॉंर्मर्ज हैं वह प्रदेश के कितने जिलों में लगाये गये हैं तथा दूसरा प्रश्न यह है कि जब किसान के ट्रॉंसफॉंर्मर्ज की चोरी हो जाती है तो क्या उसके बाद किसान को बिना पैसे लिए चोरी किए गए ट्रॉंसफॉंर्मर्ज की जगह नया ट्रॉंसफॉंर्मर्ज प्रोवाईड करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जो ट्रॉंसफॉंर्मर्ज खेतों में लगाए हुए थे उनकी चोरी की घटनायें बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। इस मामले को गंभीरता से लिया गया है। वर्तमान में अब यदि किसान के ट्रॉंसफॉंर्मर्ज की चोरी हो जाती है तो उस किसान से चोरी हुए ट्रॉंसफॉंर्मर्ज की 20 प्रतिशत कॉंस्ट डिपोजिट करवा ली जाती है जिसे किसान खुशी-खुशी डिपोजिट भी करवा रहे हैं और इस संबंध में विभाग को कोई ऑब्जैक्शन भी प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही किसान द्वारा ट्रॉंसफॉंर्मर्ज की 20 प्रतिशत कॉंस्ट डिपोजिट करवा दी जाती है उसी समय चोरी किये गये ट्रॉंसफॉंर्मर्ज की जगह नये ट्रॉंसफॉंर्मर्ज लगवा दिये जाते हैं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मंत्री जी कृपया मेरे पहले प्रश्न के बारे में भी तो बतायें कि किन-किन जिलों में एच.पी.डी.एस.सी. स्कीम के तहत प्राईवेट कॉंट्रेक्टर्ज को पीले रंग के ट्रॉंसफार्मर्ज की देखरेख का जिम्मा दिया गया है?

कैप्टन अजय सिंह यादव : सर, यह योजना कुरूक्षेत्र, करनाल, कैथल तथा एक अन्य जिले में भी लागू है। (विघ्न)

Mr. Speaker : Yes Sampat Ji, I know you can only give a suggestion in this regard.(Interruption) Hon'ble Minister, Prof. Sampat ji is giving just a suggestion. (Noise & Interruption)

Prof. Sampat Singh : Speaker Sir, I want to give two suggestions in this regard. My first suggestion is that राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत गरीब परिवारों को बिजली सुविधा करवाने के लिए बिजली के कनैक्शंज प्रोवाईड करवाये गये हैं तथा इस योजना के तहत ट्रॉंसफार्मर्ज भी लगवा दिये गये हैं। एक तरह से इस योजना का लगभग सारा इंफ्रॉस्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है लेकिन बावजूद इसके भी ट्रॉंसफार्मर्ज की कनैक्टिविटी मीटर तक नहीं हो पाई है और फलतः इन ट्रॉंसफॉर्मर्ज का कोई यूज नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी को सुझाव है कि इन ट्रॉंसफार्मर्ज की कनैक्टिविटी मीटर तक करवा दी जाये तो लोगों को बहुत फायदा होगा तथा साथ ही इस योजना पर लगाये गये पैसे का भी भरपूर इस्तेमाल हो सकेगा। ट्रॉंसफॉर्मर्ज के बारे में मेरा दूसरा सुजैशन यह है कि on contract basis सारे ट्रॉंसफॉर्मर्ज लगाये जा रहे हैं। कॉंट्रैक्ट बेसिज पर लगाये जाने वाली ट्रॉंसफॉर्मर्ज में यह समस्या आ रही है कि यदि ट्रॉंसफॉर्मर्ज खराब हो जाते हैं तो खराब ट्रॉंसफॉर्मर्ज को महीनों तक भी नहीं बदला जाता है। इस संबंध में मेरा सिर्फ यही कहना है कि यदि विभाग का संबंधित एजेंसी के साथ कॉंट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो उसके तुरन्त बाद उस काम को "ऑपरेशन विंग" को दे दिया जाना चाहिए। ट्रॉंसफॉर्मर्ज की कमी की वजह से भी हमारे सामने कई बार यह समस्या आकर खड़ी हो जाती है कि जब "ऑपरेशन विंग" के पास ट्रॉंसफॉर्मर्ज के लिए जाते हैं तो जिम्मेदारी "कंस्ट्रक्शन विंग" पर डाल दी जाती है। जब "कंस्ट्रक्शन विंग" के पास जाया जाता है तो कह दिया जाता है कि यह काम तो "प्राईवेट ठेकेदार" का था जोकि काम छोड़कर बीच में ही भाग गया है। 10 एम.वी.ए. के जो ट्रॉंसफॉर्मर्ज होते हैं उनको सब-स्टेशंज के अपग्रेडेशन के लिए यूज किया जाता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के साढ़वा गाँव में भी ऐसा अनुभव हमें देखने को मिला है कि जहां पर विगत दो साल से ट्रॉंसफॉर्मर मंजूर हो चुके हैं, पैसे भी मंजूर हैं लेकिन ट्रॉंसफॉर्मर अभी तक नहीं लगाया गया है। विभाग ने कितने सालों के बाद 10 एम.वी.ए. के ट्रॉंसफार्मर्ज खरीदे हैं जोकि बहुत गलत बात है। वास्तव में इसके लिए एक "रेगुलर खरीद सिस्टम" बनाना बहुत जरूरी है। रेगुलर खरीद न होने की वजह से सारे सब-स्टेशंज में ट्रॉंसफॉर्मर्ज की उपलब्धता डिले होती रहती है। सरकार के पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं हैं, जो सब-स्टेशंज ओवर लॉडिड हो रहे हैं उसकी वजह से समस्याएँ पैदा होती हैं। स्पीकर सर, केवीए ट्रॉंसफार्मर्ज तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होते हैं। एम.वी.ए. के ट्रॉंसफार्मर्ज ट्रॉंसमिशन के लिए होते हैं। इसके बिना जो सब-स्टेशंज ओवर लॉडिड हो रहे हैं, उन सभी सब-स्टेशंज में समस्याएँ आ रही हैं वे चाहे कहीं पर भी हों। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि इन ट्रॉंसफार्मर्ज की रैगुलर खरीद का सिस्टम बनायें और इसके लिए आपकी एक रैगुलर डेयरी हो जिसमें इसका पूरा विवरण हो, यदि संभव हो सके तो ऑन-लाईन सिस्टम भी बनाया जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आये। अब तक एच.पी.डी.सी.सी. सिस्टम में से जो ट्रॉंसफार्मर्ज उतारे थे, जो कुछ रिप्लैस किये थे, पहले वाले ट्रॉंसफार्मर्ज का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं हैं, यदि रिकॉर्ड हो तो विभाग से मंगवा लिया जाये कि कितने रिप्लैस हुये और कितने उनमें से कम हुये हैं।

Mr. Speaker : Simple suggestion है, नोट कर लिया है।

तारांकित प्रश्न संख्या 1799

(इस समय माननीय सदस्य श्री राम निवास घोड़ेला सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न नहीं पूछा गया)

Arrangements for Drinking Water

***1803. Dr. Hari Chand Middha :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to stae whether it is a fact that there is no facility of drinking water in village Baraudi; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a water works in village Baraudi; if so, the time by which it is likely to be constructed?

Public Health Engineering Minister (Smt. Kiran Chaudhary) : No Sir.

डॉ० हरि चन्द मिद्ढा : अध्यक्ष महोदय, हमारे स्टेट के अंदर पानी की बहुत कमी रहती है फिर भी मंत्री जी ने अपने जवाब में ना कह दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मेरे हल्के के गाँव बड़ौदी और बरसौला में तथा कई गाँवों में पीने के पानी की बहुत कमी है और इसमें मन्त्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि नहीं। इस प्रकार से लोगों की समस्याओं का कौन ध्यान रखेगा?

श्री अध्यक्ष : आपकी सप्लीमैंटरी क्या है? It is not a supplementary.

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, बड़ौदी गाँव एक ऐसा गाँव है, कि उस गाँव में और आस-पास के 8 किलोमीटर के एरिया के गाँवों में जमीन के नीचे का पानी एवेलेबल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, वहाँ पर नहर की कोई भी आउट लाईन नजदीक नहीं है। इस वजह से वहाँ के लोगों को पीने के पानी के लिए उपलब्ध करवाने के बारे में यह ओरीजनल प्रश्न था। मैं माननीय मंत्री जी से और सरकार से भी प्रार्थना करता हूँ कि उस इलाके के अंदर नाबार्ड जैसी कोई योजना लाई जायेगी ताकि वहाँ के गाँवों के लोगों को पीने का पानी जल्दी से जल्दी मुहैया करवाया जा सके। क्योंकि आसपास के दस गाँवों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, do you have any planning like that?

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि they have 37 villages and जो मापदंड है, उसके हिसाब से 40 LPCD पानी वहाँ पर उपलब्ध है परन्तु इनकी यह बात सही है, वहाँ पर पानी की कमी है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कभी भी इस बात के लिए रिक्वेस्ट नहीं की है। माननीय सदस्य को इस बात की खुशी होगी कि विलेज बड़ौदी में इंडिपेंडेंट canal water based water works के लिए 106 लाख रुपये सरकार मंजूर करने जा रही है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैंने हाउस में उस दिन भी यह बात कही थी कि जहाँ-जहाँ किसी को कोई भी समस्या आती है। हम सैनेट्री बोर्ड की मीटिंग में इन समस्याओं को उठाते हैं और जितनी भी दिक्कतें होती हैं हम उनको सॉल्व करते हैं। आज सैनेट्री बोर्ड की मीटिंग होने जा रही है और उस मीटिंग में यह मुद्दा भी रखेंगे। जिस-जिस ने भी अपनी समस्याएँ मुझे लिखित तौर पर दी हैं, मैं उनकी समस्याओं को कमेटी में रखूँगी और उन सभी

समस्याओं को हल करने का प्रयास भी किया जायेगा, लेकिन इनकी तरफ से आज तक कभी भी हमारे पास रिक्वेस्ट नहीं आई है। अध्यक्ष महोदय, जहाँ पर भी पानी की कमी है, सरकार वहाँ पर भी पानी की कमी को दूर करने का प्रयास कर रही है।

Four Laning of Hisar to Rohtak road

***1792. Shri Sampat Singh :** Will the PW(B&R) Minister be pleased to state:—

(a) the status of the four laning project from Hisar to Rohtak togehterwith the time by which the work of aforesaid project is likely to be started alongwith the total cost and the amount spent on this project till today;

(b) the salient features of this project and the time by which this project is likely to be completed; and

(c) the status of railway line from Hansi to Rohtak via Meham?

Public Health Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir,

(a) & (b) The maintenance and upkeep of NH-10 is the responsibility of the National Highways Authorty of India (NHAI), Ministry of Road Transport and Highways (MORT&H), Government of India (GOI).

The work on the project of 4 lanning of the Hisar-Rohtak road costing approximately Rs. 959 crore (excluding land and utility shifting costs) was commenced on 26.1.2013. Till date, an amount of Rs. 230.93 crore has been spent on this project in land acquisition and other preconstruction activities.

The salient features of this project are as under :—

- Length of the project is 99 Km.
- Project is on BOT (Toll) basis.
- The name of the concessionaire is M/s Rohtak Hisar Tollway Private Limited.
- The construction period is 910 days.
- Concession period is 22 years.
- 2 ROBs, 5 Grade separators, 1 FOB and 5 By-passes (at Rohtak, Medina, Kharkhara, Meham & Hansi) are to be constructed under the project.
- There are 2 Toll Plazas at Km. 94 and Km. 149.

The likely date of completion of this poejcts is June, 2016.

[Shri Randeep Singh Surjewala]

(c) The construction of railway line from Hansi to Rohtak via Meham is being executed by the Ministry of Railways, Government of India.

Tentative total cost of the project is Rs. 406.87 crore including land cost of Rs. 114 crore. Haryana Government has accorded administrative approval for Rs. 260.43 (state portion) vide letter No. 6/1/2013-2B&R (W) dated 18.03.2013 to provide land free of cost and to share 50% construction cost for this project. The State has initiated the process for acquisition of required land under Section-4 of L.A. Act, 1894 vide Notification No. 28RA/199/IV/45 dated 20-12-2013 which was published in Haryana Government Gazette on dated 20-12-2013. The State has deposited a sum of Rs. 10 crore with Railways for preconstruction activities of the project.

प्रो.संपत सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है लैंड एक्वीजिशन पर सरकार द्वारा अब तक इतना पैसा खर्च किया जा चुका है। रोड़ के ऊपर टोटल लैंड एक्वायर हो चुकी है और पोजैशन भी मिल चुकी है। इसके टन्डरफलोर करने के बारे वर्क ऑर्डर कब तक हो जायेगें। इसी तरह रेलवे के बारे में भी है, उसके ऊपर लैंड एक्वीजिशन की प्रक्रिया कब पूरी हो जायेगी और वर्क आर्डर कब तक हो जायेंगे?

Shri Aftab Ahmed : Sir, the project is to be completed by June, 2016. Already, the work of the acquisition has been completed. Other reconstruction activities are already going on. इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि रेलवे लाईन का सैक्शन चार का नोटिस 20.12.2013 को हो गया है और स्टेट ने 10 करोड़ रुपये रिकंस्ट्रक्शन एक्टीविटीस के लिये जमा भी करवा दिये हैं।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि कुण्डली मानेसर एक्सप्रैस हाइवे की क्या प्रोग्रैस है ?

Mr. Speaker : That is a separate question?

श्री राम पाल माजरा : सर, मैं सवाल के बारे में भी पूछ लूंगा। सर, यह जो बी.ओ.टी. लेवल पर बनेगा, जो सवाल पूछा है उसके जवाब में आया है। सर, हरियाणा प्रदेश में आन्दोलन हो रहे हैं और नेशनल हाइवे फीस एण्ड कलैक्शन रूल 2008 की उल्लंघना हो रही है। सर, बिना किसी आधार के टोल टैक्स में वृद्धि कर दी जाती है। (विघ्न)

Mr. Speaker : It is not a supplementary. It is not related to this matter. You should ask only specific question. Not be taken notice of it. (Interruption). You should ask only specific question.(Interruption). You are only making a speech. It is not required to be answered. I am not recognizing this question at all. Shri Phool Singh Kheri ji, please carry on.

---

* Answered by Shri Aftab Ahmed (Transport Minister)

Haryana Roadways Bus Service

***1948. Shri Phool Singh Kheri :** Will the Transport Minister be pleased to stae whether there is any proposal under consideration of the Government to start Haryana Roadways Bys-Service from Kangthali to Kakrala, Kakrala to Pabsar, Pabsar to Kakyor Majra, Kakyor Majra to Prempura, Prempura to Rampura, Kawarton to Kaithal; if so, the time by which it is likely to be started?

Transport Minister (Shri Aftab Ahmed :) : No Sir.

भाई फूल सिंह खेड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि कांगथली, ककराला, पाबसर, प्रेमपुरा, रामपुरा और कवारतन के लिए हरियाणा परिवहन बस-सेवा आरम्भ होगी क्या ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, पाबसर से कक्योर माजरा को-ऑपरेटिव बस चल रही है। कवारतन से कैथल भी चल रही है। बाकी रूटों पर बस नहीं चल रही है, जैसे ही अवेलिबिलिटी हो जाएगी बस-सेवा आरम्भ कर दी जायेगी।

भाई फूल सिंह खेड़ी : स्पीकर सर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि कब तक यह सेवा आरम्भ कर देंगे ? सर, मैंने हर बार अपने सवाल लगाए। सभी सवालों का कोई जवाब नहीं आता है। चाहे मैंने प्रश्न लड़कियों के स्कूल के बारे में और सड़कों के बारे में लगाया हो, सभी प्रश्नों का उत्तर ना में ही आता है।

श्री आफताब अहमद : स्पीकर सर, हम जल्दी ही इस रूट पर बस-सेवा आरम्भ कर देंगे।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि हरियाणा सरकार लड़कियों के लिए बहुत से कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोल रही हैं। क्या मंत्री जी हरियाणा प्रदेश में महिला स्पेशल बस सर्विस के तहत जो हमारे गांव से लड़कियाँ और बेटियां शहर में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आती हैं, जिन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए बस सेवा शुरू करने जा रहे हैं। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आपसे नम्र निवेदन है कि खासतौर से गांव की लड़कियों और बेटियों के लिए यह सेवा शुरू कर दीजिए।

Shri Aftab Ahmad : Sir, we will certainly consider it positively.

श्री जगदीश नैय्यर : स्पीकर सर, आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि हमारे होडल में एक सब डिपो था और वह तोड़ दिया उसे दोबारा बनाने का काम करेंगे ? होडल के लोगों के साथ यह बड़ा भेद-भाव किया जा रहा है।

श्री अफताब अहमद : स्पीकर सर, माननीय सदस्य इस बारे में लिख कर दे दें। हम उस पर विचार करेंगे।

Regulatory Body for Alternate Medicine

***1862. Shri Krishan Lal Panwar :** Will the Health Minister be pleased to stae whether there is any proposal under consideration of the Government for setting up a Board or a Body to regulate the practice of alternate medicine especially Yoga and Naturopathy in the city State of Haryana?

Health Minister (Rao Narender Singh) : No Sir.

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने आयुष विभाग में बी.एन.वाई.एस. (Bachelor of Naturopathy and Yogic Sciences) स्कीम के तहत पी.जी. डिग्री में योगा तथा नैचरोपैथी डॉक्टर भर्ती किये हैं। क्या उन डाक्टर्ज के पास प्रौपर क्वालिफिकेशन जो कि निर्धारित है, वह है। उनमें से एक डॉक्टर पंचकूला के सामान्य अस्पताल में कार्यरत है।

Mr. Speaker : You mean they do not possess requisite qualification. Will you give names of those doctors?

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, पंचकूला सामान्य अस्पताल में कर्म सिंह के नाम से एक डॉक्टर भर्ती किया है जिसके पास बी.एन.वाई.एस. डिग्री और पी.जी. इन योगा एंड नैचुरोपैथी की डिग्री नहीं है। इसी तरह से फतेहाबाद में इन्होंने एक डॉक्टर भर्ती किया है उसका नाम मैं आपको बाद में बता दूंगा। उसकी क्वालिफिकेशन बी.ए. और एम.ए. है।

Mr. Speaker : What is his name?

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैंने पंचकूला में नियुक्त किए गए डॉक्टर का नाम बता दिया है। फतेहाबाद वाले डॉक्टर का नाम मैं बता दूंगा।

Mr. Speaker : Let him check.

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि क्या जो डॉक्टर भर्ती किए गए हैं उनकी क्वालिफिकेशन की वैरीफिकेशन कराएंगे ? सर, उनके पास प्रौपर डिग्री नहीं है।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister please respond to his question.

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि हमने 21 योगा और नैचुरोपैथी के स्पैशलिस्ट डॉक्टर हर जिले के अंदर एन.आर.एच.एम. के तहत कंट्रैक्ट पर भर्ती किए हैं। उन सभी की क्वालिफिकेशन आयुर्वेद से या होम्योपैथी से या दूसरी डिग्रीज से जो पी.जी.डिप्लोमा थे, उनको भर्ती किया गया है। ऐसा कोई डॉक्टर मेरी जानकारी में नहीं है जो क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं करता हो फिर भी माननीय सदस्य ने यह मुद्दा सदन के समक्ष रखा है तो हम इस बात की जांच करेंगे।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने भर्ती के लिए बोर्ड का गठन ही नहीं किया। भारत सरकार के पैटर्न के तहत भी हरियाणा सरकार द्वारा बोर्ड का गठन किया जाना जरूरी था।

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, बोर्ड एक अलग चीज है। जो स्टूडैंट्स क्वालिफिकेशन फुलफिल करके आ रहे हैं उन्हीं को नौकरी में लिया जा रहा है। हमारे प्रदेश में या आस पास कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जो कि योगा और नैचुरोपैथी के कोर्सिज की डिग्री देता हो, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर 18 ऐसे कालेजिज हैं। उनकी लिस्ट मैं माननीय सदस्य यदि चाहेंगे तो उनके पास भी भिजवा दूंगा। जो उन संस्थानों से डिग्री लेकर आते हैं उनको हम इन पदों पर भर्ती कर सकते हैं।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, बैचलर ऑफ नैचुरोपैथी डिग्री इन यौगिक साइंसिज प्लस पी.जी.डिग्री इन यौगिक एंड नैचुरोपैथी क्या इस डिग्री के डॉक्टर भर्ती किए गए हैं, यदि नहीं किए गए हैं तो क्या सरकार उनके खिलाफ या भर्ती करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ?

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि हमने डॉक्टर भर्ती किए हैं जो क्वालिफिकेशन फुलफिल करते थे उनको भर्ती किया गया है। ऐसा कोई डॉक्टर मेरी जानकारी में नहीं है जो क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं करता हो। जहां तक माननीय सदस्य श्री कृष्ण लाल पंवार ने एक डॉक्टर कर्म सिंह का नाम बताया है he is having Post Graduation qualification. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि essential qualification for Yoga specialist is Bachelor Degree in Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Homeopathy or B.N.Y.S. (Bachelor of Naturopathy and Yogic Sciences) or in any stream from any university / institution established by law and recognized by the Government. And the second essentiality required for this post is Post Graduate Degree or Diploma in Yoga and Naturopathy of not less than two years duration with regular course only. इस तरह से हमने नॉर्म्स बनाये हुये हैं और उसी के आधार पर भर्तियां की गई हैं। कोई भी भर्ती इल्लीगल या गलत तरीके से नहीं की गई है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह जो डॉक्टर का नाम माननीय सदस्य ने बताया है इस मामले की इंक्वायरी के लिए तो आदेश दे दें।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, please have an enquiry into the matter properly.

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य लिखकर दे दें तो हम इस मामले की इंक्वायरी करवा लेंगे।

To Include Village Bandepur in the Municipal Council

***1854. Smt. Kavita Jain :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to stae—

(a) whether there is any proposal under consieration of the Government to include the village Bandepur adjacent ot Sonepat city in the Municipal Council; and

(b) is so, the time by which the aforesaid village is likely to be included in Municipal Council?

शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री (श्रीमती सावित्री जिन्दल) : श्रीमान् जी, विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) नगर परिषद्, सोनीपत में गांव बन्देपुर के क्षेत्र को शामिल करने हेतु हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की धारा 4 (2) में निहित प्रावधानों अनुसार उपायुक्त के माध्यम से क्षेत्र के निवासियों से छः सप्ताह के अन्दर आपत्तियां, यदि कोई हो, आमन्त्रित करने हेतु दिनांक 06.02.2014 को प्राथमिक अधिसूचना जारी की गई है। निर्धारित प्रक्रिया अपनाने उपरान्त तदानुसार इस सम्बन्ध में अन्तिम अधिसूचना जारी कर दी जायेगी।

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि वर्ष 2009 में सोनीपत विधान सभा क्षेत्र का जब परिसीमन हुआ तो उसमें कबीरपुर पंचायत को सोनीपत नगर परिषद के एरिया में ले लिया गया। कबीरपुर पंचायत के अंतर्गत तीन गाँव कबीरपुर, शादीपुर और बंदेपुर आते हैं। उन तीन गांवों के स्थान पर दो गांवों कबीरपुर और शादीपुर को तो उसमें शामिल कर लिया गया लेकिन बंदेपुर को लावारिस छोड़ दिया गया। 2009 के बाद से अब तक सोनीपत के चार डी.सी. आ चुके हैं और इस बारे में लगातार बार बार हम सभी डी.सीज. से मिल चुके हैं। म्युनिसिपल कमेटी में जा जाकर भी मिल चुके हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। पिछले सत्र में मैंने विधान सभा में भी बंदेपुर को नगरपरिषद की सीमा में शामिल करने के लिए प्रश्न लगाया था। स्पीकर सर, इस बजट सत्र के शुरू होने के बाद हमने बान्देपुर गाँव को म्यूनिस्पिल काउंसिल में शामिल करने के लिए दोबारा से क्वैश्चन लगाया है। यह क्वैश्चन लगाने के बाद ही इस गाँव को म्यूनिस्पिल काउंसिल में शामिल किया गया है उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करती हूं।

Mr. Speaker : Your question was limited to that extent. You can't ask anymore question on that because the Government has already included it in its reply.

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, पिछले साढ़े साल चार के समय में उस गाँव में विकास के नाम पर एक भी ईंट नहीं लगाई गई। इस समय के दौरान सड़कों के मामले में , बिजली के मामले में, पीने के पानी के मामले में वहां के लोगों के लिए म्यूनिस्पिल काउंसिल द्वारा कुछ नहीं किया गया। क्या सरकार द्वारा इन कामों को दुरूस्त करने के लिए कोई कदम उठाये जायेंगे ? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि इस काम के लिए विभाग की तरफ से जो लापरवाही हुई है उसके बारे में एक्शन लेने के लिए क्या कोई कदम उठाये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, माननीय सदस्या यह पूछ रही हैं कि बान्देपुर गाँव को म्यूनिस्पिल काउंसिल में शामिल करने के बाद क्या आप वहां पर विकास के कार्य करवायेंगे ?

श्रीमती सावित्री जिन्दल : स्पीकर सर, म्यूनिस्पिल काउंसिल के तहत जो भी विकास के कार्य करवाये जाते हैं वे सभी कार्य बान्देपुर गाँव में भी करवा दिये जायेंगे।

Cash Less Medical Scheme

***1889. Shri Naseem Ahmed :** Will the Health Minister be pleased to stae the time by which the Cast Less Medical Scheme is likely to be implemented in the State for the Haryana Government Employees?

स्वास्थ्य मन्त्री (राव नरेन्द्र सिंह) : श्रीमान् जी, मामला सक्रिय विचाराधीन है।

श्री नसीम अहमद : स्पीकर सर, यह हरियाणा सरकार के कर्मचारियों का एक महत्वपूर्ण मामला है। आज जिस तरीके से प्रदेश के कर्मचारी समस्या झेल रहे हैं उसके लिए कैशलैस मेडिकल स्कीम बनाना बहुत जरूरी है।

Mr. Speaker : Please ask your supplementary. Don't make a speech. Nothing is to be recorded.

श्री नसीम अहमद : स्पीकर सर, ***** यह स्कीम हरियाणा प्रदेश के अन्दर कब तक लागू कर दी जायेगी और इस स्कीम को लागू करने की कोई प्रक्रिया सरकार द्वारा क्या शुरू की है या नहीं ?

राव नरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस मामले को लेकर चीफ सक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है और यह मामला उस कमेटी के पास विचाराधीन है। इसके अलावा मैं माननीय सदस्य को और इस सदन को यह बात जरूर बताना चाहूंगा कि आज की डेट में हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए मेडिकल की सुविधा को लेकर जो पॉलिसी हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई हैं वह बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। इस पॉलिसी के तहत हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को हर प्रकार की मेडिकल सुविधाएं मुफ्त दी जा रही हैं। उसमें चाहे कोई आपरेशन हो चाहे दूसरी कोई भी बीमारी हो उसका ईलाज हर सरकारी अस्पताल में मुफ्त दिया जा रहा है। इसके साथ ही हरियाणा के कर्मचारियों को हर महीने 500 रुपये मेडिकल एलाउंस भी दिया जा रहा है। इसके अलावा जो 18 क्रोनिक बिमारियां हैं उनके लिए भी हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को ईलाज के खर्चे की फुल रिईम्ब्रैसमैंट की सुविधा दी जा रही है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी हरियाणा के किसी सरकारी अस्पताल में, यू.टी. चण्डीगढ़ के अस्पताल में या एम्स, नई दिल्ली में ईलाज करवाता है तो उसके लिए भी उसके ईलाज पर हुए खर्चे का फुल रिइम्ब्रैसमैंट दिया जा रहा है। इसके अलावा 34 प्राईवेट होस्पिटल्ज को हमने सरकार के इम्पैनल पर रखा है। इन होस्पिटल्ज से भी हरियाणा के कर्मचारी ईलाज की पूरी सुविधा ले सकते हैं। इसके अलावा 13 प्राईवेट अस्पताल भी इस लिस्ट में शामिल किए हैं। इसके साथ ही 21 ऐसे पैकेज तैयार किए हैं जिनका फुल रिइम्ब्रैसमैंट दिया जाता है। जिस प्रकार की हैल्थ पॉलिसी हरियाणा प्रदेश के अन्दर है ऐसी पॉलिसी देश के अन्दर कहीं पर भी नहीं है।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Upgradation of Schools

***1906. Shri Narender Sangwan :** Will the Education Minister be pleased to stae whether there is anry proposal under consideration of the Government to upgrade Government Schools, including G.S.S., Hassanpur upto 10+2 in Gharaunda Constituency; if so, the details thereof?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matenhail) : No Sir.

श्री नरेन्द्र सांगवान : स्पीकर सर, आज तक मैंने जितने भी सवाल सदन में दिए हैं उन सब सवालों का उत्तर मंत्री जी की तरफ से "ना" में ही आया है। सरकार की तरफ से बड़े दावे किए जाते हैं कि हरियाणा प्रदेश एजुकेशन के मामले में हब बना दिया गया है और हरियाणा एजुकेशन के मामले में नम्बर एक बन गया है।

श्री अध्यक्ष : सांगवान जी, आप अपना सप्लीमैंट्री पूछिये।

श्री नरेन्द्र सांगवान : सर, यह स्कूल सरकार के सारे नार्म्ज पूरे करता है।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, अगर यह स्कूल सरकार के नार्म्ज पूरा करता है तो हम उस स्कूल को अपग्रेड कर देंगे।

श्री नरेन्द्र सांगवान : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि अगर यह स्कूल सरकारी नार्म्ज पूरे करता है तो इस स्कूल को क्या अपग्रेड कर दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : सांगवान जी, मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है कि अगर यह स्कूल नार्म्ज पूरे करता होगा तो इसको अवश्य ही अपग्रेड कर दिया जायेगा।

श्री नरेन्द्र सांगवान : स्पीकर सर, मेरे हल्के में एक स्कूल ऐसा है जिसके दसवीं कक्षा के सारे बच्चे फेल हो गये हैं। क्या सरकार द्वारा इस प्रकार से ही एजुकेशन के मामले में ध्यान दिया जा रहा है ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने कहा है कि सरकार शिक्षा के बड़े बड़े दावे कर रही है इसलिए मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगी कि गवर्नमैंट हाई स्कूल, हसनपुर में नौवीं और 10वीं के बच्चों की संख्या 74 है जबकि नार्म्ज के मुताबिक स्कूल अपग्रेडेशन के लिए बच्चों की संख्या 150 होनी चाहिए। जहां तक एवेलेबिलिटी आफॅ स्कूल की बात है तो थोड़े डिस्टैंस पर दूसरा स्कूल है इसलिए भी इनका स्कूल अपग्रेड नहीं किया जा सकता। इस स्कूल में कमरों की जरूर कमी है। बच्चे पूरे होंगे तो हम कमरे भी बना देंगे। इनके हल्के में हम आलरेडी 13 स्कूल अपग्रेड कर चुके हैं। 8 प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल में अपग्रेड किया गया है। 3 नए प्राइमरी स्कूल भी खोले गए हैं तथा कुछ हाई स्कूलों को सीनियर सैकेंडरी स्कूलों में भी अपग्रेड किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सदस्य को यह लिस्ट दे दूंगी ताकि उनकी जानकारी में आ जाए कि उनके हल्के में कौन कौन से स्कूल अपग्रेड किए गए हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, नरेन्द्र सांगवान जी ने प्रश्न किया कि क्या हमारे हसनपुर के हाई स्कूल को सीनियर सैकेंडरी स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा तो मंत्री जी ने एक

मिन्ट में जवाब दे दिया कि यह स्कूल नार्म्ज पूरे नहीं करता। यह ठीक है कि नार्म्ज पूरे होने चाहिएं लेकिन नार्म्ज तब पूरे होंगे जब शिक्षा की हालत में सुधार होगा। जब तक शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं होगा तब तक नार्म्ज पूरे नहीं हो सकते।

Mr. Speaker : You have started a speech. Ask your Supplementary.

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, 15 स्कूलों का रिजल्ट जीरो परसैंट जो रहा है उसकी जिम्मेवारी किस की है, इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इसकी जिम्मेवारी शिक्षा विभाग और सरकार की है। अगर ये शिक्षा के स्तर में सुधार करेंगें तो मान कर चलो कि रिजल्ट में सुधार आएगा। शिक्षा में सुधार करेंगें तो बच्चे अपने आप स्कूलों में आ जाएंगें। शिक्षा का स्तर ठीक न होने की वजह से बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए ये क्या कर रहे हैं।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय साथी ने जो चिंता जाहिर की है यह वास्तव में ही चिंता का विषय है। जहां हम शिक्षा के अधिकार को लागू कर रहे हैं वहीं शिक्षा के अधिकार के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन देना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। जिन स्कूलों में जीरो से 20 परसैंट रिजल्ट आया है वहां हमने रिस्पोंसबिलिटी फिक्स की है। कुछ स्कूलों में टीचर्स की एवेलेबिलिटी न होना इसका कारण है और दूसरा कारण एबसैंटिज्म था। जिन स्कूलों में जो भी कारण निकल कर आए हैं हम उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं और इस समैस्टर में जो रिजल्ट निकल कर आया है उसमें काफी ज्यादा सुधार भी आया है। इसके अलावा हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम क्वालिटी एजूकेशन पर जोर दें। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत फ्री कापी, बुक्स और वर्दी दी जाती है लेकिन आठवीं कक्षा तक किसी बच्चे को हम फेल नहीं कर सकते जिसकी वजह से जो स्क्रीनिंग 8वीं के स्तर पर होती थी वह अब10वीं के स्तर पर होती है। मैं हमारे सम्मानित साथी को कहना चाहूंगी कि हमने नए स्कूल अपग्रेड भी किए हैं, स्कूलों में टीचर्स भी दिए हैं और जीरो से 20 परसैंट रिजल्ट के जो कारण हैं हम उनकी जांच करके उन पर कार्यवाही भी कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आप इन स्कूलों की लिस्ट मंत्री महोदया को दे दें।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, हमारे पास लिस्ट एवेलेबल है और हमने कार्यवाही भी की है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, वह लिस्ट रोजाना दैनिक ट्रिब्यून में आ रही है। लगातार 15 दिन से दैनिक ट्रिब्यून पेपर में आ रहा है कि किस तरह से किस किस स्कूल में कितने टीचर्स की कमी है और यदि कहीं टीचर्स पूरे हैं तो उस स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है उसके सारे कारण उसमें लिखे हुए हैं। एक एक चीज इनके पास है और यदि नहीं है तो मैं इनको दे देता हूं।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, हमारे पास सब चीजें हैं। अध्यक्ष महोदय, रामपाल माजरा जी बार बार यहां स्कूलों की लिस्ट लहरा रहे हैं। ये कलायत से एम.एल.ए. हैं। इन्होंने कलायत में कभी मॉडल स्कूल खोलने का, स्कूल अपग्रेड करने का या कोई स्कूल बनाने का धन्यवाद नहीं किया। इन्होंने वहां किसी स्कूल का विजिट नहीं किया। मैं विधानसभा में इनसे पूछना चाहती हूं कि क्या ये कभी स्कूलों में गए हैं या स्कूलों का कभी जिक्र भी किया है।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, जीरो रिजल्ट आने का सबसे बड़ा कारण 8वीं क्लास तक के बच्चों को फेल न करना है। चाहे कोई पेपर दे या न दे उसको फेल न किया जाना इसका सबसे बड़ा कारण है। मेनली देहाती इलाके के लिए यह चीज बहुत खतरनाक है। हमारी बहन जी बहुत काबिल मंत्री हैं और ये सैंटर कमेटी की भी मैम्बर बन गई हैं। इस बारे में मैंने पहले भी विधानसभा में यह बात उठाई थी और मैंने उनसे रिक्वैस्ट भी की थी कि आप इस बात को सैंटर कमेटी में उठाएं। बड़े लोग तो अपने बच्चों को शहरों में पढ़ाते हैं और शहरों के बाद विदेशों में भेज देते हैं। इस हिन्दुस्तान में 70 परसैंट आबादी देहात में रहती है इसलिए देहाती इलाके के बच्चों का क्या होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इसमें सैंटर नीति को छोड़कर अपने प्रदेश की नीति बना ली जाए। कोई जरूरी नहीं है कि इस बारे में हम सैंटर के एक्ट पर चलें। इस बारे में हमें गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। अगर इसी तरह रहा तो आने वाले समय में हमारे देहात के बच्चे आगे नहीं बढ़ सकेंगे इसलिए इस पर विचार करके हमें अपनी स्टेट के एक्ट में संशोधन करना चाहिए।

डॉ. बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि पिछले सैशन में मैंने रादौर ब्लॉक के खुरदबंद गांव के स्कूल को अपग्रेड करने के बारे में प्रश्न किया था और मंत्री महोदया ने इस स्कूल को अपग्रेड करने का आश्वासन भी दिया था। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या इस सत्र से खुरदबंद गांव का स्कूल बढ़ी हुई क्लासिज के साथ चलेगा ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, हम प्रदेश में जो भी स्कूल नार्म्ज पूरे करते हैं उनको अपग्रेड कर रहे हैं। हमारे पास पहले टीचर्स की कमी थी लेकिन अब टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया चल रही है जिसके कारण टीचर्स की आने वाले समय में कोई कमी नहीं रहेगी। मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगी कि जिला यमुनानगर में सबसे ज्यादा 207 स्कूल 2001 से लेकर 2014 के दौरान अपग्रेड किये गए हैं।

डॉ. बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। मैंने खुरदबंद गांव के स्कूल को अपग्रेड करने के बारे में सवाल किया है।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, इसको हम एक्जामिन करवा लेंगे। यदि इस गांव का स्कूल भी नॉर्म्ज पूरे करता होगा तो उसे जरूर अपग्रेड किया जायेगा।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मानती हूं कि राईट टू एजुकेशन एक्ट के तहत किसी भी बच्चे को 8वीं कक्षा तक फेल नहीं कर सकते लेकिन मैं मंत्री महोदया से जानना चाहती हूं कि जिस तरह से प्राईवेट स्कूल्ज में बच्चों के वीकली और मंथली टैस्ट लिए जाते हैं क्या उसी तरह से हमारे सरकारी स्कूल्ज में भी बच्चों के टैस्ट लेने के लिए टीचर्स को हिदायतें दी गई हैं ताकि उनकी शिक्षा में सुधार हो सके।

Mr. Speaker : It is a very healthy suggestion. Internal examinations can be started.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहती हूं कि सैंट्रल गवर्नमैंट के राईट टू एजुकेशन एक्ट के तहत बच्चों को फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन देना जरूरी है तथा पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को

फेल भी नहीं कर सकते। विपक्ष के साथी भी इस बात को सुन लें, यह बात काम आयेगी। इसी हिसाब से हमने अपना स्टेट का एजुकेशन एक्ट बनाया है। उसमें no detention plus continuous and comprehensive evaluation लिखा हुआ है जिसके तहत हम लोग लगातार स्तर मूल्यांकन बच्चों का करेंगे। राईट टू एजुकेशन एक्ट में बच्चों के पेपर लेने पर कोई मनाही नहीं है तथा बच्चों की रैगूलर मोनीटरिंग भी की जाती है। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहती हूं कि शिक्षा का अधिकार एक्ट आने के बाद से कुछ कंफ्यूजन लोगों को जरूर हुआ है। इस एक्ट के आने के बाद 8वीं कक्षा का बोर्ड खत्म किया गया है लेकिन बच्चों के पेपर लेने की कोई पाबंदी नहीं है। हम no detention plus continuous and comprehensive evaluation के तहत बच्चों का अनालिसिज वगैरा समय-समय पर करवाते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पिछले दिनों जो हमारा शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम हुआ उसमें घोषणा की थी कि तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों के स्क्रीनिंग टैस्ट रखे जायेंगे। भाई आनंद सिंह दांगी जी ने भी इस बारे में चिंता जाहिर की है। केन्द्रीय कैब की सब कमेटी की मैं चेयरमैन हूं। हमने राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्ट तैयार कर ली है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे शिक्षा में गिरावट आई है तथा इस बारे में आज विधान सभा में भी चर्चा हुई है। इस बारे में हमें अवश्य सोचना चाहिए। मैं सदन को आश्वस्त करूंगी कि क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं।

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, इसमें टीचर्स की जिम्मेवारी भी फिक्स होनी चाहिए। 8वीं के बाद 9वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं रहते इसलिए टीचर्स की जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए। यदि टीचर्स की रिजल्ट के लिए जिम्मेवारी फिक्स हो जायेगी तो जीरो रिजल्ट नहीं आयेंगे। केवल बच्चों को मिड डे मील खिलाकर घर भेज दें इससे काम चलने वाला नहीं है इसलिए टीचर्स की जिम्मेवारी भी फिक्स करनी चाहिए।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, दांगी साहब ने प्रदेश में शिक्षा के गिरते स्तर पर चिंता जाहिर की है और स्कूलों में जो जीरो रिजल्ट आ रहे हैं उसके बारे में भी सवाल उठाया है। (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आने के बाद प्रदेश में शिक्षा का स्तर कहीं नहीं गिरा है बल्कि शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ा है। माननीय सदस्य इस बारे में आंकड़े निकालकर हमें बतायें। यह मुंह जबानी करने वाली बात नहीं है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, 15 स्कूलों के बारे में तो हमने जानकारी दे दी है कि वहां जीरो रिजल्ट रहा है।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, अरोड़ा जी के समय में प्रदेश में शिक्षा का क्या स्तर था इस बारे में वे स्वयं ही बता दें। इनके समय में कितने स्कूलों में जीरो रिजल्ट रहता था इस बारे में भी इनको जानकारी देनी चाहिए। हमारी सरकार आने के बाद प्रदेश में शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है। कोई भी सदस्य हमें शिक्षा को लेकर जो भी अच्छे सुझाव देंगे उनको हम जरूर मानेंगे।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सुजैशन देना चाहूंगा कि जैसा कि दांगी साहब ने भी कहा कि राईट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 8वीं तक की कक्षा के बच्चों को फेल नहीं कर सकते। जिसके कारण आगे 10वीं और 12वीं कक्षा में बच्चे पास नहीं होंगे और शिक्षा में

[श्री अशोक कुमार अरोड़ा]

गिरावट आयेगी। माननीय मंत्री महोदया ने सैंटरल एक्ट का जिक्र किया है क्या हम अपने यहां के एक्ट में बदलाव करके 8वीं कक्षा में दोबारा से बोर्ड शुरू नहीं कर सकते और यदि कर सकते हैं तो 8वीं कक्षा में दोबारा से बोर्ड लागू करना चाहिए ?

श्रीमती गीता भुक्कल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगी कि यह हम भी जानते हैं कि सैंट्रल एक्ट के कारण बहुत सी दिक्कतें थी इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने एच.आर.डी. मिनिस्ट्री और केब को हरियाणा सरकार की तरफ से पत्र लिखा हुआ है कि इससे रिलज्ट्स काफी डैटोरेट होते जा रहे हैं। इसलिए मैं पुन: यह बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने आलरेडी एच.आर.डी. मिनिस्ट्री और केब को पत्र लिख दिया है कि हमारे यहां पर आठवीं कक्षा के बाद बोर्ड की प्रॉपर परीक्षायें दोबारा से शुरू की जायें।

Provision of Computer Labs

***1899. Sardar Charanjeet Singh Rori :** Will the Education Minister be pleased to state whether it is a fact that there is a scheme of the Government to provide Labs for Computer Education in Government Schools; if so, the time by which this facility alongwith the computer teaching staff is likely to be provided inthe Government School of District Sirsa?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matenhail) : Yes Sir. There is a scheme to provide labs for computer education in Government Schools.

In District Sirsa, 188 labs have been established in 177 Government High/ Senior Secondary Schools, At present 175 computer teachers have been provided through service provider against 188 labs, 13 computer teachers in remaining labs will be provided by 30 June, 2014.

सरदार चरणजीत सिंह रोड़ी : स्पीकर सर, यह बात ठीक है कि जो माननीय मंत्री महोदया जी कह रही हैं कि सिरसा जिले में कुल 177 स्कूल हैं जिनमें से 71 स्कूल 10+2 लैवल के हैं और 106 स्कूल मैट्रिक लैवल के हैं। मैं यह बताना चाहूंगा कि इनमें से 13 स्कूलों में कोई कम्प्युटर लैब नहीं है और 82 स्कूल ऐसे हैं जिनमें कम्प्युटर ऐसे ही बेकार पड़े हैं वहां पर न तो कम्प्युटर टीचर है और न ही जैनरेटर सैट्स का ही इंतजाम है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इन कम्प्युटर लैब्स को चलाने के लिए सरकार द्वारा बजट में कोई पैसा रखा गया है, अगर रखा है तो कितना पैसा रखा है और इसके साथ यह भी बताया जाये कि इन कम्प्युटर लैब्स को कब तक फंक्शनल बनाया जायेगा। मेरा दूसरा सवाल यह है कि कम्प्युटर ऑपरेटरों को पिछले 24 महीने से वेतन नहीं मिला है क्या इन कम्प्युटर ऑपरेटरों को वेतन देने के लिए भी सरकार ने बजट में कोई पैसा रखा है क्योंकि ये कम्प्युटर टीचर जगह-जगह धक्के खा रहे हैं, कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और आखिर में उनको हारकर धरने पर बैठना पड़ा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया जी से कहना चाहता हूं कि सरकार को इन कम्प्युटर टीचर का वेतन रिलीज़ करने के लिए वांछित कारगर कदम जल्दी से जल्दी उठाने चाहिएं।

श्रीमती गीता भुक्कल मालनहेल : स्पीकर सर, सरदार चरणजीत सिंह जी ने जो मुद्दा उठाया है मैं यह मानती हूं कि इस बारे में उनकी चिंता बिलकुल जायज़ है। हमारे स्कूलों में सैंट्रल स्पॉसर्ड इनफर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलोजी स्कीम है इसके तहत हम अपने प्रदेश के छठी से लेकर बाहरवीं कक्षा तक के 3117 स्कूलों में कम्प्युटर शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने सभी स्कूलों में कम्प्युटर एजूकेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की है। आई.सी.टी. के माध्यम से हमने तकरीबन 1500 स्कूलों में कम्प्युटर शिक्षा प्रोवाईड की है। हमारे सभी स्कूलों में कम्प्युटर लैब्स शुरू हुई और बच्चों के बैठने की व्यवस्था हुई। जो यह स्कूलों में कम्प्युटर लगाने का काम था यह काम हमने हाई पॉवर परचेज़ कमेटी के माध्यम से एक कम्पनी को सौंपा था जिसमें कि बहुत ज्यादा दिक्कतें और शिकायतें आई। इस बारे में मैं एक स्टेटमैंट देना चाहूंगी कि In order to provide computer education to the students from Class-6 to Class-12 in 2622 High and Senior Secondary Schools in the State of Haryana, an agreement of supply, installation and maintenance of Information Technology and physical infrastructure has been made. सर, इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगी कि हमारे विधायक सरदार चरणजीत सिंह जी का इलाका पंजाबी भाषी एरिया है इसमें हमने सभी स्कूलों में कम्प्युटर लैब्स स्थापित करके कम्प्युटर शिक्षा देने का पूरा बंदोबस्त किया है। मैंने इनको बताया है कि वहां पर 181 कम्प्युटर लैब्स हैं जिनमें से 177 में काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक क्वैश्चन यह भी पूछा है कि जो कम्प्युटर लैब्स खराब पड़ी हैं उनको हम कब तक ठीक करवायेंगे। इसके बारे में मैं उनको बताना चाहूंगी कि इन कम्प्युटर लैब्स को फंक्शनल बनाने के लिए हमने कोर एजुकेशन एण्ड टेकनॉलोजी नामक कम्पनी को ठेका दिया है लेकिन इन कम्पनी ने कंडीशंज़ के मुताबिक काम नहीं किया। हमने उनके कांट्रेक्ट को टर्मीनेशन करने के लिए लिख दिया है और उनके खिलाफ हम कार्यवाही कर रहे हैं। यह हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को अच्छी कम्प्युटर शिक्षा उपलब्ध करवायें। Speaker Sir, as a Minister I am saying on the floor of the House that I am not satisfied with the performance of the company. हमने अपने अधिकारियों की एक कमेटी कांस्टीच्युट करके सम्बंधित ऑफिसर्ज़ की जिम्मेदारी भी फिक्स करने के लिए कहा है। हमने इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट जल्दी देने के लिए कहा है। हमारे जो लैब अटैंडैंट लगे हुए हैं हमने उनको कहा है कि हम कम्पनी के साथ अपना करार टर्मीनेट कर रहे हैं। लैब अटैंडैंट को हमने डॉयरैक्ट भर्ती नहीं किया था बल्कि ये कम्पनी द्वारा स्वयं लगाये गये थे। इनको सैलरी नहीं मिली इस कारण हमें भी समस्या है। फाइनैंस डिपार्टमैंट द्वारा जो 20 प्रतिशत पैसा सैंक्शन कर दिया गया था उसके आधार पर ही उनको सैलरी मिली है बाकियों को नहीं मिली क्योंकि इस समय इस कम्पनी के साथ हमारा कोई कांट्रैक्ट नहीं हैं। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम यह इंश्योर करें कि हम अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दें। इस मामले में हमारे विभाग और सरकार दोनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं ऑन दि फ्लोर ऑफ दी हाउस यह एश्योर कर सकती हूं कि जहां भी कोई कमी होगी हम उसे जल्दी से जल्दी दूर करके सुधार करने की हर सम्भव कोशिश करेंगे।

डॉ. अशोक कश्यप : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इन्द्री में सरकारी कॉलेज है और वहाँ पर आर्ट्स और कोमर्स की क्लासिज लग रही हैं लेकिन साइंस स्ट्रीम की पढ़ाई करने के लिए 150-200 बच्चों को इंद्री से करनाल जाना पड़ता है। क्या मंत्री जी बतायेंगी कि इंद्री के सरकारी कॉलेज में साइंस की क्लासिज कब तक शुरू कर देंगे ?

Mr. Speaker : It is a separate question but Hon'ble Minister may note down his suggestion please.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, यह एक पृथक प्रश्न है लेकिन हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्प्यूटर लैब्स और टीचरों के बारे में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने 3 कंपनियों के माध्यम से 3 हजार कम्प्यूटर टीचर रखे और उन कंपनियों के नाम मैसर्ज श्रीराम न्यू होरिजन्स, ट्रांसलाइन टैक्नॉलोजी व भूपेन्द्रा सोसायटी थे। इन कम्पनियों ने हर टीचर से सिक्योरिटी के रूप में 24000/- रुपये जमा करवाये। इस प्रकार ये कम्पनियाँ लगभग 7 करोड़ रुपये लेकर भाग गई। उन कम्प्यूटर टीचरों को पिछले 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। पंचकुला में वे 1 हजार कम्प्यूटर टीचर अपनी तनख्वाह के लिए आमरण अनशन पर बैठे हुये हैं और उनमें से 2 टीचरों की तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या मंत्री जी इस मामले की जाँच करवायेंगी कि ये तीन कम्पनियाँ कौन-कौन सी हैं और कौन-कौन आदमी उनके साथ हैं ? इन्होंने उन बच्चों से 24-24 हजार रुपये सिक्योरिटी लेने की इजाजत दी और वे कम्पनियाँ पैसे लेकर भाग गई। क्या मंत्री जी इन कम्पनियों की जाँच इंटैलीजैंस, सी.बी.आई. या अन्य किसी ऐजेन्सी से करवायेंगी? इन टीचरों की तनख्वाह कब तक मिल जायेगी क्योंकि उन टीचरों को तनख्वाह देने की जिम्मेदारी सरकार की है? सरकार के भरोसे पर उन्होंने कम्पनियों को पैसे दिये हैं वरना वे कम्पनियों को पैसे नहीं देते। उनको तनख्वाह मिले 6 महीने हो गये हैं और उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। ये सभी टीचर अच्छी क्वालिफिकेशन वाले हैं।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि शिक्षा विभाग ने 19 अगस्त, 2013 को 3 कम्पनियों नामत: मैसर्ज श्रीराम न्यू होरिजन फॉर अम्बाला एण्ड गुड़गांव डिविजन्स, मैसर्ज ट्रांसलाइन टैक्नॉलोजी फॉर हिसार डिविजन व मैसर्ज भूपेन्द्रा सोसायटी फॉर रोहतक डिविजन के साथ हाई पॉवर परचेज कमेटी के माध्यम से हाई स्कूलों और सीनियर सैकेंड्री स्कूलों के लिए 3122 कम्प्यूटर टीचरों के लिए 19.8.2013 को कॉंट्रैक्ट किया तथा एक-एक साल के बाद इस कॉंट्रैक्ट को आगे बढ़ाना था। 14403 रुपये इन कम्पनियों की ओर से इन सर्विस प्रोवाइडर को दिये जाने थे लेकिन उन्होंने कम्प्यूटर फैकल्टी के लिए 12000/- रुपये वेतन देने की बात कही। सर्विस प्रोवाइडर्स ने 2602 स्कूलों में कम्प्यूटर फैकल्टी प्रोवाइड की हैं। उनको सैलरी देने में थोड़ी सी दिक्कत आई। अब हमने 20,79,55,000/- रुपये तनख्वाह के लिए बिल विभाग से क्लीयर करवा कर ट्रैजरी में केस भिजवाया है। उन सभी कम्प्यूटर टीचरों को 31 दिसम्बर, 2013 तक की उनकी तनख्वाह एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर मिल जायेगी। जहां तक आपने कार्यवाई की बात कही है जो बिल बाकी रहते हैं उनकी पेमेंट भी हम जल्दी करवा देंगे। सर, जब यह शिकायत आई है कि जब इन प्राइवेट कम्पनियों को ठेका दिया गया है। उस समय इसके लिए हमने एक मॉनेटरिंग कमेटी की व्यवस्था की थी। हमारी इस बारे में यह कोशिश होनी चाहिए कि इस कमेटी में जिन ऑफिसर्ज को मैंबर बनाया गया था उनकी यह जिम्मेवारी बनती है कि उनके बिलों की पेमेंट समय पर करवा दें। परन्तु ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जरूर कोताही हुई है। जो ये कम्प्यूटर टीचर्ज सर्विसिज फैकल्टी के आधार पर लगे हुए थे जब ये हमें मिले तो उसके बाद जब हमने कार्यवाही करवाई तो जो इनसे

24 हजार एडवांस सिक्योरिटी ली गई है जो कि रिफंडेबल है, वह हम उनको वापस करेंगे क्योंकि जब हम इनको लगा लेते हैं तो उनमें से कुछ बच्चे छोड़कर चले जाते हैं लेकिन हमने सभी के लिए यह कहा है कि जो यह सिक्योरिटी ली गई है वह इललीगल तरीके से ली गई है क्योंकि यह टर्म्ज एण्ड कंडीशंज में नहीं थी इसलिए वह वापस की जाए। इसके अलावा हमने एक सैकेन्डरी एजुकेशन की डिप्टी डायरेक्टर ऑफिसर्ज मिसिज भलनी मेहमानी जो एक इन्कवायरी कम डिप्टी डायरेक्टर ऑफिसर हैं उनको इस काम के लिए नियुक्त किया गया है और वह इन्कवायरी करके सरकार को रिपोर्ट करेंगी और जल्दी ही हमारे पास इसकी सूचना आ जाएगी और हम इस बारे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।

Repair/Renovation G.H. Rania

***1901. Shri Krishan Kamboj:** Will the Health Minister be pleased to state whether there is a any proposal under consideration of the Government to repairing/renovate the building of Government Hospital, Rania; if so, the details thereof ?

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) : हां, श्रीमान जी। नियमित/सामान्य मरम्मत के अतिरिक्त 24.00 लाख रुपये की राशि से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए एक नया विंग जोड़ा जा रहा है।

श्री कृष्ण काम्बोज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि रानियां शहर में जो अस्पताल की बिल्डिंग बनाई गई थी वह 30-35 साल पहले बनाई गई थी। अब यह बिल्डिंग मेन सड़क से तकरीबन 10 फुट नीचे हो चुकी है और इसकी छत आज बिल्कुल जर्जर हालत में है। ऐसा न हो कोई हादसा हो जाए। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या उस बिल्डिंग के लिए कुछ पैसे का प्रावधान है या उसको तोड़कर नई बिल्डिंग बनाने का कोई प्रावधान है या उसमें कोई सुधार करने का प्रावधान है। अगर मंत्री जी का इसमें सुधार करने का कोई प्रावधान है तो यह कब होगी और कैसे होगी। इसका समय बताया जाए।

राव नरेन्द्र सिंह : सर, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे माननीय सदस्य की चिन्ता वाजिब है। वह पी.एच.सी. बिल्डिंग सन् 1965 में बनाई गई थी। सन् 1989 में उसको सी.एच.सी. बनाया गया था। उसकी मुरम्मत के लिए आज तक लगभग 12 लाख रुपये दिए जा चुके हैं। सन् 2012-13 में एक लाख 87 हजार रुपये , सन् 2013-14 में 1 लाख 24 हजार 982 रुपये और उसके बाद सन् 2013-14 में ही 7 लाख 24 हजार रुपये इस पर अलग से खर्च किये गये हैं और इसके क्वार्टर्ज की मुरम्मत पर भी हमने लगभग पौने 2 लाख रुपये खर्च किए हैं। बाकी इन फ्यूचर यह हमारी प्लान के अन्दर है और हम चाहेंगे कि यह पुरानी बिल्डिंग है इन फ्यूचर इस बिल्डिंग को गिराकर अच्छी बनाया जाएगा लेकिन फिलहाल उस बिल्डिंग की हालत ठीक है, कंडम वाली बात नहीं है।

तारांकित प्रश्न संख्या-1971

(इस समय माननीय श्री सुभाष चौधरी सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया।)

Repair of Road

***1995. Shri Raj Pal Bhukhri :** Will the PWD(B&R) Minister be pleased to state the time by which the repair work of the road from village Pabani to village Sarawan is likely to be started?

Public Works Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, the administrative approval for special repair of this road at an estimated cost of Rs. 456.77 lakh was issued on 24.12.2013. After completion of the tendering process, work will be started. However, at this juncture no categorical assertion can be made on the date of start of work.

श्री राजपाल भूखड़ी : सर, मैं दो बार मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर चुका हूं और आज भी मैं धन्यवाद करता हूं दो सैशन पहले भी मैं धन्यवाद कर चुका हूं। यह रोड़ बनाने के लिए 12 करोड़ रुपये का टैंडर है उसमें तीन काम है और तीनों को एक ही जगह एक ही टैंडर में लगा दिया। सर, 28 तारीख को इसका टैंडर था टैंडर नहीं खुला तो मुझे इसमें किसी अधिकारी की नीयत पर शक है। सर, इसके लिए दो बार मैं पहले मंत्री जी का धन्यवाद कर चुका हूं और आज भी धन्यवाद कर रहा हूं तो मंत्री जी बताएं कि क्या ये काम हो जाएगा?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, इतनी बार मंत्री जी का धन्यवाद करने पर भी सड़क नहीं बनी।

Shri Aftab Ahmed : Sir, we would ensure that work is started as per the tender. We have recalled the tender for 24th March, 2014.

श्री राजपाल भूखड़ी : स्पीकर सर, मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि उस टैंडर के तीन काम हैं तीनों अलग-अलग लगा दिए जाएं।

श्री रामेश्वर दयाल राजोरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी 24 फरवरी 2013 को बावल में घोषणा करके आए थे कि बावल फाटक से एन.एच. 8 तक का जो एक किलोमीटर का रोड़ है वह बिल्कुल टूटा हुआ है एक तरफ उस पर होस्पीटल है और दूसरी तरफ कॉलेज है तो वह रोड़ बनकर कब तक पूरा हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : रिपेयर होना है।

श्री रामेश्वर दयाल राजोरिया : हां सर, रिपेयर ही होना है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आप इसको नोट कर लें।

श्री आफताब अहमद : ठीक है सर, माननीय सदस्य इस बारे में लिख कर दे दें हम इसको ठीक करवा देंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या-1784

(इस समय माननीय श्री राव बहादुर सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया।)

Construction of Sports Stadium

***1795. Col. Raghbir Singh :** Will the Minister of State for Sports & Youth Affairs be pleased to state—

(a) the number of sports stadiums constructed by the Government in the Badhra Constituency since January, 2010 till to date together with the name of those villages where these sports stadiums have been constructed; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the sports stadium in village Pichopa Kalan; if so, the time by which it is likely to constructed?

खेल एवं युवा कार्यक्रम राज्य मंत्री (श्री सुखबीर कटारिया) :

(क) कोई नहीं, श्रीमान जी।

(ख) नहीं, श्रीमान जी।

कर्नल रघबीर सिंह : स्पीकर सर, मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो सवाल पूछे हैं। पहला सवाल यह है कि क्या जनवरी 2010 से आज तक बाढड़ा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्टेडियम बनाया गया है तथा मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या गांव पिचोपा कलां में स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। दोनों प्रश्नों का साइक्लोस्टाइल जवाब "न" में ही प्राप्त हुआ है जिसकी मुझे उम्मीद भी लग रही थी कि इसी तरह की बात होने वाली है। आज तक मैंने इस महान सदन में जितने भी प्रश्न किये हैं चाहे वे किसी भी विभाग से संबंधित हो उन सभी प्रश्नों का साइक्लोस्टाइल जवाब "न" में ही प्राप्त हुआ है (विघ्न) माननीय मंत्री जी यह बता दें कि भिवानी जिले में कितने स्टेडियम बनाये हैं और झज्जर और गुड़गांव जिलों में कितने बनाये हैं ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आप केवल भिवानी जिले में बनाये गये स्टेडियम्ज का ही ब्यौरा सदन में रखें?

खेल एवं युवा कार्यक्रम राज्य मंत्री (श्री सुखबीर कटारिया) : स्पीकर सर, राजीव गांधी खेल परिसर, चांधवास में बनाया गया है। जो वर्ष 2010 में पूरा हो गया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कटारिया जी, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, आप यह बतायें कि भिवानी जिले में कुल कितने स्टेडियम्ज बनाये गये हैं?

Shri Sukhbir Kataria : Speaker Sir, 16 Stadiums have been built up in the villages i.e. Chandwas, Bahal, Dhareru, Makrana, Achina, Birhi Kalan, Jhojhoo Kalan, Chhapper, Ledha Hetwan, Dhigoan Jatan, Barwa, Tosham, Sandhwa, Tigarana, Mithathal and Bhiaini Jatan of Bhiwani District. (Noise & Interruption)

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, आप मंत्री जी को बतायें कि कर्नल साहब यह जानना चाह रहे हैं कि वर्ष 2010 से आज तक क्या बाढड़ा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्टेडियम बनाया गया है?(शोर एवं व्यवधान)

कर्नल रघबीर सिंह : स्पीकर सर, मैंने मंत्री महोदय से बाढ़डा निर्वाचन क्षेत्र में स्टेडियम बनाने के संबंध में प्रश्न किया है और मंत्री जी बता कुछ और रहे हैं?

श्री सुखबीर सिंह कटारिया : स्पीकर सर, वैसे तो मैंने पहले जो अभी राजीव गांधी खेल परिसर चांदवास में बनाने की बात की है वह बाढ़डा निर्वाचन क्षेत्र से ही तो संबंधित है?

कर्नल रघबीर सिंह : स्पीकर सर, मंत्री महोदय ने बाढ़डा निर्वाचन क्षेत्र में स्टेडियम बनाने का कोई जवाब नहीं दिया है बल्कि वे तो भिवानी जिले में बनाये गये स्टेडियम्ज के बारे में ही बताने लग गये है।(शोर एवं व्यवधान) मेरा सपैसिफिक प्रश्न बाढडा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है। मंत्री जी केवल उसके बारे में बतायें? (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुखबीर सिंह कटारिया : स्पीकर सर, अभी थोड़ी देर पहले माननीय सदस्य ने खुद जानना चाहा था कि भिवानी जिले में कितने खेल स्टेडियम्ज बनाये गये हैं। मैंने जो जवाब देना शुरू किया था वह उसी सवाल के परिपेक्ष्य में था लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करता माननीय सदस्य ने मुझे बीच में ही टोक दिया है। वैसे मैं एक और बात भिवानी के बारे में माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि हम जल्द ही पूरे भिवानी जिले में synthetic track लेकर भी आ रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, क्या माननीय सदस्य के द्वारा बाढ़डा निर्वाचन क्षेत्र में स्टेडियम बनाने संबंधी आपको कोई रिक्वैस्ट भेजी है?

श्री सुखबीर कटारिया : स्पीकर सर, माननीय सदस्य की तरफ से ऐसी कोई भी रिक्वैस्ट हमें प्राप्त नहीं हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

कर्नल रघबीर सिंह : स्पीकर सर, जो मैंने अपना प्रश्न विधान सभा में लगाया है वह मेरी तरफ से लिखकर दी गई डिमांड अर्थात रिक्वैस्ट ही मानी जा सकती है। आप उसका जवाब "न" में दे रहे हो?

श्री सुखबीर कटारिया : स्पीकर सर, मैं मेरे माननीय साथी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि वे अपनी डिमांड मेरे पास लिखकर भेज दें यदि डिमांड नॉमर्ज पूरी करती होगी तो उस पर हर संभव कार्यवाही की जायेगी।

Pitiable condition of Road from Kaithal to Ambala

***1976. Shri Ram Pal Majra :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the condition of the road from Kaithal to Ambala is very pitiable; and

(b) if so, whether there is any proposal uder consideration of the Government to widen and re-carpet the aforesaid road, if so, whether any funds have also been allocated for this purpose?

Transport Minister (Shri Aftab Ahmed) : Sir, a statement is laid on the Table fo the House.

Statement

(a) (i) The National Highway No. 65 is an important Highway starting from Ambala and passing through Kaithal-Narwana-Barwala-Hisar-Siwani and ending at Rajgarh in Rajasthan. This NH has been entrusted to the National Highways Authority of India (NHAI), Ministry of Road Transport & Highways, Government of India but the maintenance is being got done through State PWD as Deposit Work of NHAI.

(ii) The length of this NH from Ambala to Kaithal is 77.00 km. The carriageway width on this National Highway is only 5.50m in Km. 21.65 to 32.00, 34.25 to 37.80, 38.75 to 41.90 and Km. 53.60 to 56.00 (Total 19.45 km.) whereas, the width in remaining stretch varies from 7.00m to 10.00m. The width of the road is not sufficient in view of heavy traffic plying on this road. The road edges get frequently damaged in the stretch particularly where the carriageway width is 5.5m further causing damage to the berms as well and causing difficuly to the traffic plying on the road. Further pot holes also have developed on the road due to recent rains/winter season.

(iii) The stretches from Km. 0.00 to 15.00, 15.00 to 32.00, 32.00 to 33.54, 34.395 to 41.900 and 53.600 to 56.00 are in defect libility period of the contractual agency. Remaining stretches i.e. 33.54 to 34.395, 41.900 to 53.600 and 56.00 to 77.15 are being maintained by the department. The berms in the stretches under defect liability shall be got repaired and patch work carried out through the contractual agency before end of April 2014. The patch work on other stretches is being carried out departmentally and is likely to be completed by March, 2014.

(iv) Haryana PWD also submitted estimates of periodic renewal required on various stretches for proper repair to NHAI but the same were not approved since the road has already been taken up under NHDP Phase-III.

(b) Haryana PWD had also forwarded an estimate of widening of the road to the Ministry of Road Trasnport & Highways earlier but the Ministry did not approve the same citing the reason that the road has been included under NGDP Phase-III by NHAI.

The NHAI has invited bids for 4-laning of the extended atretch from Ambala to Kaithal section of NH-65 upto Titram turning as BOT Project with Viable Gap Funding under NHDP Phase-III, which are to be opened on 27.03.2014 with a construction period of 30 months from appointed date.

[Shri Aftab Ahmed]

Salient features of this project are as under:-

Section of National Highway	Salient features
Ambala-Kaithal Section upto Titram Mor (NH-65) NHDP Phase-III	* The project of 4-laning of Ambala to Kaithal Section of NH-65 to be executed as BOT Project with VHF under NHDP Phase-III in the State of Haryana. * Total length of the Project is 95 Km. * Total Project cost if Rs. 1141 Cr. * Feasibility Consultant M/s Meinhardt Singapore Pvt. Ltd. * Bids are to be opened on 27.03.2014 with a construction period of 30 months from appointed date. * The scope of work includes 3 ROBs, 3 Flyovers, 6 Underpass, 5 Byepass (at Ambala, Matheri, Ismailabad, Pehowa and Kaithal).

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, यदि माननीय मंत्री जी सुरजेवाला जी सदन में मौजूद होते तो ज्यादा अच्छा होता क्योंकि मेरा जो प्रश्न है वह उन्हीं के डिपार्टमैंट से संबंधित है। श्री सुरजेवाला जी भी कैथल जिले का प्रतिनिधित्व इस सदन में करते हैं। आज कैथल में यह हालत हो गई है कि कैथल से अंबाला, कैथल से करनाल, कैथल से कुरुक्षेत्र और कैथल से पानीपत वाया असंध की सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई हैं। यहां पर रोड्ज की इतनी दयनीय स्थिति है कि कैथल वाले सोचने को मजबूर हो गये हैं कि कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई है जो उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। आज कैथल से अम्बाला रोड की बदहाली इतनी बुरी स्थिति में पहुँच गई कि लोगों के लिए आवाजाही भी मुश्किल हो गई है। जैसाकि बजट में भी इन सड़कों को बनाने के लिए प्रावधान किया गया है, तो इस संबंध में मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इन रोड्ज को बी.ओ.टी (Built Operate Transfer) के आधार पर बनाया जायेगा? यदि बी.ओ.टी बेसिज पर बनाया जायेगा तो फिर स्वाभाविक है कि टोल टैक्स भी लगाया जायेगा? इस संबंध में मैं माननीय परिवहन मंत्री जी, जो माननीय सुरजेवाला जी की तरफ से सदन में जवाब देंगे, से पूछना चाहता हूँ कि क्या प्रदेश को टोल टैक्स फ्री बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? क्या प्रदेश को टोल टैक्स फ्री बनाने पर सरकार कोई विचार करेगी?

चौधरी आफताब अहमद : स्पीकर सर, अम्बाला कैथल सैक्शन अप टू तीतरम (एन.एच. 65) फेस-III जो नैशनल हाईवे है, उसको बी.ओ.टी. प्रोजैक्ट के तहत ही बनाया जायेगा। इस कार्य पर 1141 करोड़ रुपये की टोटल लागत आयेगी। 27 मार्च, 2014 को इस कार्य के लिए बिड्ज खोली जायेंगी। इसका कंस्ट्रक्शन पीरियड 30 महीने का रखा गया है। जहां तक "टोल टैक्स" लगाने की बात है तो एन.एच.ए.आई के तहत आने वाले रोड्ज पर गवर्नमैंट ऑफ इंडिया के "टोल टैक्स एक्ट" के तहत ही ये टैक्स चार्ज किये जाते हैं और किसी भी सूरत में यह टैक्स स्टेट के अंडर नहीं आते हैं।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, मंत्री जी इस महान सदन में रोड्ज बनाने की बात करते हैं। इनको यह कहते हुए बहुत दिन हो गये हैं कि खरक से लेकर दादरी, नारनौल और कोटपुतली तक की रोड़ बना दी गई हैं लेकिन बावजूद इसके भी आज तक वहां पर कोई भी रोड नहीं बनाई गई है। कुंडली एक्सप्रैस हाईवे को बनाने की बात को भी एक काफी लंबा समय बीत चुका है लेकिन यह भी आज तक नहीं बनाया गया है। इसी प्रकार मेरे द्वारा बताई गई रोड्ज को भी 2014 तक बनाने की बात करते हैं, जो मुश्किल ही लगता है। आज प्रदेश में "टोल टैक्स" की वसूली में National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 का उल्लंघन किया जा रहा है। बिना किसी आधार के "टोल टैक्स" बढ़ा दिया जाता है और "टोल टैक्स" की समयावधि भी बढ़ा दी जाती है। जब हम डीजल तथा पैट्रोल पर "सैश" पे करते हैं तथा स्टेट गवर्नमैंट को सेल टैक्स प्राप्त होता है तो फिर किस बात के लिए "टोल टैक्स" लगाये जाते हैं? अब रोड़ बनाने संबंधी जैसाकि मंत्री जी का बयान है कि 27 मार्च, 2014 को इस कार्य के लिए बिड्ज खोली जायेंगी तथा इन रोड्ज के लिए कंस्ट्रक्शन पीरियड 30 महीने का रखा गया है, तो उस संबंध में मेरा कहना है कि जिन रोड्ज को बनाने की घोषणा किये हुए काफी लंबा समय बीत चुका है जब वे ही आज तक नहीं बनाई गई हैं तो फिर ऐसे में अब मंत्री जी जो बयान दे रहे हैं उस पर शंका होना स्वाभाविक है? जिन ठेकेदारों को उन रोड्ज का काम सौंपा गया था वे भी बीच में ही काम छोड़कर भाग गये हैं। अत: इन रोड्ज को बनाने के संबंध में मैं फिर से पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरे द्वारा बताई गई रोड्ज को बी.ओ.टी. बेसिज पर तैयार किया जायेगा तथा इन पर कितनी जगहों पर "टोल टैक्स" लगाये जायेंगे।

15.00 बजे **श्री आफताब अहमद :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि एक टोल टैक्स ईस्माइलाबाद के नजदीक लगाने का प्रस्ताव है और दूसरा टोल टैक्स क्योंडक के नजदीक लगाने का प्रस्ताव है। फिलहाल अम्बाला से पेहवा की सड़क पर ये दो टोल टैक्स ही लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

Power to Mayors

***1881. Shri Ashok Kumar Arora :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether it is a fact that there is a dispute regarding exercise of powers between the Mayors and officers of various Municipal Corporations in the State; if so, whethere the State Government has taken any steps to give the mandatory and required powers to the Mayors of Municipal Corporations?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती सावित्री जिन्दल) : श्रीमान् जी, विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

नहीं, श्रीमान् जी। नगर निगमों के महापौरों द्वारा नगर निगमों के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये कर्मचारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किये जाने का अनुरोध किया है। इसलिए नगर निगमों के सभी आयुक्तों को निर्देश जारी किये गये हैं कि नियमों में निहित व्यवस्था अनुसार सदन की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करवाना सुनिश्चित करें, बेहतर समन्वय के लिये सम्बन्धित महापौरों के साथ पाक्षिक रूप से बैठक आयोजित करें ताकि विकास कार्यों, आय-

[श्रीमती सावित्री जिन्दल]

व्यय और स्वीकृत बजट के बारे में उन्हें अद्यतन जानकारी उपलब्ध करायें। सम्बन्धित विभागों को यह भी हिदायतें जारी की गई हैं कि वे नियमित रूप से निगम के सदन की बैठकों में भाग लेने के लिये अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दें।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रश्न पूछा था कि हरियाणा प्रदेश में सात नगर-निगमों में मेयर चुने गये हैं उनमें और अधिकारियों में टकराव है या नहीं। मंत्री जी ने जवाब दिया था कि नहीं। स्पीकर सर, आप जानते हैं कि करनाल के अंदर और पानीपत के अंदर जितने भी नगर निगम हैं उन सब के मेयर मुख्यमंत्री जी से मिले कि हमें कोई पावर दी जाये। हरियाणा सरकार ने मेयर तो बना दिये। मैं जानना चाहता हूँ कि उनके पास क्या-क्या पावर है? कृपा इस बात का मंत्री जी जवाब दें।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Questions Hour is over. (Interruption)

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Metalling of Streets

***1960. Shri Bishan Lal Saini :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether it is a fact that many streets of village Farakpur in Municipal Corporation, Yamunanagar are lying unmetaled; if so, the time by which these streets are likely to be metalled?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती सावित्री जिन्दल) : हां, श्रीमान् जी। नगर निगम, यमुनानगर-जगाधरी द्वारा पांच गलियों का कार्य आबंटित किया गया है तथा सात अतिरिक्त गलियों का प्रस्ताव प्रक्रिया अधीन है। कार्य छः मास में पूर्ण किए जाने की सम्भावना है।

To Open a Government Girls School in Bhiwani City

***1889. Shri Ghanshyam Dass Saraf :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Girls School in Bhiwani city as announced by the Hon'ble Chief Minister; if so, the time by which aforesaid Girls School is likely to be opened?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : श्रीमान् जी, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भिवानी शहर में कन्या विद्यालय खोलने की घोषणा करना सम्भव नहीं है क्योंकि वास्तविकता यह है कि इस विद्यालय को स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Disposal of Rain/Storm Water

577. Prof. Sampat Singh : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state—

(a) when the project for the disposal of rain/storm water in Patel Nagar, Jawahar Nagar, Housing Board, Sector 15 and Defence Colony, Hisar was sanctioned;

(b) whether it is a fact that this is a joint project of Public Health Department and HUDA; if so, the time by which HUDA will approve its own share of work; and

(c) whether the work of this porject has been allotted to any agency; if so, the time by which the work is likely to be started and completed?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) :

(क) श्रीमान जी। हाउसिंग बोर्ड व सैक्टर 15 को छोड़कर पटेल नगर, जवाहर नगर और डिफैन्स कालोनी, हिसार में बारिश/तूफान पानी के निपटान के लिए 298.50 लाख रुपये की लागत वाली परियोजना को बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा 27.01.2011 को अनुमोदित किया गया था।

(ख) नहीं। पूरी परियोजना की लागत जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग द्वारा वहन की जानी है।

(ग) यह कार्य 02.09.2013 को एजेंसी को आबंटित किया गया है। एजेंसी द्वारा सामग्री के निरीक्षण के लिए पेशकश की है तथा यह कार्य 31.03.2015 तक पूरा होने की सम्भावना है।

Construction of Silos/Godowns

591. Smt. Renuka Bishnoi : Will the Food and Supplies Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Government has decided to construct Silos/Godowns for storage of wheat with the assistance of Argentina and Brazil;

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) the steps being taken by the Government to help the farmers in construction of such silos/godowns by providing them this technology at cost effective and discounted prices?

खाद्य एवं पूर्ति मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) :

(क) नहीं माननीय

(ख) व (ग) उपरोक्त 'क' के सन्दर्भ में लागू नहीं होता है।

Adjustment of Staff of Government Aided Schools

610. Smt. Kavita Jain : Will the Education Minister be pleased to state whether it is a fact that an announcement was made by the Hon'ble Chief Minister in Gohana rally held on 10.11.2013 that teaching and non-teaching staff working in Government Aided Schools against sanctioned posts will be merged/adjusted in Education Department, Haryana; if so, the time by which the aforesaid staff of Government Aided Schools is likely to be merge/adjusted in Education Department, Haryana?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : जी हां, मान्यवर। एक प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। यद्यपि निश्चित समय या तिथि इस अवस्था में अंकित नहीं की जा सकती।

Film and Television Institute at Rohtak

578. Prof. Sampat Singh : Will the Technical Education Minister be pleased to state—

(a) when the Film and TV institute was started in Rohtak;

(b) the number of Laboratories required together with the number of Laboratories that exist in the institute and whether it is a fact that there are no Laboratories for Drawing, Printing, Stitching, Sewing, Pattern and Module;

(c) whether it is a fact that only one faculty is available for Apparel and Life Style trades for second and third year students and all the students are being taught in the same period jointly;

(d) whether it is a fact that the student of second and third year are forced to work jointly due to lack of the machines;

(e) whether it is a fact that the machine of knitting, Inter Lock, Flat Lock and Over Lock and software for learning for the students of design are also now available and even the material is also not available; and

(f) the time by which all the facilities are likely to be provided in aforesaid institute?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) : श्रीमान् जी,

सूचना सदन की मेज पर उपलब्ध है/उपस्थित है।

प्रश्न संख्या 578 के सन्दर्भ में सूचना निम्न प्रकार से है :

(क) फिल्म एवम् टेलीविज़न संस्थान, रोहतक को शैक्षणिक सत्र 2011-12 में शुरू किया गया था तथा कक्षाएं अगस्त 2011 में लगनी शुरू हुई थी।

(ख) रोहतक में चारों संस्थानों के अन्दर प्रयोगशालाओं की आवश्यकता एवं उपलब्धता नीचे क्रमवार दर्शायी गई है :

1. राज्य फिल्म एवं टेलिविज़न संस्थान में प्रयोगशालाओं की स्थिति निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	प्रयोगशाला का नाम	प्रयोगशालाओं की आवश्यकता	प्रयोगशालाओं की उपलब्धता	टिप्पणी
1.	एडिटिंग प्रयोगशाला	02	02	एडिटिंग प्रयोगशालाएं पूर्ण रूप से कार्यरत हैं और 9 विद्यार्थी उनका उपयोग कर रहे हैं।
2.	कम्प्यूटर प्रयोगशाला	02	01	एक प्रयोगशाला पूर्ण रूप से कार्यरत है और 103 विद्यार्थी समय सारणी के अनुसार इसका उपयोग कर रहे हैं। दूसरी प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है।
3.	साउंड प्रयोगशाला	02	01	एक प्रयोगशाला पूर्ण रूप से कार्यरत है और 02 विद्यार्थी समय सारणी के अनुसार इसका उपयोग कर रहे हैं। दूसरी प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है।

2. राज्य डिज़ाइन संस्थान में प्रयोगशालाओं की स्थिति निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	प्रयोगशाला का नाम	प्रयोगशालाओं की आवश्यकता	प्रयोगशालाओं की उपलब्धता	टिप्पणी
1.	फाउंडेशन (मैनुअल वर्कशाप)	01	01	पूर्ण रूप से कार्यरत
2.	मेटल वर्कशाप	01	01	पूर्ण रूप से कार्यरत
3.	वुड वर्कशाप	01	-	स्थापना की जा रही है
4.	टैक्सटाईल प्रिंटिंग प्रयोगशाला	01	01	पूर्ण रूप से कार्यरत
5.	टैक्सटाईल डाइंग प्रयोगशाला	01	01	पूर्ण रूप से कार्यरत
6.	टैक्सटाईल विविंग प्रयोगशाला	01	01	पूर्ण रूप से कार्यरत
7.	पैट्रन मेकिंग वर्कशाप	01	01	पूर्ण रूप से कार्यरत
8.	सिलाई वर्कशाप	01	01	पूर्ण रूप से कार्यरत
9.	सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला	01	01	पूर्ण रूप से कार्यरत
10.	फोटोग्राफी प्रयोगशाला	01	-	स्थापना की जा रही है।

[श्री महेन्द्र प्रताप सिंह]

3. राज्य फाईन आर्टस संस्थान में प्रयोगशालाओं की स्थिति निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	प्रयोगशाला का नाम	प्रयोगशालाओं की आवश्यकता	प्रयोगशालाओं की उपलब्धता	टिप्पणी
1.	कम्प्यूटर प्रयोगशाला को अप्लाइड आर्ट और पेंटिंग एवम् ग्राफिक्स विभाग द्वारा संयुक्त रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है	02	01	एक प्रयोगशाला पूर्ण रूप से कार्यरत है और अप्लाइड आर्ट, विभाग के 19 विद्यार्थियों तथा पेंटिंग एवम् ग्राफिक्स विभाग के 18 विद्यार्थियों द्वारा समय सारणी के अनुसार इसका उपयोग किया जा रहा है। दूसरी प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है।
2.	एनिमेशन प्रयोगशाला	02	01	एक प्रयोगशाला पूर्ण रूप से कार्यरत है और 03 विद्यार्थी समय सारणी के अनुसार इसका उपयोग कर रहे हैं। दूसरी प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है।
3.	प्रिंट मेकिंग प्रयोगशाला	03	03	सभी प्रयोगशालाएं पूर्ण रूप से कार्यरत हैं और अप्लाइड आर्ट, विभाग के 19 विद्यार्थियों तथा पेंटिंग एवम् ग्राफिक्स विभाग के 18 विद्यार्थियों एवं प्रथम वर्ष के 46 विद्यार्थियों द्वारा समय सारणी के अनुसार इनका उपयोग किया जा रहा है।

4. राज्य अर्बन प्लानिंग एवं आर्किटेक्चर संस्थान में प्रयोगशालाओं की स्थिति निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	प्रयोगशाला का नाम	प्रयोगशालाओं की आवश्यकता	प्रयोगशालाओं की उपलब्धता	टिप्पणी
1.	कम्प्यूटर प्रयोगशाला	01	01	प्रयोगशाला पूर्ण रूप से कार्यरत है तथा 40 विद्यार्थियों के द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है।
2.	सर्वेक्षण प्रयोगशाला	01	01	प्रयोगशाला पूर्ण रूप से कार्यरत है तथा 40 विद्यार्थियों के द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है।

ड्राईंग, प्रिंटिंग, स्टिचिंग, सिलाई एवं पैट्रन प्रयोगशालाएं राज्य डिजाइन संस्थान से सम्बन्धित हैं तथा पूर्ण रूप से कार्यरत हैं।

(ग) अपैरल और लाइफ स्टाइल एक्सेसरीज़ विभाग राज्य डिज़ाइन संस्थान से सम्बन्धित है।

राज्य डिजाइन संस्थान में तीन वर्षों के लिए (2011-14) 160 सीटें अनुमोदित हैं तथा इनमें से 86 सीटें भरी हुई हैं। नियमानुसार 160 विद्यार्थियों पर 11 प्राध्यापकों की आवश्यकता होती है। राज्य डिज़ाइन संस्थान में प्राध्यापकों की स्थिति इस प्रकार है:-

क्रम संख्या	विभाग	प्राध्यापक का नाम	पद
1.	प्रोडक्ट डिज़ाइन	पियुष घोघारी	सह आचार्य
2.	प्रोडक्ट डिज़ाइन	सोनल अत्रेय	प्राध्यापक
3.	प्रोडक्ट डिज़ाइन	अतहर अली	प्राध्यापक
4.	अपैरल डिज़ाइन	मनीष सोलंकी	प्राध्यापक
5.	लाइफ स्टाइल एक्सैसरीज डिज़ाइन	सुधीर कुमार तिरंगा	प्राध्यापक
6.	लाइफ स्टाइल एक्सैसरीज डिज़ाइन	जोशना हान्डा	प्राध्यापक
7.	लाइफ स्टाइल एक्सैसरीज डिज़ाइन	सतीश कुमार	प्राध्यापक
8.	टैक्सटाइल डिज़ाइन	वजाहत हुसैन	प्राध्यापक
9.	टैक्सटाइल डिज़ाइन	अनिल कुमार	प्राध्यापक
10.	टैक्सटाइल डिज़ाइन	राशिद इमाम	प्राध्यापक
11.	टैक्सटाइल डिज़ाइन	निहारिका सिंह	प्राध्यापक

ऊपर लिखित नियमित प्राध्यापकों के अलावा संस्थान में विज़िटिंग फैकल्टी तथा अनुभवी पेशेवरों को आवश्यकता अनुसार प्रत्येक सेमेस्टर में बुलाया जाता है। ये बाह्य एक्सपर्ट, विज़िटिंग फैकल्टी के तौर पर विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए बुलाए जाते हैं, जिससे विद्यार्थियों की शिक्षा का स्तर सुधारने में मदद मिलती है।

द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्रों को सैमेस्टर की समय सारणी के अनुसार अलग-अलग पढ़ाया जाता है। जब अनुभवी पेशेवरों के द्वारा व्याख्यान दिया जाता है केवल तभी सभी बच्चों को इकट्ठा पढ़ाया जाता है।

(घ) इस संस्थान में संयुक्त रूप से कोई भी कक्षा नहीं लगाई जाती। द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्रों की कक्षाएं सेमेस्टर समय सारणी के अनुसार अलग से लगाई जाती हैं। मशीनों की आवश्यकता केवल डिज़ाइन और फाइन आर्टस संस्थानों में ही है। विद्यार्थियों को संस्थान में पर्याप्त मात्रा में मशीनें प्रदान की गई हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

[श्री महेन्द्र प्रताप सिंह]

1. **राज्य डिज़ाइन संस्थान**

क्रम संख्या	विभाग	मशीनों के नाम
1.	प्रोडक्ट डिज़ाइन	मैकेनिकल लेथ, सी.एन.सी. लेथ, यूनिवर्सल मिलिंग, पिलर ड्रिल एवं अन्य टूल्स।
2.	अपैरल डिज़ाइन	सिलाई मशीन
3.	लाईफ स्टाइल एक्सैसरीज	सिलाई मशीन
4.	टैक्सटाइल डिज़ाइन	सिलाई मशीन, विविंग लूम मशीन

1. **राज्य फाइन आर्टस संस्थान**

क्रम संख्या	विभाग	मशीनों के नाम
1.	प्रिंट मेकिंग	लिथोग्राफी सैरिग्राफी इचिंग इटांगलियो

(ङ) बुनाई, इन्टर लॉक, फ्लैट लॉक, ऑवर लॉक की मशीनें राज्य डिज़ाइन संस्थान से सम्बन्धित हैं। संस्थान के पास इस प्रकार की मशीनें पर्याप्त मात्रा में हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	विभाग	मशीनों के नाम	संख्या	द्वितीय और तृतीय वर्ष के पंजीकृत छात्र
1.	प्रोडक्ट डिज़ाइन	मैकेनिकल लेथ	01	6
		सी.एन.सी. लेथ	01	
		यूनिवर्सल मिलिंग मशीन	01	
		पिलर ड्रिल मशीन	01	
2.	अपैरल डिज़ाइन	सिंगल निडल लॉक स्टिच सिलाई मशीन	30	18
		चेन स्टिच मशीन	2	
		थ्रेड ओवर लॉक मशीन	3	
3.	लाइफ स्टाइल एक्सैसरीज डिज़ाइन	सिलाई मशीन	अपैरल डिज़ाइन प्रयोगशाला के साथ संयुक्त रूप से इस्तेमाल की जाती है।	2
4.	टैक्सटाइल डिज़ाइन	सिलाई मशीन		18
		विविंग लूम मशीन	6	

इन संस्थानों में विशेष तरह के साफ्टवेयर की आवश्यकता होती है तथा आटोकेड, कोरलड्रा, फोटोशाप, माइक्रो साफ्ट ऑफिस सोलिड वर्कस के साफ्टवेयर संस्थान में उपलब्ध हैं। संस्थान में प्रयोगशालाओं में आवश्यकता अनुसार सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।

(च) इन संस्थान में बाकी बची सभी सुविधाएं नये शैक्षणिक सत्र 2014-15 (जुलाई 2014) के प्रारम्भ होने से पहले उपलब्ध करा दी जायेंगी।

Yellow Rust Attack on Wheat

592. Smt. Renuka Bishnoi : I wants to draw the kind attention of this house towards :—

(a) whether the Government has taken note of the large scale yellow rust attack on wheat crop at several places in Haryana;

(b) if so, the main reasons for recurrence of the disease togetherwith its likely impact on the wheat production during the current year; and

(c) the preventive steps being taken by the Government to check the spread of the disease in more areas?

कृषि मंत्री (सरदार परमवीर सिंह) :

(क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) पीले रतुए की बीमारी पत्तियों पर पीली धारियों के रूप में प्रकट होती है। ठण्डा मौसम, वर्षा की सम्भावना, ओस एवं धुन्ध पीले रतुए के आक्रमण में मदद करते हैं। जब तापमान 10-20 डिग्री सैं० होता है तब पीला रतुआ हवा में यूरीडिस्पोर्स के माध्यम से फैलता है तथा 25 डिग्री सैं० से अधिक तापमान होने पर इसका विस्तार अपने आप रूक जाता है। इस रोग का आक्रमण वृक्षों या छाया में उगाई गई फसल पर काफी मात्रा में पाया जाता है। इस रोग का आक्रमण यमुनानगर, अम्बाला, कुरूक्षेत्र, करनाल एवं सिरसा जिलों के कुछ भागों में पाया गया है। अभी तक राज्य के किसी भी क्षेत्र में गेहूं की फसल में किसी नुकसान की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। किसान इस रोग को प्रोपीकोनाजोल 25 प्रतिशत ई०सी० 0.1 प्रतिशत या टेबुकोनाजोल 250 ई०सी० (पोलीकर 250 प्रतिशत ई०सी०) 0.1 प्रतिशत की दर से अपने खेतों में छिड़काव करके सफलतापूर्वक नियन्त्रण कर चुके हैं। वर्तमान वर्ष में गेहूं के उत्पादन पर इस रोग का प्रभाव नाममात्र होने की सम्भावना है।

(क) विभाग द्वारा उठाए गए कदम -

1. कृषि विभाग द्वारा पीले रतुए के आक्रमण के नियन्त्रण हेतु किसानों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया है। पीले रतुए की बीमारी के नियन्त्रण हेतु प्रभावित फसल पर छिड़काव करने के लिए किसानों की सलाह हेतु अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जा रहे हैं। विभाग ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर रहा है, जिसमें किसानों को पम्फलैट एवं पोस्टर

[सरदार परमवीर सिंह]

वितरित किए जाते हैं। किसानों को इस बारे शिक्षित करने के लिए प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक माध्यमों का भी उपयोग किया गया है।

2. पीला रतुआ प्रतिरोधी किस्में जैसे कि डब्ल्यू०एच०-1105, डीबी०डब्ल्यू०-621-50, डब्ल्यू०एच०-1021, डब्ल्यू०एच०1080, डब्ल्यू०एच०-1124, राज०-3765 को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

3. इस बीमारी को नियन्त्रण करने के लिए संस्तुत रसायनों के पर्याप्त मात्रा में भण्डारण को सुनिश्चित किया जा रहा है।

4. पीला रतुआ रोग से ग्रस्त हो जाने वाली किस्मों को हतोत्साहित किया जा रहा है।

5. पीले रतुए के रोग के नियन्त्रण हेतु किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर फफूंदनाशियों की पूर्ति की जा रही है।

Selection of Drivers

600. Prof. Sampat Singh : Will the Transport Minister be please to state—

(a) the number of Heavy Vehicle Drivers selected by Haryana Roadways recently in the state;

(b) the Depotwise number of recently selected drivers posted in the state;

(c) the number of such selected drivers whose driving license have been found bogus; and

(d) whether it was not necessary to scrutinize the licenses of the candidates before their selection?

परिवहन मंत्री (श्री आफताब अहमद) : श्रीमान, एक तालिका सदन के पटल पर रखी जाती है।

तालिका

(क) राज्य में हाल ही में हरियाणा परिवहन द्वारा 1074 भारी वाहन चालक चयन किए गए हैं।

(ख) अभी हाल ही में चयन किए गए चालकों की डिपोवार आबंटन की सूची अनुबन्ध 'क' पर संलग्न हैं।

(ग) अब तक 37 चयनित चालकों (अनुबन्ध 'ख') के चालक लाइसैंस फर्जी पाए गए। फिर भी चालक लाइसैंस सत्यापित करवाने की प्रक्रिया जारी है।

(घ) हरियाणा राज्य परिवहन के महाप्रबन्धकों को चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति देने से पूर्व उनके लाइसैंसों की छानबीन करने के निर्देश दिए गए हैं।

Annexure-'A'

Statement depot-wise driver position

Sr. No.	Name of Depot	Allotted Drivers
1.	Ambala	45
2.	Bhiwani	35
3.	Chandigarh	65
4.	Charkhi Dadri	48
5.	Delhi	12
6.	Fatehabad	31
7.	Faridabad CBS	82
8.	Faridabad	66
9.	Gurgaon	100
10.	Nuh	50
11.	Hisar	22
12.	Jind	43
13.	Jhajjar	17
14.	Kurukshetra	45
15.	Karnal	35
16.	Kaithal	48
17.	Narnaul	35
18.	Panipat	38
19.	Palwal	31
20.	Rohtak	42
21.	Rewari	26
22.	Sonepat	32
23.	Sirsa	81
24.	Yamuna Nagar	45
	Total	**1074**

[श्री आफताब अहमद]

Annexure-'B'

Statement depot-wise fake driving license

Sr. No.	Name of Depot	Fake Driving License
1.	Ambala	0
2.	Bhiwani	02
3.	Chandigarh	0
4.	Charkhi Dadri	05
5.	Delhi	0
6.	Fatehabad	0
7.	Faridabad CBS	0
8.	Faridabad	0
9.	Gurgaon	06
10.	Nuh	01
11.	Hisar	0
12.	Jind	05
13.	Jhajjar	01
14.	Kurukshetra	0
15.	Karnal	0
16.	Kaithal	0
17.	Narnaul	01
18.	Panipat	03
19.	Palwal	03
20.	Rohtak	03
21.	Rewari	02
22.	Sonepat	0
23.	Sirsa	02
24.	Yamuna Nagar	03
	Total	**37**

Recommendations of National Police Commission

593. Smt. Renuka Bishnoi : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether in 2006 the Hon'ble Apex Court has advised to all the State Governments to implement the recommendations of National Police Commission;

(b) if so, the reasons for not implementing the recommendations of the National Police Commission in Haryana;

(c) the steps being taken by the Government to implement the recommendations of National Police Commission in Haryana and to remove the anomalies in the pay scales, allowances and terms and conditions of service of Haryana Police Personnel's; and

(d) the steps being taken by the Government to grant the equal pay scale to the Haryana Police Personnel's at par with the Himachal Pradesh and Punjab Police Personnel?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान जी, कथन सदन के पटल पर रखा गया है।

कथन

(क) जी हाँ, श्रीमान,

(ख) हरियाणा सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 310/1996 प्रकाश सिंह व अन्य बनाम भारतीय संघ व अन्य में जारी किए गए दिशा-निर्देशों की भी यथासम्भव व मुख्यत: अनुपालना की जा चुकी है।

(ग) सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुलिस आयोग के दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं, वे निम्नानुसार हैं:-

I. सरकार ने हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 कानून बनाया और इसे दिनांक 02-06-2008 को अधिसूचित किया गया है।

II. हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 के अध्याय संख्या 3 में वर्णित कार्यों को क्रियान्वित करने हेतु दिनांक 24-12-2009 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य पुलिस बोर्ड का गठन किया गया है।

III. पुलिस महानिदेशक की पदावधि उनकी अधिवर्षिता की सामान्य तिथि को ध्यान में लिए बिना कम से कम एक वर्ष होगी।

IV. रेंज पुलिस महानिरीक्षक एवं जिला पुलिस अधीक्षकों का कार्यकाल एक वर्ष के लिए निश्चित किया गया है। इसी प्रकार प्रबन्धक थाना तथा पुलिस चौकी इंचार्ज का कार्यकाल न्यूनतम एक वर्ष और अधिकतम 3 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

V. राज्य के प्रत्येक जिला में विशेष जाँच ईकाईयाँ - जैसे आपराधिक अनुसंधान शाखा, महिला विरुद्ध अपराध शाखा व आर्थिक अपराध शाखा सृजित की गई है।

VI. भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के स्थानान्तरण एवं नियुक्ति की प्रक्रिया को सरल व कारगर बनाने के लिए गृह विभाग के आदेश क्रमांक 1/1/2014-2एच1, दिनांक 17-02-2014 के अनुसार मुख्य सचिव, हरियाणा की अध्यक्षता में एक सिविल सेवा बोर्ड का गठन किया गया है।

VII. पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध दुराचरण के गंभीर आरोपों की जाँच हेतु दिनांक 16-08-2010 को एक राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित किया गया है।

VIII. दिनांक 06-05-2014 को हरियाणा पुलिस में सिपाहियों की भर्ती हेतु एक 'राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड' सृजित किया गया है।

सरकार ने हरियाणा पुलिस कर्मचारियों की सेवा-शर्तें, उनके वेतनमानों एवं भत्तों की विसंगतियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए है:-

1. केन्द्र सरकार द्वारा गठित छठे वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें दिनांक 24-03-2008 को दी थी। छठे वेतन आयोग की इन सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को नए वेतनमान दिनांक 30-12-2008 को प्रदान किए हैं। हरियाणा पुलिस के सिपाहियों के वेतनमान 3050-5325 रुपये को संशोधित/परिवर्तित करके पेबैण्ड-1, जो कि पे बैण्ड 5200-20200+2000 रुपये (ग्रेड पे के रूप में), निर्धारित किए गए, जो दिनांक 01-01-2006 से प्रभावी हैं। महंगाई भत्ता, पे बैण्ड और ग्रेड पे के योग पर दिया जा रहा है।

2. राज्य सरकार ने सिपाही से निरीक्षक पद तक के पुलिस कर्मचारियों को गृह विभाग के ज्ञापन क्रमांक 7/13/2013-3एचजी-1, दिनांक 09-01-2014 द्वारा जोखिम भत्ते के रूप में 5000/- रु0 प्रति माह स्वीकृत किए गए हैं, जो दिनांक 01-01-2014 से प्रभावी हैं।

3. राज्य सरकार ने वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 4/1/2013-1 एफआर/31960, दिनांक 17-12-2013 द्वारा पुलिस कर्मियों तथा ग्रुप-सी व ग्रुप-डी के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत के रूप में 2000/- रुपये प्रति माह स्वीकृत किए हैं।

4. इसके अतिरिक्त पुलिस कर्मचारियों को मासिक आधार पर वर्दी रख-रखाव भत्ता, वाहन भत्ता, निश्चित चिकित्सा भत्ता व राशन भत्ते की अदायगी भी की जा रही है।

5. सिपाहियों को कठिनाई भत्ते के रूप में 100/- रु0 प्रति माह दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

6. सभी ग्रुप-सी व ग्रुप-डी पुलिस कर्मचारियों को प्रति माह एक निश्चित राशि अदा करने पर हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में असीमित यात्रा करने की सुविधा प्रदत्त है।

7. हरियाणा पुलिस के सिपाही से निरीक्षक पद तक के पुलिस कर्मचारियों को लम्बे समय तक ड्यिूटी करने व सभी प्रकार के अवकाशों के दौरान कार्य करने की प्रतिपूर्ति में एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया जा रहा है।

8. पुलिस कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा भत्ता (एलटीसी) या इसकी प्रतिपूर्ति हेतु एक माह का वेतन दिए जाने की सुविधा है।

9. सिपाहियों को कम से कम दो 'एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन' (एसीपी) दिए जा रहे हैं। एसीपी के रूप में उच्च वेतनमान का लाभ 10 और 20 वर्ष की सेवा उपरान्त दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उन्हें 12 वर्ष, 22 वर्ष व 30 वर्ष के सेवाकाल उपरान्त 'एग्जेम्पटी नॉन काडर' पदोन्नति भी दी जा रही है।

10. सिपाही के सहायक उप-निरीक्षक स्तर के पुलिसकर्मियों की पदोन्ति प्रशिक्षण से जुड़ी है, और

घ- हरियाणा सरकार के पुलिसकर्मियों का वेतनमान पड़ोसी राज्यों दिल्ली, राजस्थान व केन्द्रीय सरकार के संगठनों के समतुल्य है। अधिकतर श्रेणियों में पुलिसकर्मियों के ये वेतनमान या तो पड़ोसी राज्यों/केन्द्र सरकार के संगठनों के कर्मचारियों के समान हैं या उनसे औसतन अधिक है। हरियाणा राज्य की वेतन एवं भत्तों की संरचना तर्कसंगत एवं आवश्यकता आधारित है।

Selection of Schools Lecturers

601. Prof. Sampat Singh : Will the Education Minister be please to state—

(a) the number of School Lecturers of different streams selected by Teacher Recruitment Board;

(b) the number of such teachers who have been given their postings;

(c) the reason as to why the remaining selected teachers have not been given postings so far;

(d) the number of such selected teachers whose experience certificates have been found bogus; and

(e) whether it was not necessary to scrutinize these certificates before their interview?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) :

(क) कुल चयनित पी.जी.टी. की संख्या :- 8828.

(ख) कुल 4138 पी.जी.टीज़ को नियुक्ति स्थान प्रदान किये जा चुके है।

(ग) अध्यापक भर्ती बोर्ड द्वारा बहुत से उम्मीदवारों का चयन 4 वर्ष के अनुभव के आधार

[श्रीमती गीता भुक्कल मालनहेल]

पर किया गया है, जिन उम्मीदवारों द्वारा अनुभव सरकारी/अनुदान प्राप्त/मान्यता प्राप्त/निजी स्कूलों से लिया गया है। बोर्ड ने अनुरोध किया है कि ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने से पूर्व उनके अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच की जाये। इस उद्देश्य के लिए गठित कमेटियों द्वारा इन उम्मीदवारों के अनुभव जांचे गये हैं। ऐसे उम्मीदवार, जो इन कमेटियों द्वारा नियुक्ति के लिए योग्य पाए गए हैं, उनके आदेश जारी किये जा चुके हैं। शेष बचे हुए उम्मीदवारों के मामलों का भी भली-भांती निरीक्षण किया जा रहा है और विभाग द्वारा सूचना अद्यतन की जा रही है।

(घ) इस दिशा में मामला विचाराधीन है। इस समय यह दर्शाना सम्भव नहीं है कि कितने उम्मीदवारों के अनुभव प्रमाण पत्र जाली पाए गए हैं।

(ङ) हाँ।

Constitution of Gurdwara Prabandhak Committee

594. Smt. Renuka Bishnoi : Will the Chief Minister be please to state—

(a) whether the Government is aware of the fact that the independent Gurdwara Management Committees are functioning in various states in the country, and

(b) the steps being taken by the Government to constitute an independent Gurdwara Prabandhak Committee in Haryana at the earliest?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश में गुरुद्वारों का प्रबन्ध एक एकल समिति कर रही है। दिल्ली में गुरुद्वारों के प्रबन्धन की देखभाल डी.एस. जी.एम.सी. कर रही है।

(ख) श्री एच.एस. चड्ढा, कृषि मन्त्री, तत्कालीन हरियाणा सरकार (अब वित्त मन्त्री) की अध्यक्षता में एक समिति इस विषय पर बनाई गई थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। अब यह मामला महाधिवक्ता, हरियाणा की अध्यक्षता में समिति की विधिक जांच के अधीन है।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना

श्री रामपाल माजरा (कलायत) : * * * *

Mr. Speaker : It is over please. (Interruption). Nothing will come on record, not a signal word about this may be recorded. Nothing will come on record (Interruption). Nothing will come on record. This is a malicious campaign. I will not allow (Interruption). Nothing is to be recorded.

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Co-operation Minister (Shri Satpal) : Speaker Sir, it is not fact. स्पीकर सर, यह हाउस है, इन लोगों के मन में जो आता है वही कागज उठा कर ले आते हैं। सर, ये लोग हर रोज नया-नया कागज लेकर आते हैं। स्पीकर सर, इन लोगों को कोई और काम ही नहीं है।

Mr. Speaker : Everything will be expunged regarding this issue. Nothing is to be recorded regarding this issue. I am not taking notice of this issue (Interruption). Nothing will be a part of proceedings of this House.

श्री अनिल विज : सर, * * * (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded

श्री भारत भूषण बत्रा : स्पीकर सर, * * * (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Nothing is on record. Please switch off the mike. It shall not go to the press. It is a malicious campaign. Nothing is to be recorded. No whisper regarding all this. (interruption). Nothing is to be recorded. Nothing will go to the press. (Interruption). Hon'ble members, I have received a calling attention Notice from Shri Ram Pal Majra, MLA regarding resentment amongst the managements of private schools in the State of Haryana. I admit it. He may read his notice (Interruption). I think he is not responding.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मुझे मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का फेट बताएं (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : I have already taken up one issue.

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. I can take up at a time one issue. I have allowed Mr. Majra to speak. (Interruptions).

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, मैं आपका ध्यान अति महत्वपूर्ण लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ (विघ्न)।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है।

Mr. Speaker : Mr. Vij, please sit down. Mr. Vij let Shri Majra Ji, complete. Mr. Vij, please resume your seat. You can speak after Shri Ram Pal Majra.

श्री अनिल विज : सर, * * * (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Mr. Vij, please resume your seat. I am warning you. Nothing is to be recorded.

श्री अनिल विज : सर, * * * (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Mr. Vij, please resume your seat. I am giving you last warning. You can not force me. I will tell you. प्लीज बैठ जाइये।

श्री अनिल विज : सर, * * * (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

वाक-आउट

Mr. Speaker : Now, I have started discussion on another issue. Please sit down. (Interruption). Mr. Anil Vij, please sit down otherwise, I will name you.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के फेट के बारे में मुझे जानकारी नहीं दी जा रही है, इसलिए हम सदन से वॉक आउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य सदन से वॉकआउट कर गये।)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-----

(i) राज्य में निजी विद्यालयों के संचालकों में रोष संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Motion Notice No. 3 from Shri Ram Pal Majra, MLA regarding the resentment amongst the managements of private schools in the State, which has been admitted. Now, Shri Ram Pal Majra, MLA is called upon to read out his notice.

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक तथा अति लौक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि प्रदेश में जो व्यक्ति प्राईवेट स्कूलों का संचालन कर रहे है इन दिनों अन्दोलित हैं क्योंकि प्रदेश सरकार ने उनकी मांगों पर विचार न करके अडियल रवैया अपनाया हुआ है। शिक्षा के अधिकार कानून के अनुसार प्राईवेट स्कूलों में गरीब परिवारों के 25 प्रतिशत बच्चों को दाखिला देना जरूरी है। यह अति सराहनीय पग है परन्तु इन बच्चों को पढ़ाने के बदले में प्राईवेट स्कूलों को सरकारी सहायता या अनुदान देना भी अपेक्षित है जिससे गरीब परिवारों के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करें व आगे बढ़ सकें। प्राईवेट स्कूलों को स्थाई मान्यता देने व स्कूलों का दर्जा बढ़ाने में सरकार कोई रूचि नहीं ले रही है। बिजली व पानी आदि पर व्यावसायिक दरों पर प्रभार वसूले जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप स्कूलों की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। प्राईवेट स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों को पात्रता परीक्षा की शर्त लगाई है जिसकी वजह से प्राईवेट स्कूलों के संचालको में भारी रोष है।

मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस संबंध में सदन के पटल पर एक वक्तव्य देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

वक्तव्य

शिक्षा मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will make a statement.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukhal Matanhail) : Speaker Sir,

1. It would be incorrect to state that the State Government has adopted rigid attitude by not considering the demands of private school. On the contrary, State has considered the demands of private schools time and again and also organized consultations with them from time to time at various levels.

2. That with regard to reserving 25% seats for the children belonging to weaker and disadvantageous sections is related, it is submitted that Rule 134-A of Haryana School Education Rules 2003 provides for 25% reservation of seats for the meritorious students belonging to the economically weaker sections for all classes i.e. I to XII. Acceding to the demand of Recognized School Association, the State Government has already reduced the quota of reserved seats for the economically weaker section from 25% to 10%. This rule was amended by the Government on request of the Private Schools Association. The extract of this rule is reproduced as under:-

> **"134 A reservation for meritorious students belonging to econmically weaker section. Section 24(2) and 15. The recognized private schools shall reserve 10% seats for meritorious students belonging to economically weaker section and BPL (Below Poverty Line) category. The school shall charge fee from these students at the same rate as charged in Government schools".**

There is no provision in the aforesaid rule for reimbursement of fees to the private schools. It is pertinent to mention here that no private school in the state has been declared as neighbourhood school under the RTE Act. Thus, the private schools are not entitled to any reimbursement from the Government. The State is very much committed for providing education to each student belonging to the EWS and B.P.L. categories.

3. Further, Government has larege number of Government schools covering entire neighbourhood areas. At present, State of Haryana has 14925 schools (primary and middle) in neighbourhood areas. Besides providing free education as mentioned above, other facilities such as free stationery, work books, text books, school bags and uniform are also being provided by the Government of Haryana to the children studying in Class I to VIII.

4. That in response to the question raised by the Hon'ble M.L.A. regarding the grant of recognition and upgradation to the private school, it is clarified that the state had framed Haryana Schools Education Rules 2003 which govern the private aided and unaided schools in the State. Keeping in view, demands of various Associations to relax the Rules of 2003, the government amended these rules in 2007 and granted various relaxations with regard to building and land norms to the existing schools which were running before 31.03.2007. Thereafter, in 2009 the Government notified the list of nearly about 3200 existing schools. Out of these 3200 existing schools nearly about 782 schools which fulfilled the relaxed norms have already been granted permanent recognition by the District Level Committees headed by the Deputy Commissioner. The remaining existing schools do not fulfill even the relaxed norms for permanent recognition. Taking a lenient view, since 2007 these schools are being granted extension by the State to fulfill the norms for recognition. However, even after a lapse of seven years the position of these schools remains unchanged and norms have still not been complied with.

[Smt. Geeta Bhukhal Matenhail]

5. That as far as the question of commercial rates being charged from private schools for basic amenities such as water and electricity is concerned, the right of charging and fixing tariff plans for the said utilities vests with the concerned utilities and regulatory authorities. Any aggrieved party can approach the concerned authorities.

6. That as far as the condition of imposing the eligibility test on the teachers of private schools is concerned, it is clarified that this condition has been imposed to improve the quality of education as per the provisions of RTE Act. Moreover, eligibility test being conducted for teachers of private school is not unique to State of Haryana as the same is equally applicable to other states as well in consonance with the provisions envisaged in Section 17 of RTE Act.

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसाकि प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेने के लिए प्राय: रुझान बढ़ रहा है। इस बारे में जैसाकि एन.जी.ओ.प्रथम ने भी अपनी रिपोर्ट में दिया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों का जो उन्होंने 552 गांवों का सर्वे किया है उसमें पाया है कि 51.4 प्रतिशत बच्चों का रुख निजी स्कूलों की तरफ है और यह इसलिए भी है कि उसने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि सरकारी स्कूलों की हालत बड़ी खस्ता हो गई है। सरकारी स्कूलों के पांचवीं कक्षा तक के बच्चों को जोड़ घटा के सवाल भी हल करने नहीं आते हैं। घटा और जोड़ का सवाल 51 फीसदी बच्चे जानते ही नहीं हैं। कक्षा दो के 40 प्रतिशत बच्चे दैनिक उपयोग में आने वाले हिन्दी के शब्द ही नहीं पढ़ पाये और 11 से 99 तक के अंकों को पहचान नहीं पाये। इसके अलावा बायोमिट्रीक मशीन खराब हैं और 10564 एजु सैट बन्द हैं, 19402 कम्प्यूटर्ज बन्द पड़े हैं। 40 हजार अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। जिसकी वजह से बच्चों का रुझान प्राईवेट स्कूलों की तरफ बढ़ रहा है। यह तो ठीक है कि गरीब आदमी के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े। शिक्षा में सुधार हो। जैसा कि मैंने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में लिखा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 25 प्रतिशत बच्चों को प्राईवेट स्कूलों में दाखिला देने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। प्राईवेट स्कूल जो उन बच्चों को एडमिशन देंगे उनकी फीस वगैरह के लिए जो खर्चा करेंगे उसको रीइम्बर्स करने या और किसी प्रकार की ऐसी ऐड उन स्कूलों को देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि सैक्शन 134 ए के तहत 25 प्रतिशत बी.पी.एल. परिवार के बच्चों को प्राईवेट स्कूलों में एडमिशन देना था लेकिन अब उसको घटाकर दस प्रतिशत कर दिया गया है। जबकि प्राईवेट स्कूलों को 25 प्रतिशत बच्चों को एडमिशन देना चाहिए था। यह सब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ प्राईवेट स्कूल की मैनेजमैंट की मीटिंग में सहमति के बाद ही फैसला लिया गया है जिसके तहत 25 प्रतिशत की बजाए यह दस प्रतिशत किया गया है। शिक्षा का अधिकार लागू होने के बाद यह प्रावधान किया गया था कि प्राईवेट स्कूल वाले अपने स्कूल में 25 प्रतिशत एडमिशन बी.पी.एल. परिवारों के बच्चों को देंगे। शिक्षा के अधिकार के कानून के तहत एडमिशन देने की स्थिति अलग से हैं और सैक्शन 134-ए के तहत एक अलग स्थिति है। जैसा कि हमारे सम्मानित सदस्य ने कहा कि प्रथम-एक की रिपोर्ट के अनुसार प्राईवेट स्कूलों में एडमिशन लेने की बच्चों की संख्या बढ़ी है। सरकारी स्कूलों में भी सरकार ने हर संभव सभी सुविधाएं बच्चों को देने की कोशिश की है। सब

सुविधाएं सरकार दे रही हैं जिसके कारण सरकारी स्कूलों में भी बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। नये स्कूल खोले गये हैं, नये स्कूल अपग्रेड किए गये हैं। क्वालिटी एजुकेशन पर भी सरकार का पूरा ध्यान है। जब कोई भी रिपोर्ट आती है तो सरकार उस पर पूरी गम्भीरता से विचार करती है। 134-ए के तहत जो भी एडमिशन दिए जायेंगे तो सरकार उस में से कोई भी पैसा रीइम्बर्स नहीं करेगी। अगर शिक्षा के अधिकार के तहत किसी स्कूल को नेबरहुड स्कूल डिक्लेयर किया जाता है तो ही उस स्कूल में बच्चों को एडमिशन मिल सकता है। उसी स्थिति में अगर प्राईवेट स्कूल पहली कक्षा में बच्चों को एडमिशन देते हैं। तब केवल उसी स्थिति में ही सरकार उन स्कूलों को पैसे रीइम्बर्स करेगी। लेकिन आज हरियाणा में स्थिति इतनी बेहतरीन है कि नेशनल एवरेज से अच्छी हमारे सरकारी स्कूलों की स्थिति है। इसलिए कोई भी नेबरहुड स्कूल हमने प्राईवेट स्कूल को डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। इसलिए प्राईवेट स्कूलों में दस प्रतिशत एडमिशन देना एक दूभाग्यपूर्ण स्थिति है जबकि इन प्राईवेट स्कूलों को 25 प्रतिशत एडमिशन देना चाहिए था। लेकिन प्राईवेट स्कूल एसोसिएशंज ने धरना, जलूस आदि करके सरकार पर प्रैशर डालकर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कई बार मीटिंग करके 25 प्रतिशत की बजाए दस प्रतिशत एडमिशन देने का काम किया है। मैं तो सदन के माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को यह कहना चाहूंगी कि हम सभी ने यह एन्श्योर करना चाहिए क्योंकि यह मामला कोर्ट में भी गया और कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि हमारे गरीब बच्चों को चाहे सरकारी स्कूलों में शिक्षा देने की बात हो चाहे प्राईवेट स्कूलों में शिक्षा देने की बात हो लेकिन उनको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। इसलिए दस प्रतिशत ई.डब्ल्यू.एस. के बच्चो को स्कूलों में एडमिशन प्राईवेट स्कूलों को जरूर देना चाहिए।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, गरीब बच्चों को दाखिला देने के लिए जिस प्रकार की इन्फर्मेशन मांगी जाती है वह इन्फर्मेशन प्राईवेट स्कूल नहीं दे रहे हैं। क्या सरकार द्वारा उन स्कूलों से यह पूछा जाता है कि उन्होंने दस प्रतिशत गरीब बच्चों को एडमिशन दिया है या नहीं ? क्या सरकार ने इस काम के लिए विभाग की कोई मॉनिटरिंग कमेटी बनाई हुई है। क्योंकि प्राईवेट स्कूलों पर भी सी.एल.यू. आदि की कई कंडीशंज लगाई जाती हैं, बिजली और पानी के लिए उन पर कॉमर्शिएल रेट लगाये जाते हैं। क्या इन पर प्राईवेट स्कूलों को किसी प्रकार का रिबेट देने का प्रावधान सरकार की तरफ से किया गया है , क्या ऐसा मामला सरकार के या विभाग के विचाराधीन है ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : स्पीकर सर, दस प्रतिशत गरीब बच्चों को प्राईवेट स्कूलों द्वारा एडमिशन देना बहुत जरूरी है। इसलिए विभाग ने फी एण्ड फण्ड रेगूलेटरी कमेटी डिविजनल लैवल पर कान्टीच्यूट की है। डिविजनल कमिशनर उस कमेटी के चेयरपर्सन हैं और डिस्ट्रिक्ट एलीमैंट्री आफिसर उस कमेटी के एक्स आफिशियो मैम्बर हैं और एक रिटायर्ड एकाउंट्स आफिसर या चारटर्ड एकाउंटैंट जो भी चेयरपर्सन की तरफ से नोमिनेट किया जाता है उस कमेटी का मैम्बर बनाया गया है। इसके लिए हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जो प्राईवेट स्कूल हैं वे न केवल एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे बल्कि वे समय समय पर जो फीस बढ़ा देते हैं उस पर भी नजर रखेंगे। उसके लिए बाद में काफी ज्यादा दिक्कत आती है और विभाग इसके लिए बहुत ज्यादा संजीदा है। इसीलिए हमने इसके लिए कमेटी का गठन किया है। हम इसके लिए एन्श्योर करेंगे कि जो स्कूल गरीब बच्चों को 10 प्रतिशत एडमिशन नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। 134-ए के तहत 25 प्रतिशत की बजाए दस प्रतिशत एडमिशन देने के बारे में रिवाईज्ड नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। इस समय दस प्रतिशत एडमिशन देना अनिवार्य हो चुका है इसके लिए हमने कमेटी का गठन भी किया है।

श्री अध्यक्ष : माजरा जी, आपकी दो सप्लीमैंट्री हो चुकी है। आप एक और सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, 1372 स्कूल आज हरियाणा प्रदेश में बन्द होने के कगार पर हैं जो अपनी मांगों को लेकर आन्दोलित हैं। क्या उनकी मान्यता पर सरकार विचार करेगी ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी से जानना चाहूंगी कि क्या हम शिक्षा की दुकानें इस तरह से चलने दें। जैसा मैंने बताया कि हम लोगों ने प्राइवेट स्कूलों की मान्यता के लिए बहुत बार नार्म्ज रिलैक्स किए। शिक्षा के अधिकार के तहत उन स्कूलों को भी मान्यता लेना जरूरी है जो आलरेडी मान्यता ले चुके थे। सभी स्कूलों ने एप्लाई किया और सरकार की ओर से उनको बार बार मौका दिया गया। केन्द्र सरकार ने भी कहा और इसने मिनिस्ट्री आफ एच.आर.डी. में भी कहा कि ऐसे स्कूलों को एक बार छूट दे दी जाए लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत मार्च, 2013 तक सभी स्कूलों को मान्यता लेना जरूरी था जोकि उन स्कूलों ने नहीं ली। कोर्ट के आदेशानुसार हमने उन स्कूलों को बन्द करने के आदेश दिए और ये स्कूल कोर्ट में भी गए। सरकार ने हर सम्भव प्रयास किया कि जो बच्चे इन 1372 स्कूलों में पढ़ रहे हैं उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए उन्हें यह सत्र पूरा करने दिया जाए लेकिन शिक्षा के नाम पर जो इस तरह के टयूशन सैंटर्ज खुल रहे हैं वह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात सदन में कहना चाहूंगी कि स्कूलों को मान्यता लेना अति जरूरी है और मान्यता लेने के लिए सभी स्कूल जरूर एप्लाई करें। मान्यता प्राप्त करने के बाद ही बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए।

(ii) हरियाणा के खेलकूद प्राधिकरण के गठन संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Motion Notice No. 22 from Shri Bharat Bhusan Bhatra, MLA regarding the constitution of Sports Authority of Haryana, which has been admitted. Now, Shri Bharat Bhushan Batra, MLA is called upon to read out his notice.

Shri Bharat Bhushan Batra : Sir, I want to draw the attention of this August House to a matter to urgent public importance regarding looking after the whole infrastructure created by the Government for the development of the sports activities in the State, popularising sports, identifying and developing athletes from an early age, creating income and employment opportunities for career sportspersons, as Haryana has a name for glorious achievements in the filed to sports. In London Olympic, 1/3rd Medals were won by the State athletes. The population of the Haryana State is only 2% of the country, whereas the State contributed 23% players in these games. Out of six medal winners, four were from Haryana. In Asian Games the State bagged 5 Gold, 9 Silver and 7 Bronze medals, besides one silver and 3 Bronze medals in Asian Games held in China. Similarly in Commenwealth Games, the sportspersons from Haryana won 21 Gold, 6 Silver and 8 Bronze medals. Besides these achievements, there are many other achievements of the Haryana Sports persons at the National and State levels. No doubt, the Haryana Government is giving much more incentives to the sports persons as compared to the other States.

There are two State Sports Complexes, one at Faridabad and another Rajiv Gandhi State Sports Complex at Rohtak, 21 District Sports Complexes, 13 Sub-Divisional Stadiums and 159 Rajiv Gandhi Gramin Khel Parisars. 67 Rajiv Gandhi Khel Parisars are under development. There are also 232 Mini/Rural stadiums. So, there is a huge infrastructure which is required to be maintained and developed further.

The Sports department alone can not take care of this huge infrastructure and also take effective steps for rapid development of the sports activities in the State. Therefore, I would suggest to the Government to constitute Sports Authority of Haryana which will take care of this infrastructure as also take other necessary steps for development of sports activities in the State and help the Sports department in its developmental activities. This authority may be given a separate budget apart from the Sports department.

I request the Hon'ble Minister to make a Statement on the floor of the House in this regard.

वक्तव्य-

खेल एवं राज्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में

खेल एवं युवा राज्य मंत्री (श्री सुखबीर कटारिया) : अध्यक्ष महोदय

1. माननीय विधायक ने खेल के क्षेत्र में हरियाणा की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला है। हरियाणा राष्ट्र में खेलों के क्षेत्र में एक अहम भूमिका अदा करता है। गत ओलम्पिक, एशियाई एवं राष्ट्रमण्डल खेलों के अतिरिक्त, वर्ष 2013 में जर्मनी में आयोजित विश्व हॉकी महिला प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीत कर राज्य की 06 महिला खिलाड़ियों ने राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। जिला भिवानी की कुमारी निर्मला ने जुलाई, 2013 में पूना में आयोजित वरिष्ठ एशियाई एथलैटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर रिले रेस में स्वर्ण पदक जीता तथा अगस्त, 2013 में मास्को में आयोजित विश्व स्तरीय एथलैटिक्स प्रतियोगिता में भी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया। एशियाई कैडिट कुश्ती प्रतियोगिता में अनु पंघाल ने रजत तथा मंजु ने कांस्य पदक जीते। अप्रैल, 2013 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में राज्य के 04 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीते। राज्य के खिलाड़ियों ने दिसम्बर, 2013 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित राष्ट्रमण्डल कुश्ती प्रतियोगिता में 09 स्वर्ण, 03 रजत तथा 03 कांस्य पदक जीते। अमित ने दिसम्बर, 2013 में बुडापेस्ट में आयोजित वरिष्ठ विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में रजत तथा बजरंग ने कांस्य पदक जीते। राज्य ने वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में पायका राष्ट्रीय ग्रामीण प्रतियोगिताओं में समग्र चैम्पियनशिप जीती।

2. राज्य सरकार ने राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों, अशक्त खिलाड़ियों सहित, को उदार नकद ईनाम देकर प्रोत्साहित किया है। ओलम्पिक खेल-2012, एशियाई खेल-2010 तथा राष्ट्रमण्डल खेल-2010 में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को क्रमशः 665.00 लाख रुपये, 638.00 लाख रुपये तथा 455.50 लाख रुपये के नकद ईनाम प्रदान किये गये थे। इसके अतिरिक्त, ओलम्पिक खेल-2016 के लिए नकद ईनाम की दरें दोगुनी कर दी गई है। अब ओलम्पिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को 5.00 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेताओं को 3.00 करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक विजेताओं को 2.00 करोड़ रुपये प्रदान किये जायेंगे।

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
(5)50
LIBRARY
Chandigarh

[श्री सुखबीर कटारिया]

राज्य में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत व उनके भवष्यि को सुरक्षित बनाने के लिए अशक्त खिलाड़ियों सहित राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां प्रदान करने के लिए एक नीति बनाई गई है। इस नीति के अनुसार, ओलम्पिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को श्रेणी-1 में नौकरियां प्रदान की जायेगी; जबकि ओलम्पिक खेलों में रजत व कांस्य पदक विजेताओं, एशियाई खेलों एवं राष्ट्रमण्डल खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को श्रेणी-2 में नौकरियां प्रदान की जायेंगी। ओलम्पिक खेलों में प्रतिभागिता करने वाले खिलाड़ियों, एशियाई खेलों एवं राष्ट्रमण्डल खेलों में रजत तथा कांस्य पदक विजेताओं को श्रेणी-3 में नौकरियां प्रदान की जायेंगी। अब तक इस नई नीति के अन्तर्गत 11 खिलाड़ियों को नौकरियां दी जा चुकी हैं।

4. प्रतिस्पर्द्धात्मक खेलों में ग्रामीण बच्चों की भागदारी बढ़ाने की वृहद वार्षिक पहल को सुदृढ़ किया गया। वर्ष 2012-13 के दौरान स्पैट के अन्तर्गत 5000 चयनित खिलाड़ियों को 8.81 करोड़ रुपये वितरित किये गये। स्पैट-2014 में 12.7 लाख होनहार बच्चों ने प्रतिभागिता की, जिसमें से 1.8 लाख बच्चों का प्रथम चरण में चयन किया गया। अन्ततः 5000 बच्चे छात्रवृत्ति एवं आगे प्रशिक्षण के लिए चयनित किये जायेंगे तथा इन चयनित खिलाड़ियों को लगभग 10.00 करोड़ रुपये की संकलित वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।

5. केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान' के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 तक ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल मैदानों की स्थापना करके तथा स्थायी खेल उपकरणों की संस्थापना करके 2476 गांवों तथ 48 खण्डों को शामिल किया गया।

6. राज्य सरकार ने राज्य में सुदृढ़ खेल अवसंरचना नेटवर्क सृजित किया है। इसमें 2 राज्य स्तरीय खेल काम्पलैक्स, 21 जिला स्तरीय खेल परिसर, 3 सब डिविजनल स्टेडियम, 226 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर है, जिनमें से 159 संचालित हो चुके हैं तथा 67 निर्माणाधीन हैं। 232 मिनी/ग्रामीण खेल स्टेडियम, 16 एस.सी. कम्पौनेंट स्टेडियमों में आधारभूत सुविधायें प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य में 7 तरणताल, 4 सिंथैटिक एथलैटिक्स ट्रैक, 5 हाकी एस्ट्रोटर्फ, 6 बहुउद्देशीय हाल तथा 5 जिम्नेजियम हाल संचालित हैं। भारत सरकार की सहायता से जिला फतेहाबाद के दरियापुर में एक फुटबाल कृत्रिम सतह, हिसार में हॉकी की कृत्रिम सतह लगाई जा रही है। हाल ही में, भारत सरकार ने भिवानी के लिए एक एथलैटिक ट्रैक लगाने की स्वीकृति प्रदान की है।

7. वर्ष 2013-14 के दौरान विभाग द्वारा 14 आवासीय तथा 10 डे-बोर्डिंग नर्सरियां संचालित की गई थीं जिससे 541 खिलाड़ी लाभांवित हुये। हिसार, पंचकूला, भिवानी में एथैलेटिक्स, मटीण्डू (सोनीपत) में क्रिकेट, सिरसा, हिसार में जूडो, बिरधाना (झज्जर), उमरा (हिसार), झज्जर में कुश्ती, सिरसा, सोनीपत में हॉकी, सांपला (रोहतक), चुलियाना (रोहतक) में कुश्ती तथा किलोई (रोहतक) में कबड्डी खेल की नर्सरियां चलाई जा रही है। पुरखास (सोनीपत), खेडी जाटां (झज्जर) में कुश्ती, गुड़गांव, रिवाड़ी में हॉकी, भालौट (रोहतक) में कुश्ती, रूड़की (रोहतक) में बाक्सिंग, बोहर (रोहतक) में हॉकी, मान्डोठी (झज्जर) में कुश्ती, महराना (झज्जर) में खो-खो, फरीदाबाद में क्रिकेट तथा रोहतक में हॉकी डे-बोर्डिंग खेल नर्सरियां हैं। विभाग ने उत्कृष्ट तथा कुशल खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से भिन्न-भिन्न खेल विधाओं में 02 आवासीय तथा 16 डे-बोर्डिंग खेल नर्सरियां प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है।

8. सरकार ने हरियाणा के ओलम्पिक पदक विजेताओं द्वारा भिन्न-भिन्न खेलों में विश्व स्तरीय अकादमियां स्थापित करने के लिए एक नीति बनाई है। राज्य के खिलाड़ियों के लिए अकादमियां स्थापित करने के लिए श्री सुशील कुमार-कुश्ती खिलाड़ी, श्री योगेश्वर दत्त-कुश्ती खिलाड़ी तथा श्री विजेन्द्र सिंह-बॉक्सर को भूमि प्रदान की गई है। विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान 04 आवासीय तथा 10 डे-बोर्डिंग अकादमियां संचालित की गई थी जिससे 320 खिलाड़ी लाभान्वित हुये थे। भिवानी में बाक्सिंग, कुरूक्षेत्र में हॉकी, चण्डीगढ़ मे लॉन-टैनिस तथा नरवाना, जीन्द में हैण्डबाल की आवासीय खेल अकादमियां संचालित है। इन आवासीय खेल अकादमियों के अतिरिक्त, विभाग द्वारा जीन्द में कबड्डी, सोनीपत में कुश्ती, पंचकूला में बैडमिंटन, कुरूक्षेत्र में वालीबाल, सिरसा में हॉकी, रोहतक में एथलैटिक्स एवं कुश्ती, किलोई, रोहतक में बास्केटबाल, राई, सोनीपत में हॉकी तथा रोहतक में लॉन-टैनिस डे-बोर्डिंग खेल अकादमियां संचालित की जा रही हैं।

9. हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को भिन्न-भिन्न खेलों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 686 कनिष्ठ खेल प्रशिक्षकों को भर्ती करने की प्रक्रिया में है। विभाग को प्रशिक्षित मानव संसाधनों से सुसज्जित करने हेतु व खेल केन्द्रों, नर्सरियों, अकादमियों तथा स्पैट प्रशिक्षण केन्द्रों तथा ग्रामीण एवं शहरी खेल परिसरों को संचालित करने के लिए वर्ष 2013-14 में भिन्न-भिन्न खेल विधाओं में 686 खेल प्रशिक्षकों की भर्ती आरम्भ की गई है। रियो - ब्राजील में होने वाले ओलम्पिक खेल-2016 के दृष्टिगत, सभी लोकप्रिय खेल विधाओं के लिए तथा ओलम्पिक पदक परियोजना के लिए प्रशिक्षकों की आवश्यकता है।

10. खेल विभाग उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिलों में गठित जिला खेल परिषदों की सहायता से खेल अवसंरचना का निर्माण तथा रख-रखाव करता है। खेल अवसंरचना की विभिन्न परियोजनाएं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड तथा पंचायती राज द्वारा भी निर्मित तथा अनुरक्षित की जाती है। ऐसी सभी खेल अवसंरचनाओं के क्रिया-कलापों को खेल विभाग द्वारा समन्वय किया जाता है। यह प्रणाली सुचारू रूप से चल रही है तथ प्रमुख अवसंरचनात्मक परियोजनायें शामिल की जा चुकी है तथा अनुरक्षण की जा रही है। इनमें हॉकी के लिए कृत्रिम सतह, फुटबाल, सिंथैटिक ट्रैक तथा बहुद्देशीय हाल शामिल हैं। विभाग का बजट वर्ष 2005-06 में 36.33 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 162.32 करोड़ रुपये हो गया है। खेल विभाग राज्य में खेल गतिविधियों में तीव्र विकास लाने तथा नई अवसंरचना का निर्माण एवं अनुरक्षण करने में प्रभावशाली प्रबन्धन करने में सफल रहा है।

11. खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग के अतिरिक्त, सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में हरियाणा राज्य खेल परिषद की स्थापना भी की है जिसमें माननीय वित्त मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री तथा माननीय विकास एवं पंचायत मंत्री इत्यादि सदस्य है। परिषद का उद्देश्य राज्य में खेलों को लोकप्रिय बनाना, खेल संघों को प्रोत्साहित करना तथा विभिन्न खेलों एवं प्रतियोगिताओं के मानकों एवं प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार लाना है। वर्तमान समय में हरियाणा राज्य खेल परिषद के साथ मिलकर तथा सभी संबंधित विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करके खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग, हरियाणा राज्य में विभिन्न खेल अवसंरचना का सृजन व अनुरक्षण करने तथा खेल गतिविधियों का तीव्र गति से प्रचार करने में सक्षम है। हरियाणा राज्य खेल परिषद का अधिदेश व्यापक रूप से स्पष्ट है जिससे माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये गये

[श्री सुखबीर कटारिया]

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में निहित मुद्दों एवं चिंताओं को प्रभावशाली ढंग से निपटाया जा सकता है। अत: इन कार्यों को करने के लिए फिलहाल हरियाणा खेल प्राधिकरण जैसी अन्य संस्था स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

Shri Bharat Bhushan Batra : Hon'ble Speaker Sir, I only want one answer from the Minister that why the Govt. should not have a Sports Authority of Haryana like Sports Authority of India ताकि हरियाणा प्रदेश खेलों के क्षेत्र में और आगे बढ़ सके। आज हम पूरे प्रदेश में स्पैट भी बना रहे हैं और खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्कूल और कालेजों में भी इन्फ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाया जा रहा है लेकिन स्टेट में जो खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है उसको अलग-अलग विभागों द्वारा मेनटेन किया जाता है। कहीं पर हुडा मेनटेन करता है और कहीं पर पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा मेनटेन किया जाता है। यदि हमारे प्रदेश में स्पोर्ट्स को भविष्य में जीवित रखना है या स्पोर्ट्स को ज्यादा अच्छा बनाना है तो मैं चाहूंगा कि स्पोर्ट्स एथोरिटी ऑफ हरियाणा बनाकर सरकार नया एग्जामपल स्थापित करे जिसमें यह प्रोविजन भी करना चाहिए कि स्पोर्ट्स एथोरिटी में स्पोर्ट्स पर्सन के अलावा किसी और का ज्यादा दखल न हो।

श्री सुखबीर कटारिया : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में पहले से ही डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कांउसिल चल रही हैं जिनका काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। इसके अतिरिक्त 2010 में स्पेशल स्पोर्ट्स कांउसिल रजिस्टर हो चुकी है जिसकी रिव्यू मीटिंग्ज चलती रहती हैं। हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों ने स्टेट, नैशनल और इंटर नैशनल, कॉमनवैल्थ, एशियन आदि गेम्ज में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके अतिरिक्त ओलम्पिक में भी हमारे प्रदेश के खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। हमारे हिसाब से हमारी स्पोर्ट्स नीति अच्छी चल रही है और रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। इसके बावजूद भी यदि माननीय साथी कोई सुझाव देंगे तो उस पर हम जरूर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, माननीय सदस्य ने यही सुजैशन दिया है कि स्पोर्ट्स एथोरिटी ऑफ हरियाणा बनाने पर आप विचार कर रहे हैं या नहीं।

श्री सुखबीर कटारिया : अध्यक्ष महोदय, अभी स्पोर्ट्स एथोरिटी ऑफ हरियाणा हम नहीं बना रहे लेकिन माननीय साथी ने इस बारे में कालिंग अटैंशन मोशन दिया है इसलिए इस पर हम जरूर विचार करेंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/अल्पावधि चर्चा की सूचना

डॉ० बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैंने राज्य सरकार द्वारा भेदभाव नीति को लेकर नियम 73-A के अधीन शार्ट डयूरेशन डिसकशन की सूचना दी थी, जिसको आपने डिसअलाउ कर दिया ? (विघ्न) ऐसा नहीं होना चाहिए था। (विघ्न)

Mr. Speaker : It has been disallowed. (Interruption). It has been disallowed.

श्री जगदीश नॉयर : अध्यक्ष महोदय, मैंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के शोषण बारे कालिंग अटैंशन मोशन दिया था उसका क्या फेट रहा ? (विघ्न)

डॉ० बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मेरा कालिंग अटैंशन मोशन तो डिसअलाउ कर दिया गया इसलिए मुझे बजट पर बोलने का अवसर जरूर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आपको और नॉयर साहब को बजट पर बोलने का अवसर जरूर दिया जायेगा।

वर्ष 2014-15 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now general discussion on the Budget Estimates will take place. Shri Sampat Singh may start.

प्रो. सम्पत सिंह (नलवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया। मैं हरियाणा सरकार और विशेषकर वित्तमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसी विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने बैलैंस्ड, आल अराउंड डिवैल्पमैंट ओरियंटिड, इन्फ्रास्ट्रक्चर ओरियंटिड और वैलफेयर ओरियंटिड, बिना किसी टैक्स के जीरो बजट प्रदेश में पेश किया है। ऐसी विषम परिस्थितियों में इससे बड़ा चैलेंज वित्तमंत्री जी के सामने और कोई नहीं था। अध्यक्ष महोदय, एक अनुभवी और बुद्धिमान व्यक्ति ही इस तरह का बजट स्टेट असैम्बली में पेश कर सकता है। आज के दिन वर्ल्ड वाईड इनफलेशन का दौर चल रहा है जिसका असर हमारे प्रदेश पर भी पड़ा है। दूसरी तरफ हमारे प्रदेश में रिसोर्सिज भी कम हुए हैं क्योंकि स्टोन, रेत आदि की माईन्ज कोर्ट की तरफ से बंद की हुई हैं जिसके कारण प्रदेश को रिसोर्सिज भी जनरेट करना मुश्किल होता है ऐसे वक्त में भी हमारे वित्तमंत्री जी ने कर रहित बजट देकर प्रदेश के लोगों को बहुत राहत देने का कार्य किया है इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)** उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे हालातों के बावजूद भी हमारे वित्तमंत्री जी ने किसानों को 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली और 5 हजार करोड़ रुपये सब्सिडी देने का बजट में प्रावधान किया है जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसी तरह से जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आज प्रदेश में चल रहा है चाहे रोड़ज की फोर लेनिंग करने का कार्य है, चाहे आर.ओ.बीज. बनाने का कार्य है, चाहे मैट्रो का कार्य है हर किसी के अंदर स्टेट ने अपना योगदान दिया है तभी जाकर हमारे प्रदेश में मैट्रो या दूसरे कार्य पूर्ण हो रहे हैं वरना ये कार्य पूर्ण नहीं होते। योगदान न देने के कारण ही दूसरे प्रदेशों में हमारे प्रदेश की तरह मैट्रो आदि के कार्य नहीं हो पाये हैं। इन सभी मामलों में स्टेट गवर्नमैंट कंट्रीब्यूट कर रही हैं। चाहे वह लैंड एक्वीजिशन का मामला हो, एयरपोर्ट का मामला हो या इस तरह का कोई दूसरा मामला हो। इसके बावजूद इतना बढ़िया बजट देना बहुत बड़े साहस का काम है। इसके अलावा हरियाणा में 70 लाख ऐसी फैमिलीज हैं जिनके घरों में इस सरकार ने Cash या Kind की हैल्प दी है। इस बारे में मेरे पास एक-एक कैलकूलेशन है लेकिन मैं इस मामले में ज्यादा नहीं बोलूंगा। अगर आप पैंशन का देखेंगे तो वह 23 लाख है और 20 लाख रुपये की बच्चों को वन टाईम हैल्प मिल रही है। इसी प्रकार और भी बहुत से वर्ग हैं जिनको लाखों और हजारों रुपये में हैल्प मिल रही है। नम्बरदारों, पंचों, सरपंचों, सफाई कर्मचारी, आंगनवाड़ी वर्कर्स और दूसरे वर्ग के कर्मचारियों के मानदेय व वेतन में अभूतपूर्व वृद्धि की माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एनाऊंसमैंट की थी उन सबको लागू करके बजट में उसके लिए बाकायदा प्रावधान करना कोई आसान काम नहीं था लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको भी कर दिखाया। पूरे हिन्दुस्तान

[प्रो० सम्पत सिंह]

में मिनीमम वेजिज 8100 रुपये करना भी बहुत बड़ी बात है। यह भी सारे देश में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा सभी गरीबों के लिए फ्री मैडीसन और फ्री टैस्ट की व्यवस्था करना कोई छोटी बात नहीं है और इसके लिए 262 करोड़ रुपये का प्रावधान करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। इसी प्रकार से सभी स्कूल और कालेजिज में जाने वाली लड़कियों के लिए बस पास फ्री कर दिया गया। इसी प्रकार से पहले 60 साल की महिलाओं के लिए हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में 50 परसैंट किराया वसूल किया जाता था अब यह सुविधा 65 साल के पुरुषों के लिए भी कर दी गई है। अभी स्पोर्टस का जिक्र भी आ रहा था जिसमें विभिन्न मैडल लाने वाले खिलाड़ियों के लिए 5 करोड़, 3 करोड़ व 2 करोड़ रुपये ईनामस्वरूप देने की घोषणा सरकार के स्तर पर की गई है और उनको विभिन्न स्तर की सरकारी नौकरियां देना कोई छोटा काम नहीं हैं ये सभी अपने आप में बहुत बड़े काम हैं। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए इतना कुछ करना कोई आसान काम नहीं हैं। इसी प्रकार से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू करना और इसके साथ ही दाल भी फ्री कर देना भी काबिलेतारीफ है। ये सभी योजनायें भी अस्तित्व में आ गई। इसी के साथ किसान को 11 परसैंट से कम करके 4 परसैंट ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है। इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। स्टैम्प ड्यूटी फ्री कर देना भी कोई छोटा काम नहीं है। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर सर, मैंने विधान सभा में सत्य बोलने की शपथ ली है इसलिए मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह सत्य कह रहा हूं। मैं यहां पर बिना किसी दूसरे की परवाह किए बगैर सत्य बात बोलता हूं। कुछेक लोगों को और उनके नेताओं को मुझसे जलन है। मैं यह भी जानता हूं कि वह जलन मेरे रहने तक रहेगी ही रहेगी। मेरे पास इसका कोई ईलाज भी नहीं है इसलिए वह किसी भी प्रकार से दूर नहीं हो सकती। डिप्टी स्पीकर सर, मैं मंत्री बनने वाला नहीं हूं बल्कि मैं मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री बनाने वाला हूं। (शोर एवं व्यवधान) जो लोग बैठे-बैठे बोल रहे हैं ये तो राजनीति में कल के बच्चे हैं इसलिए इनको राजनीति का कोई विशेष ज्ञान नहीं है। इनको किसी भी प्रकार की किसी हिस्ट्री का कोई पता नहीं है। मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि मैंने मुख्यमंत्री बनाये हैं और डिप्टी प्राईम मिनिस्टर तक बनाये हैं। मैंने बहुत कुछ बनाया है। इनको कुछ मालूम नहीं है। ये कल के बच्चे हैं और इनको किसी भी मामले की कोई विशेष जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी ये बचकाने सवाल करने लग रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कली राम जी, कृपया आप शांत बैठिए। सम्पत सिंह जी, कृपया आप बोलिए।

प्रो. सम्पत सिंह : जिन दिनों की ये बात कर रहे हैं उन दिनों मेरी आमदनी इनके नेताओं से भी बहुत ज्यादा थी। अगर ये चाहे तो वर्ष 1972 का रिकार्ड निकालकर चैक कर सकते हैं। क्या ये यह मानते हैं कि अगर इनकी ढ़ाई बीघे जमीन मुझसे फालतू हो गई तो क्या ऐसा होने से इनकी मुझसे ज्यादा आमदनी हो गई। मैं मेहनत की नेक कमाई किया करता था। अब इनको तकलीफ हो रही है। मैं तो यह कह रहा हूं कि इनको तकलीफ होगी ही होगी। मैं यही चाहता हूं कि इनकी यह तकलीफ सदा के लिए और सारी उम्र के लिए बनी रही। इन सामंती परिवारों को ऐसी तकलीफ रहती ही है यह मेरे बस से बाहर की बात है। डिप्टी स्पीकर सर, इसी प्रकार से मैं स्टैम्प ड्यूटी के बारे में बता रहा था कि एग्रीकल्चर लोन पर स्टैम्प ड्यूटी फ्री कर देना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिसकी लैंड एक्वीजिशन हो जाती है अगर वह लैंड परचेज़ करता है उसके ऊपर भी

स्टैम्प ड्यूटी फ्री कर दी गई है। मैं यह सारी की सारी सच्ची बातें बोल रहा हूं। महिलाओं के लिए 3 परसैंट स्टैम्प ड्यूटी फ्री करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पूरे देश में केवल हरियाणा ऐसा प्रदेश है जिसमें वैट 8.8 परसैंट है। यहां पर गुजरात और महाराष्ट्र का जिक्र किया जाता है मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा कि वहां पर 28 प्रतिशत से लेकर 35 प्रतिशत स्टैम्प ड्यूटी है। इसलिए आज डीजल हरियाणा में सबसे ज्यादा सस्ता है। इसी प्रकार से डीज़ल पर हरियाणा में 5.25 परसैंट वैट है। सी.एन.जी. हरियाणा में ही सबसे सस्ती है। (शोर एवं व्यवधान) डिप्टी स्पीकर सर, मेरे बोलने से कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। आप इनको चुप बैठने के लिए कहें। मैं अपने स्टेट की बात कर रहा हूं मैं कोई देश की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि हरियाणा स्टेट के अंदर 8.8 परसैंट वैट है। इस प्रकार से अगर पूरे देश में कहीं सबसे कम वैट है तो वह हरियाणा प्रदेश में है। (शोर एवं व्यवधान) डिप्टी स्पीकर सर, इन लोगों को शांति से बैठकर दूसरों की बात सुननी चाहिए अगर इनको कुछ बोलना है तो जब इनको बोलने का समय मिले उस समय ये अपनी सारी बातें कह लें। इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि किसानों को पूरे देश में सबसे ज्यादा गन्ने का भाव 301 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हरियाणा प्रदेश में ही दिया गया है। इतना सब होने के बावजूद भी बजट के अंदर प्रदेश के लोगों पर जीरो बरडन डाला गया है। इसके विपरीत विभिन्न प्रकार की सुविधायें प्रदेश की जनता को मुहैया करवाई गई है। इसी प्रकार से व्यपारियों के लिए फार्म नम्बर 38 को वापस किया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रदेश की जनता पर बरडन डालने के बजाये प्रदेश की जनता को सुविधायें दी गई हैं। इसी प्रकार से रिसोर्स मोबिलाइजेशन सरकार द्वारा की गई है। सर, हरियाणा सरकार द्वारा जो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर टारगैट फिक्स किये गये थे उसका 192 परसैंट एचीव किया है जबकि इस मामले में नेशनल एवरेज़ 92.5 परसैंट थी। इसके अलावा जहां तक जी.एस.डी.पी. का सम्बंध है उसमें हरियाणा सरकार ने 14.16 इनक्रीज़ दी है जो कि इस समय अपने आप में बहुत ज्यादा है। इसी प्रकार से पर कैपिटा इनकम पिछले साल के मुकाबले 12.90 परसैंट ज्यादा है। इसी तरह से एक्सपैंडीचर फ्रॉम कंसोलिडेटिड फंड पिछले साल की तुलना में 14 प्रतिशत ज्यादा है। अगर हम प्लान एक्सपैंडीचर की बात करें तो पिछले साल से 16.27 प्रतिशत ज्यादा है। टोटल रिसीप्ट 14.57 परसैंट ज्यादा है। इसी प्रकार से टोटल एक्सपैंडीचर की बात की जाये तो वर्ष 2012-13 के मुकाबले 2013-14 में 11.02 प्रतिशत ज्यादा है। रेवेन्यू रिसीप्ट 14.54 परसैंट ज्यादा है। रेवेन्यू डैफिसिट 1.43 प्रतिशत ज्यादा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से फिस्कल डेफिसिट की बात की जाये तो यह पिछली बार के 2.9 प्रतिशत के मुकाबले 2.5 प्रतिशत है तथा उसको हमने कम किया है जबकि यह 3 परसैंट तक अलाउड है। इसी तरह से डैट लायबिलिटी की बात करें तो उपाध्यक्ष महोदय, जिसके घर में दाने होते हैं लोन उसी को मिलता है, और लोन काम करने के लिए लिया जाता है। भले ही आज वह 80 हज़ार करोड़ रुपये पर पहुंच गया है लेकिन उसको सकल घरेलू उत्पाद के साथ-साथ कम्पेयर किया जाता है और वह 18.24 परसैंट है जबकि हरियाणा प्रदेश में 24-25 परसैंट तक लोन लायबिलिटी होती रही है। उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं देखा जाता कि आपकी लोन लायबिलिटी 20 हजार करोड़ रुपये है या 80 हजार करोड़ रुपये है लेकिन यह देखा जाता है कि आपकी आमदनी कितनी है और आप जो लोन ले रहे हैं वह कितना है और क्या आप उसको वापस कर सकते हैं या नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो एक अच्छी बात है, कंसोलिडेटिड फंड में से जो लोन की टोटल रिकवरी थी जो पिछली बार 29.5 परसैंट थी वह इस साल 28.32 परसैंट तक आ गई है। कहने का

[प्रो० सम्पत सिंह]

मतलब यह है कि जो लोन का पैसा वापस किया जाना है जिसका स्टेट पर कैश बर्डन आता है वह कम हुआ है और यह पिछले साल के मुकाबले 1 परसैंट कम देना पड़ेगा। चाहे आपकी लोन लायबिलिटी 80 हजार करोड़ रुपये हो लेकिन पिछले साल के मुकाबले में वह 1 परसैंट कम देना पड़ेगा। जब आप यह देखेंगे कि पैसा कहाँ जा रहा है तो डैट को देखने से आपको साफ पता चल जायेगा कि पिछली बार डैट में आपका कितना पैसा जा रहा था और इस साल कितना पैसा जा रहा है। मैं आदरणीय वित्त मंत्री श्री चड्ढा साहब का इस मैनेजमैंट के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से फिस्कल डेफिसिट और डैट लायबिलिटी के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है जो कि किसी भी बजट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। इसी प्रकार से अगर कैपिटल एक्सपैंडीचर की बात की जाये तो उसमें 7 परसैंट की इंक्रीज हुई है। अगर हम सोशल वैल्फेयर की बात करें तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो पैंशन वगैरह की घोषणाएं की हैं उनके कारण पिछले साल के मुकाबले इस साल 42 परसैंट बजट ज्यादा दिया गया है और इसके लिए भी मैं माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। इन सब बातों के बावजूद भी मैं चड्ढा साहब को कुछ चैलेंजिज के बारे में भी बताना चाहता हूँ जो इनको फेस करने हैं। हालाँकि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है लेकिन मैं इनको रेवेन्यू रिसीप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। पिछली बार जो बजटरी ऐस्टीमेट था और जो रिवाईज्ड ऐस्टीमेट आया है उसमें आपकी रेवेन्यू रिसीप्ट 5 परसैंट घटी हैं जो कि एक चिन्ता का विषय है। इसी प्रकार से टैक्स रिसीप्ट में आपका 32262 करोड़ रुपये का बजटरी ऐस्टीमेट था और जब रिवाईज्ड ऐस्टीमेट आया तो 30235 करोड़ रुपये का है। अगर टैक्स रिसीप्ट में बजटरी व रिवाईज्ड ऐस्टीमेट की बात की जाये तो यह भी 6 परसैंट घटा है। इसी प्रकार से अगर सेल टैक्स की बात की जाये तो जो बजटरी ऐस्टीमेट है और रिवाईज्ड ऐस्टीमेट है उसमें आपका 10 परसैंट सेल टैक्स घटा है। यह एक ऐसी चिन्ता है जिसके ऊपर आपको गौर करना पड़ेगा। रेवन्यू टोटल रिसीप्ट, टैक्स रिसीप्ट और सेल टैक्स के बारे में आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि इसमें कहाँ पर लूप होल हैं और कहाँ कमियाँ रह गई हैं जिनको दूर किया जा सके। इसी प्रकार से कैपिटल एक्सपैंडीचर जो आपका वर्ष 2013-14 में बजटरी ऐस्टीमेट 6548.50 करोड़ रुपये था लेकिन जो रिवाईज्ड ऐस्टीमेट आया वह 62299 करोड़ रुपये आया है जो कि वर्ष 2012-13 के बराबर आ रहा है। वर्ष 2012-13 में 6283 करोड़ रुपये था और 2013-14 में 6299 करोड़ रुपये आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कैपिटल एक्सपैंडीचर के लिए हमारे पास कम पैसे बचे हुये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री को कहना चाहता हूँ कि आपको कैपिटल एक्सपैंडीचर पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि असली खर्चा तो कैपिटल एक्सपैंडीचर होता है। ये ऐसी कैपिटल क्रिएट करें जिससे कि स्टेट को आमदनी आती रहेगी, जिससे की स्टेट के असैट्स बढ़ेंगे। इस तरफ भी माननीय वित्त मंत्री महोदय को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस बार आपने 6748 करोड़ रुपये कैपिटल एक्सपैंडीचर जरूर रखा है लेकिन मुझे इस बारे में संदेह है क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से कैपिटल एक्सपैंडीचर आया है उसी तरह से अबकी बार भी न आ जाए। उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को जो बिजली पर सब्सिडी दी जा रही है वह भी एक चिन्ता का विषय है। यह बात ठीक है कि इससे किसान को 10 पैसे का फायदा हो रहा है लेकिन इसमें भी ध्यान देने की जरूरत है। सर, मैंने इस सब्सिडीज के बारे में पिछले सत्र में एक

अनस्टार्ड क्वैश्चन पूछा था। 50 प्रतिशत बिजली के फीडर्ज ऐसे हैं जिनमें 50 प्रतिशत लौसिज हैं। अगर उन लौसिज को सरकार कन्ट्रोल नहीं करेगी तो यह इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेटरी कम्पनी हमारे बजट को धीरे-धीरे खा जाएगी। सर, यह पावर लौसिज तो एक प्रकार से जौंक की तरह लग गये हैं जिनको दूर करने की आवश्यकता है इसके लिए सरकार को बिजली की थेफ्ट को रोकना पड़ेगा। जब तक यह थेफ्ट नहीं रोकेंगे तब तक यह लौसिज खत्म नहीं होंगे। सर, सरकार ने 1700 करोड़ रुपये की रिकवरीज माफ कर दी लेकिन उसके बाद भी 5000 करोड़ रुपये से ऊपर की रिकवरी बकाया पड़ी है। इसमें कुछ रिकवरी तो सरकारी महकमों की हैं और कुछ कार्पोरेशनों की हैं। सरकार को यह वसूली भी करनी चाहिए वरना ये कम्पनियां एक दिन हमारे बजट को खराब कर देंगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को एक बात और कहना चाहता हूं।जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने कुछ घोषणाएं की हैं लेकिन उनको पूरा करने के लिए कुछ रिसोर्सिज भी जुटाने पड़ेंगे।

श्री कृष्ण लाल पंवार : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ओर्डर है। प्रो. सम्पत सिंह जी ने जो रिकवरी की बात कही है मैं आपके माध्यम से वित मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस रिकवरी में बिजली बोर्ड की देनदारी कितनी है ?

श्री उपाध्यक्ष : पंवार साहब, जब मंत्री जी रिप्लाई देंगे तब बता देंगे।

प्रो. सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में तो मैं भी बता सकता हूं क्योंकि मेरे पास इसके आंकड़े हैं।

श्री कृष्ण लाल पंवार : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मुझे भी पता है कि बिजली बोर्ड की देनदारी कितनी है लेकिन मैं तो रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं।

प्रो. सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ऑनरेबल मैम्बर मेरे साथी हैं और बिजली बोर्ड में इन्होंने काम भी किया है इसलिए इनको इसके बारे में काफी ज्ञान भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, चाहे लायबिलिटी की बात हो, चाहे कर्जे की बात हो, चाहे रिकवरी की बात हो बिजली कम्पनियां हमें हर प्रकार से नुकसान पहुंचा रही हैं। मैं जो बात कह रहा हूं उसमें अमाऊंट की कोई बात नहीं है। मैं तो बस इतना कहता हूं कि इस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। सर, पिछली बार सरकार ने रेवेन्यू डेफिसिट एज कम्पेयर टू जी.एस.डी.पी. कैपिटल एक्सपैंडीचर प्वाइंट 62 का रखा था लेकिन अब वह 1.43 आ गया है इसलिए इस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। फिजिकल डेफिसिट 2.28 रखा गया था और इस बार 2.93 आ गया है इसलिए इसके रिजल्ट पर भी आपको कन्ट्रोल करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इन दिनों मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं यूनिवर्सिटी की और सैंटर्ज की वह सब सच्ची हैं। इनके एक्ट भी पास होंगे, जिनके बिल भी एसेम्बली के अन्दर पास होंगे और बाद में इनके बजट का प्रावधान भी आएगा लेकिन सरकार ने इनके लिए भी रिसोर्सिज जुटाने पड़ेंगे ताकि ये चीजें कारगर हो सकें और प्रैक्टीकल रूप में ये सकल ले सकें। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ सुजैशन देना चाहता हूं। हिसार जिले का काफी हिस्सा भाखड़ा सिस्टम से जुड़ा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, चड्ढा साहब इरीगेशन मंत्री भी हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि भाखड़ा नहर के पानी की दो बारियां बनी हुई हैं। दो हफ्ते पानी चलता है और एक हफ्ता पानी बंद रहता है। भाखड़ा नहर से ही बरवाला ब्रांच निकलती है और बरवाला ब्रांच के नीचे के एरिया को आपने तीन ग्रुप में बांट दिया। मेरा आपसे निवेदन है कि जब सरकार ने भाखड़ा सिस्टम की दो ग्रुपिंग की हुई हैं तो हिसार का जो भाखड़ा सिस्टम है उसको भी

[प्रो० सम्पत सिंह]

आप तीन ग्रुपिंग की बजाए दो ग्रुपिंग में कर दें ताकि वहां के किसानों को भी इसका फायदा मिल सके। दूसरा सुझाव मैं आपको देना चाहता हूं कि रिक्रूटमैंट में भी आप कुछ परिवर्तन करें। सर, सरकार बहुत कुछ कर रही है और सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से कर रही है। हर भर्ती में मैरिट की 83 प्रतिशत, 85 प्रतिशत, 88 प्रतिशत कट ऑफ लिस्ट भी रखी जाती है। सर, आजकल बच्चों के मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं। चार-पांच साल पहले उनके इतने मार्क्स नहीं आते थे। आप इसमें कट ऑफ मार्क्स की बजाय रिटन टैस्ट रख दें ताकि शक की कोई गुंजाईश ही न बचे। कई बार गांव के बच्चे प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते वह अकैडमी वगैरा में ज्यादा अच्छा नहीं कर पाते हैं रिटन में तो उनके 80 प्रतिशत मार्क्स आ जाते हैं लेकिन इंटरव्यू में वह रह जाते हैं। वह बाद में कहते हैं कि मेरे इंटरव्यू में नम्बर ज्यादा थे मुझे सिलैक्ट नहीं किया दूसरे को सिलैक्ट कर लिया। सरकार इंटरव्यू वाला झंझट ही खत्म कर दें। क्लास दो, तीन और चार कर्मचारियों की एक ही किस्म की कटेगरी हैं उनमें रिटन कर दें और क्लास एक में आप इन्ट्रव्यू रख दें और उसकी वीडियो ग्राफी करवा दें। क्लास दो, तीन, और चार में इंटरव्यू बिल्कुल खत्म कर दें क्योंकि बाकि स्टेट्स ने भी ऑल मोस्ट यही सिस्टम कर रखा है ! स्पीकर सर, पंजाब, राजस्थान तथा अन्य कई स्ट्रेटस में इंटरव्यू सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। हम भी यदि इस इंटरव्यू सिस्टम को खत्म कर देंगे तो हमारे बच्चों में जो फ्रस्ट्रेशन आ रही है, वह फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जायेगी। यह सच है कि हम सभी को सरकारी नौकरी उपलब्ध नहीं करा सकते हैं लेकिन जितने बच्चों को नौकरी दी जायेगी अगर वह मैरिट के आधार पर दी जायेगी तो उससे एक स्वच्छ वातावरण तैयार होगा। अब मैं पुलिस की रिक्रूटमैंट पर अपनी बात सदन में रखना चाहूँगा। पुलिस डिपार्टमैंट में लगभग 11-12 हजार पुलिस कर्मचारियों की भर्ती होनी है, जिनका प्रोसैस भी शुरू हो चुका है। इस प्रोसैस को पूरा करने में 4-4 साल तक का एक लंबा वक्त लग जाता है। मान लो 9 लाख आवेदकों से आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं। स्वाभाविक है कि पहले आवेदन पत्रों का मिजरमेंट किया जायेगा जिसमें छह महीने का एक लंबा टाइम लगेगा। उसके बाद उनकी 100 मीटर या 800 मीटर की दौड़ तथा ऊंचाई और लंबाई वाली कूद करवाई जायेगी जिसमें और छह महीनों का समय लगेगा। उसके बाद इंटरव्यू का प्रोसैस होगा जिसमें छह महीने और लग जायेंगे। उसके बाद ही भर्ती का प्रोसैस शुरू होगा। डिप्टी स्पीकर सर, यदि इतने लंबे भर्ती के प्रोसैस की जगह एक सीधा साधा सिस्टम शुरू कर दिया जाये जैसेकि पहले रिटन टैस्ट लिया जाये, उसके बाद 10 किलोमीटर की दौड़ करवाई जाये, उसके बाद जिसके नम्बर फालतू आ जाएं उसको भर्ती कर लिया जाये तो मैं समझता हूँ कि 15 दिन के अन्दर ही पुलिस की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। ऑफिसर्ज गैलरी में होम सैक्रेटरी साहब बैठे हैं, मैं उनको सुझाव के तौर पर यह बात बताना चाहता हूँ। इस प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती के लिए किये जाने वाली सभी टैस्ट एक दिन में ही पूर्ण किये जा सकते हैं और 15 दिन के अन्दर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। ऐसा सिस्टम राजस्थान स्टेट में है जो रिक्रूटमैंट का प्रोसैस सबसे उत्तम है।

श्री उपाध्यक्ष : सम्पत जी, आप कंक्लूड कीजिये?

प्रो. सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ सुझाव दे रहा हूँ कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। (विघ्न)

सहकारिता मंत्री (श्री सतपाल) : सम्पत सिंह जी, रिटन टैस्ट में भी गड़बड़ की संभावना तो बनी ही रहती है?

प्रो. सम्पत सिंह : सांगवान जी, आप गड़बड़ की बात छोड़िये, ऐसे तो हर चीज को स्मैल आउट किया जा सकता है? मैं तो एक सुझाव दे रहा हूँ उसे माना जाये तो ठीक है अगर ना माना जाये तो भी ठीक है। आप तो कैबिनेट मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री को सरकार ही माना जाता है। अब मैं मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मुलाजिमों के संबंध में की गई घोषणाओं के संबंध में अपने विचार रखना चाहूँगा। पुलिस और जेल विभाग को मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा 5 हजार रुपये का रिस्क भत्ता दिया गया है तथा 2000 रुपये की अंतरिम राहत प्रदान की गई है। मेरा निवेदन है कि 5 हजार रुपये का रिस्क भत्ता और 2000 रुपये की अंतरिम राहत देने की बजाय यदि सिपाहियों का स्केल ही बढ़ा दिया जाये तो कितना अच्छा होगा? इस तरह की राहत देने से इनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। डिप्टी स्पीकर सर, हर आदमी अपने भविष्य को ध्यान में रखकर ही कार्य करता है। आजकल देखने में आ रहा है कि पुलिस तथा जेल विभाग में एम.बी.ए. या इंजीनियरिंग की योग्यता वाले बच्चे भी भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं और भर्ती भी हो रहे हैं। सातवां वेतन आयोग जल्द ही आने वाला है। सातवें वेतन आयोग में अलाउंसिज कहीं भी जुड़ने वाले नहीं है। अत: मेरा निवेदन है कि कितना अच्छा हो कि यदि रिस्क भत्ता तथा अंतरिम राहत को उनके पे-स्केल्ज में जोड़ दिया जाये? यदि ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ कि हमारे पुलिस और जेल महकमे से संबंधित जवान ठीक तरीके से अपनी ड्यूटी कर सकेंगे। जब कोई त्यौहार होता है तो हर आदमी छुट्टी मनाता है लेकिन ये बेचारे पुलिस के जवान बावर्दी अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं उनको किसी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं दी जाती है। इस प्रकार से उनके अंदर लैक्सिटी अर्थात फ्रस्ट्रेशन आना स्वाभाविक सी बात है। इसका दुष्परिणाम यह हो सकता है कि हमारे जवान कामचोर हो सकते हैं या फिर वे कमाई के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग करने लग जाते हैं या अनुचित आदतों के आदी हो जाते हैं। आजकल देखा भी जा रहा है कि हमारे कांस्टेबल्ज में कई प्रकार की बुराइयां देखने को भी मिल रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमें इंप्रूव करने की आवश्यकता है। We are to reform them. चड्ढा साहब, आप इस हाऊस के एक सीनियर मैम्बर हैं और प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस दिशा में हरसंभव कदम उठायें। मैंने आपको पिछले सैशन में भी इस प्रकार का निवेदन किया था। अभी हाल ही में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की घोषणा के मद्देनजर हमारे कर्मचारियों को 2000 रुपये की अंतरिम राहत के तहत फायदा पहुंचाया गया है। इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि जिन कर्मचारियों की पे-एनोमलीज हैं, उनकी तरफ ध्यान देने की आज बहुत आवश्यकता है। विशेषतौर से जे.ई.ज. और आई.टी.आई. इंस्ट्रक्टर्ज आदि कटैगरीज की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त शिक्षा की तरफ भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एक तरफ योग्यता प्राप्त टीचर्ज हैं जबकि दूसरी तरफ गैस्ट टीचर्ज हैं उनकी समस्या की तरफ बहुत ज्यादा गंभीर होना समय की मांग बन चुका है। इस समस्या को चाहे कैसे भी हो, दूर करने की आवश्यकता है। इस समस्या की वजह से शिक्षा क्षेत्र को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है तथा हमारे गैस्ट टीचर्ज तथा पात्रता अध्यापकों का फ्यूचर भी अनसर्टन बना हुआ है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री महोदय से एक निवेदन और भी करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजली के बिलों का टैरिफ टेलीस्कोपी सिस्टम दोबारा से लागू कर दिया है और नॉन-टेलीस्कोपी सिस्टम जिसे 31 अप्रैल 2013 को लागू किया गया था उसे 1 जनवरी 2014 को खत्म कर दिया है। अत: मेरा निवेदन है कि नॉन-टेलिस्कोपी सिस्टम को 31 अप्रैल, 2013 से ही अर्थात जिस दिन यह लागू किया गया था उसी दिन से ही खत्म किया जाये। अब मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। हरियाणा प्रदेश में सैंटर

[प्रो० सम्पत सिंह]

पैट्रन के आधार पर ही डी.ए. की किस्त की अदायगी की जाती है। सैंटर गवर्नमैंट ने 10 प्रतिशत डी.ए. अनाउँस कर दिया है। जब प्रदेश को चलना ही सैंटर पैट्रन पर है तो वित्त मंत्री जी आपको यह डी.ए. की किस्त हरियाणा के मुलाजिमों के लिए आज ही अनाउँस कर देनी चाहिए। यदि बाद में भी डी.ए. की किस्त को अनाउँस करना ही है तो मेरी रिक्वैस्ट है कि क्यों न इसको आज ही अनाउँस कर दिया जाये। इससे आपको और प्रदेश सरकार को वाहवाही ही मिलेगी। अब मैं बिजली डिपार्टमैंट में रिफॉर्म संबंधी प्रयासों के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूँ। पिलर बॉक्स सिस्टम के द्वारा बिजली की चोरी रोकने के प्रयास किये गये हैं। बिल की पेमैंट न करनी पड़े तथा कुंडी लगाकर बिजली की चोरी करते रहें, इस प्रकार की मानसिकता लोगों के अन्दर पैदा करने में कहीं न कहीं हम लोग भी दोषी रहे हैं। बिजली चोरी संबंधी समस्या से निजात पाने के लिए मैं समझता हूँ कि पिलर बॉक्स सिस्टम इतना कारगर नहीं है जितना कि इंसुलेटिड तारों द्वारा बिजली की सप्लाई है। यदि बिजली की सप्लाई नंगी तारों की बजाय इंसुलेटिड तारों के माध्यम से की जाये तो आप पायेंगे कि बिजली की चोरी की समस्या घटकर आधी रह जायेगी। इसके साथ ही मेरा यह भी सुझाव है कि जिन गांवों में इंसुलेटिड वॉयर लगाई गई हो या फिर कोई भाई अपनी मर्जी से पिलर बॉक्स सिस्टम लगाना चाहे तो उनको बिजली के बिलों में 50 प्रतिशत की रिबेट अवश्य देनी चाहिए। ऐसा करने से बिजली की चोरी को काफी हद तक रोका जा सकता है और इस प्रकार से उपभोक्ता को रैगुलर पैमेंट करने की आदत पड़ जायेगी। ऐसा करने से सरकार को भी फायदा होगा। इसी तरीके से जो लोग बिल रैगुलरली पे कर रहे हैं उनको बिल में 10 प्रतिशत का रिबेट दिया है मैं चाहता हूँ कि रैगुलर पेई को भी इन्सैंटिव दिया जाये जैसे आप किसान से 11 प्रतिशत ब्याज दर की बजाये सिर्फ 4 प्रतिशत ब्याज दर लेते हैं। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि बिजली के बिलों में भी 30 प्रतिशत रिबेट दे दिया जाये। अब मैं पार्किंग ऑफ फंड्ज के बारे में कहना चाहता हूँ। पार्किंग ऑफ फंड्ज को ऑल मोस्ट बंद कर दिया है। सारे फंड्ज ट्रेजरी में जमा होते हैं लेकिन आज भी कुछ सैंट्रल गवर्नमैंट से पैसा आता है। वह पैसा पार्किंग होता है और पड़ा रहता है। मैं फॉरेस्ट का एक उदाहरण देता हूँ। फॉरेस्ट विभाग में 46 करोड़ रुपये जमा हैं और इस काम के लिए कुल बजट 120 करोड़ रुपये का था। जिसमें सिर्फ प्लांटेशन करनी थी, उस पैसे से आप ये काम कर सकते थे और अपना बजट बचा सकते थे, खर्च कर सकते थे। केवल 2 प्रतिशत से 4 प्रतिशत ब्याज पर वह एमांउट पड़ी रहती है लेकिन कुछ लोगों की मंशा यह होती है कि यह पैसा पड़ा रहे। इसी तरह से एजुकेशन डिपार्टमैंट के अंदर बजट की बहुत सारी एजेंसीज हैं उनके कितने एकाऊंट्स हैं मुझे भी मालूम नहीं है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : संपत सिंह जी, प्लीज बैठ जाइये।

प्रो० संपत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूँ एक तो जो पार्किंग फंड का सिस्टम है इसे बंद किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं स्पोर्ट्स के बारे में कहना चाहता हूँ कि यह पॉलिसी बहुत अच्छी है लेकिन इस पॉलिसी में जूनियर बच्चे के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। 19 साल से नीचे का बच्चा जूनियर बच्चा है, अंडर 19 की टूर्नामैंट होती है। वर्ल्ड लैवल की टूर्नामैंट होती है,19 साल का बच्चा जीतकर आता है। उसको क्या मिलता है? गाँव में केवल फूलों की माला मिल जाती है, गाँव में जिप्सी में बिठाकर जुलूस निकालकर चारों तरफ चक्कर लगा दिया जाता है। उस बच्चे को कुछ नहीं मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय मैं कहना

चाहता हूँ कि एक "जूनियर स्पोर्ट्स पॉलिसी" बच्चों के लिए होनी चाहिए, उनको नौकरी के साथ-साथ कैश का भी प्रोविजन हो। इसी तरह से माउन्टेनरिंग को भी स्पोर्ट्स में शामिल किया जाये। मुख्यमंत्री जी की यह दरियादिली है कि एक बच्ची को जिसका नाम "ममता सोधा" है उसने हाल ही में "माऊंट एवरेस्ट" की विजय की, और उस लड़की को डी.एस.पी. का पद दिया गया, यह बहुत अच्छी बात है। उससे सभी बच्चों को प्रेरणा मिली। उसके बाद अनेकों बच्चों ने "माऊंट एवरेस्ट" पर विजय प्राप्त की है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, इन बच्चों को भी पुलिस में भर्ती किया जाये और उनको कैश प्राइज दिया जाये और माउन्टेनरिंग को स्पोर्ट्स में भी शामिल किया जाये। I will not narrate and I will not define. I will only suggest.

श्री उपाध्यक्ष : संपत सिंह जी, अब आप कन्कलूड कीजिए।

प्रो० संपत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बच्चे बौने पैदा होते हैं। लड़के हों या लड़कियाँ हों सरकार ने बौने बच्चों को पैंशन के रूप में आर्थिक सहायता देना शुरू किया है यह बहुत अच्छी बात है लेकिन सरकार ने उनकी हाइट की लिमिटेशन रख दी है जैसे कि व्यक्ति की हाईट 3 फुट 8 इंच हैं, उनको तो पैंशन मिलेगी। उसके बाद अगर एक इंच भी ऊपर है तो उनको पैंशन नहीं मिलेगी। हमारे सामने इस प्रकार के कई केस आये हैं। एक बच्चा है, उसको मैं बच्चा ही कहूँगा क्योंकि वह आयु में तो बड़ा है लेकिन उसकी हाइट 4 फुट ही है। वह हमारे लिए तो बच्चा ही है। वह कहने लगा कि मुझे सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती है। तब मैंने इस बारे में पता किया और मुझे हाइट की लिमिटेशन का पता चला। हाइट के लिए कोई कंसीड्रेशन बौने के लिए नहीं होनी चाहिए इसको रिवाइज किया जाना चाहिए। इसी तरह से जितने ओल्ड इन्डस्ट्रियल एरियाज हैं उनको कॉमर्शियली कंवर्ट आप कर दें। "चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय", हिसार में हैं। इस विश्वविद्यालय में "बी-टैक" की डिग्री सरकार देती है लेकिन उसे इंजीनियरिंग की डिग्री के बराबर नहीं माना जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि "बी.ई." और "बी.टैक" अलग नहीं हैं दोनों एक ही चीज हैं इसलिए बच्चों को नौकरी पर नहीं रखा जाता है इसलिए जिन बच्चों ने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर रखी है उन बच्चों के बारे में सरकार को कदम उठाने की जरूरत है। ये बच्चे ही हरियाणा प्रदेश का गौरव हैं। जितने हमारे एम्पलॉइज हैं चाहे डैली वैजिज पर लगे हों चाहे कांट्रेक्ट पर लगे हों चाहे प्लेसमैंट एजेंसीज के थ्रू कांट्रेक्ट पर लगे हुये हैं, उन सब को रैगुलर कर देना चाहिए। 15-15 साल की सर्विस होने के बावजूद भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, उन सभी एम्पलॉइज में बहुत त्राहि-त्राहि मची हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं कृषि पर भी बोलना चाहता हूँ कि "हेल-स्टॉर्म" जो कि मेरे अपने इलाके में पड़े हैं, मेरे अपने खेत में पड़े हैं, अग्रोहा ब्लॉक, बरवाला ब्लॉक, आदमपुर ब्लॉक के बाद राई ब्लॉक में भी ओले पड़े हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इनका मुआवजा तुरन्त दिया जाये। सर, मुआवजा कई बार दो-दो साल बाद देते हैं। सर, खाद का, बीज का और मजदूरी का मुआवजा यदि तुरन्त मिल जायेगा तो किसानों को फायदा होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूँ कि सदन में कुछ सीनियर मंत्री हैं, उनका फाइलों का सिस्टम ठीक है। मेरे कुछ साथी स्टॉफ की बदौलत मार खा जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के पास फाइल एप्रूव होने के लिए जाती है और वह फाइल वहीं फाईल हो जाती है। मेरा कहना है कि या तो इस फाइल पर एक्शन ले लो नहीं तो उस फाइल को अपने सुजैशन के साथ वापस कर दो। सर, इनको देखते हुए कई ऑफिसर भी फाइल को फाइल कर देते हैं। सर, इस सिस्टम से ऐफीशिएन्सी गिरती है।

[प्रो० सम्पत सिंह]

इस तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। सर, ट्रॉमा सैन्टर को बने दो साल हो गया है लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। उसमें मशीनरी तुरन्त लगाई जाए व डॉक्टर जल्दी से जल्दी नियुक्त करके उसे शुरू किया जाये। सर, मुझे लास्ट बात यह कहनी है कि रेवेन्यु एक्ट बना हुआ है। सर, आपको पता है इसमें जमीन के बंटवारे का इतना झगड़ा है कि सांझे खाते चले आ रहे हैं। जिससे उस एक्ट के अंदर बंटवारा हो ही नहीं सकता। सर, चार-चार पीढ़ियाँ अपने हिसाब-किताब के लिए चण्डीगढ़ के चक्कर लगाती रहती हैं। पहले तहसीलदार, एस.डी.एम., डी.सी., कमिश्नर और फिर एफ.सी. के पास केस जायेगा यदि उनमें से एक भी ऑफिसर नहीं उपलब्ध होगा तो अगली तारीख मिलेगी। इस मैटर को कब सौर्ट आउट करेंगे? इसे टाइम बाउण्ड करें या इस नियम में अमेंडमैंट करें, ताकि ये झगड़े मिट जाये। सर, दूसरे अपराध की जगह सामाजिक अपराध घर के अन्दर ज्यादा हो रहे हैं। पहले नुकसान की वजह से आगे वाली जमीन को कोई नहीं लेता था, हमेशा पीछे की जमीन लेते थे। आज प्रोपर्टी डीलर से पूछा जाता है कि आगे कितनी जमीन है, इस प्रकार के झगड़े हो गए हैं। सर, इस सिस्टम के अन्दर बदलाव करना चाहिए ताकि हम सबको इसका फायदा हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो वित्त मंत्री जी ने यहां बजट पेश किया है उस पर बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री राम पाल माजरा (कलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए जो समय दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सर, टैक्स फ्री बजट मात्र एक छलावा है। हरियाणा प्रदेश ने वर्ष 2011 से आज तक टैक्स फ्री बजट पेश किए हैं। बजट पास होने के बाद टैक्स लगा दिये जाते हैं। जिस प्रकार से माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बजट पेश किया है, बजट को सुनने के लिए सत्ता पक्ष के लोग भी नहीं थे। बजट नीरस होने के कारण मेजें थपथपाई ही नहीं गई। सर, इस बजट में कोई विजन नहीं था, कोई चिन्तन नहीं था, कोई गवर्नेंस नहीं, कोई डिलीवरी नहीं, कोई उद्देश्य नहीं यानी बजट दिशाहीन था। किसान, मजदूर, व्यापारी और आम जन मानस के विरोध में यह बजट प्रस्तुत किया गया। सर, ना किसी से लिया, ना किसी को दिया, ना किसी का भला, ना किसी का बुरा इससे लगता है कि हरियाणा प्रदेश की अर्थ व्यवस्था कोमा में आ गई है। सर, रेलगाड़ी पटरी पर तो खड़ी है ना तो रेलगाड़ी आगे की तरफ जा रही है, ना ही पीछे की तरफ जा रही है, ऐसा बजट हमारे प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है। हरियाणा प्रदेश में बजट एस्टीमेट्स के अनुसार वर्ष 2014-15 में 81,806 करोड़ रुपये का कर्जा होगा। पिछली बार के बजट एस्टीमेट्स में यह कर्जा 67,772 करोड़ रुपये का बताया गया और आगे जाकर यह कर्जा 70,369 करोड़ रुपये हो गया है। इसी तरह से 2014-15 के बजट एस्टीमेट में कर्जा और बढ़ेगा। सर, किसी भी प्रदेश में यदि विकास को मापना है तो विकास की दर से ही मापा जाता है। सर, विकास दर जिस प्रकार से 2009-10 में 11 प्रतिशत थी और 2013 में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 7.1 प्रतिशत थी और 2014-15 में इसके 6.9 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। इससे साफ झलकता है कि हमारे सकल घरेलू उत्पाद में विकास दर घट रही है। इसी के साथ साथ जहां कृषि के मामले में हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। वर्ष 2011 में कृषि का योगदान 16.8 प्रतिशत, 2013-14 में 15.1 प्रतिशत हुआ और इस साल भी लगता है कि कृषि उत्पादन में गिरावट आ रही है। जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया कि कैपिटल ऐक्सपैंडीचर से पूंजी का निर्माण होता है किसी भी विकास का इन्फ्रास्ट्रक्चर

16.00 बजे

अगर बनता है तो वह कैपिटल ऐक्सपैंडीचर से ही बनता है। उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि घरेलू उत्पाद का पूंजी खर्च 1.70 प्रतिशत था जो कि 2014-15 में 1.50 प्रतिशत हो गया है जो कि चिंता का विषय है, इससे ऐसा लगता है कि विकास का मामला खत्म हो जाएगा क्योंकि इस मद में बजट में भी कोई खास बढ़ौतरी नहीं की गई है। इसी प्रकार से बजट के आंकड़े बताते हैं कि 5 वर्ष में 800 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज अदायगी बढ़ रही है। 2008-09 में 2339 करोड़ रुपये ब्याज की अदायगी में खर्च किए गए और 2013-14 में 1302 करोड़ रुपये और 2014-15 में 7139 करोड़ रुपये ब्याज की अदायगी में खर्च किए जाने हैं। इस प्रकार से हमारे बजट का मुख्य भाग ऋण और ब्याज की अदायगी में जा रहा है जो कि 20988.74 करोड़ रुपये बनता है। कुल आय का 44 प्रतिशत भाग ऋण और ब्याज की अदायगी में खर्च हो जाएगा। वेतन और पेंशन भुगतान में राजस्व प्राप्तियों का 40.33 प्रतिशत खर्च होगा। इस प्रकार ब्याज की अदायगी और वेतन व पेंशन के भुगतान में 84 प्रतिशत राशि खर्च हो जाएगी, शेष 16 प्रतिशत राशि विकास के लिए बची है। इससे साफ झलकता है कि हमारे प्रदेश में किस प्रकार से राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। हरियाणा राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार 3 प्रतिशत से कम रहना चाहिए जो कि आंकड़ों में तो 3 प्रतिशत से कम ही दिखाया गया है परन्तु 11393 करोड़ रुपये राजकोषीय घाटा हुआ है। पिछले वर्ष भी राजकोषीय बजट ऐस्टीमेट रखा गया था लेकिन इससे कहीं ज्यादा बढ़कर आया। पहले तो 8975.97 करोड़ रुपये का आंका गया था लेकिन बजट ऐस्टीमेट्स में हुआ 11515 करोड़ रुपये और उसके बाद 11393.29 करोड़ रुपये बताया गया, लेकिन यह भी बढ़ने की उम्मीद है। इसी प्रकार से राजस्व घाटा पिछली बार 2442 करोड़ रुपये बताया गया था किन्तु बाद में ऐस्टीमेट में 5612 करोड़ रुपये हो गया। अब की बार 6012 करोड़ रुपये रखा गया किन्तु ऐस्टीमेट में इसके भी बढ़ने की उम्मीद है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से राजकोषीय और राजस्व घाटा आपे से बाहर है और इसको कंट्रोल करने की दिशा में सरकार द्वारा पग भी नहीं उठाए गए हैं। इसी प्रकार से प्रदेश का कृषि उत्पादन घट रहा है वर्ष 2011-12 में कुल उत्पादन 183.70 लाख टन था, 2012-13 में 162.26 लाख टन रह गया। इससे और भी ज्यादा चिंता की बात है कि मुख्य उत्पादन गेहूं की फसल में भी 15 प्रतिशत की कमी आई है। पिछले वर्ष गेहूं का उत्पादन 88 लाख मीट्रिक टन था जो कि इस वर्ष 58 लाख मीट्रिक टन के लगभग प्रिक्योरमैंट हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, अब की बार वर्ष 2012-13 में 111.17 प्रतिशत उत्पादन हुआ। हमारे यहां पर यह भी दावे किये जाते हैं कि हमारी उद्योग नीति बहुत अच्छी है। यह कहा गया था कि दस लाख युवाओं को रोजगार दिए जायेंगे और दो लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा। ये सारे दावे कोरे साबित हुए हैं। न तो किसी युवा को रोजगार मिला है और न ही कोई नया उद्योग लगा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया है कि राज्य का निर्यात 8 प्रतिशत बढ़ा है लेकिन जब माननीय सदस्य अपना जवाब दें तो यह बता दें कि आऊटसोर्सिंग के माध्यम से निर्यात कितना हुआ है। इसी प्रकार से इण्डस्ट्रीज के बारे में यह कहा गया है कि हमारी इण्डस्ट्रीज पॉलिसी ने बहुत अच्छा काम किया है। जबकि 101 स्पेशल इकॉनामिक जॉन बनने थे जबकि 4 पर ही काम शुरू हो पाया है। जिस प्रकार सरकार द्वारा यह कहा गया था कि इन इकॉनामिक जॉन में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। परन्तु लघु उद्योगों में 42 प्रतिशत रोजगार घटा है। वर्ष 2008-2009 के मुकाबले में 39 प्रतिशत उद्योग कम लगे हैं और 42 प्रतिशत रोजगार में कमी आई है। सर, इतना ही नहीं हरियाणा के उद्योग उत्पादन के बारे में हरियाणा सरकार के इकॉनामिक सर्वे के सूचकांक में यह सब दर्शाया गया है। उसमें यह कहा

[श्री रामपाल माजरा]

गया है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पूंजीगत पदार्थों के उद्योगों में जैसे मशीनरी, बिजली का मीटर, मोटर, चीनी मशीनरी, खोदने की मशीन, सभी प्रकार की तारें आदि सूचकांक में वर्ष 2012-2013 में नये स्थापित लघु उद्योगों की संख्या घटकर 1592 रह गई है और 28962 व्यक्तियों को जो रोजगार मिलना था उसकी संख्या भी घटी है। हरियाणा सरकार के सूचकांक में रोजगार के बारें में यह कहा गया है कि वर्ष 2011-12 में 203.5 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012-13 में 189.9 प्रतिशत हो गया है जिसमें 6.7 प्रतिशत की कमी आई है। सर, मैं हरियाणा के उद्योगों की बात कह रहा हूं। माननीय उद्योग मंत्री जी आज सदन में नहीं हैं। कैथल जिले में एक भी उद्योग नहीं लगाया गया। न ही किसी युवक को रोजगार मिला है और न ही किसी पैसे का निवेश किया गया। अम्बाला में न तो कोई उद्योग लगा और न ही कोई निवेश हुआ है न ही किसी युवा को रोजगार मिला है। कैथल जिले में जीरो उद्योग लगे हैं, महेन्द्रगढ़ में जीरो उद्योग लगे हैं और जींद जिले में दो उद्योग लगे हैं। जिससे 116 युवाओं को रोजगार मिला है। मेरे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज आंकड़े हैं। पूरे हरियाणा के 21 जिलों में से केवल पानीपत, गुड़गाँव और फरीदाबाद जिलों में ही निवेश किया गया है बाकी के 18 जिलों में कोई निवेश नहीं किया गया। उद्योग नीति के बारे में यह कहा गया कि उद्योग नीति सफल हुई है। इसी प्रकार से बिजली के मामले में सरकार को लगता है कि घर की खाण्ड किरकिरी लगती है और चोरी का गुड़ मीठा लगता है। सरकार ने अपने थर्मल प्लांट्स को तो बन्द कर दिये और अदानी ग्रुप वैगरह दूसरी कम्पनियों से बिजली खरीद रहे हैं। हमारे अपने थर्मल प्लांट बन्द पड़े हैं उनका कोयला मैसर्ज चाइना लाइट पॉवर नाम की निजी कम्पनी को ट्रांसफर कर दिया है। मंत्री जी अपने जवाब में यह बतायें कि फरीदाबाद का जो थर्मल पावर प्लांट बन्द हुआ है उसकी 200 एकड़ जमीन है उस 200 एकड़ जमीन पर सरकार क्या करने जा रही है। उस जमीन पर कोई ग्लोबल इम्बैजलमैंट तो नहीं करने जा रही है या वहां पर कोई ग्लोबल सिटी तो नहीं बनाने जा रहे हैं। इस बारे में सरकार स्पष्ट करे क्योंकि वह बहुत कीमती जमीन है। इसी प्रकार से गुड़गांव में जो जमीन है और इसी प्रकार से जो दूसरी जमीनें हैं उनका सी.ए.जी. ने ऑडिट करना था। सरकार ने उस ऑडिट को वर्ष 2012-13 में इसलिए रोक दिया क्योंकि उन जमीनों के कई धपले और घोटाले उजागर होने थे। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रदेश की कानून-व्यवस्था की बात करना चाहूंगा। प्रदेश की कानून-व्यवस्था इस सरकार के समय में जीर्ण-शीर्ण रही है। जिस प्रकार से वर्ष 2004 से वर्ष 2012 तक भ्रूण हत्याओं में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और हत्याओं में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, बलात्कार में 73 प्रतिशत की वृद्धि हुई है , अपहरण में 219 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, लूटपाट में 191 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, डकेती में 292 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, सैंधमारी में 84 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, चोरी में 168 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध में 88 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जिस प्रकार से इन्होंने पुलिस महकमे के आधुनिकीकरण के नाम पर ढोल पीटे थे उससे साफ झलकता है कि किस प्रकार से इन्होंने पुलिस महकमे पर पैसा खर्च किया लेकिन उससे कोई ज्यादा लाभ नहीं हुआ। एग्रो माल की ये बात करते है। आज तक कोई एग्रो माल ओपरेशनल नहीं है। इनकी एग्रो माल को जनरल माल में बदलने की सोच है। पूल चैन में से एक या दो ही किराए पर गए हैं बाकी सभी खाली पड़े हैं। किसानों की ये बात करते हैं किसानों के लिए अबूझ शहर में सिट्रस ग्रेडिंग प्लांट लगा था जिसको बंद कर दिया

गया। उस पर 10 करोड़ रुपये लगे थे लेकिन लगता है वह खराब हो गया है इसलिए सरकार को चाहिए कि उसको तुरंत प्रभाव से चालू करे। जब भी रैक्सीन खरीदते हैं तो घोटाला हो जाता है, बीच में ही घपला हो जाता है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि किसानों की सुध लेने वाले ये लोग नहीं हैं। जिस प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं की बात मंत्री जी ने की और उन्होंने इसके लिए 1175.62 करोड़ रुपये अलॉट किए हैं। ये कहते हैं कि हमने स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत सुधार किया है। राष्ट्रीय जनहित शिशु सुरक्षा कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया है उसका मुख्य उद्देश्य इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को बढ़ावा देना था। 27 अगस्त को करनाल के सिविल होस्पिटल में डाचर गांव की गीता देवी को डाक्टर्ज ने देखने से मना कर दिया और मजबूरन उसको सड़क पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। उसके एक सप्ताह बाद दवलाना गांव की गर्भवती महिला ने गांव घरौंडा के अस्पताल में बरामदे में ही बच्चे को जन्म दे दिया। इसी प्रकार से नरवाना के अंदर मानब बरामना गांव की महिला गीता पुत्री सत्य नारायण नरवाना के अस्पताल में गई तो डाक्टर्ज ने उसको देखने से मना कर दिया, वह बस से चढ़कर जींद जा रही थी तो उसने 9 तारीख को बस में ही बच्चे को जन्म दे दिया। 23 सितम्बर, 2013 को एक गर्भवती महिला 4 घण्टे तक भूना के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सामने तड़पती रही और उस गर्भवती महिला ने खुले आसमान के नीचे बच्चे को जन्म दिया। पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए चीफ सैक्रेटरी को इसके लिए तलब किया। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हरियाणा में शिशु मृत्यु दर में कोई सुधार इनसे नहीं हो सका। हरियाणा प्रदेश में एक हजार में से 48 बच्चे मर जाते हैं। शिशु मृत्यु दर की बात करें तो हरियाणा में शिशु मृत्यु दर 48 परसैंट, हिमाचल में 44 प्रतिशत है जोकि चिंता का विषय है। (विघ्न) हरियाणा में अनीमिया के बच्चों की परसैंटेज 75 है जोकि पूरे हिन्दुस्तान में 10 वें स्थान पर है जबकि हिमाचल में 59 और केरल में 56 परसैंट है। इसी प्रकार से मातृत्व मृत्यु दर हमारे यहां एक हजार पर 153 है जो कि 35 केन्द्र शासित राज्यों में 12 वें स्थान पर है। उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगें कि आज स्वास्थ्य सेवाएं पूरे हरियाणा प्रदेश में ठप्प हैं। आज प्रदेश में आधे से ज्यादा डाक्टर्ज के पद खाली पड़े हैं। लगभग 3 हजार पद डाक्टर्ज के स्वीकृत हैं जिनमें से 1500-1600 ही कार्यरत हैं और बाकी के पद खाली पड़े हैं। डाक्टर्ज या तो डैपुटेशन पर चले गए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने चले गए या एबसैंट फ्रोम डयूटी हैं या लोंग लीव पर या अर्जित अवकाश पर या फिर चाइल्ड केयर लीव पर चले गए हैं। रजिस्टरों में तो लगता है कि हरियाणा प्रदेश में सब जगह डाक्टर्ज हैं लेकिन डाक्टर्ज का हर जगह अभाव है। जो प्रदेश स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे सकता वह प्रदेश और क्या देगा। स्वास्थ्य सेवाएं जिस प्रदेश की ठप्प हों वह प्रदेश उन्नति कैसे कर सकता है। इसी प्रकार से ये कहते हैं कि हमने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का मानदेय 4800 से बढ़ाकर 8100 रुपये कर दिया है जबकि उनकी मांग थी कि उनको नियमित किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से प्रदेश के कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है जोकि आज आन्दोलित हैं चाहे वे कम्प्यूटर ओपरेटर्ज हैं या अन्य कर्मधारी हैं, कुल मिलाकर तकरीबन 3 लाख कर्मचारी आज प्रदेश में हड़ताल पर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हमारे पुलिस के कर्मचारियों की सैलरी पंजाब पुलिस के कर्मचारियों से तकरीबन हाफ है। हमारे पुलिस के एक सिपाही की सैलरी 14939 रुपये प्रति माह है जबकि पंजाब पुलिस के एक सिपाही की सैलरी 28926 रुपये प्रति माह है। इसी तरह से हमारे पुलिस के एक हवलदार की सैलरी 18245 रुपये प्रति माह है जबकि पंजाब पुलिस के एक हवलदार की सैलरी 30872 रुपये प्रति माह है। इसी तरह से हमारे पुलिस के एक ए.एस.आई. की सैलरी 19173 रुपये प्रति माह है जबकि पंजाब पुलिस के एक

[श्री रामपाल माजरा]

ए.एस.आई. की सैलरी 37093 रुपये प्रति माह है। इसी तरह से हमारे पुलिस के एक एस.आई. की सैलरी 25408 रुपये प्रति माह है जबकि पंजाब पुलिस के एक एस.आई. की सैलरी 38387 रुपये प्रति माह है। इसी तरह से हमारे पुलिस के एक इनसपैक्टर की सैलरी 30497 रुपये प्रति माह है जबकि पंजाब पुलिस के एक इनसपैक्टर की सैलरी 38925 रुपये प्रति माह है। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से जो कर्मचारी कानून व्यवस्था की देखरेख करने वाले हैं उनकी सैलरी में बहुत भेदभाव है। उपाध्यक्ष महोदय, बड़े लम्बे समय से प्रदेश के अंदर 15040 वैकेंसिज का बैकलोग रहा इसके लिए केवल सरकार ही जिम्मेवार है। मौजूदा सरकार चाहे स्थाई भर्ती की बात हो, चाहे आरक्षित श्रेणी की भर्ती की बात हो, सरकार ठेका प्रथा अपनाकर आऊटसोर्सिज से भर्तियां करवा रही है और पिछले कई-कई सालों से जो कर्मचारी कंट्रैक्ट पर लगे हुए हैं उन्हें पक्का नहीं कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार ने प्रिय दर्शनी आवास योजना का बहुत व्याख्यान बजट में किया है ताकि दो लाख गरीब लोगों को पक्के मकान मुहैया करवाये जा सकें। इस बारे में मैं सदन में बताना चाहूंगा कि सरकार ने 75 हजार लोगों को पक्के मकान बनाने के लिए पहली किस्त तो दे दी, दूसरी किस्त नहीं दी जिसके कारण उनके मकान गिर गये, यही वजह रही कि गरीब लोगों को सर्दी के दिनों में चौपालों और टैंटों में रहना पड़ा। सरकार ने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि जिन लोगों को पहली किस्त दे दी है उनको दूसरी किस्त दे दी जाये ताकि उनके मकानों की छत डल जाये। इसी तरह से सरकार ने न्यूनतम मजदूरी 8100 रुपये प्रति माह कर दिया है लेकिन इण्डस्ट्रीज और प्राइवेट इन्स्टीच्यूशंज में यह मानदेय लागू नहीं किया गया। सरकार को जानकारी होनी चाहिए कि ज्यादा श्रमिक हमारे प्रदेश में प्राइवेट इण्डस्ट्रीज और इन्स्टीच्यूशंज में कार्य करते हैं लेकिन इससे सरकार बचकर निकल गई है, इस बारे में सरकार अपना जवाब दे। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : माजरा जी, अब आप कंकलूड कीजिए।

श्री रामपाल माजरा : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक नरेगा की बात है इस बारे में भी सरकार ने बहुत ढोल पीटा है। इस बारे में पार्लियामैंट में बताया गया है कि हरियाणा प्रदेश में 100 दिन का रोजगार 5 प्रतिशत लोगों को मिला है। इस बारे में मैं ईयरवाईज बताना चाहूंगा कि 2010-11 में हमारे प्रदेश में 39 दिन, 2011-12 में 40 दिन , 2012-13 में 35 दिन औषतन रोजगार गरीब लोगों को मिला है और हमारे साथ लगते हिमाचल प्रदेश में 49 दिन औषतन रोजगार गरीब लोगों को मिला है। उपाध्यक्ष महोदय, अंबाला जिले में नरेगा के 25 करोड़ रुपये फोरैस्ट विभाग को आये थे जिनका कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ और विभागीय अधिकारी वह सारा पैसा खा गये। इस बारे में सदन में विश्वास दिलाया था कि इस मैटर की जांच कराई जायेगी। 5-6 वर्ष हो गये हैं उस नरेगा की फाइल को पता नहीं कहां पर दबा दिया गया है। उस 25 करोड़ रुपये में से एक पैसा लोगों को नहीं मिला। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, वह पैसा फोरैस्ट विभाग को गया था और वहीं के अधिकारी उस पैसे को खा गये। फोरैस्ट विभाग के वजीर खा गये। यह रिकार्ड की बात है। उसकी इन्क्वायरी भी हुई थी लेकिन पता नहीं उस फाइल को कहां दबा दिया गया। (विघ्न)

श्री नरेश कुमार बादली : उपाध्यक्ष महोदय, कौन खा गया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, माजरा साहब ने जो 25 करोड़ रुपये के गबन की बात की है इस बारे में विजीलैंस से इन्क्वायरी करवाई गई थी और वह फाइल मुख्यमंत्री जी के

पास आई थी लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है और माजरा जी उसी का जिक्र कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माजरा जी, प्लीज आप कंकलूड करें।

श्री रामपाल माजरा : उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में फोरैस्ट विभाग आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। आज प्रदेश के 33 प्रतिशत हिस्से पर वन होना चाहिए था। वह इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि करोड़ों रुपये झज्जर और हिसार जिलों में खाये गये हैं। इस बारे में संजीव चतुर्वेदी ने रिपोर्ट दे दी तो उसको सरकार ने तंग करना शुरू कर दिया। उसने अपनी रिपोर्ट में यहां तक कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री आफिस भी जिम्मेवार है उसके बाद उसके तबादले किए गए। (शोर एवं व्यवधान) डिप्टी स्पीकर सर, सरकार की वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की दो सदस्यीय समिति ने इस मामले में जो रिपोर्ट दी है सरकार उसको कोर्ट में चैलेंज करना चाहती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नरेश शर्मा जी, कृपया आप बैठ जाइये। Ram Pal Ji, please conclude.

श्री राम पाल माजरा : डिप्टी स्पीकर सर, उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि चर्तुवेदी जी का कोई कसूर नहीं था। इस मामले में लाखों-करोड़ों रुपये खाये गये हैं। वन विभाग में करोड़ों रुपये का गबन घोटाला हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : राम पाल जी, आपको बोलते हुए 25 मिनट हो गये हैं इसलिए अब आप कृपया कंनक्लूड कीजिए क्योंकि बाकी सदस्यों को भी बजट पर बोलना है।

श्री राम पाल माजरा : डिप्टी स्पीकर सर, मैं सरकार को अच्छे-अच्छे सुझाव ही दे रहा हूं। मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूं इसलिए आप मुझे इतनी जल्दी बैठने के लिए न कहें। सर, मैं यह कह रहा था कि प्रदेश के सहकारी बैंक किसानों को नोटिस देकर उनकी कैद कराने का काम कर रहे हैं। ये बैंक किसानों से खाली चैक ले लेते हैं। आज प्रदेश के सहकारी बैंकों की दुर्दशा है इसलिए सहकारी बैंकों को अपैक्स बैंक में मर्ज करने की योजना सरकार द्वारा बनाई जा रही है। इसी प्रकार से लैंड डवैल्पमैंट बैंकों को बंद किया जा रहा है जो कि किसानों के समर्पित बैंक थे। मैं यह बात एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि किसानों को नोटिस देकर उनकी कैद कराई जा रही है। सर, वित्त मंत्री जी बैठे हैं मैं इनको अपने इलाके की बात कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज से डेढ़ वर्ष पहले यह घोषणा की गई थी कि कलायत को उप मण्डल का दर्जा दिया जायेगा लेकिन आज तक भी इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया है। मैं यह चाहता हूं कि कलायत को जल्दी से जल्दी उप मण्डल का दर्जा दिया जाये। (विघ्न) डिप्टी सपीकर सर, मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार को और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री को भी यह कहना चाहूंगा कि वे किस के ऊपर विश्वास कर बैठे ये इनको धोखा देंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री को यह करना चाहिए कि इनको पहचान करके हरियाणा प्रदेश के गवर्नर के पास जा करके विधान सभा को डिजाल्व कर दें और चुनाव करवायें। (विघ्न) सर, मुझे सिर्फ एक मिनट और दिया जाये। मैं यह कह रहा था कि गोहाना रैली में अनेकों घोषणायें की गई। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : राम पाल जी, अब आप कृपया बैठ जाइए। राजपाल भूखड़ी जी, अब आप बोलिए।

श्री राजपाल भूखड़ी (साढ़ौरा) (अनुसूचित जाति) : माननीय डिप्टी स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए मौका दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। डिप्टी स्पीकर सर, इसके साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्तमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं जो उन्होंने प्रदेश का समुचित विकास करने वाला इतना अच्छा बजट यहां पर पेश किया। किसान और व्यापारी सहित प्रदेश के सभी वर्गों के हित के लिए यह बजट यहां पर पेश किया गया है। चाहे गरीब वर्ग है, चाहे किसान है और चाहे व्यापारी है सबका हित इस बजट में निहित है। मैं इस बजट की सराहना करता हूं और इसके साथ ही साथ इसका समर्थन भी करता हूं। आज हमारे प्रदेश के मेहनतकश किसानों ने खाद्यान्नों और दूसरे कृषि उत्पादों की रिकार्ड पैदावार की है जिस कारण भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दो बार कृषि कर्मण अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है। मैं यह मानता हूं कि मेहनतकश किसानों और गरीब मज़दूरों की मेहनत से ही यह सम्भव हो पाया है। (शोर एवं व्यवधान) सर, जैसा कि सभी जानते हैं कि कृषि पर हमारे प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता अपनी आजीविका के लिए निर्भर करती है। इसी को देखते हुए हमारी सरकार ने कृषि क्षेत्र में भारी सब्सिडी दी हैं। इसी कारण खाद्यान्नों की पैदावार में हरियाणा प्रदेश बहुत आगे बढ़ा है। इसका एक कारण और भी है कि हरियाणा प्रदेश में बिजली का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। आज के दिन वर्ष 2014 में 5300 मैगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है और 1205 लाख यूनिट प्रतिदिन बिजली की सप्लाई की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं सिंचाई के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। सिंचाई सिस्टम में हमारी सरकार ने बहुत सुधार किये हैं जिसकी वजह से किसानों को पर्याप्त पानी मिला और उनका उत्पादन बढ़ा है। इसी प्रकार से अगर सड़कों की बात की जाये तो वर्ष 2005 से पहले सड़कों की बुरी हालत थी लेकिन हमारी सरकार ने सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत प्रयास किये हैं और सड़क तंत्र को मजबूत भी किया गया है, उसमें सुधार किये गये हैं उसके लिए मैं सरकार का और माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इलके में भी सड़कों की बहुत बुरी स्थिति थी और आपके एरिया यमुनानगर में भी स्थिति अच्छी नहीं थी। सरकार ने उन सड़कों को मजबूत किया गया है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि उन अधिकारियों के खिलाफ अवश्य कार्रवाई की जाये जिन्होंने अपने काम में लापरवाही बरती है। मेरे इल्के के 12 करोड़ रुपये के सड़कों के काम जिनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल हो चुकी थी और उसके बाद भी उन कामों को लटकाया गया और अब वे काम आदर्श आचार संहिता में फंस कर रह गये हैं और उनको जानबूझकर लटकाया गया है। अब वे काम चुनाव के बाद ही पूरे हो सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, अगर प्रति व्यक्ति आय की बात की जाये तो देश के दो छोटे-छोटे राज्य गोवा और सिक्किम को छोड़ कर बड़े राज्यों में हरियाणा नम्बर 1 पर है। हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय 1,35,007/- रुपये है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मैं प्रियदर्शनी आवास योजना के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। इस स्कीम से लगभग 78 हजार लोगों को फायदा हुआ है और मेरे हल्के में भी बहुत से लोग लाभान्वित हुये हैं। प्रियदर्शनी आवास योजना के तहत जो पैसा दिया जाता है वह 3 किस्तों में दिया जाता है। ऐसी स्थिति में अगर कोई आदमी अपने पुराने मकान को तोड़ कर दोबारा से नया बनाना चाहे तो वह नहीं बना पाता क्योंकि पैसा मिलने में काफी समय लग जाता है और उसको समय पर पैसा नहीं मिलता। इसलिए वह पैसा 2 किस्तों में दिया जाये ताकि उसको समय पर पैसा मिल जाये और वह समय पर अपना मकान बना सके। इसी प्रकार से अगर वृद्धावस्था पैंशन की बात की जाये तो मैं नहीं जानता कि 2005 से पहले कितनी पैंशन मिलती थी

लेकिन आज के दिन हमारी सरकार 1000/- रुपये महीना वृद्धावस्था पैंशन दे रही है और उसमें निरन्तर बढ़ोतरी की है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, उसमें एक दिक्कत है और मैं आपसे रिक्वैस्ट्स करना चाहूँगा कि जिला स्तर के जो अधिकारी हैं वे वृद्धावस्था पैंशन के लिए वोटर का मांगते हैं। वोटर कार्ड पहचान के लिए, डोमिसाइल के लिए ही होना चाहिए। अगर किसी के पास स्कूल का सर्टिफिकेट है या उसके किसी के बच्चे का 40-42 साल का सर्टिफिकेट है तो उनकी तो पैंशन बननी ही चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं फूड सिक्योरिटी के बारे में भी कुछ कहना चाहूँगा। हमारी केन्द्र की सरकार में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह व कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गाँधी के प्रयासों से यह बिल पास हुआ है जिससे हरियाणा में लगभग 64 प्रतिशत आबादी को इसका फायदा पहुंचेगा। (विघ्न)

श्री कृष्ण लाल पंवार : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। माननीय साथी ने जो 64 परसैंट का आंकड़ा दिया है वह ठीक नहीं है। इसका जो अखिल भारतीय आँकड़ा है वह 65 परसैंट है और हरियाणा में यह आँकड़ा 49.5 प्रतिशत है, माननीय सदस्य इसको 64 परसैंट कैसे कह रहे हैं इस बारे में माननीय वित्त मंत्री जी अपने जवाब में जरूर बतायें ?

श्री राजपाल भूखड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, उससे बहुत से लोगों को लाभ होगा तथा लोगों को 2-3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से राशन मिलेगा। यह एक बहुत अच्छी योजना है और हरियाणा सरकार ने इस योजना को लागू करने में बड़ी जल्दी दिखाई है इसके लिए मैं हरियाणा सरकार के मुखिया का धन्यवाद करता हूं। सर, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस योजना में कहीं धांधली न हो इसके लिए अच्छे तरीके से इसके काम की मॉनिटरिंग की जाए ताकि गरीब आदमी को समय पर राशन और दाल-रोटी की योजना का लाभ मिल सके उसमें कई जगह यह बातें सुनने को मिली हैं कि डिपो होल्डर दाल को प्रोपर तरीके से नहीं बांट रहे इसलिए उसमें कुछ सुधार किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी कुछ डिमांड्स सदन के सामने रखना चाहता हूं कि हमारी सरकार की बी.पी.एल. परिवार की लड़कियों की शादी में 31 हजार रुपये देने की योजना की मैं सराहना करता हूं और उसके लिए मैं यह प्रार्थना करता हूं कि उस योजना का लाभ गरीब आदमी को शादी से 10 या 15 दिन पहले पहुंचना चाहिए ताकि वह किसी से पैसा उधार लेकर या ब्याज पर पैसा लेकर शादी न करे इसलिए गरीब आदमी को पैसा शादी से पहले मिले। सर, जहां तक सड़कों का सवाल है हमारे प्रदेश में बहुत सारे नैशनल हाइवे बनाए गये हैं। बहुत सारे सिक्स लेन, फॉर लेन बनाए गये लेकिन हमारा एन.एच. 73-ए जो जगाधरी से पंचकूला वाया साहा आता है उसका कॉन्ट्रेक्ट गेमन इण्डिया लिमिटेड कम्पनी के पास है। दो साल से सारी फॉरमल्टीज पूरी कर ली गई हैं लेकिन पता नहीं किन कारणों से आज वह कम्पनी काम को छोड़कर भागना चाहती है। अगर मुख्यमंत्री जी यहां होते या मेरी आवाज सुन रहे हों तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि गेमन इण्डिया कम्पनी, जो एक कंस्ट्रक्शन कम्पनी है उस को वापस न जाने दिया जाए इस काम को शुरू कराया जाए क्योंकि हमारी यह सड़क हरियाणा को यू.पी. और हिमाचल से जोड़ती है जिसकी बहुत बुरी दशा है इसलिए उस पर ध्यान दिया जाए क्योंकि यह कार्य एक या दो दिन में ही रुक सकता है नहीं तो वह कम्पनी विदड्रा करके भाग जाएगी। इसलिए मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। सर, ग्रामीण विकास में काफी कुछ कार्य हुए हैं। मेरे इलाके में भी जो टोटली ग्रामीण एरिया था और काफी पीछे था उसमें हमें एच.आर.डी.एफ. से काफी पैसा मिला है और बहुत सारे कार्य हुए हैं। सर, आप मेरे क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को भी अच्छी तरह से जानते हैं जो मेरा घाहड़ का

[श्री राजपाल भूखड़ी]

क्षेत्र है उसमें अभी भी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जहां पर गलियों, नालियों में कीचड़ है जिससे लोगों को आने-जाने में काफी दिक्कत है तो उसके सुधार के लिए मुझे और पैसा दिया जाए ताकि जो घाहड़ क्षेत्र के लोग पहाड़ी की तलहटी में रहते हैं उनके जीवन स्तर में सुधार हो। क्योंकि वहां उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। अगर उनके गांव का माहोल अच्छा होगा तो वह कुछ न कुछ अपने को विकास में सम्मिलित समझेंगे। सर, जल आपूर्ति की मैं बात करूं तो हमारे सभी गांवों में स्वच्छ जल दिया जाता है। सर, आपके माध्यम से मेरी मंत्री जी से और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 16 गांव ऐसे हैं जिनमें पानी के टयूबवैल फेल हो चुके हैं और इन टयूबवैलों के अगेंस्ट डेढ साल से कोई नये टयूबवैल नहीं लगे हैं तो आगे सेनेटिरिंग बोर्ड की मीटिंग में नये टयूबवैलों को मंजूर किया जाए ताकि वहां के लोगों को पानी मिल सके क्योंकि वहां के लोगों को किसानों के टयूबवैलों से पानी पीना पड़ रहा है और वह टेस्टिड पानी नहीं है इससे लोगों को कोई भी बीमारी हो सकती है इसलिए मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया जाए। सर, जहाँ तक बिजली की बात है, मेरे हल्के में चार सब स्टेशन पड़ते हैं जिनकी पावर क्षमता बढ़ाने के लिए 16 एम.वी.ए. से 32 एम.वी.ए. कराने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र दिया था जिसमें से हमारे तीन सब स्टेशनों को 16 एम.वी.ए. से 32 एम.वी.ए. कर दिया है लेकिन हमारा एक सब स्टेशन तलाकौर का है वह रहता है तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस तलाकौर के सब स्टेशन को भी 16 एम.वी.ए. से 32 एम.वी.ए. का ट्रांसफार्मर देकर उसकी क्षमता बढ़ाई जाए ताकि किसानों को फसलों को लगाने के कार्य में जैसे धान की फसल को लगाने में फायदा मिल सकेगा। डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से एक और प्रार्थना करना चाहता हूँ। सोम नदी आपके क्षेत्र के साथ-साथ मेरे क्षेत्र को भी बहुत प्रभावित करती है। इस सोम नदी में हिमाचल की बरसात का पानी ढलान की वजह से बहुत तेज गति से आता है और यह तेज बहाव का पानी कई नई जगहों पर भी अपना रास्ता बना लेता है जिसकी वजह से आपके और मेरे क्षेत्र की हजारों-हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि बर्बाद हो जाती है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि इस नदी के दोनों तटों पर रणजीत पुर से लेकर मलिकपुर बांगर से आगे का वह एरिया जहां पर जाकर यह नदी यमुना नदी में मिल जाती है, वहां तक इस नदी के तटबंध बनाये जायें ताकि नदी का पानी किनारे तोड़कर बाहर न जाने पाये। यदि ऐसा होता है तो इससे हमारे किसानों को बहुत ज्यादा लाभ पहुँचेगा। किसानों की जमीन बर्बाद होने से बच सकेगी। डिप्टी स्पीकर सर, हमारे क्षेत्र में काफी लोग खनन उद्योग से जुड़े हुए हैं। कोई व्यक्ति ट्रैक्टर-ट्राली या ट्रक चलाकर अपनी आजीविका कमाता है तो कोई मजदूरी करके अपना काम चलाता है। हमारे यहां खनन का कार्य काफी दिनों से बंद पड़ा था। माननीय कोर्ट के आदेशानुसार अब खनन का कार्य करने के लिए छूट दे दी गई है तथा खनन कार्य के लिए बोली भी हो चुकी है। इस प्रकार सरकार को 2133 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। अतः अब मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि खनन संबंधी कार्य को पर्यावरण डिपार्टमैंट की जल्द से जल्द क्लीयरैन्स दिलवाकर मेरे क्षेत्र में खनन का कार्य शुरू किया जाये। इससे हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार तो प्राप्त होगा ही साथ ही साथ प्रदेश में जो बिल्डिंग मैटीरियल की समस्या फेस की जा रही है वह भी काफी हद तक दूर हो सकेगी। अब मैं सहकारिता पर अपने विचार सदन में रखना चाहूँगा। सहकारिता विभाग के तहत गरीब लोगों के कर्जे माफ हुए थे लेकिन इन गरीब लोगों को विभाग की तरफ से अभी तक भी क्लीयरैन्स सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुए हैं।

अगर इन गरीब लोगों को यह क्लीयरैन्स सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाते हैं तो इन गरीब लोगों को किसी अन्य साधन से भी कर्ज मिलने में सुविधा मिल जायेगी। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ। अब मैं खेलों के बारे में विचार रखूंगा। खेलों में हमारे राज्य ने नये-नये आयाम स्थापित किये हैं। प्रदेश के खिलाड़ियों ने विदेशों में जाकर वर्ल्ड कप और अन्य खेलो में भाग लेकर स्वर्ण पदक जीते हैं। हमारी सरकार ने ऐसे खिलाड़ियों को जो ईनाम देने की योजना बनाई है वह भी एक अच्छी योजना है तथा मैं दिल से उसकी सराहना भी करता हूँ। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास के लिए जहां तक एच.आर.डी.एफ. से मिलने वाली राशि का प्रश्न है, मैं चाहता हूँ इस फंड से विकास करवाने में मेरे क्षेत्र का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाये। अंत में डिप्टी स्पीकर सर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया और आशा करता हूँ कि जो डिमांड्स मैंने आज सदन में रखी है सरकार उन पर जरूर विचार करेगी।

डॉ. बिशन लाल सैनी : डिप्टी स्पीकर सर, जो आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। चड्ढा साहब ने जो बजट पेश किया है उससे न किसी का फायदा हुआ है और न किसी का नुकसान हुआ है। क्यों चड्ढा साहब मैं ठीक कह रहा हूँ ना? (विघ्न)

श्री नरेश कुमार बादली : सैनी साहब, आप क्या बात करते हैं? माननीय चड्ढा साहब ने जो बजट पेश किया है वह बजट प्रदेश के हर वर्ग के लिए उन्नति और तरक्की का मार्ग प्रशस्त करता है। इस बजट के माध्यम प्रदेश की 36 बिरादरी की भलाई का ध्यान रखा गया है। आप इस तरह की अलूल-जलूल बातें करके सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हों। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० बिशन लाल सैनी : नरेश जी, आप सुनों तो? चड्ढा साहब ने जो बजट पेश किया है इसमें गुणगान तो बहुत किया गया है लेकिन . . . (शोर एवं व्यवधान)

श्री कली राम पटवारी : डिप्टी स्पीकर सर, इस नरेश शर्मा को कह दो कि बैठ जाये। नरेश तेरे द्वारा बड़ी-बड़ी बातें करने से तेरी हकीकत नहीं छुप सकती है। मेरे हाथ में जो चिट्ठी है वह तेरा इलाज अच्छी तरह करेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली : क्या तेरे हाथ में "ब्याह की चिट्ठी" है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० बिशन लाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्ढा, वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है। इस बजट में हरियाणा सरकार का गुणगान तो बहुत गाया गया और जैसा कि..... (शोर एवं व्यवधान)

श्री कली राम पटवारी : उपाध्यक्ष महोदय..... (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कली राम जी, आपकी पार्टी के माननीय सदस्य बोल रहे हैं। आप इनको डिस्टर्ब ना करे। प्लीज आप बैठ जाईये (विघ्न) प्लीज आप बैठ जाईये (विघ्न)

श्री धर्म सिंह छौक्कर : उपाध्यक्ष महोदय, क्या इन्होंने गलत बोलने का ठेका ले लिया है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : छौक्कर जी.....(विघ्न)

श्री नरेश कुमार बादली : उपाध्यक्ष महोदय..... (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : शर्मा जी प्लीज बैठ जाईये, कौन क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय..... (शोर एवं व्यवधान) आप लोग बात तो सुनिये। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज आप बैठ जाईये।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय..... सैनी साहब बोल रहे थे कि..... (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज आप सारे बैठ जाईये.....(शोर एवं व्यवधान) सैनी जी, आप बोलिये।

डॉ० बिशन लाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, बजट भाषण के पैरा नम्बर 45 पर सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों के बारे में वित्त मंत्री जी ने जिक्र किया है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि किसी प्रदेश की सड़कें उसका आईना होती है कि उस प्रदेश में कितना विकास हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी इस समय सदन में उपस्थित नहीं है, वे छोटी सी बात सुनकर चले गये और उद्योग मंत्री जी भी सदन में उपस्थित नहीं हैं। आज उनका चार्ज श्री आफताब अहमद परिवहन मंत्री जी के पास है। मैं एक मैसेज मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाना चाहता हूँ कि उन्होंने 10 साल तक हवाई जहाज में देश और दुनिया की सैर की है। अब मुख्यमंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि वे अपनी कार से यमुनानगर जिले की सड़कों को भी देखें, उन सड़कों की हालत को देखकर उनको इस बात का आभास हो जायेगा कि हरियाणा नम्बर वन है या किसी और नम्बर पर है? उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा, वित्त मंत्री जी ने बजट में 33 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को दर्शाया है और साथ में यह भी कहा है कि सारी परियोजनाओं का काम पूरा हो गया है सभी सड़कों के भी काम कंपलीट हो गये हैं। मेरा आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को यह कहना है कि कि अभी भी 5800 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। श्री राजपाल जी चले गये, मेरे भाई हैं, मेरे पड़ोसी हल्के के भी हैं। वे एक कम्पनी का जिक्र कर रहे थे, जिसका नाम "गैमन इंडिया लिमिटेड कम्पनी" है। "गैमन इंडिया लिमिटेड कम्पनी" ने एन.एच.73 राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने और सड़क को अच्छी तरह से बनाने का ठेका लिया था। श्री राजपाल भूखड़ी जी जो बात नहीं कह पा रहे थे, वह बात अब मैं कहूँगा, "गैमन इंडिया लिमिटेड कम्पनी" सरकार के पैसे लेकर भाग गई यानी काम बीच में छोड़कर भाग गई। (विघ्न)

श्री जगदीश नायर : उपाध्यक्ष महोदय, श्री नरेश कुमार बादली बार-बार उठकर खड़े हो जाते हैं। यह ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० बिशन लाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, उस कम्पनी के साथ सरकार का कमीशन सैट नहीं हुआ था, इसलिए वह कम्पनी बीच में ही काम छोड़कर चली गई। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक बात और सदन को बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली अपनी कार से 40 किलोमीटर का सफर तय करने में मुश्किल से 40-50 मिनट ही लगते हैं। यदि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय तथा प्रदेश के मंत्री अम्बाला से यमुनानगर के इस सफर को 3 घंटे में भी अपनी कार से पूरा कर के दिखा दें तो भी गनीमत की बात होगी। उस सड़क की पोजीशन का इस बात से अंदाजा

लगाया जा सकता है। अपने हल्के की लिंक रोड़ की सड़कों की हालत के बारे में मैं पिछली कई बैठकों में आवाज उठाता आ रहा हूँ। जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि सरकार ने सड़कों की रिपेयर के लिए काफी पैसा खर्च किया है। सर, यह रिपेयर हमें कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी और भवन और सड़कें मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि सड़कें रिपेयर होने से पहले ही टूट जाती हैं। सर, मेरा कहने का मतलब यह है कि सड़कों की स्थिति जैसे पहले थी, अब भी वैसी ही है, बल्कि बढ़िया तारकोल और बजरी न लगने की वजह से उनकी हालत पहले से भी खराब हो गई है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण के पैरा नम्बर-23 में नहरों का जिक्र करते हुए यह कहा है कि नहरों पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया गया है ताकि टेलों तक पानी पहुँचाया जा सके। माननीय वित्त मंत्री जी के पास सिंचाई का विभाग भी है। बार-बार सदन में प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था कि दादूपुर नलवी नहर के चार चरणों में से दो चरणों का कार्य पूरा हो चुका है। इस वर्ष 2014-15 के बजट में दादूपुर नलवी नहर का कोई जिक्र नहीं किया। सरकार यह कहती थी कि दादूपुर नलवी नहर उत्तरी हरियाणा के किसानों के लिए लाइफ लाइन बनेगी। वॉटर रिचार्ज होने से किसानों को बहुत फायदा होगा। लेकिन सर, यह लाइफ लाइन वहां के किसानों के गले की फांस बन गई है, क्योंकि चतंग और रॉक्सी नालों में बरसाती पानी आने से और दूसरी तरफ सरकार द्वारा दादूपुर नलवी नहर में पानी छोड़ने से इन तीनों के मिलने के कारण किसानों की फसलें बर्बाद होती है। सर, पिछली बार भी पांच सौ एकड़ रकबे में धान की फसल बर्बाद हो गई थी। वह धान दोबारा से लगानी पड़ी, ऊपर से एक मुसीबत यह है कि धान की पौध ही नहीं मिलती है। इस बार किसान ने पेहवा से जीरी की पौध ढो ढो कर लाकर वहां लगाने का काम किया। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि ऐसा लगता है कि सरकार इसके चार चरण पूरे नहीं करना चाहते थी, तभी इस बारे में न तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहीं जिक्र किया गया न ही बजट में इस बारे में कोई जिक्र किया गया है और न ही इस बारे में पैसे का प्रावधान बजट में किया गया है। अगर ऐसा है तो सरकार किसान को क्यों मारना चाहती है। उस नहर में मिट्टी डलवाकर उसे बंद करें। उस नहर के खुदे होने की वजह से किसान की बर्बादी हो रही है। इस बारे में कुछ न कुछ ध्यान अवश्य दिया जाना चाहिए। इस नहर के चार चरण पूरे हो जाएँ तभी यह किसान के लिए लाइफलाइन बन सकती है। (विघ्न)

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि उस नहर में पानी डालकर उसकी रिचार्जिंग की जाती है।

डॉ० बिशन लाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, उस नहर की रिचार्जिंग की जरूरत तो आज के दिन है। जबकि पानी चौमासे के दिनों में उसमें डाला जाता है। चौमासे में तो आलरेडी उसमें पानी बहुत होता है। वहां पर नहर कंप्लीट ही नहीं है क्योंकि रेलवे लाइन जहां से निकलती है उसके नीचे से उसका साइफन बनना अभी बाकी है। (विघ्न) जब उसमें अभी काम ही बकाया रहता है तो उसे आप कंप्लीट कैसे मानेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से एक निवेदन और करना चाहूंगा कि मेरे हल्के में बम्भौली गांव है वहां पता नहीं हरियाणा सरकार की तरफ से या केन्द्र सरकार की तरफ से एक होटल मैनेजमैंट का इंस्टीच्यूट खोला जा रहा है उसको वहां बनाने से पहले किसी की राय ही नहीं ली गई, यहां तक कि डी.सी. से भी नहीं पूछा गया और वह बिल्डिंग ऐसी जगह बनाई जा रही है कि जब बरसात आती है और राक्सी व चतंग नालों के अंदर पानी आ

[डॉ० बिशन लाल सैनी]

जाता है तो जहां वह बिल्डिंग बन रही है वहां 5-5 फुट तक कमरों में पानी घुस जाता है। अभी वह बिल्डिंग इन्कंप्लीट है। अब आप ही बताइए वहां उस बिल्डिंग के बनाने का क्या फायदा है? इतना सारा पैसा लगने के बाद उसका लाभ भी नहीं हो पाएगा। मैं चाहूंगा कि इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए कि किसकी रिकमंडेशन पर वह बिल्डिंग वहां बनाई जा रही है और उसको वहीं क्यों बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, बजट भाषण के पैरा 41 में जो नगर एवं ग्राम आयोजना एवं शहरी विकास विभाग के हैडिंग में इस बारे में लिखा हुआ है। जब यमुनानगर को नगर निगम बनाया गया था तो उस समय उसमें 40 गांवों की पंचायतों को तोड़कर शहर के अंदर मिलाकर के नगर निगम का गठन किया गया था। जब ये नगर निगम बना तो उसमें जितने भी गांव मिलाए गए थे उन गाँवों की जब उनकी पंचायतें थीं तब तो वहां कुछ न कुछ काम हो जाता था लेकिन जब से वे गाँव नगर निगम में मिले हैं। 3-4 साल हो गए हैं तब से वहां कोई भी विकास का काम आज तक हुआ दिखाई नहीं दिया। कभी नगर निगम लाल डोरे का बहाना बना देता है। वहां जो कालोनियां हैं उनमें जगह की तंगी की वजह से उन गांवों से लाल लकीर से बाहर लोग बस गए। आज 65 परसैंट आबादी लाल डोरे से बाहर बसी हुई है और उनके बारे में कहा जाता है कि लाल डोरे से बाहर होने के कारण नियमानुसार वहां कोई विकास का काम नहीं होगा, लेकिन जो बिजली के कनैक्शन हैं उन घरों में दिये गये हैं या पानी की सप्लाई है वह तो सरकार ने दे रखी है। एक खम्भे से लगभग 40-40 और 50-50 घरों को बिजली के कनेक्शन दे रखे हैं। जब विभाग को इस बारे में जाकर बोलते हैं कि एक दो खम्भे और लगा दो तो वे यह कह देते हैं कि ये घर तो लाल डोरे से बाहर स्थित हैं इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन नियमों में कुछ ढील देकर वहां पर एक या दो खम्भे और लगवाये जायें ताकि रोजाना इन से जो हादसे हो रहे हैं उनको कुछ कम किया जा सके। अभी हमारे एक भाई ने यह कहा कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति सालाना आय एक लाख 35 हजार रुपये है। वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं क्या उनकी अन्तरआत्मा यह कहती है कि इतनी आय हमारे प्रदेश के प्रति व्यक्ति की सालाना है या नहीं ? क्या यह अनुमान ही तो नहीं है ? (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : सैनी साहब, आप कन्क्लूड कीजिए।

डॉ० बिशन लाल सैनी : डिप्टी स्पीकर सर, अब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की समस्याओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में बैठे नहीं हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि रादौर एरिया यमुना नदी के क्षेत्र में पड़ता है और जैसा कि अभी हमारे एक भाई ने जिक्र किया कि जब यमुना नदी में बाढ़ आती है तो रादौर के किसानों की फसल बाढ़ में खराब हो जाती है। रादौर के किसानों की जमीन यमुना के साथ साथ लगती है इसलिए जब बाढ़ आती है तो उनकी जमीन भी बाढ़ में चली जाती है। जैसा कि अभी जिक्र किया गया कि खनन की जो बोली रेत और बजरी के लिए दी गई हैं उनके माध्यम से सरकार को 2133 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। सरकार को तो उसका लाभ हो गया और हो सकता है कि बोली लेने वाले ठेकेदार को भी लाभ हुआ हो। लेकिन जिन किसानों की जमीन यमुना नदी के दरिया में चली गई और जो किसान लैंड लैस हो गये जिनके पास अपनी जमीन नहीं रही उनको क्या फायदा हुआ ? मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जब खनन का काम शुरू होगा

और उससे जो सरकार को लाभ हो उसका दस प्रतिशत वहां के किसानों को देना चाहिए जिनकी जमीन इस खनन के एरिया में गई है। अगर ऐसा संभव नहीं है तो उन किसानों को 50 हजार रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से मिलना चाहिए। तब तो उन किसानों को फायदा होगा और इस सरकार को किसानों की सरकार कहा जायेगा। डिप्टी स्पीकर सर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे इलाके में लड़कियों का कोई भी डिग्री कालेज नहीं है और हमारी लड़कियों को कालेज की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 25-30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां बैठी हुई हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि रादौर में लड़कियों का कालेज खोल दिया जाए। इसके अलावा वहां पर एक सरकारी आई.टी.आई. भी खोल दी जाए यह भी सरकार से मेरा अनुरोध है। इसके अलावा एक अनुरोध मैं यह करना चाहता हूं कि रादौर हल्के की सड़कें टूटी-फूटी पड़ी हैं उनको ठीक करवाया जाए क्योंकि वहां पर हर रोज औसतन दो एक्सीडैंटल डैथ हो रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सैनी साहब, आप बैठ जाईये धन्यवाद।

डॉ० बिशन लाल सैनी : डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री धर्म सिंह छोकर (समालखा) : डिप्टी स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो टैक्स फ्री बजट पेश किया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इस बजट के लिए पूरे प्रदेश की गली-गली में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि बहुत ही अच्छा बजट पेश किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां तर्क वितर्क बहुत हो चुका है। सभी सम्मानित सदस्यों ने, पक्ष और विपक्ष ने मिलकर अपनी आत्मा के अनुसार अपनी बात कही लेकिन मैं तथ्यों पर आधारित बात कहना चाहता हूं। शोर मचाने से और व्यक्तिगत कटाक्ष करने से कोई फायदा नहीं होता। सदन की गरिमा को मद्देनजर रखते हुए मैं सम्मानित सदस्यों से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यहां आंकड़ों पर आधारित अपनी बात करें। तर्क वितर्क न करते हुए मैं प्रैक्टिकली बात यहां करना चाहता हूँ। आंकड़ों के हिसाब से हरियाणा सरकार ने और हुड्डा सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं वह किसी से छिपे नहीं हैं। (विघ्न)उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन कामों की बात करूंगा जो हमारी सरकार कर चुकी है। चाहे कृषि की बात हो, चाहे इरीगेशन की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे एग्रीकल्चर की बात हो, चाहे रेलवे लाइनें बिछाने की बात हो, चाहे उद्योगों की बात हो, चाहे गरीबों को 100-100 गज के प्लाट देने की बात हो या मनरेगा की बात हो, मैं तो कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में जो विकास किया है वह किसी से छिपा नहीं है। सरकार ने, वित्त मंत्री ने, कैबिनेट ने, कार्यपालिका ने और हम सबने मुख्यमंत्री की रहनुमाई में ज्वांयट होकर जो बजट पेश किया है और जो विकास कार्य प्रदेश में किए हैं उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। हरियाणा सरकार में पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के लोग कार्यपालिका की बात करते हैं इसलिए इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि कार्यपालिका 4 स्तम्भों में से एक स्तम्भ है। कैबिनेट और कार्यपालिका का तालमेल न होता तो इतना विकास नहीं होना था। आज पूरे प्रदेश में सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है। आंकड़ों पर यहां बहुत तर्क वितर्क हो चुका है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मोटी मोटी बात करना चाहूंगा। सभी ने यहां पावर की बात की, पूरे प्रदेश में सभी को पता है इसलिए एक बात

[श्री धर्म सिंह छोकर]

बार बार कहने से कोई फायदा नहीं होता। पावर में जो डिवैल्पमैंट हुआ है और दूसरे क्षेत्रों में हमारी सरकार ने जो विकास किए हैं वह किसी से छिपा नहीं हैं। जहां तक हम शिक्षा की बात करें तो जितनी यूनिवर्सिटीज और जितने मेडिकल कालेज पूरे प्रदेश में दिए गए हैं उससे साफ झलकता है कि पूरे प्रदेश में एक समान विकास हुआ है। चाहे यमुनानगर की बात हो, गुड़गांव की बात हो, रोहतक की बात हो, पानीपत की बात हो हर जगह एक समान विकास किया गया है। मैं पानीपत जिले के अपने समालखा विधानसभा क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। हमारे यहां जो विकास हुआ है वह किसी से छिपा नहीं है। बपौली में गवर्नमैंट कालेज बनाने की 43 साल पुरानी डिमांड थी। मुख्यमंत्री महोदय ने दरियादिली दिखाते हुए हमारे बापौली में गवर्नमैंट कालेज बनाने की हमारी डिमांड को पूरा किया है जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय और सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा। सरकार ने हमारे समालखा में 100 बैड का अस्पताल बनाने का कार्य किया है जिसके लिए भी मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा। चाहे सड़कें बनाने की बात हो, पावर हाउस बनाने की बात हो, स्टेडियम बनाने की बात हो, मिनी सचिवालय का निर्माण करवाने की बात हो या आर.ओ.बी. बनाने की बात हो, मैं इन सब कामों के लिए अपने विधानसभा हल्के समालखा की तरफ से मुख्यमंत्री महोदय का, सरकार का और वित्त मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे समूचे विधानसभा क्षेत्र का जो विकास करवाया गया है वह अपने आप में एक रिकार्ड है। यहां सदन में बैठकर छींटाकंशी करने से और व्यक्तिगत लांछन लगाने से सदन नहीं चलने वाला, अगर इस तरीके की बातें करनी हैं तो बाहर करनी चाहिए। हमें यहां विकास की बात करनी चाहिए और तथ्यों पर आधारित बात करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में जो विकास किए हैं वह किसी से छिपे नहीं हैं। जो काम हो चुके हैं विपक्ष उन कामों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जो काम हो चुके हैं उसको तो इंसान को मानना ही चाहिए। (विघ्न) मैं बजट की बात करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश का जो विकास किया है उसके बारे में यदि हम तारीफ कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। (विघ्न) मैं आंकड़ों पर आधारित बात कर रहा हूं। प्रदेश में थर्मल प्लांट बने हैं जो किसी से छिपे नहीं हैं। हमारे प्रदेश के खेदड़, झाड़ली और गोरखपुर में थर्मल प्लांट बने हैं और यदि नहीं बने हैं तो विपक्ष के साथी बतायें।

श्री उपाध्यक्ष : छोकर साहब, आप अपनी बात रखें , किसी से पूछें मत।

श्री धर्म सिंह छोक्कर : उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से गन्ने का भाव भी हमारे प्रदेश के किसानों को 301 रुपये प्रति क्विंटल दिया जा रहा है जो कि देश में सर्वाधिक है इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं, कभी झूठ नहीं बोलता। (विघ्न)

श्री कृष्ण लाल पंवार : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है कि भाई धर्म सिंह छोक्कर जी अपने हल्के की बात कर रहे थे जो कि बहुत अच्छी बात है लेकिन इन्होंने साथ ही साथ झाड़ली थर्मल प्लांट का भी जिक्र किया है। इस बारे में मैं वित्तमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, वे अपने बजट रिप्लाई में बतायें कि झाड़ली थर्मल पावर प्लांट में किस-किस स्टेट का कितना-कितना हिस्सा है ?

श्री धर्म सिंह छोकर : उपाध्यक्ष महोदय, कोऑप्रेटिव मिनिस्टर भाई सतपाल सांगवान जी यहां बैठे हुए हैं मैं उनका और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने पानीपत शुगर मिल की पिराई क्षमता 18000 मिट्रिक टन से बढ़ाकर 30000 मिट्रिक टन की है जो कि वहां के किसानों की 40 साल पुरानी मांग थी। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक हैल्थ की बात है समालखा में 100 बैड के हॉस्पिटल की फाउंडेशन हमारे मुख्यमंत्री जी ने रखी है इसके लिए भी मैं स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसी तरह से स्वास्थ्य मंत्री जी ने मेरे हल्के के बापौली और नरायना में सी.एच.सी. देने का काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की उपलब्धियों को गिनाना कोई गलत बात नहीं है। मैं तथ्यों पर आधारित बात कर रहा हूं। मेरे माननीय साथी पंवार साहब बैठे हैं जो असंध का प्रतिनिधित्व करते हैं। चाहे एजूकेशन की बात हो, चाहे हैल्थ की बात हो, चाहे स्पोर्टस की बात हो यानि हर क्षेत्र में कार्य हुए हैं और उनकी तारीफ सभी को करनी चाहिए। विपक्ष के साथियों को भी मुख्यमंत्री जी और वित्तमंत्री जी की तारीफ करनी चाहिए कि इन्होंने इतना अच्छा बजट प्रदेश के लोगों को दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी बजट का समर्थन करता हूं और वित्त मंत्री जी को फिर से धन्यवाद करते हुए अब मैं अपने हल्के की कुछ मांग रखना चाहता हूं। मेरे हल्के के हथवाला से खेड़ी मांगलपुर के पुल को बनाने के बारे में मंत्री जी ने पिछले सैशन में मेरे प्रश्न का जवाब हां में दिया था। यह पुल दो स्टेट्स को जोड़ता है। इसको बनाने का प्रस्ताव सरकार ने एन.सी.आर. को प्रस्ताव भेजा हुआ है इसलिए इसको जल्दी से जल्दी टेकअप करके बनाया जाये। इसी तरह से समालखा में जो चुलकाना का फलाईओवर है वह शहर में रेलवे रोड़ को इंटर करता है वहां एन.एच.-71 पर नैशले के पास आर.ओ.बी. बनाने की मांग करता हूं। इसी तरह से हमारे समालखा में केवल एक आई.टी.आई. है इसलिए वहां पर पालिटेक्निक बनाने की भी मैं मांग करता हूं। हमारी शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने हमारे बापोली में गवर्नमैंट कालेज और जलमाने में कस्तुरबा गांधी बालिका स्कूल, छाजपुर में सरकारी मॉडल हाई स्कूल और कुआना में केन्द्रीय स्कूल बनाना स्वीकार किया है इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। इसी प्रकार से आटा में किसान मॉडल स्कूल बनाया गया। इसके लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। जहां तक डिवैल्पमैंट की बात है हमारे विपक्ष के साथियों को सच्ची बात सुन लेनी चाहिए इसमें बहस करने का कोई मुद्दा नहीं है। हम सच बात कहते हैं। हम झूठ नहीं बोलते हैं। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : छोकर जी, आप कृपया कनकल्यूड कीजिए।

श्री धर्म सिंह छोकर : डिप्टी स्पीकर सर, ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूं। आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अनिल विज (अम्बाला कैंट) : स्पीकर सर, जो विधान सभा में बजट प्रस्तुत किया गया है यह पूरी तरह से विज़नलैस बजट है। आंकड़ों को तोड़-मरोड़ कर पेश करके लोगों को गुमराह रखने की कोशिश इस बजट के माध्यम से की गई है। मैं इस बजट पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। डिप्टी स्पीकर सर, जब यह बजट प्रस्तुत किया जा रहा था उस समय सत्ता पक्ष के साथियों द्वारा बहुत ज्यादा तालियां बजाई गई और मीडिया में जाकर भी बहुत से दावे किये गये कि हमने एक बहुत बड़ी प्लॉन बढ़ाकर बजट के माध्यम से प्रस्तुत की है और यह भी बताने की कोशिश

[श्री अनिल विज]

की गई है कि हरियाणा सभी मामलों में पहले पायदान पर है इसके समर्थन में अनेकों आंकड़ें भी प्रस्तुत किये गये हैं। मैं भी आंकड़ों के माध्यम से ही कुछ बातें बताने की कोशिश करूंगा लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना भूल गया। मैं आपके माध्यम से चड्ढा साहब को यह कहना चाहता हूं कि यह जो हमें बजट सी.डी. के रूप में दिया गया है ये बजट की सी.डी. किसी भी कम्प्युटर पर नहीं खुल रही हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें इसकी हार्ड कापी भी उपलब्ध करवानी चाहिए। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)** अध्यक्ष महोदय, जब तक बजट की सी.डी. ही न खुले तो हम किस प्रकार से और किस आधार पर तथ्यों को प्रमाणित करके यहां पर बोलें। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे भी इस सी.डी. को चलाकर देखें। इसमें जो खास तौर पर इकानामिक सर्वे था उसको देखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि कल क्या करना है यह तो आने वाला कल ही बतायेगा लेकिन कल क्या किया है यह इकानामिक सर्वे ही बताता है और इसकी जो हमें सी.डी. प्रोवाईड की गई है वह मैंने कई कम्प्युटरों में चलाकर देखी लेकिन वह कहीं पर भी नहीं चली। (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : स्पीकर सर, माननीय सदस्य कहीं ये उस सी.डी. को खराब कम्प्युटर में तो चलाकर नहीं देख रहे हैं।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, we have given Lap Tops to every Hon'ble Member. Yes, Mr. Vij, please continue.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, जिस लैप टॉप में मैंने वह सी.डी. चलाई है वह सरकार द्वारा ही दिया गया है और मेरे से ज्यादा यहां पर कोई माननीय सदस्य अच्छी तरह लैप टॉप चलाना नहीं जानता होगा। सर, मैं यह कहने जा रहा था कि ये जो आंकड़ें बजट ऐट ए ग्लांस में प्रस्तुत किये जाते हैं वह बजट ऐट ए ग्लांस मैं वर्ष 2013-14 और वर्ष 2014-15 दोनों सालों का लाया हूं। इनसे यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से यहां पर जो योजनायें प्रस्तुत की जाती हैं वास्तविकता में उनका क्या हश्र होता है। यह मैं सदन को दिखाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग के प्लान और नॉन प्लान के लिए वर्ष 2012-13 के लिए 2031.23 करोड़ रुपये रिवाईज्ड ऐस्टीमेट्स में ऐलोकेट किये गये लेकिन जो एक्च्यूअल खर्च हुआ वह 1059.66 करोड़ रुपये खर्च हुआ। उसी प्रकार से अगर पॉवर की बात की जाये पॉवर के लिए 5805.89 करोड़ रुपये के रिवाईज्ड ऐस्टीमेट्स प्रस्तुत किये गये थे लेकिन उसके विरुद्ध एक्च्यूअल एक्सपैंडीचर 5412 करोड़ रुपये का हुआ। इसी प्रकार से एजूकेशन एण्ड स्पोर्टस के लिए जो रिवाईज्ड ऐस्टीमेट्स प्रस्तुत किये गये वे 7578.44 करोड़ रुपये के थे और जो एक्च्यूअल खर्च किया गया वह 5181 करोड़ रुपये खर्च किया गया। अध्यक्ष महोदय, अब मैं टोटल बजट के बारे में बताना चाहता हूँ। जो टोटल आउटले किया गया वह वर्ष 2012-13 के लिए 56962.11 करोड़ रुपये था और जो एक्च्यूअल एक्सपैंडीचर हुआ वह 50653.69 करोड़ रुपये हुआ है। इस प्रकार जो एक्च्यूअल एक्सपैंडीचर है वह लगभग 6000/- करोड़ रुपये कम हुआ है। यही मामला, यही सिलसिला सभी योजनाओं में है, यहाँ पर योजना पेश की जाती है और तालियाँ बजाई जाती हैं कि हमने सबसे बड़ी प्लान प्रस्तुत कर दी लेकिन वास्तविकता में जब वह 2-3 साल के बाद क्लोजिंग होती है और जब एक्च्यूअल फिगर आते हैं तो वह 5-10 हजार करोड़ रुपये कम होती है। इसी

तरह से पिछले साल जो प्लान प्रस्तुत की गई थी उसका एक्सपैंडीचर केवल 52 प्रतिशत हुआ है जो कि बहुत कम है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। हम आंकड़े प्रस्तुत कर देते हैं लेकिन उनकी वास्तविकता सच्चाई से बहुत परे होती है। यह जो कट लगता है यह जो पैसा काटा जाता है इससे विकास कार्यों पर बहुत असर पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से प्लान के बारे में बताया गया है, मैं उसके आंकड़े भी बताना चाहता हूँ। यहाँ पर दावा किया गया कि हमारी प्लान सबसे अच्छी है, हम बाकी स्टेटों से आगे हैं। स्टेट तो छोटे और बड़े हो सकते हैं और जनसंख्या भी कम या ज्यादा हो सकती है। Annual Plan with respect to percentage of GSDP अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो आँकड़े हैं उनके अनुसार वर्ष 2012-13 में हरियाणा की परसैंटेज है वह 7.52 परसैंट है। मैं किसी से तुलना नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं तुलना करूँगा तो फिर ये लोग उठ खड़े होंगे। मैं कुछ आंकड़े बता रहा हूँ। गुजरात की जी.एस.डी.पी. 7.28 परसैंट है और गोवा की 11.(विघ्न)

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी सदन को गुमराह करते हैं, इनको जाना है रेवाड़ी और इन्होंने बस करनाल वाली पकड़ ली है। इनको अपनी जन्म भूमि की व अपनी कर्म भूमि की बात करनी चाहिए व अपनी विधान सभा की बात करनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, ये बातें माननीय साथी श्री नरेश शर्मा की समझ से परे की हैं, ये इनकी समझ में आने वाली नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली : स्पीकर सर, जब हरियाणा के हितों की बात होती है, मार्गदर्शन होता है तो विज साहब खराट्टे भरते रहते हैं।

श्री अनिल विज : सर, श्री नरेश जी के मुंह के ऊपर कुछ लगाएंगे। (शोर एवं व्यवधान)

सहकारिता मंत्री (श्री सतपाल) : सर, मुंह पर तो मेरे भाई विज साहब के कुछ लगाने की जरूरत है क्योंकि इनको केवल गुजरात का ही विकास नजर आता है इसलिए इनको भी वहीं गुजरात में भेज दो। सर, कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं आज बताता हूं कि ये गुजरात और बी.जे.पी. वाले कैसे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं डाटा के आधार पर बोल रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Anil Vij, your time is over. आपको बोलते हुए दस मिनट हो गए हैं।

श्री अनिल विज : सर, मुझे बोलते हुए अभी दो मिनट भी नहीं हुई है आप चाहे घड़ी को देख लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां मैंने घड़ी को देख लिया है। आप केवल तीन मिनट और बोल सकते हो।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मुझे बोलते हुए 10 मिनट हुए हैं उनमें से पांच मिनट दूसरे मैंबर साहिबान ने बीच में बोल कर खत्म कर दी। सर, मैं कोई इररैलिवैंट नहीं बोल रहा और न ही मैं मंच पर कोई भाषण दे रहा हूं। मैं तो आपको आंकड़ों के साथ बात बता रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप गुजरात के डाटा मत बताओ यहां हरियाणा के डाटा बताओ।

श्री अनिल विज : सर, मैं बाकी स्टेट्स के भी डाटा बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : हां ठीक है बता दो।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, गोआ की 11.42 प्रतिशत ,छत्तीसगढ की 14.66 प्रतिशत, बिहार की 9.51 प्रतिशत है। This is like this कि जो एक्च्यूअल ग्रोथ मानी जाती है वह percentage to GSDP मानी जाती है उसमें हमारा हरियाणा काफी पीछे हैं। हम पहले पायदान पर नहीं है जैसा कि बताया जाता रहा है। मैं सारी स्टेट्स का स्टेटवाईज ग्रोथ rate of agriculture and allied sectors in India का डाटा लाया हूं। हरियाणा की ग्रोथ 4.22 प्रतिशत है और फिर इनको तकलीफ होगी गुजरात की 6.47 प्रतिशत है। (शोर एवं व्यवधान) सर, हरियाणा के बाद एल्फाबेटिकली नाम ही गुजरात का आता है। इससे इनको किस बात की तकलीफ है। उसके बाद छत्तीसगढ की ग्रोथ 7.36 है। सर, मैं कम्पैरिजन कर रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान) आप जो कहते हैं कि हरियाणा नम्बर-1 है मैं उसके लिए कह रहा हूं कि अभी आपको प्रदेश के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। सर, उसी प्रकार से मेरे पास बाकी के आंकड़े भी हैं आपने बोलने नहीं देना इसलिए मैं मुद्दे की बात पर आता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप अम्बाला की बात क्यों नहीं करते।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं सारे स्टेट्स की बात करता हूं और अम्बाला की भी करूंगा। जो बजट प्रस्तुत किया जाए उसमें 5 चीजों पर मुख्य रूप से जोर दिया जाना चाहिए। सर, जिस प्रकार से आज राईट टू एजूकेशन और राईट टू फूड है उसी प्रकार से राईट टू पांच चीजें हैं सड़क, नाली , लाईट, सफाई, और पीने का पानी। इन पांच चीजों के ऊपर सरकार द्वारा ज्यादा बजट एलोकेशन किया जाना चाहिए। अगर बजट विधान सभा अनुसार प्रस्तुत किया जाए तो और भी ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि अलग-अलग विधान सभाओं की अलग-अलग परिस्थिति हो सकती है और जो इस प्रकार का आरोप लगता है कि भेदभाव होता है ये होता है वो होता है यह सारी बातें भी खत्म हो जाएंगी। सर, हर आदमी को घर जाने के लिए सड़क तो मिलनी चाहिए लेकिन आज सैंकड़ों ऐसे लोग हैं। जिनको यह सुविधा नहीं मिल रही है। स्पीकर सर, आज आजादी के 65 वर्षों के बाद भी हम लोगों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध नहीं करा पाये हैं। सदन के सभी 90 के 90 विधायकों के पास जितनी समस्यायें आती हैं उनमें से 95 प्रतिशत समस्यायें तो इन पांच चीजों (सड़कें, नालियां, लाईट, सफाई व पानी) से ही संबंधित होती हैं। अगर मैं गलत हूँ तो कोई भी माननीय सदस्य इस हाउस में उठकर बता सकता है? वक्त की जरूरत है कि हमें बजट में बाकी चीजों पर फंड एलोकेशन करने की बजाय सबसे पहले प्राथमिकता मेरे द्वारा अभी थोड़ी देर पहले बताई गई पांच चीजों (सड़कें, नालियां, लाईट सफाई व पानी) को देनी चाहिए। (विघ्न)

Mr. Speaker : Thank you, Vij ji. Please sit down. (Interruption)

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, विज साहब को बोलने दीजिये?

Mr. Speaker : Kavita Ji, Can I give your time to Mr. Vij ?

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, आप हमारी पार्टी के नेता गुर्जर साहब का समय विज साहब को दे दीजिये? (हंसी)

श्री अध्यक्ष : नहीं मैडम मैं आपका समय ही विज साहब को दूंगा। गुर्जर साहब का समय विज साहब को इसलिए नहीं दे सकता हूँ because Mr. Gurjar is not present in the House. (Interruption)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं कोई औचित्यहीन बात तो सदन में नहीं कर रहा हूँ। (विघ्न) अगर आप आज्ञा दें तो मैं हल्के की दो चार बातें और कहना चाहता हूँ?

Mr. Speaker : Yes, Mr. Vij, I am also saying you to speak about your constituency.

श्री नरेश कुमार बादली : स्पीकर सर, अनिल विज तो स्पीच दे रहे हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : नरेश जी, माननीय सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात कर रहे हैं इसलिए आप द्वारा विघ्न डालना ठीक नहीं है।

श्री नरेश कुमार बादली : स्पीकर सर, मैं तो केवल आपसे बोलने के लिए आज्ञा ही मांग रहा था।

श्री अनिल विज : धन्यवाद, स्पीकर सर। मैं बस दो चार बातें अपने निर्वाचन क्षेत्र की कहकर बैठ जाऊंगा। सर, जब मैंने कालिंग अटैंशन मोशंज दिये थे तो आपने मुझे कहा कि आप बजट पर सारी बातें बोल सकते हैं। आपने मेरे कालिंग अटैंशन मोशंज डिसअलाऊ कर दिये। फिर आपने मुझे कहा कि मैं गवर्नर एड्रैस पर बोल सकता हूँ। स्पीकर सर, मैंने जो कालिंग अटैंशन मोशंज दिये थे वह बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मेरा कर्मचारियों के बारे में कालिंग अटैंशन मोशन था... (विघ्न)

Mr. Speaker : Vij ji, please speak about Ambala.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, कर्मचारी तो अम्बाला में भी हो सकते हैं? कर्मचारियों की बहुत सारी मांगे हैं... (विघ्न)

Mr. Speaker : I am giving you two extra minutes so that you can talk about Ambala. I have requested you to direct your speech about Ambala. As you represent Ambala, so you should speak about Ambala.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, आप मेरे लिए समय सीमा तो निर्धारित कर सकते हैं लेकिन मैं क्या बोलूं और क्या न बोलूं इसके लिए आप मुझे बाध्य नहीं कर सकते हैं? Sir, It is my right.

Mr. Speaker : Vij ji, alright please conclude it in two minutes.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, कर्मचारियों के बारे में बहुत सी बातें सामने आई हैं। सर, हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी पंजाब के बराबर वेतन चाहते हैं। इसी तरह की इच्छा हमारे पुलिस पर्सोनल्ज की भी है। मेरे पास डिप्लोमा इंजीनियर एशोसियेशन का एक लैटर है। इन्होंने आर.टी.आई. के माध्यम से जो सूचना प्राप्त की है उस सूचना के हिसाब से पता चलता है कि वेतन के लिहाज से पूरे प्रदेश में वे अपने आपको 28वें पायदान पर पाते हैं। They rank on 28th Number. हम कहते हैं कि हरियाणा नं०-1 स्टेट है। इस तरह की स्टेट्स को देखकर क्या हम स्वयं को नं०-1 की पायदान पर खड़ा पाते हैं? नम्बर-1 स्टेट वह होता है जिसके कर्मचारियों को

[श्री अनिल विज]

सबसे ज्यादा वेतन दिया जाता हो। अब मैं रजिस्ट्रयों में होने वाली धांधलियों पर भी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मैंने गवर्नर एड्रेस पर चर्चा के समय भी यह मुद्दा सदन में उठाया था। आज हरियाणा प्रदेश में रजिस्ट्रियाँ करने पर पाबंदी लगाई गई हैं परन्तु बावजूद इसके भी प्रदेश की हर तहसील में 50-50 हजार रुपये देकर रजिस्ट्रयाँ करवा दी जाती हैं। मेरे क्षेत्र अम्बाला में इस तरह की रजिस्ट्रियाँ होना एक आम बात हो गई है। आप इसकी जांच करवाकर यदि देखेंगे तो पायेंगे कि एक महीने के अन्दर 4-5 करोड़ रुपया दो नम्बर में लोगों द्वारा कमाया जा रहा है। यह पैसा किन लोगों की जेबों में जा रहा है यह तो सरकार ही जांच करके पता कर सकती है। प्रश्न यह उठता है कि यदि 50 हजार रुपये देकर रजिस्ट्रियाँ हो जाती हैं तो फिर आम आदमी की बिना पैसे दिये रजिस्ट्रियाँ क्यों नहीं की जा रही हैं? (विघ्न)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि यदि उनके पास कोई इस संबंध में शिकायत हो तो वह लिखकर हमें भेज सकते हैं। मैं हाउस के माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वास्त करना चाहूँगा कि ऐसी किसी भी शिकायत पर इंक्वॉयरी करवाई जायेगी, बशर्ते शिकायत लिखकर जरूर भेज दें। वैसे आज तक तो इनकी तरफ से कोई शिकायत लिखकर आई नहीं है? मैं खुद इस तरह की गैरकानूनी चीजों का घोर विरोधी रहा हूँ। यदि हमें कोई भी शिकायत प्राप्त होती हैं तो मैं ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस कहना चाहता हूँ कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं आज इस सदन में जो कुछ भी बोल रहा हूँ वह सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है। अत: इस लिखित रिकॉर्ड को ही मेरी शिकायत समझ लिया जाये।(शोर एवं व्यवधान) यह ऑन रिकॉर्ड की बात है।(शोर एवं व्यवधान)

सहकारिता मंत्री (श्री सतपाल) : स्पीकर सर, ऐसे थोड़ा होता है। यदि विज साहब लिखकर शिकायत दें कि फलां व्यक्ति ने रजिस्ट्री कराने के लिए फलां व्यक्ति से पैसे लिये हैं तो उसे ही शिकायत माना जा सकता है (शोर एवं व्यवधान) मुंह जुबानी तो यह किसी भी व्यक्ति का नाम दे सकते हैं। बात तो तभी बनेगी जब यह लिखकर अपनी शिकायत देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं अम्बाला कैंट तहसील की. . . . (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, यदि विज साहब अपने द्वारा कही गई बात को सिद्ध करने के लिए कोई पर्टीकुलर (कागज-पत्र) प्रोवाईड करें या फिर किसी सपैस्फिक रजिस्ट्री के बारें में बतायें तो मैं उसकी इंक्वॉयरी करवाऊंगा and we will reach to some conclusions. (शोर एवं व्यवधान) केवल आरोप लगाने से अपराध सिद्ध नहीं हुआ करते हैं।(शोर एवं व्यवधान) विज साहब आप किसी कर्मचारी/अधिकारी का नाम बताओ या फिर किसी रजिस्ट्री का नम्बर बताओ, उसको बेस बनाकर ही तो एक्शन लिया जायेगा?(शोर एवं व्यवधान) इस तरह से शोर-शराबा करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है।(शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Mr. Vij, have you any specific allegation? If you have, I will order an enquiry for that.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि आप इस दरमयान जबकि रजिस्ट्रियों पर पाबंदी लगी हुई है, उन सभी रजिस्ट्रियों की जांच करवायें और पता लगायें कि ये रजिस्ट्रियाँ किन बेसिज पर की गई हैं? (विघ्न)

Shri Bhupinder Singh Hooda : Speaker Sir, Shri Anil Vij may give me particular registries and name of erring officers. I will take action against them.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं तो बस यह जानना चाहता हूँ कि जब पूरे प्रदेश की जनता के लिए रजिस्ट्रियां बंद हैं तो रजिस्ट्रियों के बंद वाले समय में भी किन बेसिज पर रजिस्ट्रियां की गई हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सतपाल : स्पीकर सर, आपने विज साहब को बोलने के लिए क्या केवल इसलिए ही अलाऊ किया है कि यह कुछ भी बोलता रहे? It is not good. Although, he is a senior member of this House, he does not know how to talk in the House. It is totally wrong. He should not blame any body. (Noise & Interruption)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं माईनिंग की बात करना चाहता हूँ कि माईनिंग खुली हुई है, उसके ठेके भी हो चुके हैं (विघ्न)। मैं कहना चाहता हूँ कि माईनिंग इतनी महंगी बिकी है कि हमें माईनिंग के टैंडर्ज एलॉट करने से पहले रेत की ट्रॉली कितने में बिकेगी और बजरी की ट्रॉली कितनी में बिकेगी यह तय करना चाहिए था। अगर माईनिंग खुलने के बाद भी आज वहीं चार हजार रुपये की ट्रॉली बिकेगी तो लोगों को इसका क्या फायदा हुआ। जितने भी टैंडर्ज आज तक हो चुके हैं, सारे टेंडर्ज रद् करके दोबारा टेंडर्ज करवाये जायें और उनके रेट फिक्स किये जायें। उसके बाद ठेकेदार को कहा जाये कि 400 रुपये की ही ट्रॉली बेचनी है। अब बोली लगाओ, बोली कितने की लगाओगे? तब उनको टेंडर्ज एलोकेट किये जायें। अध्यक्ष महोदय, अब मैं राईट टू फूड के बारे में कहना चाहता हूँ कि डिपो होल्डर्स को पूरा अनाज नहीं मिल पा रहा है। मुझे बाकी हरियाणा का तो पता नहीं हैं अम्बाला कैंट के बारे में मैं जानता हूँ।

Mr. Speaker : Thank you Mr. Vij, you have taken 20 minutes instead of 10 minutes.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं बोल सकता हूँ। क्योंकि आप बोल देंगे कि Nothing is to be recorded. स्पीकर सर, आज तक मेरे 20 साल के कैरियर में बजट पर एक दिन की डिरकशन कभी नहीं हुई है * * * * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded beyond this.

श्री अनिल विज : * * * * * * * *

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका हार्दिक रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। हरियाणा प्रदेश का जन कल्याकारी बजट सरदार हरमोहिन्दर सिंह चड्ढा वित्त मंत्री जी ने पेश किया है। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा 36 बिरादरी के हृदय सम्राट है। मैं इन दोनों के नेतृत्व को हरियाणा किंग और हरियाणा सिंह का तालमेल, विदूर की नीतियों से, सलाह से और योग्य रूप से हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री और चुने हुये

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री नरेश कुमार बादली]

जन प्रतिनिधियों का प्रचण्ड बहुमत मानता हूँ। आदरणीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने जो 36 बिरादरी और हरियाणा प्रदेश की महान जनता जनार्धन और महान मतदाता, गाँवों में बसने वाले भोले-भाले किसान भाई, गरीब हरिजन भाई, पिछड़े वर्ग के दलित भाई तथा मजदूरों की पीड़ा, वेदना, दु:ख-दर्द को समझा है। प्रदेश के हर वर्ग की जरूरत को समझते हुये, उनकी समस्याओं का समाधान किया है। उनकी भलाई, विकास के कल्याण हेतू, उनके बच्चों की शिक्षा, साक्षरता और अच्छे स्वास्थ्य,विकास और रोजगार, रोजी-रोटी, कपड़ा और मकान देने का काम किया है। हमारे माननीय सदस्यों और जन प्रतिनिधि लोकप्रिय सरकार ने जो हरियाणा प्रदेश की तरक्की, उन्नति में 36 बिरादरी और हर वर्ग के कल्याण के लिए जो यह बजट प्रस्तुत किया गया है। इसके लिए मैं हरियाणा सिंह और हरियाणा किंग को ढेर सारी बधाईयाँ देता हूँ और उनका आभार प्रकट भी करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2005 से पहले का बजट 2200 करोड़ रुपये का था। आज जनकल्याणकारी सरकार, जनता की सरकार, हर गरीब आदमी की सरकार और 36 बिरादरी की सरकार ने 32,700 करोड़ रुपये का जो बजट रखा है, यह अपने आप में एक बेमिसाल है। मैं माननीय विपक्ष के साथियों से आग्रह करूँगा कि वे सच्चाई को सुनने की हिम्मत रखें न कि सदन से भागने की कोशिश करें। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार की दूरदर्शी नीतियों के फलस्वरूप सभी मुख्य आर्थिक संकेतकों में राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक सुधार हुआ है। प्रदेश के मेहनतकश किसानों ने खाद्यान्नों और दूसरे कृषि उत्पादों की रिकॉर्ड पैदावार की है। हरियाणा के लोगों को गुणवत्तापरक शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना हरियाणा सरकार की उपब्धियों को दर्शाता है। विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल तथा तकनीकी शिक्षा संस्थानों का दर्जा बढ़ाया गया है। अध्यक्ष महोदय, जो मेरे सम्मानित साथी प्रजातांत्रिक प्रणाली से चुनकर आए हैं, बड़े सीनियर नेता हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जब एक विधायक सरकार की नीतियों से सदन को अवगत करवाना चाहता है तो विपक्ष के साथियों में सदन को छोड़ने की बजाय सच्चाई को सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि विपक्ष के सदस्यों को प्रजातंत्र का कुछ तो लिहाज करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के बारे में कह रहा हूँ उसमें विपक्ष के सदस्य विघ्न डालने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये अपनी आदतों से मजबूर हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वॉयंट ऑफ आर्डर है।

Mr. Speaker : Shri Naresh Ji, there is a point of order.

श्री कृष्ण लाल पंवार : सर, मेरे पास एक चिट्ठी है, इसमें लिखा हुआ है कि* * * *

श्री अध्यक्ष : यह कोई प्वॉयंट ऑफ आर्डर नहीं है। It is not a point of order. (Interruption). Hon'ble Member, please read the Law of point of order and then raise the point of order. Please send this letter to me. I will decide whether it is a point of order or not? (Interruption). Naresh Ji, please speak only on Budget. (Interruption).

श्री नरेश कुमार बादली : स्पीकर सर, * * *

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Hon'ble Member, please speak only on Budget.

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, माननीय साथी बजट के अलावा ही सारी बातें कह रहे हैं। इनका बजट से कोई लेना-देना नहीं है इसलिए उनको कृपया करके सदन की कार्यवाही से निकाला जाये। (विघ्न) माननीय साथियों को बजट पर चर्चा के दौरान बजट पर ही अपने विचार रखने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, जो बजट के अलावा उन्होंने बातें कही हैं, उनको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री नरेश बादली ने जो बातें बजट से हटकर कही हैं ये सारी की सारी बातें आपने रिकार्ड में हटवा दी हैं, इनसे आप इस बात के लिए बाकायदा तौर पर कहें कि वे बजट के ऊपर ही अपनी बात कहें। सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें जो कमियां, खामियां रह गई हैं उन पर चर्चा करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये आखिरी सैशन है, अखबार वाले भी इन बातों को देखेंगे।

Mr. Speaker: Whatever said by Mr. Naresh Badli which is not related to budget, may not to be recorded. (Interruption). Let him speak on budget.

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा सरकार ने लोगों की सेवा नेक इरादों से की है, हमें पूर्ण विश्वास है कि हम जनता की सेवा करने में, जनता का समर्थन और विश्वास हासिल करने में कामयाब रहे हैं। अक्टूबर, 2014 में होने वाले विधान सभा चुनाव में इन नेक कामों के लिए हरियाणा सरकार को हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी का अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त है और जनता इन कामों के लिए तीसरी बार हमें मौका देने जा रही है। हमारे काम से, सरकार के काम से पता चलता है कि सरकार ने वादे नहीं काम किए हैं और जो भी वादे किए हैं उन्हें पूर्ण करने का काम किया है। वर्ष 2014-15 के लिए 32031.29 करोड़ रुपये की योजना के परिव्यय का प्रस्ताव कर रखा है वह वर्ष 2013-14 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 24135.42 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। जैसा मैं कह रहा था कि हमारे से पहले की जो सरकार थी उसने 2200 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था और आज 32700 करोड़ रुपये का बजट है। (विघ्न)

Mr. Speaker : Please speak on budget. आप अपने हल्के की बात कहें।

श्री नरेश कुमार बादली : स्पीकर सर, 2200 करोड़ रुपये के बजट के स्थान पर 32700 करोड़ रुपये का बजट दर्शाता है कि हरियाणा सरकार ने उन्नति और तरक्की का काम किया। हमारे पास कोई नोटों की मशीन नहीं है और न ही कोई जादू की छड़ी है। यह हरियाणा सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का परिणाम है। सरकार ने ईमानदारी के साथ जो मेहनतकश लोगों की, कर्मचारियों की, अधिकारियों की, उद्योगपतियों की हर वर्ग की जो खूनपसीने की गाढ़ी कमाई है उसमें से सरकार को जो कोष मिलता है उसका सरकार द्वारा सही सदुपयोग किया जाता है और सही रूप में जनता के हितों के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, आप मुझे अपनी बात रखने के लिए दो मिनट का समय दे रहे हैं इस पर भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, तीन मिनट का समय दे दें तो और अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : नरेश जी, आप बैठ जाएं मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, बादली विधान सभा क्षेत्र मेरी जन्म भूमि भी है मेरी कर्म भूमि भी है, और पवित्र स्थान भी है। बरसों से हमारे बुजुर्गों की एक मांग थी। हमारे बड़े बुजुर्गों में से एक चित्रसेन सैनी थे, उनकी भी एक बहुत पुरानी मांग थी। मेरे हल्के से बहुत सारे नेता चुने गए, पक्ष विपक्ष के भी साथी वहां से रहे। वहां से हमारे एक नवयुवक दीपेन्द्र सिंह हुड्डा एम.पी.बने और वे उस मांग से अवगत हुए और उन्होंने एक संकल्प लिया कि हमारे बुजुर्ग तो स्वर्ग सिधार गये और इस इलाके के लोगों को कोई आश्वासन नहीं मिला और आश्वासनों के बोझ के नीचे इन लोगों की मांग दबती रही। इसलिए मैं संकल्प लेता हूं कि यहां पर रेल चलाऊंगा ही नहीं बल्कि झज्जर और बादली के बीच में रेल सीटी मारेगी और मैं उसमें स्वयं बैठकर आऊंगा। अब वहां पर रेल चल पड़ी है। कुछ हमारे साथी जातिवाद और क्षेत्रवाद का जहर घोल रहे हैं। मैं मेरे साथियों से यह आग्रह करना चाहूंगा कि जनता की सरकार ने और जन नायक चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने समूचे हरियाणा प्रदेश का विकास किया है। इन्होंने पूरे हरियाणा में एक-एक ब्लॉक, एक-एक तहसील, एक-एक जिला और एक-एक गाँव का विकास किया है। जिसके बारे में यह बजट दर्शाता है कि हमारे जन कल्याणाकारी सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा जी का बजट और किंग का बजट जो बड़े तालमेल के साथ पेश किया गया है वह हरियाणा प्रदेश के अन्दर तरक्की और उन्नति का रास्ता प्रशस्त करेगा (विघ्न)

Mr. Speaker : Naresh ji, your time is over. Please take your seat. I am inviting the next speaker. Mr. Arora, you may speak now.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा (थानेसर) : धन्यवाद,स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर चर्चा करने के लिए मौका दिया। स्पीकर सर, जब भी सरकार का कोई बजट पेश होता है तो उस पर प्रदेश की जनता को बहुत उम्मीदें होती हैं कि हमारे वित्त मंत्री जी बजट पेश करने जा रहे हैं उसमें प्रदेश की जनता के लिए क्या-क्या किया गया है। आज सबसे ज्यादा अगर प्रदेश की जनता बुरी तरह ग्रस्त है तो वह महंगाई और भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। इस बजट में महंगाई को रोकने के लिए क्या कोई कदम उठाये गये हैं और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कोई कदम उठाये गये हैं। सरकार के बजट को अगर गौर से देखा जाए तो इस बजट में न तो महंगाई को रोकने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं और न ही भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि पिछली सरकार के समय में 2200 करोड़ रुपये का बजट था जिसको आज सरकार ने बढ़ाकर 32700 करोड़ रुपये कर दिया गया है। स्पीकर सर, प्रदेश की सरकार को इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आज सरकार का बजट 32700 करोड़ रुपये हो गया। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहूंगा कि जब वे बजट पर अपना रिप्लाई दें तो कृपा करके सदन को यह बता दें कि 32700 करोड़ रुपये का बजट बढ़ाने में सरकार का क्या योगदान है। पिछले नौ साल में न तो प्रदेश में कोई नई इण्डस्ट्री लगाई गई है, न ही कोई बाहर से किसी ने निवेश ज्यादा किया है। स्पीकर सर, लगातार महंगाई बढ़ती गई। जब चौधरी ओमप्रकाश चौटाला की सरकार ने वैट लगाया था उस समय वर्तमान सरकार के सदस्यों ने उसका विरोध किया था कि जो यह सरकार ने वैट लगाया है। जब हमारी सरकार आयेगी तो हम इस वैट को खत्म कर देंगे। वैट लगने के कारण टैक्स कलैक्शन बढ़ा है जिसकी वजह से यह बजट बढ़ा है। जिसकी आज सरकार वाहवाही लूट रही है कि हमने बजट बढ़ा दिया है। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है। आज सारे देश के अन्दर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और आन्दोलन शुरू हुआ है कि

भ्रष्टाचार खत्म होगा। परन्तु स्पीकर सर, इस हाउस के अन्दर माननीय मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर यह कहा था कि जिस माननीय सदस्य के खिलाफ जो भी आरोप लगे हैं उनके केस की इन्क्वायरी वे लोकायुक्त को दे देंगे। स्पीकर सर, अब लोकायुक्त की रिपोर्ट भी आती है और सरकार उस रिपोर्ट को दोबारा से लोकायुक्त को पुन:विचार के लिए भेज देती है। स्पीकर सर, उस रिपोर्ट पर पुन:विचार करने के बाद भी हरियाणा सरकार के चीफ पार्लियामेंट्री सचिव के ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज करने लिए लोकायुक्त ने रिकमैण्ड किया है। परन्तु स्पीकर सर, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस रिपोर्ट पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उसके बाद पांच एम.एल.एज. के खिलाफ नोटिस हो गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जब वे अपना रिप्लाई दें तो इसके बारे में भी कम से कम जिक्र जरूर करें। (विघ्न)

श्री नरेश कुमार बादली : स्पीकर सर, क्या अरोड़ा साहब बजट पर बोल रहे हैं?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मैं बजट पर ही बोल रहा हूं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अब मैं महंगाई का जिक्र करना चाहता हूं। आज महंगाई से लोग बुरी तरह ग्रस्त हैं। इस बजट में सरकार द्वारा एक बात दिखाई गई है कि 2133 करोड़ 93 लाख रुपये हमने माइनिंग की आक्शन से इकट्ठा किया। इस पर बहुत बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है कि हमने 2133 करोड़ 93 लाख रुपये इकट्ठे किए। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा मैंने पिछले बजट में भी कहा था आप माइनिंग की ऑक्शन कीजिए परंतु ऑक्शन करने से पहले आपकी जो नीति बने उसमें यह जरूर लिख दिया जाए कि ऑक्शन के ठेकेदार आक्शन दें परंतु मैक्सीमम रिटेल प्राइज ये होगा। 2133 करोड़ रुपये किसकी जेब से जाएगा इस पर कैप लगाने की मैंने मांग की थी। उस समय भी मैंने मांग की थी और मैं आज भी मांग करता हूं कि इस पर कैप लगाओ और इसकी बोली को रद्द करो क्योंकि 2133 करोड़ रुपये लोगों की जेब से जाएंगें और महंगाई और बढ़ेगी। बिजली के रेट बढ़ा देते हैं फिर कहते हैं कि हम महंगाई कम करने के प्रयास करेंगें। इनके प्रधानमंत्री मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री महंगाई कम करने में हमारा योगदान दें। प्रदेश की सरकार जो बजट के माध्यम से कहती है उसमें इन्कम दिखाकर अपनी वाहवाही लूटने का काम करती है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बजट में एक बात और कह दी कि प्रति व्यक्ति आय हमने सबसे ज्यादा कर दी। मैंने पिछली बार भी कहा था कि प्रति व्यक्ति आय का यह इनका ड्रामा है। प्रति व्यक्ति आय को ये एवरेज से निकालते हैं। हरियाणा प्रदेश की सरकार पिछले वर्ष जब 14वें वित्तायोग के सामने पेश हुई तो इन्होंने स्वयं माना कि 84 परसैंट हिस्सा द्वितीय और तृतीय श्रेणी से आता है। लगभग 60 परसैंट आबादी कृषि पर आधारित है। जिस प्रदेश के अंदर साढ़े 49 परसैंट लोग 5 किलो अनाज लेकर अपने बच्चों का पेट पालते हों यानि कि खाद्य सुरक्षा बिल के अंतर्गत 50 परसैंट लोग आते हैं। सरकार द्वारा डी.एल.एफ. की आय बढ़ाकर, रिलांयस की आय बढ़ाकर या जिंदल जैसे लोगों की आय बढ़ाकर प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय की एवरेज निकालने का काम करके गरीब आदमी के साथ मजाक किया जाता है। वित्त मंत्री महोदय, आप द्वारा इस प्रकार के आंकड़े देकर गरीब आदमी के साथ मजाक न किया जाए इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इन आंकड़ों को बजट में न दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, सरकार कह रही है कि हमारा कृषि का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। आर्थिक सर्वे के अनुसार वर्ष 2011-12 में जो उत्पादन 121 परसैंट था आज वह घटकर 115.65 रह गया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार एस.वाई.एल. नहर की लगातार बात करती है। एस.वाई.एल. नहर के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 9 साल पहले हमारे पक्ष मे फैसला दिया हुआ है और आज

[श्री अशोक कुमार अरोड़ा]

तक वह फैसला राष्ट्रपति के पास गया हुआ है। सरकार बताए कि इन्होंने उसके लिए क्या प्रयास किया है। सरकार द्वारा अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह लिख देना कि एस.वाई.एल. नहर हमारी जीवन रेखा है और हम इसका पानी दक्षिणी हरियाणा में लाएंगे, उसके नाम पर वोट लेना केवल लोगों के साथ धोखा करने की बात है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश की सरकार हरियाणा को नम्बर वन बताने की बात करती है। कर्मधारियों के बारे में प्रोफैसर सम्पत सिंह जी ने और भाई रामपाल माजरा जी ने भी जिक्र किया कि हमारे कर्मचारी लगातार आन्दोलन कर रहे हैं। 3-3 दिन तक पूरे हरियाणा प्रदेश में बिजली और पानी गुल रहता है। कर्मचारी मांग करते हैं कि जिस छत्त के नीचे हम बैठे हैं इसी छत्त के नीचे पंजाब के कर्मचारी भी बैठे हैं इसलिए हमारा वेतन पंजाब के बराबर कर दो फिर भी उनकी बात नहीं मानी जाती और बार बार कहते हैं कि हमने हरियाणा को नम्बर वन बना दिया। इसी प्रकार ये पुलिस कर्मचारियों को कहते हैं कि हमने आपके 6 हजार रुपये बढ़ा दिए जबकि वे एक बात की मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से पंजाब में जे.बी.टी. का स्केल पुलिस वालों को दिया गया है उसी प्रकार हमें भी पंजाब की तरह जे.बी.टी. का स्केल दिया जाए लेकिन सरकार इस बारे में कुछ नहीं सोच रही है। हमारे प्रदेश के गैस्ट टीचर आज लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारे कर्मधारियों के साथ-साथ जो हमारे पैंशनभोगी हैं उनमें से बुजर्गों को तो सरकार ने बसों के किराये में रियायत दे दी है लेकिन 7वें वेतन आयोग के तहत जो इंटरिम रिलीफ उनका बनता है वह उनको न देकर उनके साथ अन्याय किया गया है। वे भी हमारे प्रदेश के कर्मचारी रहे हैं इसलिए कोई न कोई रिलीफ उन्हें भी दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में भी बहुत कुछ कहा जाता है कि प्रदेश को शिक्षा का हब बना दिया गया है और प्रदेश में बहुत सी यूनिवर्सिटीज भी बना दी गई हैं। शिक्षा के बारे में प्रश्नकाल के दौरान भी चिंता जाहिर की गई थी। आज प्रदेश में शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है। प्रदेश में शिक्षा के गिरते स्तर के कारण ही गुड़गांव में जो बड़ी-2 कंपनीज हैं उनमें लाखों कर्मचारी काम करते हैं लेकिन उनमें 2-3 प्रतिशत बच्चे हरियाणा के हैं बाकी बच्चे बाहर के प्रदेशों के हैं। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में आप चाहें तो सर्वे भी करवा सकते हैं। जहां तक एस.ई.जैड की बात है इस बारे में कहा गया था कि एस.ई.जैड के तहत युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। एस.ई.जैड के तहत रिलायंस के साथ जो समझौता हुआ था उसमें कहा गया था कि दो लाख युवाओं को रोजगार दिया जायेगा। उस समझौते में यह भी कहा गया था कि यदि रिलायंस एस.ई.जैड नहीं बनाती है तो उनसे 10 प्रतिशत पैनल्टी के साथ जमीन वापिस ली जायेगी। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार रिलायंस को फायदा पहुंचा रही है और उनसे 10 प्रतिशत पैनल्टी लेने की बजाय उनको रियायत दी जा रही है। हरियाणा प्रदेश की सरकार से वे लोग 1172 करोड़ रुपये उसी जमीन के फालतू मांग रहे हैं जो उनको सरकार ने दिलवाई थी। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने 18 करोड़ की रियायत की मांग स्टाम्प ड्यूटी पर की थी। जो जमीन वे रिलायंस से वापिस ले रहे थे लेकिन हरियाणा प्रदेश की सरकार ने उस जमीन की कीमत बढ़ा दी जिसके कारण रिलायंस को ज्यादा पैसे दिए गए। रिलायंस से जो जमीन वापिस ली गई है उस पर अब ग्लोबल सिटी बनाने की बजाय वह जमीन किसानों को वापिस देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उसके साथ लगती गुड़गांव- झज्जर के बीच की हजारों एकड़ जमीन एस.ई.जैड को दे दी जिस पर कोरीडोर बनाया जायेगा। उसके पीछे भी उन लोगों ने जमीन खरीद ली है।

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। माननीय विपक्ष के साथी सदन को गुमराह कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि बादली विधान सभा में एस.ई.जैड बन रहा है। वहां जो जमीन खाली पड़ी है उस पर मेरे भाई फसलें बोते हैं। मेरी भी जमीन वहां एक्वायर हो रखी है और उस पर भी मेरे भाइयों ने फसल बीज रखी है। माननीय सदस्य को यही जानकारी नहीं है कि वह जमीन कहां पर है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यदि मैं सदन को गुमराह कर रहा हूं तो मेरे खिलाफ माननीय सदस्य प्रिविलेज मोशन ले आयें। मैं इनको बता दूंगा कि वह जमीन कहां पर है?

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी यह तो बतायें वह कौन सी जमीन है और कहां पर दी है?

श्री अशोक कुमार अरोड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं तो इनकी बात सुन रहा हूं।

श्री भारत भूषण बत्तरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है कि माननीय साथी को इतना अहंकार करने की जरूर नहीं है। यदि माननीय साथी कोई बात तथ्यों पर आधारित नहीं करेंगे तो उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा।

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। हमारे माननीय सदस्य सदन में गलत तथ्य रख रहे थे लेकिन उस समय भी हम शांति से इनकी बात सुनते रहे। लेकिन अब मैं बताना चाहूंगी कि शिक्षा के क्षेत्र में देश का ग्रोथ इनरोलमैंट रेशो 19.4 प्रतिशत है और हरियाणा का 27.6 प्रतिशत से ज्यादा है। मैं माननीय साथी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि आज प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ है। आज प्रदेश के हर कोने में नई यूनिवर्सिटी और कालेज खोले गये हैं। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथियों को तो यह भी जानकारी नहीं है कि इनके हल्के में कौन-कौन से स्कूल अपग्रेड किए गए हैं या कौन-कौन सी नई आई.टी.आई. तथा पोलटेक्निक कालेज खोले गये हैं और कहां-कहां पर स्कूल अपग्रेडेशन की डिमांड है। पहले लोगों का कभी पढ़ाई की तरफ रुझान नहीं रहा। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि ये सही तथ्य सदन में रखें। आज हरियाणा प्रदेश में शिक्षा के स्तर में बहुत सुधार हुआ है और प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में वर्ल्ड मैप पर हब के रूप में सामने आया है।

18.00 बजे **श्री अध्यक्ष :** नरेश जी, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं क्या आपका कोई प्वायंट ऑफ आर्डर है?

श्री नरेश कुमार बादली : जी है, स्पीकर सर, मेरे से पहले माननीय शिक्षा मंत्री महोदया जी खड़ी हो गई थी इसलिए मैं बैठ गया था।

श्री अध्यक्ष : नरेश जी, अरोड़ा जी को अपनी बात पूरी कर लेने दें उसके बाद आप अपनी बात कह लेना।

श्री नरेश कुमार बादली : स्पीकर सर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आपके माध्यम से माननीय साथी श्री अरोड़ा जी को यह बताना चाहता हूं कि बादली एरिया की ज़मीन इनकी सरकार के समय 2 लाख 60 हज़ार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से एक्वायर की गई थी। इसी प्रकार से डाबौदा, कसार और बहादुरगढ़ में ज़मीन ली गई। ऐसे ही ज़मीन लेकर झज्जर में पुलिस लाइन

[श्री नरेश कुमार बादली]

बनाई। माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा उसी ज़मीन का रेट 23 लाख रुपये दिलवाया गया और इसके ऊपर ज़मीन के मालिकों को रॉयल्टी भी मिलेगी।

श्री अध्यक्ष : नरेश जी, अब आप बैठ जाईए। Arora Ji, please continue.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मैं यह कह रहा था कि पहले तो कुछ लोगों ने एस.ई.जैड. के नाम पर किसानों की ज़मीनें ली अब वे लोग वही जमीनें आगे दूसरे लोगों को बेचकर पैसे कमा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मैं माननीय श्री अशोक अरोड़ा जी से यह पूछना चाहता हूं कि डिज्नी लैंड के लिए ज़मीन कहां पर और किस भाव में ली जा रही थी?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, इसी प्रकार से मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे एक शंका है कि प्रदेश की सरकार एफ.डी.आई. को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने जा रही है जिससे खुदरा बाज़ार में छोटे दुकानदारों को बहुत ज्यादा नुकसान होने की सम्भावना है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : नरेश जी, आप बैठ जाईये। आप उन्हें अपनी बात कहने तो दें। Please don't interfere like this. Yes, Mr. Arora, please continue.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मैं यह कह रहा था कि इससे आज पूरे हरियाणा प्रदेश का दुकानदार चिन्तित है। मैं यह चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय अपने जवाब में इस बारे में अपना कलेरिफिकेशन दें कि जैसा इन्होंने कहा है कि इन्होंने फ्रूट और सब्ज़ी पर जो मार्किट फीस है उसे खत्म कर दिया है। सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में हज़ारों व्यापारी और उनके साथ मज़दूर सब्ज़ी मण्डियों में काम करते हैं। इसलिए मेरा इस बारे में एक सुझाव है कि अगर सरकार मार्किट फीस बिल्कुल समाप्त कर देगी और अपना पूरा कंट्रोल वहां से हटा लेगी तो इससे ये दुकानदार, उनके साथ काम करने वाले मज़दूर और मुनीम सारे के सारे ही बेरोज़गार हो जायेंगे क्योंकि एफ.डी.आई. वाले सीधे किसानों से बात करके उनकी फसल उठायेंगे। जब ये मण्डियां खत्म हो जायेंगी और आढ़ती खत्म हो जायेंगे उस स्थिति में दुकानदारों के साथ-साथ किसानों को भी लूटा जायेगा।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : स्पीकर सर, हमारे साथी श्री अरोड़ा जी बहुत कन्फयूज़ हो रहे हैं या तो ये खुद कन्फयूज़ हैं या फिर कन्फयूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि एफ.डी.आई. इनके समय में भी आई थी और हमारे समय में भी आई है। हां, यह हो सकता है कि इनके समय में कम आई हो और हमारे समय में ज्यादा आई है। ये शायद मल्टी प्रोडक्ट रिटेल की एफ.डी.आई. की बात कर रहे हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा कि यह दूसरा मामला है। जो इनने अडॉप्ट किया है वह किसान के हित में है। एक इन्होंने मार्किट फीस की बात कही है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि मार्किट फीस और एच.आर.डी.एफ. हमने फ्रूट और सब्ज़ी पर ज़ीरो कर दिया है। जो आढ़ती हैं उनके कमीशन पर कोई पाबंदी नहीं है। सब्ज़ी मण्डियां रहेंगी और जो वहां पर खरीद-फरोख्त करेगा उसको अपना कमीशन मिलेगा। इसमें उनका कोई नुकसान नहीं है बल्कि इनको तो इससे फायदा ही होगा। हमने यह फैसला किसान के हित के लिए लिया है क्योंकि इससे किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा।

Mr. Speaker : Naresh Ji, please sit down. I am not allowing you to speak. Arora Ji, please continue.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूँ कि हमारे देश के किसानों में और दूसरे देशों के किसानों में बहुत अंतर है। वहाँ पर बड़े-बड़े फार्मर्स हैं जबकि यहाँ पर छोटे-छोटे किसान हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मंडियों में आढ़ती तो रहेंगे ही, हमने तो सिर्फ 4 परसैंट एच.आर.डी.एफ. ही माफ किया है। मंडियाँ भी रहेंगी और आढ़ती भी रहेंगे और उनका कोई नुकसान नहीं होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक शंका जाहिर कर रहा हूँ कि विदेशों में किसानों के पास स्टोरेज की कैपेस्टी है और हमारे किसानों के पास स्टोरेज की कैपेस्टी नहीं है। अगर खेत में ही किसानों का माल कोई पहले दिन ही खरीद लेगा तो किसान मंडी में किस लिए जाएगा, वे मंडी बंद हो जायेंगी। अगर मंडी बंद हो गई तो आपका कंट्रोल भी खत्म हो जायेगा। कम्पीटीशन बंद हो जायेगा क्योंकि मंडी में माल कम्पीटीशन से बिकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अरोड़ा जी, मंडी खत्म कहाँ होगी, दिल्ली की आजादपुर की मंडी भी उठ कर गन्नौर में आयेगी, आप मंडी खत्म करने की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अरोड़ा जी को मैं बताना चाहता हूँ कि कांट्रैक्ट फार्मिंग किसानों के हित में होती है। उसको हमने किसान के हित में एडॉप्ट किया है। कांट्रैक्ट फार्मिंग में किसान को यह मालूम होता है कि उसको उसकी फसल का कितना भाव मिलेगा। इससे उसकी लूट बंद हो जायेगी और इसलिए इस काम में आपको साथ देना चाहिए तथा सरकार के इस कदम का स्वागत करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो शंका जाहिर की है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, कांट्रैक्ट फार्मिंग तो किसान के हित की बात है। उसमें किसान से पूछ कर भाव तय होता है और किसान को उतना भाव देना पड़ता है और अगर उस कांट्रैक्ट को कोई तोड़ता है तो उस पर पैनल्टी लगती है। अगर अरोड़ा साहब किसान के खिलाफ बात कर रहे हैं तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में जाते हैं वहाँ पर कोई मंडी न होने की वजह से वहाँ के किसानों की फसल हरियाणा में बिकती हैं। वहाँ किसानों को लूटा जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो बाजपुर में उत्तराखण्ड में जाता हूँ, मेरी जमीन तो उत्तराखण्ड में है और वहाँ पर मंडियाँ हैं और मैं अपनी फसल को मंडी में बेचता हूँ वहाँ बहुत बड़ी ग्रेन मार्केट है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि ये यह बात कहाँ से लेकर आये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की हरियाणा से लगती सीमा के आसपास के किसान अपनी फसलों को हरियाणा में बेचते हैं। वहाँ मंडियों में बोली नहीं बोली जाती। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर प्रदेश का माल हरियाणा में इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर भाव अच्छे मिलते हैं और अगर उत्तर प्रदेश का माल हरियाणा में आ रहा है तो उससे हरियाणा के आढ़तियों को आमदनी हो रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आप सही कह रहे हैं कि अगर मंडियों में अनाज होगा तो आढ़तियों को तो फायदा होगा हम तो उससे खुश होते हैं लेकिन उनको रोक कौन रहा है, उसको सरकार रोक रही है, हम नहीं रोक रहे। आप उस पर अंकुश लगायें, उस पर 4 परसैंट की बजाय चाहे 1 परसैंट या आधा परसैंट एच.आर.डी.एफ. लगा दें लेकिन आप अपना कंट्रोल रखिए। अगर सरकार का कंट्रोल रहेगा तो मंडियाँ आबाद रहेंगी और अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो मंडियाँ बर्बाद हो जायेंगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, आप वाइंडअप कीजिए, आपको बोलते हुए 23 मिनट का समय हो गया है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा सा समय और दीजिए मैं कंकल्यूड ही कर रहा हूँ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अरोड़ा जी की सूचना के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि सब्जी मंडी के आढ़ती मुझसे मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि आप टैक्स बेशक खत्म कर दीजिए लेकिन ऐसी व्यवस्था कीजिए कि हम मंडी में साझीदार रहें। हमसे मंडी का डिवेल्पमैंट चार्जिज लीजिए और अगर कोई नई मंडी भी बनाओ तो उसमें सब्जी मंडी जरूर बनाईये। मैंने उनकी बात मान ली थी और मैंने उनको कह दिया था कि आढ़ती अवश्य रहेंगे। किसान का भी हित होगा और आढ़ती का भी हित होगा।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि सरकार ने कहा कि हमने कन्यादान की स्कीम में पैसा भी बढ़ाया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके हलके गन्नौर में एक शादी में गया था। कन्यादान हमारे समाज में ऐसी रस्म है जिसमें हर व्यक्ति चाहता है कि लड़की की शादी है अगर कार्ड न भी मिला हो तो भी कन्यादान तो डाल ही दिया जाये। गन्नौर में मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने सन 2007 में लड़की की शादी की थी। उस व्यक्ति ने बताया कि सरकार की तरफ से मेरी लड़की की शादी में कन्यादान तो जरूर आया था लेकिन जब वह आदमी मुझे मिला और उसने मुझे एक चिट्ठी दिखाई जिसमें यह लिखा हुआ था कि आप पहले बी.पी.एल. परिवार की श्रेणी में आते थे लेकिन अब दूसरे बी.पी.एल. सर्वे में आपका नाम बी.पी.एल. परिवार की श्रेणी में शामिल नहीं है। इसलिए आप कन्यादान की राशि के पैसे वापिस करो जो आपकी लड़की की शादी के समय आपको कन्यादान के रूप में मिले थे। स्पीकर सर, सरकार इस प्रकार के लैटर निकालती है। आज सरकार कृषि के क्षेत्र में किसान के हित की बात करती है अभी सहकारिता मंत्री जी कह रहे थे कि हमने किसी भी किसान को कोई नोटिस नहीं दिया। स्पीकर सर, हमने यह तो देखा था कि फाइनैंशर तो किसान से पहले खाली चैक पर साईन करवाते थे परन्तु अब बैंक भी किसानों से पहले खाली चैक साईन करवा रहे हैं यह हमने पहली बार देखा है। अगर किसान का चैक डिसऑनर हो जाता है तो किसान को कैद भी हो जाती है और यह इस प्रदेश के अन्दर अम्बाला जिले के एक किसान के साथ हुआ है जिसको कैद हुई है।

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, जिस किसान का चैक बाऊंस हुआ था उस किसान का नाम कृष्ण कुमार है जिसका गांव अलुपर जिला पानीपत है जिसकी छः महीने की सजा हुई है।

श्री सतपाल : स्पीकर सर, यह सब झूठ कह रहे हैं। वह किसान मेरे पास आया था और मैं उस किसान से मिला था उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो यह कह रहे हैं। आज तक किसी भी किसान की कोई जमीन नीलाम नहीं हुई है।

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, जैसे कि श्री अशोक कुमार अरोड़ा जी कह रहे हैं कि जो किसान लैंड मोरटगेज बैंक या कोऑप्रेटिव बैंक से लोन लेते हैं उनके लिए सरकार और मुख्यमंत्री जी यह कहते हैं कि हम ऐसे किसानों की जमीन को कुड़क नहीं करेंगे। लेकिन बैंकों द्वारा हजारों किसानों से ब्लैंक चैक ले रखे हैं जब किसान अपने लोन की राशि नहीं दे पाता तो उन चैकों को बैंकों में जमा करा दिया जाता है और इस प्रकार से बहुत से किसानों के चैक बाऊंस हुए हैं और चैक बाऊंस होने पर ऐसे किसानों को सजा भी हुई है। ऐसा एक उदाहरण मेरे विधान सभा क्षेत्र के अलुपर गांव में एक कृष्ण नाम के किसान के साथ हुआ है और उस किसान की छः महीने की सजा भी हुई है। सरकार चाहे तो इस बात को वैरीफाई करवा सकती है।

श्री सतपाल : स्पीकर सर, मेरी पहले भी इनसे बात हुई है कि आप एक भी केस या कोई भी आदमी ऐसा दिखा दो जिसकी जमीन कुड़की की गई हो। (विघ्न)

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, मेरा प्वाईंट ऑफ ऑर्डर है। मुख्यमंत्री जी ने पंजाब लैंड डिवेल्पमैंट ऐक्ट के तहत यह प्रावधान किया है कि यदि किसी किसान का चैक डिसऑनर हो जाता है तो ऐसे किसी किसान की न तो कोई सजा होगी न ही कोई जेल होगी। यह जो चैक डिसऑनर का मामला है यह बैंकिंग रेजोल्यूशन के नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमैंट एक्ट की धारा 138 के तहत एक शिकायत का मामला होता है उस शिकायत के आधार पर कोई कार्रवाही की होगी। इस तरह इस मामले को इन्टरमिंगल करने की कोशिश न करें। यदि किसी किसान को सजा हुई होगी तो वह सजा इसलिए हुई होगी कि हो सकता है उस किसान ने सैंट्रल गवर्नमैंट के एन.आई. एक्ट की धारा 138 की वॉयलेशन की होगी और उसका चैक डिसऑनर हो गया होगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, पहले किसानों के साथ क्या होता था जो किसान कर्जा नहीं भरते थे उसको जेल में डाल देते थे और उसका खाने का खर्चा भी उसके कर्जे में जोड़ देते थे।

श्री कृष्ण लाल पंवार : मुख्यमंत्री जी , फिर आप किसानों को यह क्यों कहते हो कि किसी की जमीन कुड़क नहीं की जाएगी। सरकार ने किसानों से ब्लैंक चैक ले रखे हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, हम इनकी तरह किसानों को लूट नहीं रहे हैं।

वित्त मंत्री (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा) : स्पीकर सर, माननीय सदस्य जो ये ब्लैंक चैक की बात कर रहे हैं। अगर प्राईवेट आदमी किसी भी कर्मिशिएल बैंक से कोई लोन लेता है तो बैंक उससे जरूर पहले ब्लैंक चैक पर साईन करवा लेते हैं। सरकारी बैंक किसी किसान से ब्लैंक चैक पर साईन नहीं करवाते और यह शर्त नहीं लगाते कि आप अगर लोन वापिस नहीं करेंगे तो बैंक दावा कर देगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सतपाल : स्पीकर सर, सारे कॉमर्शियल बैंक ऐसा करते हैं। सरकार ऐसा कुछ नहीं करवाती है कि किसी किसान से ब्लैंक चैक साईन करा कर रख लें। अगर इनके नोटिस में ऐसा कोई एग्जाम्पल है तो ये हमें दिखा दें हम मान जाएंगे।

Mr. Speaker : Mr. Arora, please conclude your speech. We have to conclude it now.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, हम एग्जाम्पल भी दिखा देंगे। अभी नरेश शर्मा जी कह रहे थे कि पिछली सरकार के समय में किसानों को उनकी जमीन के पैसे कम दिए गये थे और इस सरकार ने ज्यादा दिए हैं। सर, प्रोपर्टी की कीमतें तो बढ़ती ही रहती हैं। हरियाणा इंडस्ट्रीज डिपार्टमैंट ने नई नीति से बचने के लिए परसों के अखबार में 31 दिसम्बर की तारीख में भूमि अधिग्रहण के नोटिस निकाल दिए। आपके पास अखबार है। आप इसमें यह बात देख सकते हैं। क्योंकि एक जनवरी से भूमि अधिग्रहण की नई नीति लागू हो रही है ताकि किसान को पैसा ज्यादा न जाए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से कई बार यह बयान दिया जा चुका है कि जिस भूमि का अधिग्रहण हो चुका है और जिसका अवार्ड नहीं हुआ है, उस भूमि का अवार्ड नई नीति के तहत ही दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Mr. Arora, that should satisfy you. (Interruption)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, यह तो अच्छी बात है लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि 31.12.2013 को अखबार में भूमि अधिग्रहण संबंधी नोटिफिकेशन को क्यों निकाला गया था ? 1 जनवरी, 2014 से लागू हुए भूमि अधिग्रहण संबंधी ऐक्ट को मद्देजनर रखते हुए तो ऐसा नहीं किया गया था, ताकि नये ऐक्ट की एवज में सरकार को किसानों को अवार्ड का ज्यादा पैसा न देना पड़े? मुझे इसमें शंका नजर आती है? (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, जहां तक मैंने कंपनसेशन की बात कही है तो किसान को जो कंपनशेसन दिया जायेगा वह नई नीति के तहत ही दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अरोड़ा जी, आपको पता होना चाहिए कि जो नोटिफिकेशन निकाली गई थी वह सैक्शन 4 के तहत निकाली गई थी। जहां तक आपने शंका जाहिर की है कि कहीं 31.12.2013 को भूमि अधिग्रहण संबंधी नोटिफिकेशन इस वजह से तो नहीं निकाली गई है ताकि किसानों को अवार्ड का पैसा ज्यादा न देना पड़े तो उस संबंध में मैं आपको क्लीयर कर देना चाहता हूँ कि जो अवार्ड दिया जाता है वह सैक्शन 9 के तहत ही दिया जाता है। सैक्शन 4 के तहत तो केवल अखबारों में भूमि अधिग्रहण संबंधी नोटिफिकेशन ही दी जाती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, सैक्शन 9 के तहत अवार्ड दिया जाता है और सैक्शन 4 के तहत अखबारों में भूमि अधिग्रहण संबंधी नोटिफिकेशन दी जाती है। मैं समझता हूँ कि अब आपको इस संबंध में जो भी शंका थी वह दूर हो गई होगी ?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, आप ठीक कह रहे हैं। किसी शंका को क्लीयर करना कोई बुरी बात तो नहीं है? अगर कोई शक की गुंजाइश है तो मैं समझता हूँ कि उसको दूर

करने में कोई हर्ज नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) शंका का निवारण करना तो अच्छी बात मानी जानी चाहिए। (विघ्न)

Mr. Speaker : Arora Ji, your time has already finished because you have spoken for 30 minutes. (Noise & Interruption)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, अगर आप आज्ञा दे तो मैं अपने हल्के थानेसर के बारे में भी सदन में कुछ बोलना चाहता हूँ? (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अरोड़ा जी, कभी सच भी बोल दिया करो?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं सदा सच ही बोलता हूँ। अब यदि मैंने कहा है कि मैं मेरे हल्के थानेसर के बारे में बात रखना चाहता हूँ तो मैं अपने हल्के की ही बात रखूंगा। (हंसी)

Mr. Speaker : Arora Ji, please conclude it in one minute. I have already given you 30 minutes because you are a senior member.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : ठीक है, सर। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं भी इस हाउस का एक सीनियर मैम्बर हूँ, अत: मुझे भी अपनी बात रखने का मौका दीजिये? (शोर एवं व्यवधान) (हंसी)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, अगर देखा जाये तो मैं विज साहब से दो महीने पहले यहां पर आया था। (इस समय सदन में हंसी के फव्वारें फूट पड़े) अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में सदन में अपनी बात रखना चाहूँगा। कुरुक्षेत्र एक धार्मिक नगरी है इसलिए यहां पर बाहर से अनेक लोग धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में स्थित विभिन्न मंदिरों तथा धार्मिक स्थानों के दर्शन करने आते हैं। वर्तमान में कुरुक्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। मेरी एक मांग है ट्रैफिक की बढ़ती हुई समस्या को देखते हुए कुरुक्षेत्र में एक बाई पास निकाला जाये। कुरुक्षेत्र शहर दो भागों में बंटा है। एक भाग में पुराना शहर है तथा दूसरे भाग में नया शहर स्थित है। जो पुराना शहर है उसके बीचों-बीच एक रेलवे लाईन जाती है। ट्रेन निकलने के बाद जब फाटक खुलती है तो एक घंटे के बाद तक भी जाम की स्थिति बनी रहती है। सरकार को रेलवे लाइन के नीचे अंडर पास बनाने की कोई प्रपोजल जरूर बनानी चाहिए। अगर अंडर पास नहीं बना सकती है तो रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाना चाहिए। इससे ट्रैफिक की समस्या से भी निजात मिलेगी। कुरुक्षेत्र डिव्लैपमैंट बोर्ड की जब मीटिंग हुई थी तो उसमें मुख्यमंत्री जी भी मौजूद थे और महामहीम राज्यपाल महोदय ने उस मीटिंग की अध्यक्षता की थी। मैंने उस मीटिंग में साफतौर से कहा था कि यह बात ठीक है कि कुरुक्षेत्र में बहुत ज्यादा संख्या में मंदिर मौजूद हैं और इसके साथ ही अक्षरधाम मन्दिर तथा तिरुपति बाला जी मंदिर कुरुक्षेत्र में स्थापित होने संबंधी बात भी सुनी जा रही है। मैं चाहता हूँ कि यहां पर जो तीर्थ यात्री अपने बच्चों सहित आते हैं उनके लिए थीम पार्क की तर्ज पर कोई पार्क बनाया जाना चाहिए। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मांग को स्वीकार भी किया था। अत: मेरा निवेदन है कि जब वित्त मंत्री जी अपना जवाब दें तो उसमें इसका जिक्र अवश्य करें। (विघ्न)

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) : स्पीकर सर, तीर्थ यात्री मनोरंजन के लिए नहीं आते हैं बल्कि धार्मिक आस्था की वजह से धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के दर्शन करने के लिए आते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, 6.30 बजे तक हाउस का समय है। आज वित्त मंत्री जी का रिप्लाई करवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल एप्रोप्रियेशन बिल आयेगा। As per the rules of this House ये दोनों चीजें एक दिन नहीं की जा सकती हैं. So we have to conclude it today, as far as the reply of the Finance Minister is concerned.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, हमारी पार्टी के सदस्यों को बजट पर बोलने के लिए 5-5 मिनट का समय जरूर दे दिया जाये। (विघ्न)

श्री भारत भूषण बत्रा (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, बजट पर कुछ बोलने से पहले मैं आपके माध्यम से हाउस में कुछ चन्द लाइनें बोलना चाहता हूँ-

> "लबज ही ऐसी चीज है, जिसकी वजह से इन्सान या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। जिन्दगी की इस कशमकश में वैसे तो मैं बहुत बिजी हूँ। लेकिन वक्त का बहाना बनाकर अपने को भूल जाना मुझे आज भी नहीं आता है। जहाँ यार याद न आये तो तन्हाई किस बात की, बिगड़े रिश्ते ना बने तो खुदाई किस बात की, बेशक अपनी मंजिल तक जाना है जहाँ से अपना दोस्त ना दिखे वो ऊँचाई किस काम की "।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूँ कि यह शेर किसके बारे में कहा है।

श्री भारत भूषण बत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब निकाल लो। मैंने तो ये चन्द लाइन बोली है। मैंने तो आपकी इजाजत से यह शेर हाऊस के सामने पढ़ा है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूँ कि इनके साथ किसने बेवफाई की है

श्री भारत भूषण बत्रा : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि बेवफाई तो शब्द मैंने बोला ही नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, विपक्ष ने बड़ा क्रिटिसाईज कर दिता है इत्थे। पिछले तिन सालो तों साडे सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्ढा जी ने इन्हाँ वदिया बजट दिता है। इन्हाँ नूँ स्टेट दि तरक्की नजर भी आऊँदी। इन्हाँ नूँ पता नहीं कि स्टेट विच किन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर आया है। किथे-किथे तरक्की होई है ते किथे-किथे नी होई है। ऐवे लगदा है कि अपणा समां भूल गये हन। (विघ्न) स्पीकर सर, अम्बाला तों 3 घंटे लगदे हन दिल्ली पहुँचण तक विज साहब, दसों कि नी पौंचदे दिल्ली तक। I do not want to enter into controversy otherwise. मैं तों तथ्यों दे मुताबिक ही बोलागाँ (शोर एवं व्यवधान) इस विपक्ष नूँ (शोर एवं व्यवधान)

श्री सतपाल : अध्यक्ष महोदय, क्या इनको बीच में बोलने के लिए आपने परमिशन दे रखी है। जब ये चाहे खड़े होकर बीच में बोलने लग जाते हैं।

Mr. Speaker : I can't allow this running commentary.

Shri Satpal : Sir, his behaviour is not good. इसका हमारे जैसा व्यवहार नहीं है और ये अपने आपको सीनियर बता रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं ए गल इस लई कह रिहा हाँ कि पिछले तिन सालाँ तों बजट जेड़े सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्ढा जी ने दिते। इन्हाँ दि डिटेल पढ के इन्हाँ नूँ दसो कि सोशल सर्विस कि हुँदी है, सैक्टर की हुँदे हन तें इकॉनोमी सैक्टर की हुँदे हन। रैगुलर एक्सपैंडीचर की हुँदे हन। केपिटल एक्सपैंडीचर की हुँदे हन किवे सरकार चलदी है ते किवे कम करदे हन। इन्हाँ नूँ सारा पता लग जू गा। ऐ जा के हिन्दुस्तान दे विच किसे दी बजट नूँ चुक लैण ..... (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : No running commentary please.

Shri Bharat Bhushan Batra : Sir, why is he interrupting me? Has he got the licence for this? स्पीकर सर मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि रिकॉर्ड के अगेंस्ट एक शब्द भी बोलूँ तो बीच में टोक देना। कोई भी बजट उठाकर देख लें सोशल सैक्टर की बाइफरकेशन जिन्ने पिछले तिन सालों तों दिते हन अज तक गुजरात दा बजट चुक के देख लो ते कैम्पयर कर के वी देख लो ते सोशल सैक्टर दे अंदर साडे केड़ी-केड़ी थीजाँ आऊँदियाँ हन ऐ वी मैं हाऊस दे विच दस देंदाँ हाँ (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, मैं हिन्दी में बोलूँ (शोर एवं व्यवधान) हमारे माननीय खजाना मंत्री जी ने 22,250 करोड़ रुपये का प्लान बजट पेश किया है। यदि आप सभी फैक्टर्ज की कल्कुलेशन करेंगे तो पता चलेगा कि एजुकेशन पर लगभग 3700 करोड़ रुपये, तकनीकी शिक्षा पर लगभग 682 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य पर लगभग 1674 करोड़ रुपये और सामाजिक कल्याण पर लगभग 3929 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है। सर, बजट में जो 9085 रुपये का आंकड़ा है, इसका मतलब यह है कि हरियाणा सरकार सोशल सेक्टर पर 45 से 48 प्रतिशत पैसा खर्च करती है। हरेक चीज का विस्तार होता है। आज शिक्षा का विस्तार हो रहा है, आज मेडिकल एजुकेशन का विस्तार हो रहा है। आज विपक्ष के साथी यह नहीं देखते कि प्रदेश में सरकार ने कितने मेडिकल कालेजिज खोले हैं और मेडिकल कालेजिज में सीटें कितनी बढ़ाई गई है। आज विपक्ष इस बात का बिल्कुल जिक्र नहीं करता कि हिन्दुस्तान की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी, नार्दन इण्डिया में पहली महिला यूनिवर्सिटी और पहली सैन्टर्ल यूनिवर्सिटी हरियाणा के अन्दर खोली गई है। इसी तरह से करनाल के अन्दर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, और नलहड़ (मेवात) में मेडीकल कॉलेज खोला जा रहा है, जोकि श्री आफताब जी के क्षेत्र में स्थित है। इसी तरह से ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में तथा कितने नये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हरियाणा में खोले गये हैं। इससे पता चलता है कि वर्ष 2005 से पहले कितने मेडिकल कॉलेज थे और अब कितने हैं ? हमारी सरकार बनने पर कितने मेडिकल कॉलेज हैं। तीन मेडिकल कॉलेज पी.पी.पी.मोड पर जीन्द, पानीपत और कैथल में बनाये गये हैं। सर, आज तक किसी ने अपने में भी नहीं देखा था कि हरियाणा के अन्दर एम्स-2 आयेगा। All India Institute of Medical Sciences in Haryana which is a premium institute of the State. उनके बारे में कोई श्रेय विपक्ष के साथी नहीं दे रहे हैं, वे यह नहीं कहते कि इसका कोई मुकाबला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इन मेडिकल कॉलेजों को खुलने से सभी लोगों को इनका फायदा होता है, किसी एक को नहीं। (विघ्न) सर, यह ठीक है कि विपक्ष का काम क्रीटीसाईज करना होता है। यदि विज

[Shri Bharat Bhushan Batra]

साहब को गुजरात की भाषा बोलनी है तो वह स्वयं गुजरात जायें। सर, इस सदन में उपस्थित सभी विधायकों को जनता ने चुनकर भेजा है। विपक्ष के साथियों ने किसी भी एक्ट पर सरकार की तरक्की के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। (शोर एवं व्यवधान) हरियाणा प्रदेश में एक मेडिकल कॉलेज वर्ष 1961 में आया था। अध्यक्ष महोदय, प्रिमियम इन्स्टीच्यूट जिस शहर के अन्दर आते हैं उनमें सारे पेशेन्ट्स हरियाणा प्रदेश से ही नहीं आते हैं, वहां बाहर के पेशेन्ट्स भी आते हैं। आपने कहा कि पी.जी.आई. रोहतक में स्थित है। आप यह सोचें कि वहां रोहतक के कितने पेशेन्ट्स जाते होंगे। वहां दूसरे जिलों से भी पेशेन्ट्स आते हैं। करनाल से भी पेशेन्ट्स आते हैं, हिसार से भी आते हैं, महेन्द्रगढ़ से भी आते हैं, दादरी से भी आते हैं मेरे कहने का मतलब है कि सभी जिलों से उसमें पेशेंट्स आते हैं इसलिए इस बात को लेकर इनको कंपेरिजन नहीं करना चाहिए बल्कि सबको एक ध्वनि से यह बात कहनी चाहिए कि इस इन्स्टीच्यूट को इतना अच्छा बनाओ कि जिसकी सब जगह सराहना हो। इसी तरह से आई.आई.टी. और आई.आई.एम. बनाए गए हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। अध्यक्ष महोदय, बत्तरा जी मेडिकल कॉलेज की चर्चा कर रहे थे, यह बड़ी अच्छी बात है। यह भी खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश के अंदर दो बड़े इंस्टीच्यूट इस तरह के हैं। (विघ्न) हर सदस्य की इच्छा होती है कि उसके हल्के में भी इस किस्म के इंस्टीच्यूट्स होते तो ज्यादा अच्छा होता। (विघ्न)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय आधे घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाए ?

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय आधे घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2014-15 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भण)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सरकार की सबसे ज्यादा ग्रांट अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के लिए जाती है। इसमें मैक्सिमम पैसा सरकार का जाता है। मैं आदरणीय हुड्डा साहब से प्रार्थना करूंगा कि जैसे कि सदन में मेडिकल कालेज के बारे में जिक्र हो रहा है तो वे अपने जवाब में इस बारे में भी जरूर बताएं कि आपकी सरकार बनने के बाद 10 साल के अंदर अग्रोहा मेडिकल कालेज में कौन कौन सी फैसिलिटीज दी गई हैं जिनसे कि लोगों को लाभ हुआ हो या वहां जो अच्छी फैसिलिटीज पहले से चल रही थीं उन फैसिलिटीज को वहां से शिफ्ट करने का काम किया गया है। यह भी अपने जवाब में बताएं कि जो मेडिकल कालेज खोले जा रहे हैं उनका हरियाणा की जनता को लाभ मिल रहा है या केवल हरियाणा सरकार का पैसा खर्च करके उन इंस्टीच्यूट्स का भट्ठा बिठाने का काम किया गया है।

श्री भारत भूषण बत्तरा : अध्यक्ष महोदय, कुरुक्षेत्र में नेशनल डिजाइन इंस्टीच्यूट आया है जो कि इससे पूर्व पूरे भारत वर्ष में एक ही था। अरोड़ा साहब उसके लिए धन्यवाद तो करेंगे नहीं। (विघ्न) उसके बाद सैन्ट्रल प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी इंस्टीच्यूट, आई.आई.टी.,

निफ्ड भी सोनीपत के अंदर आए हैं। पंचकूला में नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ फैशन टैक्नोलॉजी आया है। इसी प्रकार से ग्लोबल सैन्टर फार न्यूक्लियर ऐनर्जी, जसौरखेड़ी में आया है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन दि नेम ऑफ फार्मर चीफ मिनिस्टर चौधरी बंसी लाल के नाम से भिवानी में खोली जा रही है। सोनीपत में ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का निर्माण शीघ्र शुरू होने वाला है जिसका नाम डॉ. बी.आर.अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। कुरुक्षेत्र यूनीवर्सिटी के जींद स्थित रीजनल सैन्टर को अपग्रेड करके उसे यूनिवर्सिटी बनाना है। (विघ्न)

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, श्री बत्तरा जी ने जींद में यूनीवर्सिटी की बात कही हैं। मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जब ये जवाब दें तो बता दें कि कब ये यूनिवर्सिटी बनेगी क्योंकि दिनांक 14.5.2005 को जींद में रीजनल सैन्टर बनाने की घोषणा की गई थी वह अब तक नहीं बना है। मैं चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी वहां कब तक बना दी जाएगी, यह हमें बता दें।

श्री भारत भूषण बत्तरा : अध्यक्ष महोदय, एक बुधैन यूनिवर्सिटी लुला अहीर, रिवाड़ी में आई है, एक कन्या गुरुकुल, फरल डिस्ट्रिक्ट जींद में आई है एक मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद का एक रीजनल सैंटर नूंह, जिला मेवात में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए मुझे उम्मीद है कि श्री आफताब अहमद जी भी धन्यवाद करेंगे। इसके अलावा मैं सदन को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2005 से पहले प्रान्त के अंदर 5 स्टेट यूनीवर्सिटी थीं अब 14 यूनीवर्सिटीज हो गई है। मीरपुर रेवाड़ी के अन्दर इन्दिरा गान्धी यूनिवर्सिटी बनाई गई। वर्ष 2005 के अन्दर प्रदेश के अन्दर सरकारी कालेज कितने थे (विघ्न)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, कोई यूनिवर्सिटी सरदार भगत सिंह जी के नाम से भी बना दें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, चण्डीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह जी के नाम पर ही रखा गया है।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, उसके लिए हरियाणा सरकार का क्या योगदान है?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, विज साहब को शायद यह मालूम नहीं है कि चण्डीगढ़ एयरपोर्ट में हरियाणा सरकार का साढ़े चौबीस प्रतिशत हिस्सा है और साढ़े चौबीस प्रतिशत हिस्सा पंजाब सरकार का है। हरियाणा सरकार की प्रोपोजल पर ही उस एयरपोर्ट का नाम सरदार शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखा गया है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी यह कह रहे हैं कि चण्डीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखा गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार की कौन सी ऐसी जमीन है जिसकी सीमा चण्डीगढ़ के एयरपोर्ट के साथ लगती है। हरियाणा सरकार की कौन सी हिस्सेदारी उस एयरपोर्ट पर बनती है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लोगों के गाढ़े खून पसीने की कमाई का 200 करोड़ रुपया बिना मतलब के पंजाब सरकार को दे दिया अगर उस पैसे को प्रदेश के लोगों के लिए लगाते तो प्रदेश के लोगों को काफी लाभ मिलता। चण्डीगढ़ एयरपोर्ट का नाम तो पंजाब सरकार ने ही सरदार भगत सिंह के नाम पर रखा है उसमें हरियाणा सरकार का कोई सरोकार नहीं है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, चण्डीगढ़ एयरपोर्ट का नाम यू.पी.ए. की सरकार ने हमारे सुझाव पर रखा है इसमें पंजाब सरकार का क्या वास्ता है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चण्डीगढ़ एयरपोर्ट तो भारत सरकार का है वह पंजाब सरकार का नहीं है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, पंजाब सरकार तो चण्डीगढ़ एयरपोर्ट का नाम केवल मोहाली के नाम पर ही रख रही थी वह तो चण्डीगढ़ का नाम ही उड़ा रही थी। लेकिन चण्डीगढ़ हरियाणा की राजधानी है इसलिए हमने ही इस एयरपोर्ट का नाम सरदार भगत सिंह के नाम पर रखने के लिए भारत सरकार को सुझाव दिया था। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी (जन स्वास्थ्य आभियांत्रिकी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने चण्डीगढ़ एयरपोर्ट के लिए पैसा दिया है वरना सारा शेयर पंजाब सरकार ही ले जाती।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, इस पैसे के देने से हरियाणा सरकार को क्या मिला?

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, हमे अपना हिस्सा मिला है इसीलिए ही तो आज चण्डीगढ़ एयरपोर्ट हैं उसमें हरियाणा और पंजाब का बराबर का हिस्सा है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, चण्डीगढ़ एयरपोर्ट एक कॉमर्शिएल एयरपोर्ट हैं इस एयरपोर्ट से जो भी मुनाफा आयेगा उसका शेयर हरियाणा सरकार को भी मिलेगा क्योंकि इस एयरपोर्ट में हरियाणा सरकार का साढ़े चौबीस प्रतिशत हिस्सा है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, चण्डीगढ़ एयरपोर्ट के एग्रीमेंट में यह कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि इस एयरपोर्ट से जो भी रेवेन्यू आयेगा उसमें हरियाणा सरकार का भी हिस्सा होगा। यह तो हाउस को गुमराह करने की बात है। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस एग्रीमेंट की कापी सदन के पटल पर रखें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में एयरपोर्ट एथोरिटी ऑफ इण्डिया को मालूम है कि चण्डीगढ़ एयरपोर्ट में साढ़े चौबीस प्रतिशत हिस्सा हरियाणा सरकार का है, साढ़े चौबीस प्रतिशत पंजाब सरकार का है और 51 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार का है। इस एयरपोर्ट से जो भी मुनाफा आयेगा उसका साढ़े चौबीस प्रतिशत हरियाणा सरकार को मिलेगा।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, ****

श्री सतपाल : स्पीकर साहब, आप विज साहब को बोलने से रोकते ही नहीं हैं। ये बार बार बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं? आपको इनको रोकना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : विज साहब की कोई बात रिकार्ड ही नहीं करवा रहे हैं।

श्रीमती किरण चौधरी (जन स्वास्थ्य आभियांत्रिकी मंत्री) : स्पीकर सर, श्रीमती इन्दिरा गान्धी और श्री राजीव गान्धी इस देश के प्रधान मंत्री रह चुके हैं इसलिए ये माननीय सदस्य ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उनके नाम से कोई एयरपोर्ट क्यों नहीं बन सकता (विघ्न)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, विज साहब को शायद यह पता नहीं है कि स्वतंत्रता की लड़ाई किस के द्वारा लड़ी गई थी। हमने हसन मेवाती स्वतंत्रता सेनानी के नाम से मेवात में एक मेडिकल कालेज बनाया है। कल्पना चावला के नाम से करनाल में एक मेडिकल कालेज बनाया है। माननीय सदस्य को हरियाणा के इतिहास के बारे में ही नहीं मालूम कि इस देश के स्वतंत्रता सेनानी कौन-कौन थे (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, लाला लाजपतराय के नाम से हमने यूनीवर्सिटी बनाई हैं। आजादी की लड़ाई का इनको क्या पता। इनका स्वतंत्रता सेनानियों के साथ क्या सम्बंध है? एक भी स्वतंत्रता सेनानी बी.जे.पी. में नहीं गया है। (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, ..

Shri Satpal : Speaker Sir, why are you allowing Shri Anil Vij again and again? It is not good.

Mr. Speaker : I am not allowing him. (Interruption)

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, सिरसा में इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी चौधरी देवीलाल के नाम से यूनीवर्सिटी बनाई थी परंतु चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, जननायक ने उसके लिए 300 करोड़ रुपये दिए हैं। (शोर एवं व्यवधान)क्या वे स्वतंत्रता सेनानी इनको दिखाई नहीं देते। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे विनती है कि अगर इस तरह हाउस चलना है तो सबको बोलने के लिए खुला टाइम दे दिया जाए। ये एक दूसरे को बात नहीं करने देते। बतरा जी बात कर रहे हैं और कोई कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं तो विज साहब खड़े हो जाते हैं और उनकी आदत है कि उन्होंने कुछ न कुछ बोलना है। विज साहब इधर बात करके प्रैस की तरफ देखते हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, ..

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, भगतसिंह का नाम लेकर, राजगुरू का नाम लेकर और चन्द्रशेखर का नाम लेकर मैंने क्या कोई गलती कर दी है।(शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, we are wasting the precious time of the House. It is being wasted. (Interruption)

श्री सतपाल : अध्यक्ष महोदय, विज साहब इतने सीनियर मैम्बर हैं और हर बात पर खड़े होकर बोलने लग जाते हैं जोकि ठीक बात नहीं है।(शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, keep silence please.

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा विज साहब से सविनय निवेदन है कि मैं 10 मिन्ट का समय लूंगा इसलिए मुझे बीच में डिस्टर्ब न करें। वर्ष 2005 तक प्रदेश में गवर्नमैंट कालेज 60 थे जोकि आज 95 हो गए हैं।(शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : We are wasting the time of the House like this. Please, maintain some decorum. Let him speak.

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, आई.टी.आईज. की बात करें तो सरकार की बहुत ज्यादा आई.टी.आईज. हैं जिनमें वर्ष 2005 तक intake capacity of the students 16468 थी जबकि आज intake capacity of the students 56832 है। मैडिकल कालेज बनाना कोई आसान काम नहीं होता। इस पर सरकार का बहुत पैसा लगता है। प्रांत में आज अच्छे मैडिकल कालेज बने हुए हैं जिनका एक स्टैण्डर्ड है। हमें सबसे ज्यादा इस बात के लिए तवज्जो रखनी चाहिए और हमें एप्रीशिएट करना चाहिए कि वर्ष 2005 तक इस प्रांत के अंदर मैडिकल कालेजिज में स्टूडैंट्स का इन्टैक टोटल 350 था जो आज 850 हो गया है यानि 500 की वृद्धि इन सालों में हुई है। अध्यक्ष महोदय, माननीय अरोड़ा जी ने भी अपने अभिभाषण में एजुकेशन के स्तर के बारे में जिक्र किया यह हम मानते हैं कि एजूकेशन के स्तर को बढ़ाना बहुत जरूरी है लेकिन इसको बढ़ाने के लिए अकेली सरकार जिम्मेवार नहीं है इसके लिए हम सब और प्रदेश की जनता भी जिम्मेवार है कि किस तरह से प्रदेश में शिक्षा के स्तर को आगे ले जाया जाये। अध्यक्ष महोदय, जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय देश में 18 प्रतिशत लिट्रेसी थी और आज के दिन देश में 76 प्रतिशत लिट्रेसी है। इस बात की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि आज के दिन देश में सबसे ज्यादा ऐबसन्टी सरकारी नौकरीज में हमारे टीचर्स ही रहते हैं जो कि चिंता का विषय है। इस बारे में यदि मैं पूरी रिपोर्ट बताऊंगा तो बहुत समय लग जायेगा। इसके अतिरिक्त यह भी चिंता का विषय है कि आज सरकारी स्कूल्ज में अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। सभी अभिभावक अपने बच्चों को प्राईवेट स्कूल्ज में ही पढ़ने के लिए भेजते हैं। सरकारी स्कूल्ज में तो गरीबों के बच्चे ही आते हैं। इस तरफ केवल सरकार को ही नहीं बल्कि हम सबको सोचने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय साथी ने गुड़गांव की कंपनीज में प्रदेश के युवाओं को नौकरी देने के बारे में जिक्र किया है इस बारे में, मैं कहना चाहूंगा कि यह रिकार्ड की बात है कि सिरसा से लेकर पंथकुला तक और नारनौल से लेकर पंचकुला तक यानि पूरे प्रदेश से गुड़गांव की आई.टी. कंपनीज में हमारे हजारों बच्चे काम कर रहे हैं। हम मानते हैं कि हमें अपने शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता है लेकिन यह अकेले सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए हम सबकी और समाज की भी जिम्मेवारी है। आज प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए हर तरह के एवेन्यूज उपलब्ध हैं। इनफोसिस कंपनी यदि बैंगलोर में है तो वहां केवल तमिलनाडू या कर्नाटक के बच्चे नौकरी कर रहे हों ऐसा नहीं है। वहां पर पूरे देश से बच्चे काम कर रहे हैं। आज गुडगांव साईबर सिटी बन गया है इस बारे में भी विपक्ष के साथी कहेंगे कि यदि गुड़गांव साईबर सिटी बन गया है तो अपने आप बना है इसमें सरकार ने कुछ नहीं किया है। मैं विपक्ष के साथियों को बताना चाहूंगा कि आज गुड़गांव इंटरनेशनल मैप पर आ गया है इसमें प्रदेश के लोगों का भी हाथ है।

Mr. Speaker : Batra ji, please wind up.

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मैं अब केवल दो टॉपिक्स पर बात करना चाहूंगा। जहां तक इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात है इसमें मैं रोड्ज के बारे में बात नहीं करना चाहूंगा। मैं नैशनल हाई-वे की कितनी स्ट्रैंथ है या लम्बाई है इस बारे में जिक्र नहीं करना चाहूंगा। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस समय वर्ष 1966 में हरियाणा प्रांत बना था तब से लेकर वर्ष 2000 तक प्रदेश में केवल 16 आर.ओ.बी. थे जबकि आज के दिन 41 आर.ओ.बी. और एक रेलवे अंडर ब्रिज है। इसके अलावा 31 आर.ओ.बी. प्रोसैस में हैं जिन पर कार्य चल रहा है। इसके लिए विपक्ष के साथियों को सरकार का थैंक्स करना चाहिए।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है कि माननीय सदस्य यह भी बता दें कि पूरे हरियाणा में कितने आर.ओ.बी. बने हैं और अकेले रोहतक में कितने बने हैं?

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मैं अरोड़ा जी को बताना चाहूंगा कि सिरसा में आर.ओ.बी. किसने बनवाया है? यह भी ये जानते होंगे और इनके कुरुक्षेत्र में भी नैशनल हाई-वे पर आर.ओ.बी. बनाया जा रहा है जिसका काम सुप्रीम कोर्ट में स्टे के कारण रुका हुआ है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा फिर से प्वायंट ऑफ आर्डर है कि माननीय सदस्य कुरुक्षेत्र के जिस आर.ओ.बी. का जिक्र कर रहे हैं उस पर पिछले कई सालों से काम बंद पड़ा है। जिसके कारण वहां बहुत दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें लोगों की जानें भी गई हैं। इससे तो वहां पर पहले जो सड़क बनी हुई थी वही अच्छी थी। उस दौरान वहां कोई दुर्घटना तो नहीं होती थी। (विघ्न)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, वह आर.ओ.बी. कई सालों से नहीं बल्कि साल-डेढ़ साल से बंद पड़ा है। मेरे विपक्ष के साथी तो विकास की बात कर ही नहीं सकते। इनके समय में प्लान बजट 2 हजार करोड़ रुपये से भी कम का था और प्लान तथा नॉन प्लान बजट भी इनके समय में 8 हजार करोड़ रुपये से कम का था जबकि हमारे वित्तमंत्री जी ने 73 हजार करोड़ रुपये का बजट सदन में पेश किया है जोकि बहुत साहस का काम है। इसके बावजूद भी विपक्ष के साथी कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है।

Mr. Speaker : Batra ji, please wind up.

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के साथियों को यह भी चैलेंज करता हूं कि पिछला प्रपोज्ड बजट क्या है? इसको भी छोड़ो, एक्चूवल बजट ही देख लें और इसके लिए इनको वित्तमंत्री जी का थैंक्स करना चाहिए। एक्चूवल फीगर तो दो साल बाद आ जाती हैं कि इतना बजट प्रपोज किया और इतना खर्च किया गया। जो पार्टी केवल 2 हजार करोड़ रुपये प्लान बजट और नॉन प्लान को मिलाकर 8 हजार करोड़ तक सीमित रह गई हो उसको आज 73 हजार करोड़ रुपये के बजट के लिए वित्तमंत्री जी और सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद की जगह ये लोग तो इस तरह की बातें करते हैं कि इतना घाटा हो गया, उतना घाटा हो गया, सरकार खर्चा कहां से लेकर आयेगी। सरकार भूखी हो गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के साथियों को बताना चाहूंगा कि रेवेन्यू तो सरकार ही लेकर आयेगी इनके भरोसे प्रांत नहीं चलने वाला है। स्पीकर सर, विपक्ष के साथी बता दें अगर किसी भी टैक्स रेवेन्यू में आज तक कोई कमी हुई हो। किसी सैल्ज़ टैक्स और एक्साईज़ टैक्स में भी अगर कोई कमी हुई हो ये उसके बारे में भी बतायें। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार के समय में सभी प्रकार के टैक्स रेवेन्यू में हमेशा वृद्धि ही हुई है। स्पीकर सर, हमारे विपक्ष के साथियों को तो यह भी पता नहीं होगा हरियाणा प्रदेश के कितने जिले एन.सी.आर. में आ गये हैं। आज तक इनकी पार्टी के किसी नेता की यह सोच नहीं थी कि प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को एन.सी.आर. के तहत लाया जाये। माननीय मुख्यमंत्री जी की यह सोच थी कि प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को एन.सी.आर. के अंदर लाया जाये क्योंकि एन.सी.आर. के अंदर आ जाने से किसी क्षेत्र को कितना फायदा होता है यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री के प्रयासों से आज करनाल, भिवानी,

[श्री भारत भूषण बतरा]

महेन्द्रगढ़ और जींद तक हरियाणा प्रदेश के अनेक जिले एन.सी.आर. में शामिल हो चुके हैं। एन.सी.आर. में यू.डी.आई. का काफी पैसा मिलता है। जवाहर लाल नेहरू स्कीम का पैसा आता है। अर्बन डवैल्पमैंट का पैसा आता है। सैंट्रल गवर्नमैंट का पैसा आता है। इसके अलावा भी और मदों के अंतर्गत काफी पैसा मिलता है। यह विपक्ष के साथियों में से किसी को भी पता नहीं है स्पीकर सर, अंतिम बात मैं एग्रीकल्चर सैक्टर के बारे में बोलना चाहता हूं। विपक्ष के साथियों को इस बात को एप्रिशियेट करना चाहिए कि आज हमारे क्षेत्र ने पिछले 5-6-7 साल से जितनी तरक्की की है वह अभूतपूर्व है। आज के दिन पॉली हाऊसिज में जो वेजिटेबल का प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए विपक्ष को सरकार को मुबारकबाद देनी चाहिए क्योंकि इससे प्रदेश में फ्रूट्स और वेजीटेबल्स की प्रोडक्शन बढ़ रही है। किसानों का रूझान इस ओर तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि किसानों के आधे एकड़ के पॉली हाऊस के लिए लोग डेढ़ से दो लाख रुपये वार्षिक तक का ठेका देने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई आधे एकड़ में पॉली हाऊस लगाये तो उसे डेढ़ से दो लाख रुपये की प्रति वर्ष बचत होगी। ये सारी टेक्नॉलोजी वर्तमान सरकार की देन है। इसके साथ ही सरकार इस पर सब्सिडी भी दे रही है।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि अगर माननीय सदस्य प्रदेश में विभिन्न जगहों पर जाकर देखें तो ये पायेंगे कि आधे से ज्यादा पॉली हाऊसिज़ तो बंद पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : माजरा जी, प्लीज़ अब आप बैठ जाइये। बतरा जी, आप कन्कलूड कीजिए।

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, मैं माजरा जी को यह बताना चाहता हूं कि मैंने खुद 2000 गज में पॉली हाऊस लगाया हुआ है जिसको मैंने डेढ़ लाख रुपये प्रति वर्ष के ठेके पर दिया हुआ है। यह पॉली हाऊस मेरे घर के पास खाली पड़ी हुई जमीन पर मैंने बनाया हुआ है जिसे मैंने गांव के आदमी को दिया हुआ है। (विघ्न) आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं चड्ढा साहब को एप्रीशीएट करता हूं और साथ में मुबारकबाद देता हूं कि पॉवर सैक्टर के अंदर जितनी बिजली इन नौ सालों के अंदर पैदा हुई है वह पहले कभी भी पैदा नहीं हुई। आज के दिन हमारा 10 हजार मैगावॉट बिजली पैदा करने का टारगेट है। जो बिजली चोरी की बात की गई है वह बात ठीक है। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि बिजली के बिल के पैसे कम होने चाहिएं। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस बात की भी जिम्मेदारी फिक्स की जाये कि वे कौन सी सरकारें थी जिनके कारण लोगों को यह बिजली चोरी करने की आदत पड़ गई। इस बात का विपक्ष के साथियों को जवाब देना चाहिए कि किस ने यह कहा था कि बिजली के बिल नहीं भरने और इसके साथ यह भी बताया जाये कि कुण्डी कनैक्शन लगाने के लिए लोगों को किस पार्टी ने प्रेरित किया था। अब लोगों को बिजली चोरी की आदत पड़ गई है जो सरकार के भरसक प्रयास करने के बावजूद भी नहीं छूट रही है। स्पीकर सर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री खट्टा साहब का धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य कृपया शांति से बैठ जायें। श्रीमती सरोज मोर अब आप बजट पर अपने विचार रखें।

श्रीमती सरोज मोर (नारनौंद) : स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। सर, मैं यह कहना चाहूंगी कि वर्तमान बजट में महिला सुरक्षा तथा महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों को रोकने के लिए न तो कोई योजना बनाई गई है और न ही विशेष बजट ही अलॉट किया गया है। हमारी सरकार के समय में वर्ष 2002 और वर्ष 2004 में थाना स्तर पर, जिला स्तर पर एवं मण्डल स्तर पर विशेष महिला सैल दस्ता स्थापित किये थे इसलिए उस समय महिला अपराधों में काफी कमी आई थी। इस समय हरियाणा प्रदेश में महिला पुलिस की गश्त व तैनाती भारत सरकार के निर्धारित पैमाने से बहुत ही ज्यादा कम है। महिला एन.जी.ओ. व महिला डी.एस.पी. की संख्या न के बराबर है। महिला पुलिस केवल 2-5 प्रतिशत है। इसलिए उनकी संख्या बढ़ाने का कोई प्रावधान किया जाये। रोजाना अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं हैं तो महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी? मुख्य मंत्री जी का अपने ग्रह जिले में महिलाओं के विरुद्ध अपराध रोकने में प्रथम स्थान है जबकि प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराधों में निरन्तर बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2005 से अब तक अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो घरेलू हिंसा दहेज तथा अनेक संगीन अपराधों में कई गुणा वृद्धि हो चुकी है लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मेरे हल्के की कुछ मांगें हैं जो मैंने पिछले साल भी हाउस में उठाई थी लेकिन अभी तक उन समस्याओं के बारे में कोई विचार नहीं किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नारनौंद हल्के के साथ सौतेला व्यवहार किया हुआ है जो कि उनको नहीं करना चाहिए। नारनौंद को उपमण्डल का दर्जा दिया जाये। राथल, राजपुरा, माढ़ा, माजरा, और बुड़ाना हाई स्कूलों को अपग्रेड किया जाये। इसी प्रकार से नारनौंद में सब्जी मण्डी का निर्माण किया जाये। नारनौंद में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस स्टाफ बढ़ाया जाए तथा पूरे नारनौंद में एक महिला पुलिस कर्मचारी है। महिलाओं की संख्या करीब 2 लाख है। नारनौंद में सी.एच.सी. का दर्जा बढ़ाया जाए। वहाँ पर 12 पोस्टें हैं और उनमें से केवल 4 ही भरी हुई हैं। इसी प्रकार से नारनौंद में सीवरेज की व्यवस्था की सख्त जरूरत है तथा गांव में गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था भी की जाये। पशुओं के लिए तालाबों में पानी भरने के लिए नहरों से पक्का नाला होना चाहिए। राखी गढ़ी गांव हड़प्पा संस्कृति को लेकर पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है लेकिन इसमें पीने का पानी नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था के लिए फंड उपलब्ध करवाया जाये। मेरे हलके के कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर पानी ऊंचाई पर नहीं पहुंचता। शाहपुर, किन्नर, नाड़ा कापड़ो गांवों में बुस्टर पम्प लगवा कर ऊंचाई वाली जगह पर पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाये। इसी प्रकार से गांव बास की उप तहसील में 19 गांव आते हैं न तो उप तहसील भवन है और न ही स्टाफ बैठता है इसलिए इसको तहसील का दर्जा दिया जाए व भवन बनाया जाए क्योंकि यह किराए के मकान में चल रही है। गांव बास में अस्पताल में डॉक्टरों के आवास की व्यवस्था नहीं है जिसकी वजह से डॉक्टर रात को नहीं रूकते और आपातकाल में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसलिए वहाँ पर स्टाफ के लिए आवास की व्यवस्था की जाए। निर्चपुर, खाण्डा व सिसाए गांवों के अस्पतालों में भी डॉक्टर व नर्सों की कमी है। इसी प्रकार से खेतों में ढाणियों को गांव से बिजली प्रदान की जाये। नहरों में टेलों तक पानी नहीं पहुंचता है इसलिए टेलों तक पानी पहुंचाया जाये। सुन्दर ब्रॉच नहर दो सप्ताह चलनी चाहिए जिससे किसानों को पूरा पानी मिल सके। गांव मौल्ला से गाँव उगालन वाया बड़छप्पर गाँव की सड़क पक्की बननी चाहिए। गांव पुट्ठी से गाँव मौल्ला तक पक्की सड़क का निर्माण किया जाये। गाँव पेटवाड़ से गाँव उगालन तक पक्की सड़क बनाई जाये।

[श्रीमती सरोज मोर]

इसके अतिरिक्त गाँव छोटी कोथ से मिर्चपुर तक, डाटा से खानपुर, बास से थुराना, बास से भकलाना तथा बास से खरबला खेड़ा तक पक्की सड़क का निर्माण किया जाये। मेरे पूरे हलके में एक भी सड़क ऐसी नहीं है जिसमें 2-2 फुट के गड्ढे न हों। इसी प्रकार से गांव में बिजली की पुरानी तारों को बदल कर नई तारें लगाई जायें तथा मकानों के ऊपर से बिजली की तारों को हटाया जाये। मेरे हलके नारनौंद के 3 बच्चे कॉमनवैल्थ खेलों में गोल्ड मैडल लेकर आये थे लेकिन सरकार की तरफ से उनको न ही तो कोई सम्मान दिया गया और न ही कोई सरकारी नौकरी दी गई। इसलिए उनको कोई उचित नौकरी व सम्मान प्रदान किया जाये। मैंने पिछली बार भी रिक्वैस्ट की थी कि नारनौंद में स्टेडियम बनवाया जाये लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, नारनौंद में 8 महीने से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है उनको तनख्वाह दी जाये व उनको रेगूलर किया जाये। स्पीकर सर, पूरे हल्के में एक भी सड़क ऐसी नहीं 19.00 बजे है जिनमें दो-दो फुट गड्ढे न हो, जैसा कि भयाणा साहब कह रहे थे, आप इस बारे में इनसे पूछ सकते हैं। जो सड़क नारनौंद से हांसी जाती है वह कुछ दिन पहले नई बनवाई थी लेकिन उसकी रोड़ियां हवा में उड़ रही हैं अभी एक हफ्ते पहले उस सड़क पर मेरी गाड़ी का शीशा भी टूट गया। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस रोड़ को बनवाने की ओर ध्यान दिया जाए और मेरी मांगों पर गौर किया जाये। स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the sitting of the House be extended for another half an hour?

Voices : Yes, Sir.

Mr. Speaker : The time of the sitting of the House is extended by another half an hour.

वर्ष 2014-15 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भण)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, अभी मंत्री जी ने जवाब भी देना है और मैंबर्स ने भी बोलना है अगर हाऊस का समय बढ़ाना है तो आधा घण्टा बढ़ाने की बजाय अभी एक घण्टा इक्ट्ठा ही बढ़ा दो ।

Mr. Speaker : Mr. Panwar, now you may speak. I have to restrict every body to ten minutes. Please don't interfere when any body is speaking.

श्री कृष्ण लाल पंवार (इसराना) : स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा ने वर्ष 2014-15 का जो बजट रखा उस बजट को पढ़ने के बाद कहीं भी यह नजर नहीं आया कि प्रदेश के किसान को, मजदूर को, कर्मचारी को, उद्योगपतियों को किसी को भी कहीं कोई लाभ मिला हो। इसलिए सभी मैंबरों ने सरकार को अलग-अलग डिपार्टमेंट के बारे में आंकड़ों के साथ अवगत कराया है। मैं तो केवल एक ही डिपार्टमेंट के बारे में बोल कर अपनी बात कहूंगा और सरकार को सुझाव दूंगा। सर,

मैं हर बार बोलता हूं और सरकार को सुझाव भी देता हूं कि सरकार इन बातों पर ध्यान दें। जिस प्रकार से अभी चड्ढा साहब ने कहा है कि अभी सन् 2014 में राज्य बिजली उत्पादन में 5300.5 मेगावाट की बढ़ोतरी हो गई है और आज की जो उत्पादन क्षमता है उसमें 10 हजार 277 मेगावाट की हो गई है। इस बजट में 45 सौ करोड़ रुपये का गैर योजनागत व्यय प्रस्ताव रखा है। स्पीकर सर, सरकार बार-बार बड़ा दावा करती है कि बिजली के मामले में हमने बहुत तरक्की की है। मैं आपके सामने पानीपत थर्मल प्लांट के कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा जिसमें एक से चार युनिट हमारी बहुत पुरानी युनिटें हैं जो चल रही हैं। मौजूदा सरकार में छः महीने से हमारे सात प्लांट आज भी बंद पड़े हैं। लेकिन सरकार ने उनका नवीनीकरण करने के लिए 438 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है लेकिन इन्जीनियर्स एसोशिएशन ने सरकार को एक सुझाव दिया है कि सरकार इन प्लांट्स के नवीनीकरण के लिए पैसा भी लगा रही है उसके बावजूद भी ये प्लांट्स चल नहीं रहे हैं। इसलिए सरकार को नौवां और दसवां प्लांट्स लगा लेना चाहिए। इसके लिए एच.पी.जी.सी.एल के एम.डी. ने भी सुझाव दिया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में भी यह सुझाव आया था लेकिन जिन व्यक्तियों ने सरकार को सुझाव दिया था, सरकार ने उनको चेंज कर दिया। सरकार अब एन.टी.पी.सी. से एन.के.बी. रामा राव नाम के एक इन्जीनियर को लेकर आई है जिसको एच.पी.जी.सी.एल का एम.डी. नियुक्त किया है। स्पीकर सर, इसके अलावा सरकार बार-बार यह कहती है।

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य की सूचना के लिए बताना चाहता हूं कि पानीपत थर्मल प्लांट में एक से चार युनिट तक के जो प्लांट हैं वे बहुत पुराने हो गए हैं। इसलिए अब सरकार ने फैसला किया है कि उनको बंद करके एक नया बड़ा प्लांट लगायेंगे जो हर प्रकार से मॉडर्नाइज होगा और बेहतर होगा।

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, मुझे अच्छी तरह से पता है कि पानीपत थर्मल प्लांट में 110 मेगावाट के चार युनिट्स हैं। मंत्री जी ने पहले भी इन युनिटों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 300 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए हैं। मंत्री जी कहते हैं कि हम इनकी कैपेसिटी 117 मेगावाट करेंगे। लेकिन 300 करोड़ रुपये से भी ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी आज वे युनिट्स अपनी जो नोरमल कैपेसिटी होती है उस पर भी नहीं चल रहे हैं और नौ महीने से बंद पड़े हैं। इसके अलावा सरकार कहती है कि प्रदेश के जो प्लांट बंद हैं हमने उनको नो डिमांड पर इसलिए बंद कर रखा है क्योंकि सरकार को अदानी से बिजली सस्ती मिलती है। स्पीकर सर, सरकार कहती है कि हम 2 रुपये 94 पैसे प्रति युनिट के हिसाब से अदानी ग्रूप से बिजली लेते है। उस पर लाइन लोसिज और एफ.एस.ए. लगा कर सरकार को बिजली 4 रुपये से भी ऊपर पड़ती है। सरकार ने अदानी से 25 साल का समझौता किया था कि हम बिजली के कोई रेट नहीं बढ़ाएंगे। सरकार ने अभी लेटेस्ट दोबारा 3 रुपये 33 पैसे प्रति युनिट के हिसाब से रेट रिवाइज किए हैं। स्पीकर सर, यह मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं और मैं तथ्यों पर आधारित बोलता हूं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, आज के दिन हम बिजली का 3 रुपये 26 पैसे के हिसाब से रेट ले रहे हैं और सैंटर रेगुलेटरी कमीशन के पास यह मामला गया हुआ है। अभी वहां पर मामला पैंडिंग है। इस मामले में गुजरात सरकार भी इनवोल्वड है और हमारी सरकार भी इनवोल्वड है रेगुलेटरी कमिशन का जो भी फैसला होगा वह हमें मान्य होगा। इसलिए माननीय सदस्य कोई भी बात कहें तो वह तथ्यों के आधार पर ही कहें ऐसे कोई बात न कहें।

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, मैं कोई गलत बात नहीं कहता हूँ बल्कि मैं तो जो कुछ भी सदन में कहता हूँ वह आँकड़ों के आधार पर ही कहता हूँ। हरियाणा प्रदेश अदानी पॉवर कंपनी लिमिटेड से बिजली खरीद रहा है। इस कंपनी ने सैंट्रैल इलैक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को एक सूट फाइल किया है और लगभग हफ्ता पहले ही उस कमीशन ने सरकार के खिलाफ फैसला दे दिया है कि चूंकि संबंधित कंपनी द्वारा प्रदेश को सस्ती बिजली उपलब्ध करवाई गई है जिससे कंपनी को घाटा हुआ है इसलिए कमीशन ने 409 करोड़ रुपये की रिकवरी हरियाणा प्रदेश की सरकार पर डाल दी है। उस सूट की कॉपी मेरे पास उपलब्ध है। आज प्रदेश के थर्मल पॉवर प्लांट्स बंद होने की वजह से उनमें कार्यरत हजारों कर्मचारी और इंजीनियर्ज खाली बैठे हुए हैं। यमुनानगर थर्मल पॉवर प्लांट में 3 रुपये 85 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली का उत्पादन होता है। हिसार थर्मल पॉवर प्लांट से 3 रुपये 90 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से तथा पानीपत थर्मल पॉवर प्लांट से 4 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली का उत्पादन होता है। इतना अधिक बिजली का उत्पादन हमारे थर्मल पॉवर प्लाँट्स में किया जा रहा है पर बावजूद इसके भी प्राइवेट बिजली कंपनियों से बिजली क्यों खरीदी जा रही है? अक्सर देखने में आ रहा है कि सरकार द्वारा थर्मल पॉवर प्लाँट्स बंद कर दिये जाते हैं। यदि एक बार थर्मल पॉवर प्लाँट्स को बंद करके दोबारा से लाइट अप (चालू) किया जाता है तो कम से कम 70 किलो लीटर तेल खर्च होता है जिसकी कीमत 9-10 लाख रुपये के बराबर होती है। इसी प्रकार से पानीपत की पहली से लेकर चौथी यूनिट का कोयला है (जिसमें इंपोर्टिड कोयला भी शामिल है) उस कोयले के बारे में सरकार ने एक प्रपोजल बनाई है कि उस कोयले को महात्मा गांधी सुपर थर्मल प्लाँट, झाडली में ट्राँसफर किया जायेगा। इंपोर्टिड कोयला इंडोनेशिया से आता है और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा होती है जबकि जो इंडियन कोयला होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। जो अच्छा कोयला यानी (इंपोर्टिड कोयला) है उसको प्राइवेट सैक्टर को दे दिया जाता है तथा जो हमारे थर्मल पॉवर प्लाँट्स हैं उनको घटिया किस्म का कोयला खरीदकर चलाया जा रहा है। इससे सरकार की नीयत जाहिर होती है। इसका साक्षात उदाहरण इस बात से जाहिर हो जाता है कि यमुनानगर थर्मल पॉवर प्लांट तथा हिसार थर्मल पॉवर प्लाँट को चलाने के लिए नंदी कोल लिमिटिड कंपनी से कोयला लिया जा रहा है, जबकि उसकी कैलोरिफिक वैल्यू केवल मात्र 2800 ही प्राप्त हो रही है। अब मैं खेदड़ थर्मल पॉवर प्लाँट के बारे में कहना चाहूँगा। वहां पर 600-600 मैगावाट की दो यूनिट्स हैं। यह यूनिट्स इसलिए बंद रहती है क्योंकि इनमें चाइनीज मशीनरिज का प्रयोग किया गया है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन पैदा हो जाती है और परिणामस्वरूप यह प्लाँट वर्तमान में बंद पड़ा है। स्पीकर सर, अब मैं बिजली चोरी के संबंध में अपने विचार सदन में रखना चाहूँगा। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रदेश में बिजली चोरी एक गम्भीर समस्या है। बिजली चोरी के संबंध में अखबारों में कुछ आंकडें आये थे उनके अलावा मैंने भी अपने लैवल पर कुछ आंकड़े जुटाने की कोशिश की है। इन आंकड़ों को देखकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यदि 11 प्रतिशत बिजली की चोरी पर प्रतिबंध लगा दिया जाये तो प्रदेश को 2200 करोड़ रुपये का मुनाफा होगा। बिजली चोरी के संबंध में मेरे पास 1 अप्रैल, 2013 से लेकर 30 नवम्बर, 2013 तक के कुछ आंकडें मौजूद हैं। इन आंकड़ों को देखकर आप स्वयं अनुमान लगा सकेंगे कि प्रदेश में बिजली चोरी की समस्या कितनी गम्भीर हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में जो किलोई फीडर है उस पर लाइन लॉसिज और एफ.एस.ए. को कुल मिलाकर देखें तो 85.8 प्रतिशत इस फीडर पर बिजली की चोरी दर्ज हुई है। मुख्यमंत्री

जी की ससुराल से संबंधित फीडर पर 80.46 प्रतिशत बिजली की चोरी दर्ज हुई है। बिजली मंत्री जी के रिवाड़ी जिले के तीस गांवों में 43 प्रतिशत से 67 प्रतिशत बिजली की चोरी दर्ज हुई है। बिजली मंत्री जी के जिले में बिजली चोरी प्रतिशतता: कम दर्ज हुई है इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। विधायक जिले राम शर्मा के गांव के फीडर में 81.47 प्रतिशत बिजली की चोरी दर्ज हुई है। स्पीकर सर, मुझे माफ करना, मैं अब आपके क्षेत्र में हुई बिजली की चोरी के बारे में भी बताना चाहूँगा। आपके हल्के के गांव सरदाना, कुमेर, अटेल, खूबडू तथा उदेशीपुर के फीड़रों पर 82 प्रतिशत से 83 प्रतिशत बिजली चोरी दर्ज की गई है। सहकारिता मंत्री सतपाल सांगवान जी के क्षेत्र में आने वाले फतेहगढ़ फीडर में 87.92 प्रतिशत बिजली की चोरी दर्ज की गई है तथा चरखी फीडर में 86.22 प्रतिशत बिजली की चोरी दर्ज की गई है। परिवहन मंत्री आफताब जी के गांव के फीडर में 82 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक की बिजली चोरी दर्ज की गई है।(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : पंवार साहब, आपने अपने क्षेत्र के फीडर्ज की चोरी के बारे में अभी तक नहीं बताया है?

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, मुझे पहले से ही पता था कि आप इस तरह का प्रश्न मेरे से जरूर पूछेंगे, इसलिए मैं अपने क्षेत्र में बिजली चोरी के आंकड़े भी अपने साथ लेकर सदन में आया हूँ। (हंसी) यदि आप यह प्रश्न न भी पूछते तो भी मैं यह बात अपनी रिपोर्ट के लास्ट में जरूर बताता। मेरे क्षेत्र में मात्र 31 प्रतिशत बिजली की चोरी दर्ज की गई है।(विघ्न)

परिवहन मंत्री(चौधरी आफताब अहमद) : पंवार साहब, आप मेरे क्षेत्र के फीड़रों के नाम तो बता दीजिये?

श्री कृष्ण लाल पंवार : आफताब जी, आपके नूंह क्षेत्र के उजीना तथा दसेड़ा गांवों के फीड़रों में 80 से 89 प्रतिशत बिजली की चोरी दर्ज की गई है। इसी प्रकार से हमारे राज्य सभा सांसद श्री बीरेन्द्र सिंह के डूमरखां फीडर में 82 प्रतिशत चोरी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्री राव नरेन्द्र सिंह जी के क्षेत्र में 40-44 प्रतिशत बिजली की चोरी दर्ज की गई है। इसी प्रकार से श्रीमती शारदा राठौर, सी.पी.एस. के क्षेत्र के गाँव दुल्हेड़ा और दाऊदा में 84.60 से 88.26 प्रतिशत बिजली की चोरी दर्ज की गई है और कैथल जिले के बरसाना गाँव में 79.83 प्रतिशत बिजली की चोरी हो रही है। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, बिजली के बिल न भरने की आदत लोगों को किस सरकार के समय में डाली गई। जब पिछली सरकार थी, उस समय लोगों को यह कहा गया था कि न तो बिजली का मीटर होगा और न ही बिजली की रीडिंग नोट करने वाला रीडर होगा।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में 271 फीडरों में 75 से 90 प्रतिशत बिजली की लाइन लॉसिज हो रही हैं। 834 फीडरों में 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत लाइन लॉसिज हो रही हैं और 11 प्रतिशत बिजली की चोरी रोकने से 2200 करोड़ रुपये का रेवेन्यू सरकार को आ सकता है। अध्यक्ष महोदय, आज उपभोक्ताओं पर 4500 करोड़ के बिल बकाया पड़े हैं और 1105 फीडरों में 50 प्रतिशत से ज्यादा बिजली की चोरी हो रही है। 30 मार्च 2000 तक बिजली के बिल की अदायगी के लिए 3 स्लैब बनाए हुए थे और उस समय कोई गरीब आदमी अगर 40 यूनिट महीने में बिजली की कंजम्पशन करता था तो उस पर बिजली के नॉर्मल चार्जिज लगते थे।

श्री अध्यक्ष : पंवार साहब, क्या आप एग्रीकल्चर फीडर की बात कर रहे हो?

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं जिस बारे में बात कह रहा हूँ वह एग्रीकल्चर फीडर नहीं है बल्कि डोमेस्टिक फीडर है। एक गरीब आदमी 1 से 40 यूनिट तक बिजली कन्जूयम करता है तो उस पर नॉर्मल चार्ज लगाये जाते हैं। अब सरकार ने एक नई पॉलिसी बना दी है और पहले वाला स्लैब खत्म कर दिया है। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि वे ठीक नहीं कह रहे हैं। अभी भी प्रदेश में वर्ष 2013 की तर्ज पर ही स्लैब सिस्टम लागू है। क्योंकि जो नई नॉन टेलिस्कॉपिक पॉलिसी बनाई थी उसे सरकार ने रोल बैक कर लिया है।

प्रो० संपत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि स्लैब सिस्टम ही फिर से लागू कर दिया है। मंत्री जी नॉन टेलिस्कॉपिक स्कीम को आपने 1 अप्रैल 2013 से ही इम्पलीमैंट कर दिया गया है। लेकिन 1 जनवरी, 2014 से आपने फिर से टेलिस्कॉपिक स्कीम को लागू कर दिया है। मेरी रिकवेस्ट यह है कि जिस दिन से आपने नॉन टेलिस्कॉपिक स्कीम को इम्पलीमैंट किया था उसी दिन से आप टेलिस्कॉपिक सिस्टम को लागू करें। वरना तो इस प्रकार से कई लोग डिफाल्टर हो गये हैं। मेरी कांस्टीच्यूएंसी में पहले कोई गाँव डिफाल्टर नहीं था। आज 10-15 गाँव डिफॉल्टर हो चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले 9 महीने से जिन लोगों की बिजली के बिलों की बकाया एमाउंट है वे अब नहीं देंगे। इसलिए अब आगे की एमाउंट भी रूकी हुई है। टेलिस्कॉपिक स्कीम को बहाल करने से उन रैगुलर लोगों को मौका मिलेगा। इसके लिए मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। जिस दिन से नॉन टेलिस्कॉपिक स्कीम को इम्पलीमैंट किया गया था उसी दिन से टेलिस्कॉपिक सिस्टम को लागू किया जाये यही मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है। इससे सरकार को बकाया बिलों की रिकवरी भी आयेगी और लोग अपने बिजली के बिलों के रेगुलर पेई भी बन जायेंगे।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट और झाड़ली प्लांट को लगाने में जिन किसानों की जमीन एक्वायर हुई थी उनके परिवार को सरकार द्वारा नौकरी दी जायेगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पानीपत थर्मल पावर प्लांट आता है उसमें खुखड़ाना, आसन्न, उटना और आसन्न खुर्द चार गाँवों की जमीन इस प्लांट को लगाने के लिए एक्वायर की गई थी। आज भी 55-65 प्रतिशत परिवार इन गाँवों के ऐसे रह गये हैं जिनके परिवारों के बच्चों को नौकरी नहीं मिल सकती। इससे पहले कुछ परिवारों के बच्चों को इस थर्मल पावर प्लांट में नौकरी दी गई थी। स्पीकर सर, उस खुखड़ाना गाँव को थर्मल पॉवर प्लांट के पोल्यूशन की वजह से वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। चौटाला सरकार (इंडियन नेशनल लोकदल) के समय में 58 एकड़ जमीन की प्रपोजल इस गाँव को शिफ्ट करने के लिए बनाई गई थी लेकिन अब उसको 16 एकड़ कम करके 42 एकड़ भूमि पर गाँव को शिफ्ट करने की प्रपोजल बनाई जा रही है। इन चार गाँवों के लोगों को मूलभूत सुविधाएँ देने के लिए केवल 17 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है। जोकि बहुत कम है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उसको डबल किया जाये। इसी प्रकार से अखबारों में और टी.वी. चैनलों में आप सभी देखते हैं। रिफाइनरी भारत सरकार का उपक्रम है वह मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थित है। एन.एफ.एल. पानीपत को लगाने के लिए जिन किसानों की जमीन एक्वायर की गई थी। किसान जो लैंड लुजर थे उनकी जमीन गई थी

उन परिवारों के बच्चों को रोजगार दिया गया था। अब इन 5 गाँवों के लोग कई दिनों से नैफथा क्रेशर के सामने धरने पर बैठे हैं। हालांकि यह रिफाइनरी भारत सरकार का उपक्रम है लेकिन सरकार इस रिफाइनरी से काफी टैक्स लेती है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से और सरकार से अनुरोध करूँगा कि जिन किसानों की जमीन रिफाइनरी स्थापित करने के लिए ली गई है उन परिवारों के एक व्यक्ति को रोजगार अवश्य दिया जाये। जब कोई प्लांट लगता है तो उसके आस-पास के गाँवों को सरकार 24 घंटे बिजली देती है। लेकिन इन गावों को बिजली नहीं मिल रही है इसलिए उनकी बिजली की भी माँग है। तीसरा प्वाईंट वहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। रिफाइनरी की गैस गाँव में जाती है। जिसके कारण बहुत ज्यादा स्मैल सारे गाँव में फैल जाती है। उनकी माँग है कि वहाँ ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन की जाये ताकि रिफाइनरी की गैस गाँवों के लोगों तक न पहुँच सके। स्पीकर सर, बिजली बोर्ड पर 18 हजार करोड़ रुपये का कर्जा बकाया है। वर्ष 2014-15 के बजट सत्र में सरकार को बिजली पर 6 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी देनी पड़ेगी या फिर बिजली की दर बढ़ानी पड़ेगी। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 1 अप्रैल, 2012 को 17 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिल बढ़ाये, 1 जुलाई, 2012 को 12 पैसे से 28 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिल बढ़ाये, 1 सितम्बर, 2012 को 17 से 45 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिल बढ़ाये, 1 अप्रैल, 2013 से 70 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिल बढ़ाये और 1 जुलाई, 2013 को 34 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिल बढ़ाये

श्री मामू राम (नीलोखेड़ी) (अ.जा.) : अध्यक्ष महोदय, जो वित्त मंत्री जी ने यहां बजट पेश किया है और आपने जो उस पर बोलने के लिए समय दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सर, वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है वह निराशाजनक, दिशाहीन, दलित विरोधी है तथा इसमें कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मेरा हल्का नीलोखेड़ी काफी पिछड़ा हुआ है, इसमें विकास नाम की कोई चीज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा हल्का नीलोखेड़ी हल्के में 1947 से पॉलिटेक्निक कॉलेज में सभी सुविधाएं जैसे बिल्डिंग, स्टॉफ और मशीनरी होने के बावजूद भी आज तक उसे डिग्री कॉलेज नहीं बनाया है। नीलोखेड़ी हल्के के अंदर चार मण्डियों में से तीन मण्डियां सरकारी हैं, एक प्राइवेट मण्डी निर्सिंग के अन्दर है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्सिंग के अन्दर एक नई मण्डी का दिनांक 2.5.2010 को उद्घाटन किया था। स्पीकर सर, मण्डी के सभी आढ़ती हरियाणा राज्य कृषि विप्पणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक, एग्रीकल्चर कमिश्नर तथा माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे लेकिन उसके बावजूद भी उस मंडी की सभी दुकानें अलॉट नहीं हुई हैं। सभी दुकानें अलॉट होने के बावजूद फिर भी दुकानें बचती हैं। स्पीकर सर, सरकार कहती हैं कि इतने लाइसैंस दायरे में नहीं आते हैं, जबकि सरकार ने ही आढ़तियों के लाइसैंस बनाये तथा उनसे इसके लिए रेवेन्यू फीस ली जाती है। सर, इसमें आढ़तियों का कोई भी कसूर नहीं है। अतः उन सभी आढ़तियों को दुकानें अलॉट की जायें। सर, नीलोखेड़ी हल्के में जो ड्रेनज हैं आज तक उनकी कोई सफाई नहीं हुई है। मैंने वित्त मंत्री जी जोकि सिंचाई मंत्री भी हैं, से अनुरोध किया था कि जो पुराने पुल हैं वे जर्जर हालत में हैं, उन पुलों को दोबारा से बनाया जाये। नीलोखेड़ी हल्के में बिजली की तारें इतनी पुरानी हैं कि उनके टूटने से सण्डीर गांव में एक ब्राह्मण का लड़का गुजर गया तथा तीन भैंसे भी गुजर गई, इस प्रकार के कई हादसे हुए हैं। बिजली की तारों के मामले में मैं संबंधित अधिकारियों से मिलता रहा तो भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जब कोई हादसा हो जाता है, तभी सब अपनी-अपनी गाड़ियां लेकर खड़े हो

[श्री मामू राम]

जाते हैं, ऐसा क्यों ? बिजली के अधिकारियों के ऊपर शिकंजा कसा जाये। सर, बजट में जिक्र किया गया कि सड़कों पर इतने पैसे खर्च किए गए हैं लेकिन नीलोखेड़ी हल्के की सड़कें इतनी खस्ता हालत में हैं कि कोई भी उन पर चल नहीं सकता है। सड़कों की रिपेयर और बनाने के लिए मैंने पिछले सत्र में भी यह प्रश्न उठाया था। जैसे निर्सिंग से डाचर, रायपुर रोड़ान, जी.टी.रोड़ से बड़शालु, अंजनथली से लेकर बड़थल रायपुर रोड़ान, माजरा रोड़ान से बीर बड़ालवा, जाम्बा से किरमिच, शामगढ़ से तरावड़ी, सण्डीर से अमरगढ़, कमालपुर से ऐबला जागीर और सिघंड़ा से मोतिया। इसके साथ मैंने जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री जी से यह भी निवेदन किया था कि जो जोहड़ पानी से भरे हुए हैं लेकिन उनके पानी की निकासी का कोई भी प्रबंध नहीं है। मेरे खुद के गांव गौंदर में भी पानी की निकासी न होने की वजह से हालात इतनी ज्यादा खराब है कि मैं अपने घर से निकलने में भी तंग हूं। इस बारे में मैं डी.सी. से भी मिला लेकिन मेरी समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसी तरह से ब्रास गांव की हालत भी इसी वजह से दयनीय है। इस बारे में सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर जाकर देख सकते हैं। इसी तरह से भाजरा रोड़ान, निगदू गांव की स्थिति भी ऐसी है और वहां के लोगों का भी अपने अपने घर से निकलना मुश्किल हो गया है। वित्त मंत्री जी कहते हैं कि इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है लेकिन ऐसा कोई प्रावधान किया हुआ नजर नहीं आता है। मेरे हल्के के इन गांवों में इतनी ज्यादा दुर्दशा हो रही है कि वहां न नाली है, न सड़क है। हालात ऐसे हैं कि गांव के अंदर भी नहीं जा सकते। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि नीलोखेड़ी हल्के में बिजली के ट्रांसफार्मर की बहुत कमी है जिसकी वजह से किसान मारा मारा फिरता है, ट्रांसफार्मर्स की चोरी हो जाती है और उनकी कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होती है। ट्रांसफार्मर मिलते नहीं हैं, मिलते हैं तो पैसे देकर के मिलते हैं।

Mr. Speaker : Mamu Ram ji, please conclude it.

श्री मामू राम : अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग द्वारा जो कन्यादान स्कीम चलाई गई है उसमें 31 हजार रुपये की जो राशि कन्यादान के लिए दी जाती है वह पात्र परिवारों को एक एक साल तक नहीं मिलती है। इस राशि को पात्रों को समय पर दिलवाया जाए। इन शब्दों के साथ आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए जो समय दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री कली राम पटवारी (सफीदों) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो वित्त मंत्री जी ने यहां बजट पेश किया है उस पर बोलने के लिए समय दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। वर्ष 2009-10 के अंदर बजट में विकास दर 11 प्रतिशत थी जो कि वर्तमान वित्त वर्ष में 6.9 प्रतिशत रह गई है। इस बारे में सदन में सरकार की पीठ थपथपाई गई कि राष्ट्रीय विकास दर 4.9 प्रतिशत थी और हरियाणा प्रदेश की विकास दर उससे दो प्रतिशत ज्यादा है। इस प्रकार से अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश की विकास दर में निरन्तर गिरावट आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे बोलने के लिए ज्यादा समय नहीं देंगे इसलिए मैं अपनी मुख्य बातें शीघ्र कह देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ वित्त मंत्री जी से कहना पड़ता है कि इस बजट के अंदर सफीदों हल्के का किसी भी मामले में जिक्र नहीं है। न अस्पताल का जिक्र है, न सड़क का जिक्र है। मेरे हल्के में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। उनमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि गांव में से जो बिजली के तार गुजर रहे हैं वह तकरीबन सारे टूटे पड़े हैं। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से

कहना चाहूंगा कि उसके बारे में आश्वासन दें कि गांव में जो बिजली के तार टूटे पड़े हैं उनको बदलने का काम किया जाएगा। मेरे हल्के के सिर्फ 15-16 गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था है। कई बड़े बड़े गांव ऐसे हैं जिनके बीच में ऊंचाई पड़ती है और वहां आबादी भी बहुत ज्यादा है। मैंने इस बारे में मंत्री महोदय से प्रश्न भी किया था कि उन गांवों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। ऊंचाई वाली आबादी में अभी पानी नहीं पहुंच रहा है। मेरे हल्के के कुछ गांवों के अंदर तालाब पड़ते हैं जिनमें हाट गांव है, मोरखी है, भम्भेवा है, डाटा है, सिंघाना है, मौहम्मद खेड़ा है व अन्य दूसरे गांव है जिनमें गांवों के बीच में तालाब है और उन तालाबों में पानी भरकर के गांव की गलियों में पानी पहुंच जाता है। उस गंदे पानी की निकासी के लिए क्या इस बजट में प्रावधान करेंगे, यह मैं जानना चाहूंगा। इसके अलावा मेरे हल्के में जो पशु अस्पताल हैं उनमें कुछ अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जिन अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं वहां पर डाक्टरों की व्यवस्था की जाए। इसी तरह से मेरे हल्के में एक पिल्लूखेड़ा अनाज मंडी पड़ती है वहां ब्लॉक भी है उसके तीनों साइड में ड्रेन लगती है एक तो कालवा किनाड़ा ड्रेन है और दो अन्य ड्रेन हैं जिसकी वजह से उस मंडी में पानी भर जाता है पिल्लू खेड़ा की अनाज मंडी में नालियां बनाकर पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सारे प्रदेश की सड़कें टूटी पड़ी हैं और पी.डब्लू.डी. मिनिस्टर साहब यहां सड़कों के बारे में बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं कि इतनी नयी सड़कें बनवाई हैं, इतनी सड़कों की रिपेयर की है। मेरे हल्के की सड़कों के बारे में कहना चाहूंगा कि वहां छीकल लेकर चलना तो दूर की बात है, पैदल भी नहीं चल सकते। सड़कों के अन्दर इतने गड्ढे हैं कि वे सारी की सारी टूटी पड़ी हैं। कुछ सड़कें तो ऐसी हैं जिन पर साईकिल चलाना भी बहुत मुश्किल हैं। ये सड़कें हैं डिडवाना से मलिक पुर, पिल्लुखेड़ा से भम्भेवा, सफीदो से साहनपुर, गांगोली से राम नगर, डाटरथ से मलिकपुर, धर्मगढ़ से मलिकपुर, मोहम्मद खेड़ा से बनिया खेड़ा, कारखाना से बहादुरपुर, बहादुरपुर से सफीदो, कारखाना से कुरड़, पिल्लुखेड़ा से अमरावली, बहादुरगढ़ से मलार, कारखाना से रौझला, हाट से हरीगढ़, बागडू से हाडवा, पिल्लुखेड़ा मण्डी से खेड़ी टलोडा, जामड़ी से पिल्लुखेड़ा मण्डी। स्पीकर सर, ये सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि बजट के अन्दर इन सड़कों को ठीक करने के लिए भी कुछ प्रोविजन किया जाए। इसके बारे में मैंने एक क्वैश्चन भी लगाया था (विघ्न)

Mr. Speaker : Mr. Kali Ram Patwari, your time is over.

श्री कली राम पटवारी : स्पीकर सर, हॉट गाँव का 33 के.वी.ए. का पॉवर हाऊस है जिसके अन्दर 22 गाँव पड़ते हैं उसको 132 के.वी.ए. का बनाया जाए क्योंकि इन गाँवों को बड़ी मुश्किल से चार घण्टे ही बिजली मिल पाती है। इससे पहले वर्ष 1999 से लेकर वर्ष 2004 तक जब चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी की सरकार थी उस समय मेरे हल्के की 18 सड़कें बनाई गई थीं। उसके बाद आज इस सरकार को बने हुए नौ साल हो गये हैं लेकिन इन नौ सालों के समय में मेरे हल्के में एक किलोमीटर सड़क भी नहीं बनाई गई। इसी प्रकार से चौधरी ओमप्रकाश चौटाला की सरकार के समय में मेरे हल्के के नौ माइनर्ज बनाये गये थे उसके बाद पिछले नौ सालों में एक भी माइनर नहीं बनाया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे हल्के की कुछ सड़कों को बनाया जाए जैसे भड़ाना से मोरखी, मोरखी से बागडू, रामनगर से हरीगढ़, शीलाखेड़ी से कारखाना और खेड़ा खेमावती बाई पास। इसके साथ ही सफीदों में एक आई.टी.आई. खोली जाए। पिल्लुखेड़ा मण्डी में एक कन्या महाविद्यालय खोला जाए क्योंकि

[श्री कली राम पटवारी]

सफीदो से 40 किलोमीटर की दूरी तक कोई भी कन्या महाविद्यालय नहीं है। स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं, मैंने यह मुद्दा शुन्यकाल के समय भी उठाया था। हमारे हल्के के किसान उचाना खुर्द में स्वामीनाथन कमिशन की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए 20-20 दिन से धरने पर बैठे थे। उस धरने में मेरे हल्के के गाँव रत्ताखेड़ा के एक किसान राम करण की तीन चार दिन धरने पर बैठने के बाद तबीयत खराब हो गई और जब उसको अस्पताल में लाया गया तो प्रशासन और डाक्टरों की लापरवाही के कारण उस किसान की मृत्यु हो गई। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि उस किसान के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए या उसके किसी लड़के को रोजगार दिया जाए। स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने का जो समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री प्रदीप चौधरी (कालका) : स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए जो समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि मैं खुशनसीब हूं कि मुझे तीन बार हरियाणा प्रदेश का बजट पेश करने का अवसर मिला है। लेकिन झूठे थोथे दावे, बड़े बड़े वायदे और लुभावनी चुनावी घोषणाओं का यह बजट है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणाएं की गई थी वही घोषणाएं इस बजट में दर्शा कर सरकार द्वारा वाह वाही लूटने का प्रयास किया गया है। यह कहा गया कि सरकार ने कर रहित बजट पेश किया है। जनता जो टैक्स देती है वह पैसा सरकारी कोष में जाता है। जनता की आशाएं और आकांक्षाएं इसलिए होती हैं कि हमारे लिए बजट में क्या दिया गया है। सत्ता पक्ष द्वारा बड़े वायदे किए गये कि हर ब्लॉक में, हर विधान सभा क्षेत्र में विकास किया गया है। लेकिन बिजली, सड़क, जल आपूर्ति और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए बड़े वायदे किए गये थे। चार साल के करीब हो गये मैंने जो भी बातें विधान सभा में उठाने का प्रयास आपके माध्यम से किया तो आपने भी हर बार यह कहा कि आप मंत्री जी को लिख कर दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने हर बार शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और जन स्वास्थ्य मंत्री को लिखकर भेजा लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले नौ सालों में हमारे क्षेत्र में कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है। आज मूलभूत सुविधाओं के लिए हमारे क्षेत्र के व्यक्ति तरस रहे हैं। कालका जैसे कस्बे में आज भी पानी की समस्या निरन्तर बनी हुई है। बिजली के उत्पादन के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं लेकिन आज भी हमारे क्षेत्र में बिजली की समस्या बनी हुई है। कई स्थान तो ऐसे हैं जहां बिजली का नामोनिशान नहीं है और बिजली वहां पहुंची नहीं है। मटोर, मोज, मेवास, टिप्परा, निचला कैनन, पलासरा, खेरी खोपर आदि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां बिजली का नामोनिशान तक नहीं है। देश को आजाद हुए बहुत साल हो गए हैं फिर भी ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची है। शिक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बना दी, एजूकेशन हब की बात की जाती है। शिक्षा मंत्री जी यहां बैठी हैं, मैंने इनसे कहा था कि हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ भी है और अधिकतर मोरनी क्षेत्र दुर्गम पहाड़ों में बसा हुआ है। हमारे यहां एजूकेशन का लाभ तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि नियमों में ढील न दी जाए इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में नियमों में ढील दी जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि आप नियमों में ढील मांग रहे हो इसलिए आप शिक्षा मंत्री जी को लिखकर भेज दें तो मैंने शिक्षा मंत्री जी को लिखकर भी भेज दिया लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाऊस की सहमति हो तो हाऊस का समय 30 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए ?

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाऊस का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2014-15 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भण)

श्री प्रदीप चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आज स्वास्थ्य सेवाओं का हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है। आज सड़कों की हालत बहुत खराब है। एन.एच. 73 पंचकूला से मेरे क्षेत्र बाबड़ तक टूटा पड़ा है। आज सरकार द्वारा ट्रांसपोर्ट के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं परंतु मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां न कोई क्यू शैल्टर है और न ही पिंजौर और रायपुररानी जैसी जगह में कोई शौचालय का प्रावधान किया गया है। उद्योग की बात करें तो हमारा जो सूरजपुर सीमेंट प्लांट था वह बंद हो चुका है। सरकार ने 9 सालों में हमारे यहां कोई उद्योग लगाने का काम नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, आज सरकार माइनिंग की बात करते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि आज हजारों लोग इस पर निर्भर हैं। पंजाब में माइनिंग चल रही है लेकिन हरियाणा में बन्द है चाहे बोली हो चुकी है। आज पंचायतों के मामले में हमारे क्षेत्र से भेदभाव किया जाता है। पैसे देने के लिए कहा जाता है कि यह कांग्रेस का सरपंच है इसे पैसे दिए जाएं। हमारे क्षेत्र के साथ निरंतर भेदभाव किया जा रहा है। आज युवाओं को नौकरी देने के मामले में हमारा क्षेत्र निरंतर पिछड़ता जा रहा है। हमारे युवा आज बेरोजगारी में भटक रहे हैं। आज खेल स्टेडियम की बात करते हैं तो सरकार द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि आज गांवों में खेल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। लेकिन हमारे मौली जैसे गांव में खेल स्टेडियम बनाने के बारे में मैंने प्रश्न पूछा था तो मंत्री महोदय ने मना कर दिया। अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार तभी हो सकता है जब हमारे पिछड़े क्षेत्र में और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में ढील देने का काम किया जाएगा। नियमों में ढील दी जाएगी तभी हमारे लोगों को इन समस्याओं से निजात मिलेगी और आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के लोगों को इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। रायपुररानी जैसे क्षेत्र में आज कोई पार्क की व्यवस्था नहीं की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां आज जो सड़कें टूटी पड़ी हैं उनको बनाया जाए। जो हमारा सूरजपुर- सूखु माजरी बाई पास था उसकी घोषणा को लम्बा अर्सा हो गया है। पिछले विधानसभा के दौरान भी मैंने इस बाई पास के बारे में पूछा था और मंत्री जी ने जवाब दिया था कि इस पर जल्दी काम शुरू हो जाएगा लेकिन आज तक इस बाई पास पर काम शुरू नहीं हुआ इसलिए इस पर जल्दी काम शुरू करवाया जाए क्योंकि इससे हमारे पिंजौर के लोगों की यातायात की समस्या बनी हुई है। अध्यक्ष महोदय, यही मेरी मांग है। धन्यवाद सर।

श्री जगदीश नायर (होडल) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए जो समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। 2014 का जो बजट पेश हुआ है इसमें सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी बातें की गई हैं और सरकार के विधायक बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी यूनीवर्सिटीज बनाई गई हैं और शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, कृषि को बढ़ावा दिया गया है परंतु ये सारी बातें वास्तविकता से दूर हैं। मैं सबसे पहले घाटे की बात करता हूं। 81 हजार करोड़ रुपये

[श्री जगदीश नायर]

घाटे का यह बजट है। जब इतना बड़ा घाटा बजट में है तो सरकार कैसे विकास करेगी। यह बजट संतुलित नहीं है, विकासोन्मुखी नहीं है और कर्मचारी विरोधी है।

श्री अध्यक्ष : आप अपने हल्के की बात करें।

श्री जगदीश नायर : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने हल्के की नहीं बल्कि जिले की बात करूंगा। पलवल में किसी भी जगह के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। पलवल में न कोई यूनीवर्सिटी दी गई है और न कोई शिक्षण संस्थान दिया गया है, न कोई विशेष पैकेज दिया गया और न ही पलवल में कोई बड़ा पुल बनाने का जिक्र किया गया। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में कन्या महाविद्यालय की बहुत जरूरत है। इस बारे में मैंने पिछले सैशन में भी अनुरोध किया था और प्रश्न भी लगाया था लेकिन इस बारे में कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया। मेरा अनुरोध है कि होडल विधान सभा क्षेत्र एक ग्रामीण क्षेत्र है इसलिए वहां पर कन्या महाविद्यालय बनाना बहुत जरूरी है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदया प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की बार-बार बात करती हैं। यह केवल खोखला वादा है क्योंकि हकीकत यह है कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरा है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक विकास की बात सरकार करती है इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि होडल विधान सभा क्षेत्र में होडल शहर है जहां पर न पीने के पानी की व्यवस्था है, वहां सीवरेज व्यवस्था भी ठप्प पड़ी है तथा वहां पर गंदे पानी को निकालने के लिए कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की गई है। होडल में माननीय मुख्यमंत्री जी विकास रैली के दौरान वहां 2 करोड़ रुपये विकास कार्यों के लिए देने की घोषणा करके आये थे लेकिन आज तक एक पैसा वहां विकास के नाम पर नहीं पहुंचा है। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने होडल में 100 बैड का हास्पिटल भी बनाने की घोषणा की थी लेकिन वहां के हास्पिटल की बिल्डिंग की हालत बड़ी जर्जर अवस्था में है। इस बारे में मैंने इसी सैशन में मंत्री जी से प्रश्न किया तो मंत्री जी ने जवाब में बताया कि होडल के हास्पिटल की बिल्डिंग के रखरखाव के लिए सरकार ने दो लाख रुपये दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, दो लाख रुपये में तो बिल्डिंग की वाइट-वाश भी नहीं हो सकती। जहां तक होडल में मण्डी के विस्तार करने की बात है इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यू.पी. का एरिया होडल के नजदीक लगता है। यू.पी. के किसानों का भी बहुत अनाज वहां की मण्डी में आता है। वहां पर बहुत बड़ी मण्डी बनाने की आवश्यकता है। जिस समय माननीय चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय वे होडल में 100 एकड़ एरिया पर मण्डी बनाने की घोषणा करके आये थे लेकिन हमारी सरकार जाने के बाद 9 साल हो गये मौजूदा सरकार ने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि होडल में 100 एकड़ एरिया में मण्डी बनाई जाये ताकि वहां के किसानों को इसका लाभ मिल सके। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सड़कों की बात है वित्तमंत्री जी ने बजट में 4438 करोड़ रुपये का जिक्र सड़कों के लिए किया है लेकिन एक्चूवल में यह पैसा 1987.96 करोड़ रुपये खर्च किया जायेगा। मंत्री जी ने इतने पैसे का जिक्र किस प्रकार से किया है यह मेरी समझ से परे है।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है कि बजट पर बड़ी ही अहम चर्चा चल रही है लेकिन कोई भी विभागीय सक्रेटरी या कमीशनर आफिसर गैलरी में नहीं बैठा है। यदि कोई अधिकारी बैठा होता तो वह हमारे सुझाव नोट करता जिनका जवाब सदन में आ सकता था।

श्री जगदीश नॉयर : अध्यक्ष महोदय, अब मैं मेरे हल्के की कुछ सड़कों का जिक्र करना चाहूंगा जिनके लिए बजट में पैसे का प्रावधान किया जाये। ये सड़कें हैं बिरक्की से पैंगलतू, गौडोला से खिरवी डहर वाला रोड़, बोराका से डाडका, लहरपुर से जटौली, गढ़ी से बोराका, गढ़ी पट्टी से बुलवाना, जलालपुर से मरौली, भूपगढ़ से नखरौला, भैडोली से रामगढ़ और रामगढ़ से डराना आदि। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 6 रेलवे फाटक लगते हैं। वहां पर हसनपुर रेलवे फाटक पर पुल बनने का कार्य चल रहा था लेकिन वह बीच में रूक गया। इस बारे में जब मैंने जानकारी हासिल की तो पता चला कि रेलवे विभाग ने तो काम कर दिया है लेकिन हरियाणा सरकार ने अपने हिस्से का पैसा नहीं दिया इसलिए मैं मांग करता हूं कि उस पुल की राशि को जल्द से जल्द पहुंचाने का कष्ट करें। इसी तरह से मेरे हल्के में यमुना नदी पड़ती है इसलिए हसनपुर में यमुना नदी पर भी पुल बनाया जाये। जहां तक पीने के पानी की बात है मेरे हल्के के डाकका, सौंद, बोराका और बंचारी आदि गांवों में पीने के पानी की बहुत समस्या है इसलिए उन गांवों के लिए विशेष स्कीम बनाकर पीने के पानी की व्यवस्था की जाये। (विघ्न)

श्री नसीम अहमद (नूंह) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए जो समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय वित्तमंत्री जी ने जो बजट पेश करके इसमें बड़ी-बड़ी बातें की हैं इसका मैं विरोध करता हूं। बजट में जिक्र किया गया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है जबकि कांग्रेस पार्टी के ही सांसद जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि यदि कोई बलात्कारी प्रदेश है तो वह हरियाणा प्रदेश है, फिर सरकार क्यों बिना वजह कानून व्यवस्था की ठीक स्थिति होने का ढींडौरा पीट रही है। यदि शिक्षा के लिहाज से इस बजट को देखा जाये तो आज प्रदेश में शिक्षा का स्तर पूरी तरह से गिर रहा है। हमारे प्रदेश के अंदर स्कूलों की हालत बहुत खराब है। स्पीकर सर, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे इलाके के बच्चों की जो हालत है वह किसी से छिपी नहीं है। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सरकार ने घोषणा की कि सरकार द्वारा टीचरों की भर्ती की जायेगी। इस भर्ती की घोषणा बहुत देर से की गई है। अगर सरकार द्वारा यह घोषणा सही समय पर की गई होती और उसके अनुसार टीचरों को जल्दी से जल्दी भर्ती कर लिया जाता तो यह प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा होता। आज हमारे प्रदेश का सबसे ज्यादा नाम सी.एल.यू. के मामले में आता है।

Mr. Speaker : Hon'ble Member, please speak on budget. आप अपने हल्के की डिमाण्ड के बारे में बात कीजिए।

श्री नसीम अहमद : स्पीकर सर, माननीय वित्तमंत्री जी ने कहा है कि हमने गुड़गांव क्षेत्र में हज़ारों एकड़ ज़मीन को विकसित करने के लिए प्रयास किये हैं। वित्तमंत्री जी ने ऐसा कहकर प्रदेश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। वित्तमंत्री द्वारा सिर्फ गुड़गांव की बात कही गई है जबकि गुड़गांव के साथ मेवात जिला भी लगता है। सरकार और सरकार के मंत्री यह कहते हैं कि मेवात पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैं यहां पर यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि मेवात पिछड़ा हुआ क्षेत्र नहीं है बल्कि मेवात को इस सरकार ने जानबूझकर पिछड़ा रखा हुआ है। इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि किस प्रकार से वह मेवात जिले को तरक्की के रास्ते पर लाये ताकि मेवात के लोगों की इस सरकार से जो उम्मीदें और आशायें हैं वे पूरी हों। सर, सबसे पहले तो मैं मेवात के पिछड़ेपन के बारे में यह बात कहना चाहता हूं कि अब तक हरियाणा प्रदेश में 3,35,945 नौकरियां लगाई

[श्री नसीम अहमद]

गई हैं जिनमें से मेवात को केवल 9381 नौकरियां दी गई हैं। यह इस बात का सबूत है कि हरियाणा सरकार मेवात के लिए कितनी चिन्तित है जबकि जो दूसरे जिले हैं उनमें सरकार द्वारा नौकरियों की भरमार की हुई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि रोहतक, सोनीपत और झज्जर में जो सरकारी नौकरियों का कोटा दिया हुआ है अगर उसका रुख मेवात की तरफ भी कर दिया जाये तो यह मेवात क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मेरे हल्के की कुछ डिमाण्डज़ हैं जिनको यह सरकार पूरा नहीं करना चाहती। मैंने उन मांगों का जिक्र इससे पहले भी विधान सभा में किया है। फिरोजपुर-झिरका को सब-डिपो बनाने की हमारी बहुत पुरानी डिमाण्ड है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में वहां पर घोषणा भी करके आये थे और मैंने इस बारे में विधान सभा में क्वैश्चन भी दिया था जिसके जवाब में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था कि हम फिरोजपुर-झिरका को सब-डिपो जल्दी से जल्दी बनायेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि फिरोजपुर-झिरका को सब-डिपो बनाने के बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए क्योंकि हमारा क्षेत्र राजस्थान और यू.पी. से सटा हुआ है जिस कारण हमारे यहां इन दोनों राज्यों से बसों का काफी आवागमन होता रहता है। इसलिए मैं पुन: कहना चाहता हूं कि फिरोजपुर-झिरका को सब-डिपो जल्दी से जल्दी बनाया जाये। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि फिरोजपुर-झिरका में कोई खेल स्टेडियम नहीं है इसलिए वहां पर जल्दी से जल्दी एक आधुनिक खेल स्टेडियम बनाया जाये और उसमें सभी खेलों के कोचिज की नियुक्ति भी की जाये। सर, अगर सरकार इस तरफ ध्यान दे तो मेवात के बच्चों में खेल प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। मेवात के बच्चों में बहुत काबिलियत है। इसके लिए अगर उन्हें सही मायनों में उचित प्लेटफार्म मिले तो वे देश और प्रदेश का नाम रोशन करने में पीछे नहीं रहेंगे। हमारे फिरोजपुर-झिरका क्षेत्र में नगीना ब्लॉक पड़ता है उसमें पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है जिसको दूर करने के लिए रेनीवैल प्रोजैक्ट बनाया गया था ताकि वहां पर पानी की कमी को पूरा किया जाये। माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मडियाकी गांव में इस रेनीवैल प्रोजैक्ट का उद्घाटन किया था लेकिन यह परियोजना आज महज एक दिखावा बनकर रह गई है। चौटाला साहब ने इस परियोजना को बड़े उत्साह और लगन के साथ लागू किया था लेकिन इस सरकार ने उसको बिल्कुल दरकिनार करके रखा हुआ है। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उप तहसील, नगीना को तहसील का दर्जा दिया जाये। इसके अलावा मेरी एक और बहुत महत्वपूर्ण डिमाण्ड है कि हमारे नगीना शहर से तिजारा (राजस्थान) एक रास्ता वाया फिरोजपुर जाता है। नगीना से तिजारा (राजस्थान) तक इस रास्ते से जाने से करीब 40 किलोमीटर का अतिरिक्त रास्ता तय करना पड़ता है। अगर इसको नगीना से सीधा तिजारा जोड़ दिया जाये तो यह मात्र पांच किलोमीटर का रास्ता बनता है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से डिमाण्ड है कि इसको तुरन्त बनवाया जाये। अगर सरकार इस रास्ते को बनवा देती है तो इससे हमारी एक बहुत पुरानी डिमाण्ड पूरी हो जायेगी और हरियाणा के साथ-साथ राजस्थान की जनता को भी इससे बहुत राहत मिलेगी। स्पीकर सर, जो एम.डी.ए. का सी.ई.ओ. होता है उसका चार्ज़ मेवात के डी.सी. को दिया हुआ है। मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि एक डी.सी. के पास जिले के दूसरे इतने काम होते हैं कि वह न तो एम.डी.ए. के कामों को देख पाता है और न ही अपने कार्यालय के काम को ही सही ढंग से सम्भाल पाता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वहाँ पर स्वतंत्र सी.ई.ओ. लगाया जाये ताकि मेवात के विकास कार्यों को गति मिल सके क्योंकि

उपायुक्त के पास समय का अभाव होता है और वे मेवात के कार्यों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मेरी एक पर्सनल प्रार्थना है, आपने एक बहुत अच्छी प्रथा डाली है कि आपने विधान सभा में फोटो गैलरी बनवाई है। फिरोजपुर झिरका से हमारे वालिद चौधरी शकरूला खान तीन बार विधायक चुने गये हैं और मंत्री भी रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि उनका फोटो भी फोटो गैलरी में लगाया जाए। इसी तरह से मेवात से ही चौधरी तैयब हुसैन जी एक जाने माने नेता थे और वे तीन स्टेट्स में मिनिस्टर रहे हैं उनका फोटो भी फोटो गैलरी में लगाया जाये।

श्री अध्यक्ष : तैयब हुसैन जी की फोटो तो शायद लगी हुई है, आप अपने पिता जी का फोटो हमें दे दीजिए हम उसको लगवा देंगे।

श्री नसीम अहमद : ठीक है सर, धन्यवाद।

मास्टर धर्मपाल ओबरा (लोहारू) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर बजट की बात करूँ तो बजट संतुलित नहीं है यह बात बजट के आँकड़े स्वयं बताते हैं। इसके अतिरिक्त बजट के दावे भ्रामक और चिंतनीय है। यह बात सच है कि सर्विस सैक्टर के विकास को पश्चिम देशों में उसके समाज के लिए उत्तम माना गया है परन्तु यह तब सम्भव है जब वह समाज उत्पादन क्षेत्र में तकनीकी विकास के कारण एक विशेष स्तर को प्राप्त कर चुका हो परन्तु जो समाज अभी विकासशील देशों की परिभाषा के दायरे में आता हो वहाँ इसे विसंगति और चिन्ता का विषय माना जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे हलके की बात करूँ तो 5 साल से सिवानी खेड़ा गांव में आई.टी.आई. का पत्थर लगाया गया था लेकिन वहाँ पर एक ईंट भी नहीं लगी है। वहाँ पर शिलान्यास के लिए लगाई गई ईंटें तो बची हैं और कुछ भी नहीं है। अब तो वह पत्थर भी उखड़ गया है जो शिलान्यास के लिए लगाया गया था। उस पत्थर पर 8 मंत्रियों के नाम लिखे हुये थे जो उस शिलान्यास के समय मौजूद थे। आज वहाँ पर शिलान्यास की ईंटें तो हैं परन्तु वह पत्थर नहीं है।

जन स्वास्थ्य आभियांत्रिकी मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, जब पत्थर ही नहीं है तो माननीय सदस्य को कैसे मालूम की पत्थर पर 8 मंत्रियों के नाम लिखे हुये हैं।

मास्टर धर्मपाल ओबरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का नाम भी उस पत्थर पर है और सांसद श्रुति चौधरी का नाम भी उस पत्थर पर है। यह मजाक की बात नहीं है बल्कि वास्तविकता है। इसके अतिरिक्त मेरे हलके में 4 अनाज मंडियाँ हैं और कई बार आगजनी की घटना भी हो जाती है और मंडियों में भी आग लग सकती है व किसानों के खलिहानों में भी आग लग सकती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भिवानी से फायरब्रिगेड की गाड़ी जब तक आयेगी तब तक तो सब कुछ जल कर खाक हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इन चारों मंडियों के लिए कम से कम एक-एक फायरब्रिगेड की गाड़ी का इन्तजाम अवश्य किया जाये। इसी तरह से मेरे हलके में से राजस्थान से पत्थर लेकर हर रोज लगभग 2 हजार डम्पर गुजरते हैं तथा हर रोज 1-2 या 3 एक्सीडैंट्स हो जाते हैं। इन दुर्घटनाओं में 2,4,5 आदमी भी अपनी जान गंवा देते हैं जो कि एक चिन्ता का विषय है। हर रोज इसकी खबरें अखबारों में आती हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इन दुर्घटनाओं को रोकने का कोई प्रबन्ध अवश्य किया जाये। मेरे गांव लोहारू में माननीय मुख्य मंत्री जी सी.एच.सी.

[मास्टर धर्मपाल ओबरा]

की घोषणा करके आये थे और स्वास्थ्य मंत्री जी की मेरे साथ वाले गांव में ससुराल भी है। लेकिन आज तक उस सी.एच.सी. में एक ईंट भी नहीं लगाई। तीन साल पहले गांव वालों ने पांच एकड़ जमीन सी.एच.सी. बनाने के लिए दी थी। सर, भिवानी जिले के तीन हल्कों में विशेष तौर पर फव्वारे सैट्स से खेती की जाती है। पहले इन फव्वारे सैट्स पर सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती थी लेकिन अब सरकार ने वह सब्सिडी पूर्ण रूप से बंद कर दी है। आज सरकार की तरफ से फव्वारा सैट्स पर कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है। ड्रीप इरीगेशन पर 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती थी, आज वह भी कम करके 50 प्रतिशत कर दी गई है। अंडर ग्राऊंड पाइप लाइन दबाकर जो सिंचाई की जाती थी आज उस पर भी पूर्ण रूप से सब्सिडी समाप्त कर दी गई है। सर, यह बड़ा चिन्ता का विषय है। आज बाढड़ा, लोहारू, बहल, और आधा हल्का तोशाम के किसानों के लिए सिंचाई का एक मात्र साधन फव्वारा सैट ही है। इसलिए सरकार द्वारा जो फव्वारा सैट्स पर सब्सिडी बंद कर दी गई है उसको दोबारा से चालू किया जाए। स्पीकर सर, मेरे लोहारू हल्के की सिवानी तहसील और आधी बहल तहसील में नीचे का पानी खारा है पीने लायक नहीं है और नहरों में भी वहां पानी नहीं आता है। उस क्षेत्र में जहां-जहां पर डिग्गी बनी हुई है वह सूखी रहती हैं। लोग ट्रैक्टरों से, टैंकरों से पानी लाते हैं जिसके कारण एक टैंकर के एक हजार रुपये देने पड़ते हैं। स्पीकर सर, मैं यह सच्चाई कह रहा हूं मुझे बनावटी बात करने की आदत नहीं है।

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, मैं ओबरा जी को इनके नॉलिज के लिए अपडेट करना चाहती हूं कि इनके क्षेत्र के लिए चालीस गांवों की 80 करोड़ रुपये की एक स्कीम बनाई गई है। वह सारी स्कीम कनाल वॉटर बेस्ड की है जिसके लिए नाबार्ड से पैसा आ रहा है। इस स्कीम की शुरूआत जल्दी ही होने जा रही है जिससे इनके इलाके के लोगों को नहरी पानी भी मिलेगा। आप उसके लिए बेशक सरकार का धन्यवाद कर सकते हैं।

मास्टर धर्मपाल ओबरा : स्पीकर सर, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि सिवानी तहसील में और आधी बहल तहसील में खारा पानी है। मंत्री जी जब कोई स्कीम बन जाएगी तो हम सरकार का धन्यवाद कर देंगे, पहले किस बात का धन्यवाद करें।

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि जब मैंने सदन की पटल पर आश्वासन दे दिया तो समझो वह काम हो गया। आप बेशक धन्यवाद कर सकते हैं।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल (जुलाना) : स्पीकर सर, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट सदन में पेश किया है, मैं उसके विरोध में खड़ा हुआ हूं। इस बजट के सभी दावे खोखले हैं, दिशाहीन हैं और निराशा जनक हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश का बहुत बड़ा क्षेत्र कृषि पर आधारित है और प्रदेश के ज्यादातर लोग कृषि पर डिपेंड रहते हैं। आज कृषि की उत्पादक दर में गिरावट बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है। राज्य के सकल घरेलू उत्पादन का टोटल योगदान 15.1 प्रतिशत दर्ज किया गया , इण्डस्ट्रीयल में 26.9 प्रतिशत दर्ज किया गया और सर्विस सैक्टर में 58 प्रतिशत दर्ज किया गया। सन् 2009-10 में एग्रीकल्चर का घरेलू सकल उत्पादन का जो योगदान था वह 17.3 प्रतिशत था। इण्डस्ट्रीयल का 30 प्रतिशत था जो लगातार घट रहा है। यह बहुत बड़ी चिन्ता का

विषय है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2011-12 में हमारा टोटल उत्पादन 183.70 लाख टन था जो 2012-13 में घट कर 162.26 लाख टन हो गया। इसमें निरन्तर गिरावट आ रही है जोकि बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम किसान के हितैषी हैं और दूसरी तरफ लगातार हरियाणा में उत्पादन दर में गिरावट हो रही है और उसका योगदान भी घटने लग रहा है। इसका मुख्य कारण है कि सरकार कृषि के प्रति उदासीन है। आज हमारे खुद जीन्द जिले में स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए किसान हड़ताल पर बैठे हैं। बार-बार उनकी मुख्य मांग है कि स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए लेकिन हरियाणा सरकार के रवैये से ऐसा नहीं लगता कि वह कम से कम कोई ऐसा प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार के पास भेजें जिससे यह लगे कि हरियाणा सरकार किसानों की सबसे बड़ी हितैषी है। जिस प्रकार से हांसी बुटाना नहर का प्रस्ताव पास किया गया, एस.वाई.एल. का प्रस्ताव पास किया गया, इसी प्रकार से स्वामी नाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए एक प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को भेजने के प्रति सरकार गम्भीर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे क्षेत्र से संबंध रखता हूँ जहां जमीन में न के बराबर पानी उपलब्ध है। यहां पर पीने के पानी की किल्लत भी है और खेतों के लिए भी पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी सिंचाई मंत्री भी हैं। मुझे उनकी ओर से बार-बार आश्वासन दिये गये कि आपके क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए माइनरों का पुन: निर्माण किया जायेगा। मेरे प्रश्न के उत्तर में अभी सिंचाई मंत्री जी ने माना था कि 30-35 साल पहले हरियाणा का सिंचाई सिस्टम बनाया गया था। आज यह सिस्टम इतनी बुरी हालत में हैं कि टेल तक पानी पहुँचना बहुत मुश्किल हो गया है। मेरे प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने इस बात को माना जरूर लेकिन अपने जवाब में मंत्री जी ने यह बात नहीं दर्शाई है कि मंत्री जी द्वारा मुझे तीन साल पहले जो आश्वासन दिया था कि मेरे क्षेत्र के किला जफरगढ़ रजबाहा जिसकी कैपेसिटी 34 क्यूसिक से बढ़ाकर 54 क्यूसिक की जायेगी, वह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसी प्रकार से बराड़ सैक्शन पर भी काम करने के लिए आश्वासन दिया गया था लेकिन वह काम भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। भगवान की दया से अबकी बार इस सरकार का संभवत: यह आखिरी सत्र होगा। इसके बाद मुझे तो लगता नहीं है कि आप दोबारा सत्ता में आयेंगे इसलिए कम से कम इतना तो बता ही दीजिये कि इस बारे में इस बजट में आपने कोई प्रावधान किया है या नहीं? इसी प्रकार से मुझे यह आश्वासन भी दिया गया था कि मेरे हल्के में न्यू बरोली माइनर निकाली जायेगी लेकिन इस बजट के अन्दर भी न्यू बरोली माइनर के लिए पैसे का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। (शोर एवं विघ्न) अब मैं सड़कों के बारे में कहना चाहता हूँ। मेरे अपने जुलाना क्षेत्र में हांसी रोड़ की बहुत बुरी हालत है। यह रोड़ जगह-जगह से टूटा पड़ा हुआ है। मैं सारे हाऊस को इन्वाईट करता हूँ कि वह आकर यहां के रोड़ की कंडीशन को देखे। वहां पर गाड़ी में बैठकर निकलना तो दूर की बात रही, पैदल चलना भी दूभर हो जाता है। तीन साल से यह सड़क खराब है और सरकार की तरफ से भी बार-बार आश्वासन दिये जाते रहे हैं लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। पिछली बार तो यहां तक आश्वासन दे दिया गया था कि 31 मार्च, 2013 तक यह रोड़ बना दी जायेगी लेकिन अब तो 31 मार्च, 2014 भी आने वाला है और कोई रोड़ नही बनाई गई है। अध्यक्ष महोदय, यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसमें हमारे क्षेत्र के प्रति उदासीनता ही परिलक्षित होती है। आज वन्य प्राणी जीव दिवस है। हरियाणा सरकार की तरफ से पिछले दिनों वन्य जीव प्राणियों की सुरक्षा से संबंधित एक विज्ञापन पोस्टर छपवाया गया था। उस विज्ञापन वाले पोस्टर में सरकार ने बड़ी वाहवाही लूटने का काम किया। उस पोस्टर में सरकार द्वारा दिखाया गया

[श्री परमिन्द्र सिंह ढुल]

था कि हरियाणा सरकार वन्य प्राणी जीवों के लिए बहुत सचेत है। हरियाणा सरकार ने "एडॉप्शन ऑफ एनीमल्स" नाम की एक परियोजना चालू की थी और काफी वाहवाही लूटी गई थी। उस परियोजना पर 5.20 लाख रुपये खर्च हुए थे जबकि आमदनी केवल 1.20 लाख रुपये ही हुई थी। यह स्कीम केवल वाहवाही लूटने के लिए ही चलाई गई थी जो किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो सकी और प्रदेश को इस योजना से घाटा ही उठाना पड़ा था। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में 9 वन्य जीवन संरक्षित क्षेत्र हैं। सुल्तानपुर (गुड़गाँव), कलेसर (यमुनानगर), बीड़शिकारगा पंचकूला व खोल-ही-रॉयलान (मोरनी), छिलछिला (कुरुक्षेत्र), नाहड़ (रिवाड़ी), अबूबशहर (सिरसा), भिंडावास एवं खापरवास(झज्जर) इसके अतिरिक्त दो ऐसे संरक्षित केन्द्र और भी हैं जिनमें से सरस्वती वन्य जीव संरक्षण केन्द्र, कैथल और बीरबाराबन वन्य जीव संरक्षण केन्द्र जींद में स्थित हैं। इनके विकास के लिए वर्ष 2012-13 के बजट में 1 करोड़ 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था लेकिन इस बार के बजट में इस राशि को और भी घटा दिया गया है तो कैसे माना जाये कि सरकार वन्य जीव संरक्षण के प्रति गंभीर है? इस तरह के विज्ञापन देकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। इस तरह के व्यवहार से सरकार की वन्य जीवन संरक्षण के प्रति उदासीनता ही नजर आती है। हमारी सरकार वन्य जीवन तथा पर्यावरण के प्रति कितनी उदासीन है उसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि केन्द्र सरकार ने हरियाणा के एक आई.एफ.एस. अफसर की शिकायत को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार को उस मामले की सी.बी.आई. इंक्वॉयरी करवाने के लिए कहा था किन्तु बड़े-बड़े अधिकारियों और मुख्यमंत्री जी के कार्यालय की इन्वोल्वमैंट के कारण वह इंक्वॉयरी नहीं कराई गई, इससे सरकार की वन्य जीवों के संरक्षण एवं पर्यावरण के प्रति गंभीरता की पोल खुल जाती है।

श्रीमती कविता जैन (सोनीपत) : स्पीकर सर, किसी भी प्रदेश के विकास में बजट दिशा-निर्देशक होता है और उसमें आने वाले सुनहरे समय की परिकल्पना जुड़ी हुई होती है। चुनावी वर्ष है और संभवत: प्रदेश सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट सत्र भी है इसके बावजूद भी माननीय वित्त मंत्री जी के बैग से क्या निकला है? इसमें पहले से ही की जा चुकी घोषणाओं के पैसे का प्रावधान या फिर जो काम कर लिये गये हैं उनका गुणगान किया गया है। भविष्य में क्या करना है तथा क्या कांसैप्ट होगा और क्या विजन होगा यह इस बजट में बिल्कुल भी नजर नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष : कविता जी, आप अपने क्षेत्र की बात कर लीजिये, क्योंकि समय की बहुत कमी है?

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, बजट में उत्पादन और रोजगार पर कोई भी जोर नहीं दिया गया है जिससे पता चलता है प्रदेश की प्रगति की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार ने टैक्स फ्री बजट दिया है लेकिन सरकार को यह आश्वासन देना चाहिए कि पिछले सालों की तरह बाद में टैक्स नहीं लगाये जायेंगे। इस प्रदेश और सरकार की वित्तीय हालत इस कदर खराब है कि राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा काफी बढ़ गया है। पिछले 10 वर्षों में जो कुल कर्जा था वह तीन गुणा बढ़ गया है। राजकोषीय घाटे के बढ़ने की वजह से यह साफ पता चल जाता 20.00 बजे है। स्पीकर सर, हरियाणा एक कृषि प्रधान देश है और प्रदेश की सारी की सारी अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी हुई है। कृषि और ग्रामीण विकास पर बजट का केवल 6.09 प्रतिशत खर्च किया गया है। सिंचाई की सुविधाओं के लिए बजट का 3.02 प्रतिशत खर्च किया गया है।

सिंचाई के लिए 2209.75 करोड़ आबंटित किये गये हैं, जो पिछले वर्ष के मुकाबले में 81 करोड़ रुपये कम हैं। स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश में कृषि योग्य भूमि का 45 प्रतिशत हिस्सा असिंचित हैं। बजट में ज्यादातर पैसा नहरों, खालों आदि की मरम्मत के लिए ही दिया गया है। भूमि का बाकी कितना क्षेत्रफल कैसे सिंचित किया जाएगा, इस बारे में बजट में कोई विजन नहीं दिखाया गया है।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the Sitting of the House be extended for 30 minutes?

Voices : Yes, Sir.

Mr. Speaker : O.K., the time of the Sitting of the House is extended for 30 minutes.

वर्ष 2014-15 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भण)

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, बजट में किसानों के लिए विशेष पैकेज के बारे में कुछ नहीं सोचा गया है। जहाँ तक शिक्षा का संबंध है, शिक्षा के लिए पिछले वर्ष भी सबसे अधिक बजट रखा गया था और इस वर्ष भी सबसे अधिक बजट रखा गया है। प्रदेश में नये-नये कॉलेज खोले जा रहे हैं, टैक्निकल इंस्टीच्यूट खोले जा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी एजूकेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस बात का पता पिछले महीने हुई 'HTET' की परीक्षा से पता चलता है जिसमें 3 लाख 36 हजार परीक्षार्थी बैठे थे उनमें से केवल 21000 ही पास हुये हैं। इस बारे में शिक्षकों की जवाबदेही के लिए सरकार को कुछ न कुछ तो जरूर करना चाहिए। सरकार द्वारा इतने तकनीकी संस्थान खोले जा रहे हैं लेकिन बच्चों को रोजगार देने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया जा रहा है। न ही इस बारे में किसी तरह की कोई योजना बनाई जाती है। यही वजह है आज का युवा रोजगार न मिलने के कारण हताश और निराश है। स्पीकर सर, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात इस सदन में जरूर कहना चाहूँगी। आज बहुत सारे सदस्यों ने और खुद मैंने भी, इस बात को बार-बार दोहराया है कि जब हम सदन के पटल पर अपने हल्के के बारे में कोई भी बात कहते हैं, चाहे वह बात किसी भी विभाग से संबंधित हो उस बारे में सरकार द्वारा हमेशा आश्वासन दिया जाता है कि यह काम जल्दी ही पूरा हो जायेगा लेकिन अगला सत्र आ जाता है, कोई भी काम तब तक भी पूरा नहीं हो पाता है। स्पीकर सर, ऑफिसर गैलरी भी खाली पड़ी रहती हैं। स्पीकर सर, आपके माध्यम से सरकार से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि जब गर्वनर एड्रैस या बजट पर चर्चा की जाती है उस समय सदन में विधायकों की तरफ से भी अपने हल्के की माँगे रखी जाती हैं। उन माँगों पर क्या "फोलो-अप" हुआ और क्या एक्शन लिया गया, इस बारे में अगले सत्र में सभी विधायकों को उसका "फीड-बैक" अवश्य मिलना चाहिए। हम आपके माध्यम से सरकार की तरफ से यह आश्वासन चाहते हैं, इस बारे में कोई प्रावधान किया जाये। स्पीकर सर, यह बात आप को भी मालूम होगी कि सोनीपत जिले में 5 प्राईमरी स्कूल्ज ऐसे हैं जो मन्दिरों और चौपालों में चल रहे हैं। यहाँ तक कि पिछले सत्र के दौरान आपने यह कहा था कि आप मुझे लिखकर दे दो, मैं यह काम करवाऊँगा। मुझे जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऑन दि रिकॉर्ड यहाँ पर खड़े होकर बोलना और मंत्री जी को नामों को नोट कराना एक अलग साधना रखता है। पिछले

[श्रीमती कविता जैन]

सत्र में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मुझ से कहा था कि आप मुझे लिखकर दे दें। मैंने शिक्षा मंत्री जी को लिखकर भी दिया लेकिन वह काम अब तक भी नहीं हो पाया है। शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा बजट दिया जाता है। मैंने पिछले पांच सालों में इन पांच स्कूलों के बारे में सरकार को हर बार लिखकर दिया है, परन्तु आज तक उन स्कूलों में से कोई स्कूल अपग्रेड नहीं किया गया है। मैं सिर्फ एजूकेशन डिपार्टमैंट की बात नहीं कर रही हूँ, वह चाहे कोई भी विभाग हो। सभी विभागों की तरफ से सभी माननीय सदस्यों की माँगों के बारे में सत्र के दौरान "फीड-बैक" दिया जाना चाहिए कि उनकी माँगों का क्या हुआ? शहरी क्षेत्र के विकास के लिए इस साल के बजट में पिछले वर्ष के मुकाबले में 106 करोड़ रुपये कम आबंटित किये गये हैं। इसी वर्ष 875 कॉलोनियों को सरकार द्वारा वैध किया गया है अभी उनमें विकास कार्य करवाये जाने बाकी हैं। स्पीकर सर, इतने कम बजट से किस तरह से शहर का विकास किया जायेगा? जहाँ तक सोनीपत शहर की बात है वहाँ के सैक्टर-16 में "टाऊन पार्क" बनना था। पहले भी यह माँग मैं बहुत बार सदन में उठा चुकी हूँ। आज सदन में दोबारा से उसी माँग को मैं रिपिट कर रही हूँ कि सैक्टर-16 के अंदर "टाऊन पार्क" की बहुत आवश्यकता है। इस बारे में सरकार के पास एक प्रस्ताव भी आया था कि इस "टाऊन पार्क" को बनाया जाना चाहिए। स्पीकर सर, सोनीपत शहर में जो पुराना औद्योगिक क्षेत्र है वह आबादी बढ़ने की वजह से अब शहर के बीचों-बीच आ गया है और सरकार ने उस क्षेत्र को अब कॉमर्शियल यूज के लिए घोषित कर दिया है। वहाँ पर सड़कों की बुरी हालत है, सीवरेज ठप्प है, स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था नहीं है। स्पीकर सर, हुडा के सैक्टर 14,15 और 23 में रोड़ और सीवरेज की समस्या है। पार्कों का बुरा हाल है। स्पीकर सर, ड्रेन नम्बर-6 पर शहर में मुरथल रोड़, बड़ालगढ़ रोड़ और बाबा तराना रोड़ पर तीन पुल बने हुए हैं जो बहुत तंग हैं, उनको चौड़ा करने की आवश्यकता है। जलापूर्ति एवं सीवरेज विभाग के बजट में 120 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। विभाग द्वारा नई सीवरेज की लाईनों को डालने के लिए तो पैसा दे दिया जाता है लेकिन जो 4 इंच या 6 इंच की पुरानी सीवरेज लाईनें हैं जहां पर हरदम समस्या रहती है उनको बदलने के लिए सरकार द्वारा पैसा नहीं दिया जाता है। इसी तरह से सीवरेज लाईनों की डीसिल्टिंग के लिए बजट में पैसा नहीं दिया जाता है। स्पीकर सर, शहर की कालोनियों की सीवर लाईन की सफाई के लिए एक नई मशीन की आवश्यकता है। शहर की जो पुरानी सीवरेज लाईन हैं उनको बदलने की आवश्यकता है। धन्यवाद।

राव बहादुर सिंह (नांगल चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय जी ने सदन में जो बजट पेश किया है और आपने मुझे जो उस पर बोलने के लिए समय दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि मेरे जिला महेन्द्रगढ़ में सरकार ने सड़कों को ठीक करने के बड़े ढिंढोरे पीटे थे लेकिन जिला महेन्द्रगढ़ से लेकर जिला भिवानी तक की सड़कों का बुरा हाल है, इसी प्रकार से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बिजली के बारे में भी बात की गई। माननीय परिवहन मंत्री इस समय सदन में मौजूद हैं, उन्होंने सदन में बसों के बेड़े के बारे में कहा है लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में उन्होंने एक भी बस नहीं चलाई है। स्पीकर सर, स्वयं मुख्यमंत्री महोदय या अन्य कोई मंत्री भिवानी से रायमलीपुर तक सड़क पर अपनी गाड़ी से चलकर दिखायें तो उनको मैं 51 हजार रुपये देने का काम करूँगा। स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो हर जगह हेलीकॉप्टर से ही आते-जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में एक महीने में कम से कम चार बार आती-जाती रहती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि माननीय सदस्य मुझे कितनी बार पैसे देंगे। सर, यह ठीक है कि वहां की सड़कों की हालत ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

राव बहादुर सिंह : माननीय मंत्री महोदया, मैं आपकी बात से तो सहमत हूँ। आपको तो पता है कि वहां की सड़कों की हालत क्या है। मैं तो फिर भी कच्चे में चलने वाला हूँ। स्पीकर सर, हमारे जिले से सांसद है, तीन-तीन विधायक हैं और मंत्री भी है फिर भी उनके होने के बावजूद भी सड़कों की हालत खराब है। इनमें से एक भी माननीय सदस्य यह कह दे कि वहां की सड़कें ठीक है। जिस प्रकार से बजट में हर विभाग के बारे में जिक्र किया गया। हम मानते हैं कि माननीय बिजली मंत्री जी हमारे इलाके से हैं। मैंने इनसे बार-बार अनुरोध किया है कि मेरे हल्के में लोहे के खम्भों के कारण काफी जनहानि और पशुहानि हुई है। परन्तु मेरे बार-बार कहने के बावजूद और इस सदन में प्रश्न लगाने के बावजूद भी न तो बिजली के लोहे के खम्भें ही बदले गए हैं और न ही पुरानी बिजली की तारें बदली गई हैं। माननीय खेल मंत्री श्री कटारिया जी भी दक्षिण हरियाणा से है, जो खेलों के बारे में बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारे बच्चे खेलों में काफी नाम कमा रहे हैं। मेरे जिला महेन्द्रगढ के ढांढोत गांव से एक बच्चा एशियाड गेम्स में 11 पदक जीतकर लेकर आया परन्तु सरकार की तरफ से उसको कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया आखिर में हताश होकर उस बच्चे ने उन पदकों को बकरियों के गले में डालकर अपनी फोटो खिंचवानी पड़ी क्योंकि वे पदक उसके किसी भी काम में नहीं आये। ऐसे में खेल मंत्री किस बात का ढिंढोरा पीटते हैं कि सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देती है। माननीय चड्ढा साहब, जोकि सिंचाई मंत्री भी है मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ कि साढ़े चार साल पहले जब कैप्टन अजय सिंह जी सिंचाई मंत्री थे तो मैं उनसे मिला था। उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार करते हुए मेरे हल्के में पानी पहुँचाने का काम किया था। मगर जब से चड्ढा साहब सिंचाई मंत्री बने हैं उसके बाद उस पानी को बंद कर दिया गया है। उस पानी को पता नहीं चड्ढा साहब कुरूक्षेत्र ले गये या अम्बाला ले गये, इस बारे में हमें पता नहीं है।

श्रीमती किरण चौधरी : राव साहब, आप पीने के पानी की बात करेंगे तो मैं जरूर कहूँगी। हमने पीने के पानी की सुविधा प्रदान करने के लिए 300 करोड़ रुपये लगाए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

राव बहादुर सिंह : स्पीकर सर, मैं सिंचाई के पानी की बात कर रहा हूं।

Mr. Speaker : Bahadur Singh ji, please conclude in one minute.

राव बहादुर सिंह : स्पीकर सर, परिवहन मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री जी को खुश करने के लिए जो भी पैसा लगाया वह रोहतक में ही लगाया। स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक भी बड़ा अस्पताल हमारे इलाके को नहीं दिया। अगर किसी का एक्सीडैंट हो जाए तो दूर जाना पड़ता है। ट्रॉमा सैंटर की ये बात करते हैं। इन्होंने नारनौल या महेन्द्रगढ़ में एक भी ट्रॉमा सैंटर नहीं बनाया।

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) : स्पीकर सर, माननीय सदस्य के हल्के के गाँव दौंगड़ा अहीर में पी.एच.सी. बना दी हैं। आप तो राजस्थान में ज्यादा समय रहते हैं इसलिए आपको पता नहीं है।

राव बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि मेरे हल्के में तीन रोज पहले ओलावृष्टि हुई है और उससे किसानों की फसलों का बहुत नुक्सान हुआ है इसलिए वहां गिरदावरी करवाकर सरकार उन किसानों को हुए नुक्सान की भरपाई करने का काम करे। इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री नरेन्द्र सांगवान (घरौंडा) : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो यहां बजट पेश किया है और आपने मुझे उस पर बोलने के लिए जो समय दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। स्पीकर सर, बजट पेश करते समय यह दर्शाया गया है कि यह बजट टैक्स फ्री है और जब सैशन खत्म होता है तो कई तरह के टैक्स हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन के ऊपर थोप दिये जाते हैं और हरियाणा प्रदेश के गठन से लेकर आज तक जितनी भी सरकारें बनीं। 2005 से पहले हमारे प्रदेश के सिर पर 23 हजार करोड़ रुपये के लगभग कर्ज था। इन दस सालों में वह कर्ज बढ़कर 81806 करोड़ रुपये हो गया है। बजट का 76 परसैंट हिस्सा ब्याज की अदायगी और सेलरी में जाएगा। सिर्फ 24 प्रतिशत पैसा प्रदेश के विकास पर खर्च किया जाएगा। स्पीकर सर, बजट के पैरा नंबर 23 से 28 तक प्रबन्ध और प्रावधानों का जिक्र किया गया है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि करनाल, पानीपत, यमुनानगर, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल के साथ लगते लगभग 6 जिले यमुना के साथ लगते हैं और इन जिलों में वाटर लैवल काफी नीचे जा चुका है। सरकार को चाहिए कि इन जिलों में छोटे छोटे बांध बनाकर वहां से रजबाहे निकाले जाएं ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके। इसी तरह से पैरा नंबर 31 में घरौण्डा में सब्जियों एवं सिरसा में फलों के लिए नवीनतम टैक्नोलॉजी को किसानों तक पहुंचाने के लिए और अधिक धन का प्रावधान किया गया है। इसमें सब्जी उद्योग को बेमौसमी बरसात के नुक्सान से बचाने के लिए एवं और अधिक पैदावार करने के लिए बाँस और रस्सी की विधि अपनाने के लिए सब्सिडी देने की आवश्यकता है। खेतों के चारों तरफ कांटेदार तार लगाने के लिए भी सब्सिडी दी जाए जिससे नील गायों से बचाया जा सके। बजट भाषण के पैरा न. 35 में मैट्रो कोरीडोर को दिल्ली से कुण्डली और पानीपत तक लाने के लिए पैसे का प्रावधान किया गया है।

श्री अध्यक्ष : सांगवान जी, धन्यवाद, आप कन्कल्यूड कीजिए।

श्री नरेन्द्र सांगवान : स्पीकर सर, बजट भाषण के पैरा न. 45 में सड़कों के निर्माण के लिए बात कही गई है। मैं अपने जिले की सड़कों की बात करना चाहूंगा। आज हमारे गाँवों के जो लिन्क रोड़ हैं वे जब हरियाणा प्रदेश बना था तभी बनाये गये थे उसके बाद उनको चौड़ा नहीं किया गया है। अब ट्रैफिक ज्यादा बढ़ गया है इसलिए प्रदेश के सभी 90 हल्कों की सड़कों को चौड़ा किया जाए। ऐसा करने से मेरे हल्के के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को भी इससे फायदा होगा।

Mr. Speaker : Now, the Hon'ble Finance Minister will give reply on Budget Estimates.

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर सर, आपकी बहुत मेहरबानी। तकरीबन 20 माननीय सदस्य बजट पर बोल चुके हैं। अब शायद मेरे माननीय भाइयों को खाना याद आ गया है। मैं सभी सदस्यों का बहुत मसकूर हूं। स्पीकर सर, मैं विज साहब को मिर्जा साहब की एक बात

सुनाना चाहता हूं। इन्होंने मिर्जा साहिबा तो जरूर पढ़ा होगा अगर नहीं पढ़ा हो तो ये पढ़ लें। जिसके आखिर में यह लिखा हुआ है कि गलियां होईयां सुनियां, विच मिर्जा यार मिले। उससे पहले यह लिखा हुआ है कि फलाना भी मर जाए, पिण्ड भी सड़ जाएं, यह भी हो जाए, वह भी हो जाए, गाँव की कुतिया भी मर जाएं, फकीर का जो दीया जलता है वह भी बुझ जाए, जब गाँव का बेड़ा बिलकुल सुना हो जाए उस समय मुझे मिर्जा यार मिले। विज साहब तो कुछ सीखते नहीं हैं सिर्फ खोरे पढ़ कर आ जाते हैं। विज साहब का सदन में आने का एक ही मकसद होता है कि कहां क्या उल्टा काम करना है। इनका अब जो हल्का है उसके सारे गाँव मेरे हल्के में चले गये हैं। मैं हाउस में बैठकर यह बात कह रहा हूं कि विज साहब ईमानदारी से सदन में यह बात बताएं कि इनके हल्के के जो गाँव हैं उनकी कोई डिफीकल्टी, कोई मुसीबत, कोई भाड़ी बात आज तक इन्होंने मुझे बताई हो तो मैं झूठा हूं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री महोदय को, फाईनांस डिपार्टमैंट को और बाकी मंत्रियों को जिन्होंने इस बजट को बनाने के लिए साथ दिया है उनको सक्सैसफुल और अच्छा बजट बनाने के लिए मुबारिकबाद देता हूं। कुछ भाइयों ने बजट के फीगर्ज का जिक्र किया, सम्पत सिंह जी ने सारे फीगर्ज पढ़ दिए, बलरा जी ने भी पढ़ दिए और कोई कसर बाकी नहीं रह गई। यूनीवर्सिटीज की बात आ गई कि कितनी यूनीवर्सिटीज बना दी गई। डिवैल्पमैंट की बात भी आ गई और कोई बात नहीं रह गई लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि चौटाला साहब ने कहा कि एयरपोर्ट के लिए 200 करोड़ रुपये क्यों दे दिए गए। चौटाला साहब, बात यह है कि चंडीगढ़ हरियाणा का हिस्सा है। इस तरह की आपकी शायद कोई बात हिस्सेदारी छोड़ने की हो कि हम हिस्सेदारी छोड़ने की बजाय यहां से चले जाना बेहतर समझते हैं और हिस्सेदारी क्यों छोड़ी जाए! हमारे मुख्यमंत्री महोदय की यह बात है कि चंडीगढ़ में हिस्सेदारी नहीं छोड़नी। हिस्सेदारी न छोड़ने के लिए और हम हिस्सेदार बने रहें इसलिए इस एयरपोर्ट का नाम शहीद भगतसिंह के नाम से रखने के लिए जब इन्होंने गवर्नमैंट आफ इंडिया को सजैस्ट किया था उस समय मैं हाजिर था।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। चड्ढा साहब ने अभी जिक्र किया कि 200 करोड़ रुपये इन्होंने हिस्सेदारी के लिए रखा। मैं चड्ढा साहब से एक बात कहना चाहता हूं कि चौधरी भजनलाल जी जब मुख्यमंत्री थे, उस वक्त इन्होंने चंडीगढ़ की हिस्सेदारी छोड़ दी थी। राजीव लौंगोवाल समझौते पर जब ये साइन करके आए थे उस समय ये लिख कर आए थे कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाए इसलिए यह इनकी पार्टी का फैसला था। अगर हम उस लड़ाई को न लड़ते तो चंडीगढ़ पंजाब को चला जाता, हमने तो इसको बचाया है। आपने हिस्सेदारी के लिए नहीं बल्कि केवल मात्र इसलिए 200 करोड़ रुपये खराब कर दिए कि आपको उस मीटिंग में किसी ने बुलाया नहीं और आपने कहा कि मुझे उस मीटिंग में बुला लेंगें तो मैं 200 करोड़ रुपये दे आऊंगा। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कौन सी हिस्सेदारी की। इन्होंने तो 200 करोड़ रुपये बरबाद कर दिए, इन्होंने तो चंडीगढ़ दे दिया था।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्ढा : अध्यक्ष महोदय, अगर हम हिस्सेदारी न करते तो चंडीगढ़ तो गया था लेकिन मुझे दुःख इस बात का है कि ये सिर्फ क्रिटीसाइज इसलिए करते हैं कि हमने तो कुछ न कुछ करना है। मेरे उन सभी साथियों ने भी कहा और इन्होंने भी कहा। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि 9 साल पहले जब इनका राज था इन्होंने बड़ा अच्छा राज किया। मैं इनका क्रिटीसाइज करने के लिए नहीं आया लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि इंडस्ट्रीज में हरियाणा ने क्या डिवैल्पमैंट की है और क्या आगे चले और हरियाणा वहां

[सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा]

का वहां खड़ा है। मुझे एक बात याद है क्योंकि मैं करनाल - कुरूक्षेत्र का रहने वाला हूं और वहां पर एक बड़ा इंडस्ट्रलिस्ट था अब वह बेचारा हरियाणा छोड़कर चला गया और उसकी थोड़ी सी फैक्ट्री यहां रहती है। उसकी फैक्ट्री के सामने उसको तंग करने के लिए इन्होंने एक इतनी गहरी खाई खुदवा दी थी ताकि वह अंदर न जा सके। आखिरकार वह यहां से छोड़कर चला गया। उसका कुछ हिस्सा आगरा चला गया और कुछ दूसरी जगह चला गया तथा कुछ हिस्सा यहां रह गया। हुड्डा साहब ने इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया है। जिस गुडंगाव में गुंडागर्दी होती थी उस गुडंगाव को आजकल लोग टोकियो कहते हैं। गुड़गांव आज कितनी सुंदर टोकियो है? हुड्डा साहब के समय में गुडंगाव में इतनी इंडस्ट्रीज आई जितनी पिछले 40 सालों में नहीं आई। अगर हमारा बजट बढ़ रहा है, हम ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम डिवैल्पमैंट कर रहे हैं। हमने यूनीवर्सिटीज कोई एक नहीं बनाई बल्कि हमने यूनीवर्सिटीज की लाइन लगा दी। अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली की बात है पिछली सरकार के समय में प्रदेश में बिजली की बढ़ौत्तरी के लिए कोई कार्य नहीं किया गया और हमारी सरकार आने के बाद हुड्डा साहब ने बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत से पावर प्लांट लगाये हैं। मैं मानता हूं कि बिजली के क्षेत्र में इतना कुछ करने के बावजूद भी प्रदेश में बिजली की कुछ कमी है। इसका कारण यह है कि दिन ब दिन प्रदेश में बिजली की खपत बढ़ रही है। प्रदेश में बहुत सी नई इण्डस्ट्रीज भी आई हैं और जहां पहले ट्यूबवैल पर 5 एच.पी. की मोटर से काम चल जाता था वहां अब पानी का स्तर नीचे जाने के कारण 30 एच.पी. की मोटर से काम चलता है। जहां पहले एक परिवार केवल एक टेबल फैन लगाकर उसके सामने अपने पूरे परिवार की चारपाई डालकर सौ जाते थे वहां अब हर घर में ए.सी. आ गये हैं जिसके कारण बिजली की खपत प्रदेश में बहुत बढ़ गई है। आप आज के दिन चाहे जितनी मर्जी बिजली पैदा कर लें फिर भी बिजली की कमी रहेगी ही रहेगी। हमने प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदा करने की कोशिश की है और प्रदेश के लोगों को पूरी बिजली दी है। हमारे बिजली के 4 यूनिट खराब होने के बावजूद भी हम प्रदेश में बिजली की पूरी सप्लाई दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सिंचाई की बात आई इस बारे में कुछ माननीय साथियों ने प्वायंट रेज किया कि सरकार ने स्प्रिंकलर सैट्स और सिंचाई के लिए यूज की जाने वाली पाईप्स पर सब्सिडी देनी बंद कर दी है। इस बारे में मैं सदन में बताना चाहूंगा कि हम स्प्रिंकलर सैट्स और पाईप्स दोनों पर सब्सिडी दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस समय हम गन्ने का रेट बढ़वाने की बात करते थे उस समय हम पानी में भीगकर आते थे जबकि आज प्रदेश में किसानों को गन्ने का सबसे ज्यादा भाव दिया जा रहा है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है कि वित्तमंत्री जी यह भी बता दें कि उस समय किस पार्टी की सरकार प्रदेश में थी ? (विघ्न)

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, उस समय किस पार्टी की सरकार थी यह तो मैं भी नहीं बताऊंगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक एग्रीकल्चर प्रोडैक्शन की बात है चाहे गन्ने के प्रोडैक्शन की बात है, चाहे व्हीट के प्रोडैक्शन की बात है, चाहे पैडी के प्रोडैक्शन की बात है यानि हर फसल की प्रोडैक्शन में किसानों को सुविधा हुई है, कोई असुविधा नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, यहां पर मण्डियों का भी जिक्र किया गया इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि मैं भी और हुड्डा साहब भी चाहते हैं कि मण्डियां और आढ़ती रहें। आढ़ती और किसानों का भाई-भाई तथा दोस्तों जैसा

रिश्ता रहता है। मुसीबत में आढ़ती किसान के काम आता है और इस बात को हम समझते हैं इसलिए हुड्डा साहब ने आढ़ती को भी बचाकर रखा है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश में आढ़ती, आढ़ती की तरह ही रहेंगे उनको कोई नुक्सान नहीं होगा। किसी को यह एप्रीहैंशन नहीं रखना चाहिए कि यदि बड़े-बड़े लोग आ जायेंगे तो आढ़ती डूब जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने अपनी डिमांड रखी हैं उनको मैंने और संबंधित मंत्रियों ने नोट कर लिया है, उनको हम पूरा करने का हर संभव यत्न करेंगे। इनके बारे में किसी माननीय सदस्य को दोबारा नहीं कहना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं विज साहब को कहना चाहूंगा कि मैं भी उनके हल्के से दो-तीन दफा चुनकर आया हूं। उनसे मुझे विशेष लगाव है, यदि उनको कोई तकलीफ होगी तो मैं एक टांग पर चलकर उनकी तकलीफ को दूर करूंगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं प्रार्थना करता हूं कि बजट को पास किया जाये।

वर्ष 2014-15 के बजट की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now discussion and voting on the demands for Grants on Budget Estimates for the year 2014-2015 will take place.

As per the past practice and in order to save the time of the House, all the demands for Grants (Nos. 1 to 45) on the order paper will be deemed to have been read and move together. Hon'ble Members can discuss any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise discussion.

That a sum not exceeding **₹ 63,66,12,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 1–**Vidhan Sabha.**

That a sum not exceeding **₹ 95,49,00,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 2–**Governor & Council of Ministers.**

That a sum not exceeding **₹ 169,63,58,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 3–**General Administration.**

That a sum not exceeding **₹ 891,38,26,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 4–**Revenue.**

That a sum not exceeding **₹ 181,75,73,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 5–**Excise & Taxation.**

That a sum not exceeding **₹ 4565,51,04,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 6–**Finance.**

[Mr. Speaker]

That a sum not exceeding ₹ **409,03,97,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 7–**Planing and Statistics.**

That a sum not exceeding ₹ **1159,11,53,000 for revenue expenditure** and ₹ **2073,62,25,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 8–**Buildings & Roads.**

That a sum not exceeding ₹ **9459,10,86,000 for revenue expenditure** and ₹ **27,23,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 9–**Education.**

That a sum not exceeding ₹ **491,20,00,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 10–**Technical Education.**

That a sum not exceeding ₹ **183,27,97,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 11–**Sports & Youth Welfare.**

That a sum not exceeding ₹ **12,74,89,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 12–**Art & Culture.**

That a sum not exceeding ₹ **2699,86,71,000 for revenue expenditure** and ₹ **75,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 13–**Health.**

That a sum not exceeding ₹ **136,07,82,000 for revenue expenditure** and ₹ **800,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 14–**Urban Development.**

That a sum not exceeding ₹ **2070,98,14,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 15–**Local Government.**

That a sum not exceeding ₹ **36,74,00,000 for revenue expenditure** and ₹ **10,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 16–**Labour.**

That a sum not exceeding ₹ **79,86,00,000 for revenue expenditure** and ₹ **1,60,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 17–**Employment.**

That a sum not exceeding ₹ **208,44,90,000 for revenue expenditure** and ₹ **58,20,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 18–**Industrial Training.**

That a sum not exceeding ₹ **365,09,31,000 for revenue expenditure** and ₹ **3,22,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 19–**Welfare of SCs & BCs.**

That a sum not exceeding ₹ **2909,22,16,000 for revenue expenditure** and ₹ **1,81,50,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 120–**Social Security & Welfare.**

That a sum not exceeding ₹ **886,10,43,000 for revenue expenditure** and ₹ **170,48,50,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 21–**Women & Child Development.**

That a sum not exceeding ₹ **79,09,31,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 22–**Welfare of Ex-servicemen.**

That a sum not exceeding ₹ **366,66,44,000 for revenue expenditure** and ₹ **8806,61,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 23–**Food and Supplies.**

That a sum not exceeding ₹ **1621,54,23,000 for revenue expenditure** and ₹ **510,24,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 24–**Irrigation.**

That a sum not exceeding ₹ **91,04,14,000 for revenue expenditure** and ₹ **102,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 25–**Industries.**

That a sum not exceeding ₹ **10,31,00,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 26–**Mines & Geology.**

[Mr. Speaker]

That a sum not exceeding **₹ 1254,54,25,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 27–**Agriculture.**

That a sum not exceeding **₹ 556,07,20,000 for revenue expenditure** and **₹ 20,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 28–**Animal Husbandry & Dairy Development.**

That a sum not exceeding **₹ 31,14,75,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 29–**Fisheries.**

That a sum not exceeding **₹ 315,40,80,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 30–**Forests & Wildlife.**

That a sum not exceeding **₹ 6,88,00,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 31–**Ecology & Environment.**

That a sum not exceeding **₹ 2503,00,62,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 32–**Rural & Community Development.**

That a sum not exceeding **₹ 246,58,98,000 for revenue expenditure** and **₹ 42,79,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 33–**Co-operation.**

That a sum not exceeding **₹ 1878,38,40,000 for revenue expenditure** and **₹ 196,20,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 34–**Transport.**

That a sum not exceeding **₹ 3,19,60,000 for revenue expenditure** and **₹ 31,50,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 35–**Tourism.**

That a sum not exceeding **₹ 2598,67,58,000 for revenue expenditure** and **₹ 124,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 36–**Home.**

That a sum not exceeding ₹ **100,22,99,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 37–**Elections.**

That a sum not exceeding ₹ **1427,29,00,000 for revenue expenditure** and ₹ **1000,20,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 38–**Public Health & Water Supply.**

That a sum not exceeding ₹ **145,61,82,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 39–**Information & Publicity.**

That a sum not exceeding ₹ **4533,76,50,000 for revenue expenditure** and ₹ **5,00,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 40–**Energy & Power.**

That a sum not exceeding ₹ **26,66,85,000 for revenue expenditure** and ₹ **1,10,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 41–**Electronic & IT.**

That a sum not exceeding ₹ **351,54,03,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 42–**Administration of Justice.**

That a sum not exceeding ₹ **148,06,00,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 43–**Prisons.**

That a sum not exceeding ₹ **35,69,61,000 for revenue expenditure** and ₹ **7,90,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 44–**Printing & Stationery.**

That a sum not exceeding ₹ **1001,40,50,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 45–**Loans & Advances by State Government.**

(No Member rose to speak.)

Mr. Speaker : Now, the demands will be put to the vote of the House.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding ₹ **63,66,12,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 1–**Vidhan Sabha.**

That a sum not exceeding **₹ 95,49,00,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 2–**Governor & Council of Ministers.**

That a sum not exceeding **₹ 169,63,58,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 3–**General Administration.**

That a sum not exceeding **₹ 891,38,26,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 4–**Revenue.**

That a sum not exceeding **₹ 181,75,73,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 5–**Excise & Taxation.**

That a sum not exceeding **₹ 4565,51,04,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 6–**Finance.**

That a sum not exceeding **₹ 409,03,97,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 7–**Planning and Statistics.**

That a sum not exceeding **₹ 1159,11,53,000 for revenue expenditure** and **₹ 2073,62,25,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 8–**Buildings & Roads.**

That a sum not exceeding **₹ 9459,10,86,000 for revenue expenditure** and **₹ 27,23,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 9–**Education.**

That a sum not exceeding **₹ 491,20,00,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 10–**Technical Education.**

That a sum not exceeding **₹ 183,27,97,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 11–**Sports & Youth Welfare.**

That a sum not exceeding **₹ 12,74,89,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 12–**Art & Culture.**

That a sum not exceeding ₹ **2699,86,71,000 for revenue expenditure** and ₹ **75,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 13–**Health.**

That a sum not exceeding ₹ **136,07,82,000 for revenue expenditure** and ₹ **800,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 14–**Urban Development.**

That a sum not exceeding ₹ **2070,98,14,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 15–**Local Government.**

That a sum not exceeding ₹ **36,74,00,000 for revenue expenditure** and ₹ **10,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 16–**Labour.**

That a sum not exceeding ₹ **79,86,00,000 for revenue expenditure** and ₹ **1,60,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 17–**Employment.**

That a sum not exceeding ₹ **208,44,90,000 for revenue expenditure** and ₹ **58,20,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 18–**Industrial Training.**

That a sum not exceeding ₹ **365,09,31,000 for revenue expenditure** and ₹ **3,22,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 19–**Welfare of SCs & BCs.**

That a sum not exceeding ₹ **2909,22,16,000 for revenue expenditure** and ₹ **1,81,50,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 20–**Social Security & Welfare.**

That a sum not exceeding ₹ **886,10,43,000 for revenue expenditure** and ₹ **170,48,50,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 21–**Women & Child Development.**

That a sum not exceeding ₹ **79,09,31,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 22–**Welfare of Ex-servicemen.**

[Mr. Speaker]

That a sum not exceeding **₹ 366,66,44,000 for revenue expenditure** and **₹ 8806,61,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 23–**Food & Supplies.**

That a sum not exceeding **₹ 1621,54,23,000 for revenue expenditure** and **₹ 510,24,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 24–**Irrigation.**

That a sum not exceeding **₹ 91,04,14,000 for revenue expenditure** and **₹ 1,02,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 25–**Industries.**

That a sum not exceeding **₹ 10,31,00,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 26–**Mines & Geology.**

That a sum not exceeding **₹ 1254,54,25,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 27–**Agriculture.**

That a sum not exceeding **₹ 556,07,20,000 for revenue expenditure** and **₹ 20,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 28–**Animal Husbndry & Dairy Development.**

That a sum not exceeding **₹ 31,14,75,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 29–**Fisheries.**

That a sum not exceeding **₹ 315,40,80,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 30–**Forests & Wildlife.**

That a sum not exceeding **₹ 6,88,00,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 31–**Ecology & Environment.**

That a sum not exceeding **₹ 2503,00,62,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 32–**Rural & Comunity Development.**

That a sum not exceeding ₹ **246,58,98,000 for revenue expenditure** and ₹ **42,79,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 33–**Co-operation.**

That a sum not exceeding ₹ **1878,38,40,000 for revenue expenditure** and ₹ **196,20,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 34–**Transport.**

That a sum not exceeding ₹ **3,19,60,000 for revenue expenditure** and ₹ **31,50,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 35–**Tourism.**

That a sum not exceeding ₹ **2598,67,58,000 for revenue expenditure** and ₹ **124,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 36–**Home.**

That a sum not exceeding ₹ **100,22,99,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 37–**Elections.**

That a sum not exceeding ₹ **1427,29,00,000 for revenue expenditure** and ₹ **1000,20,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 38–**Public Health & Water Supply.**

That a sum not exceeding ₹ **145,61,82,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 39–**Information & Publicity.**

That a sum not exceeding ₹ **4533,76,50,000 for revenue expenditure** and ₹ **5,00,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 40–**Energy & Power.**

That a sum not exceeding ₹ **26,66,85,000 for revenue expenditure** and ₹ **1,10,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 41–**Electronics & IT.**

That a sum not exceeding ₹ **351,54,03,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 42–**Administration of Justice.**

[Mr. Speaker]

That a sum not exceeding **₹ 148,06,00,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 43--**Prisons.**

That a sum not exceeding **₹ 35,69,61,000 for revenue expenditure** and **₹ 7,90,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 44--**Printing & Stationery.**

That a sum not exceeding **₹ 1001,40,50,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2014-15 in respect of charges under Demand No. 45--**Loans and Advances by State Government.**

The motion was carried.

विधान कार्य

(i) दि ईस्ट पंजाब यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड्स (हरियाणा अमैंडमैन्ट) बिल, 2014

Mr. Speaker : Now, the Revenue Minister will introduce the East Punjab Utilization of Lands (Haryana Amendment) Bill, 2014 and will also move the motion for its consideration.

Revenue Minister (Shri Mahendra Pratap) : Sir, I beg to introduce the East Punjab Utilization of Lands (Haryana Amendment) Bill, 2014.

Sir, I also beg to move-

That the East Punjab Utilization of Lands (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the East Punjab Utilization of Lands (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is-

That the East Punjab Utilization of Lands (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub-Clause 2 of Clause 1

Mr. Speaker : Question is-

That Sub-Clause 2 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 4 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause 1 of Clause 1

Mr. Speaker : Question is-

That Sub-Clause 1 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Revenue Minister will move that the Bill be passed.

Revenue Minister (Shri Mahendra Pratap) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(ii) दि हरियाणा वैल्यू ऐडिड टैक्स (अमैंडमैन्ट) बिल, 2014

Mr. Speaker : Now, the Excise & Taxation Minister will introduce the Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill, 2014 and will also move the motion for its consideration.

Excise & Taxation Minister (Smt. Kiran Chaudhary) : Sir, I beg to introduce the Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill, 2014.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is-

That the Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 4 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Excise & Taxation Minister will move that the Bill be passed.

Excise & Taxation Minister (Smt. Kiran Chaudhary) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iii) दि पंजाब शिड्यूल्ड रोड्ज एंड कंट्रोल्ड एरियॉज रिस्ट्रिक्शन ऑफ अनरैगुलेटिड डिवैलपमैंट (हरियाणा अमैन्डमैंट) बिल, 2014

Mr. Speaker : Now, A Minister will introduce the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill, 2014 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Aftab Ahmed) : Sir, I beg to introduce the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill, 2014.

Sir, I also beg to move-

That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

प्रो. सम्पत सिंह(नलवा) : स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि यह प्रीतम सिंह वर्सिज़ टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग के डायरैक्टर का जो केस था जिसमें ट्रिब्यूनल बैठा था, उस मामले में सरकार ने एक बहुत ही अच्छा फैसला किया है। क्या यह फैसला for all purposes है? टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग की वजह से साथ लगते आबादी देह एरिया की कोई डैफीनेशन नहीं थी इसलिए इसको पैरीफैरी तक कर दिया गया है। सभी गांवों की फिरनियों और लाल डोरे के बीच में जो एरिया है जिसमें अब आबादी बस गई है इसमें जो सुविधायें होंगी क्या वे हर गांव के लिए होंगी?

Mr. Speaker : Question is-

That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restrictions of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Minister will move that the Bill be passed.

Transport Minister (Shri Aftab Ahmed) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the Sitting of the House be extended for 15 minutes?

Voices : Yes

Mr. Speaker : The time of the Sitting of the House is extended for 15 minutes.

विधान कार्य (पुनरारम्भण)

(iv) दि हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रैग्यूलेशन ऑफ सोसायटीज (अमैंडमैंट) बिल, 2014

Mr. Speaker : Now, A Minister will introduce the Haryana Registration and Regulation of Societies (Amendment) Bill, 2014 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Aftab Ahmed) : Sir, I beg to introduce the Haryana Registration and Regulation of Societies (Amendment) Bill, 2014.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Registration and Regulation of Societies (Amendment) Bill be taken into consideration.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Haryana Registration and Regulation of Societies (Amendment) Bill be taken into consideration.

Mr. Speaker : Question is-

That the Haryana Registration and Regulation of Societies (Amendment) Bill be taken into consideration.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub-Clause 2 of Clause 1

Mr. Speaker : Question is-

That Sub-Clause 2 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause 1 of Clause 1

Mr. Speaker : Question is-

That Sub-Clause 1 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Minister will move that the Bill be passed.

Transport Minister (Shri Aftab Ahmed) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(v) दि हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्ज (टैम्परेरी रिलीज) अमैंडमैंट बिल, 2014

Mr. Speaker : Now, A Minister will introduce the Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Bill, 2014 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Aftab Ahmed) : Sir, I beg to introduce the Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Bill, 2014.

Sir, I also beg to move-

That the Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री रामपाल माजरा (कलायत) : अध्यक्ष महोदय, जो कैदी पैरोल पर बाहर आ जाते हैं और पैरोल जम्प कर जाते हैं और वापिस में नहीं जाते क्या उनके बारे में भी इस बिल में कोई प्रावधान किया गया है या नहीं, क्या उनको गिरफ्तार किया जायेगा या नहीं ?

Mr. Speaker : Question is-

That the Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Minister will move that the Bill be passed.

Transport Minister (Shri Aftab Ahmed) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(vi) दि प्रिजन्स(हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2014

Mr. Speaker : Now, A Minister will introduce the Prisons (Haryana Amendment) Bill, 2014 and also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Aftab Ahmed) : Sir, I beg to introduce the Prisons (Haryana Amendment) Bill, 2014.

Sir, I also beg to move-

That the Prisons (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Prisons (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री रामपाल माजरा (कलायत) : अध्यक्ष महोदय, जेलों में बहुत ज्यादा नशीले पदार्थ सप्लाई होते हैं उसके बारे में सरकार को कुछ करना चाहिए।

Mr. Speaker : Question is-

That the Prisons (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Minister will move that the Bill be passed.

Transport Minister (Shri Aftab Ahmed) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, the House stands adjourned till 10.00 A.M. tomorrow, the 4th March, 2014.

*20.40 Hrs. (The Sabha then *adjourned till 10.00 A.M. Tuesday, the 4th March, 2014.)

Haryana Vidhan Sabha Secretariat ★ LIBRARY ★ Chandigarh

52298—H.V.S.—H.G.P., Chd.